www.chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

संसद को अरविंद केजरीवाल का जवाब

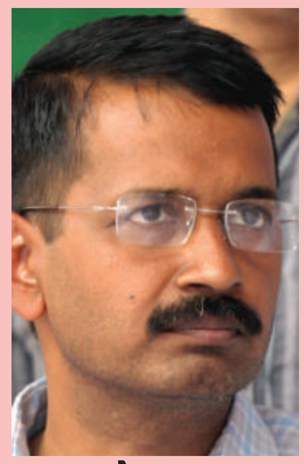

पेज-3

सरकारी लोकपाल कैसे धोखा है

पेज-7

जनता से टकराने की कोशिश मत कीजिए

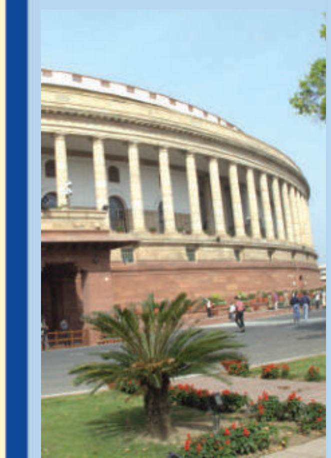

पेज-9

ईमानदारी की क़ीमत चुकाता सरपंच

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 09 अप्रैल-15 अप्रैल 2012 | मूल्य 5 रुपये

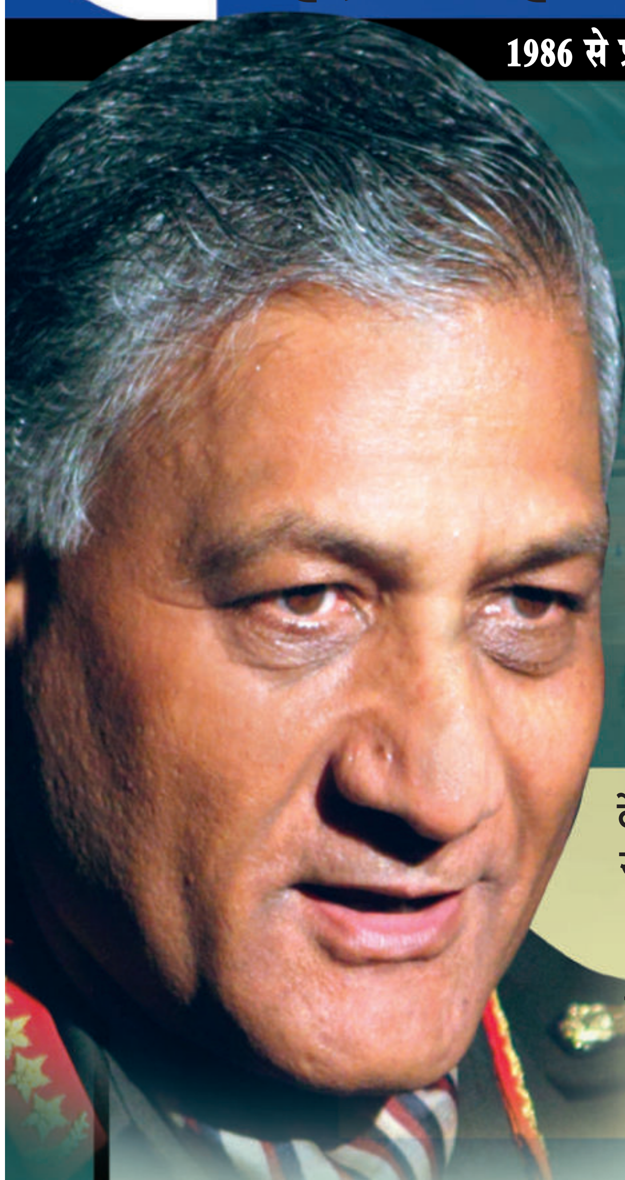

# जनरल वी के सिंह की भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग

**टेट्रा ट्रक में घोटाले की ख़बर सोनिया गांधी को थी, कांग्रेस पार्टी केअहम नेता गुलाम नबी आजाद को थी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी को थी. यह खुलासा कांग्रेस के ही एक नेता हनुमनथप्पा की चिट्ठी से हुआ है. इसलिए अब यह मामला सिर्फ जनरल वी के सिंह का नहीं है. यह मामला अब देश की सुरक्षा और सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे का है. जनरल वी के सिंह ने चौथी दुनिया को दिए गए इंटरव्यू में सिर्फ़ घूसखोरी के ऐसे सच को बताया, जिसके बारे में सरकार और कांग्रेस पार्टी को पहले से पता था. इसलिए अब इस विवाद में सरकार ख़ासकर रक्षा मंत्रालय को कुछ कठिन सवालों का जवाब देना है. अब रक्षा मंत्री ए के एंटनी यह कहकर अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं छिटक सकते कि जनरल वी के सिंह ने लिखित शिकायत नहीं की.**

मनीष कुमार

टेट्रा ट्रक घोटाले के मामले में सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है. जब चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ संतोष भारतीय को दिए गए इंटरव्यू में थलसेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने घूस की पेशकश करने के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया, तब ए के एंटनी ने संसद में जवाब दिया. रक्षा मंत्री ने पूरी घटना को सही बताया और कहा कि, उन्होंने जनरल वी के सिंह से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा था. ए के एंटनी ने यह दलील दी कि जनरल वी के सिंह ने कोई लिखित शिकायत नहीं की थी, इसलिए वह खुद कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे. अब सवाल यह है कि ए के एंटनी ने संसद में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी. उन्होंने यह क्यों नहीं बताया कि जनरल वी के सिंह से पहले भी टेट्रा ट्रक के मामले में शिकायत आ चुकी है.

डॉ. एच हनुमनथप्पा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके हैं. टेट्रा ट्रक के विवाद पर उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिससे सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद, रक्षा मंत्री ए के एंटनी के साथ कई कांग्रेस नेताओं का नाम इस विवाद से जुड़ गया है. डॉ. एच हनुमनथप्पा के मुताबिक, उन्होंने सोनिया गांधी एवं ए के एंटनी से मुलाकात की और टेट्रा ट्रक की ख़रीददारी में गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी तथा दस्तावेज़ पेश किए. यह बात वर्ष 2009 की है. डॉ. एच हनुमनथप्पा के मुताबिक़, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और रक्षा मंत्री ए के एंटनी को टेट्रा ट्रक की सौदेबाजी में घपले की जानकारी थी. उन्होंने एक चिट्ठी गुलाम नबी आज़ाद को भी लिखी थी. उन्होंने एक चिट्ठी वीरप्पा मोइली को भी लिखी थी. डॉ. एच हनुमनथप्पा के मुताबिक़ , आज तक उन्हें यह पता नहीं चला कि सरकार ने उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की, जबकि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को चिट्ठी के साथ बीईएमएल के ट्रक डिवीजन के असिस्टेंट जनरल मैनेजर एस एन अशोक की एक रिपोर्ट भी भेजी थी. रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब यह बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने पर ए के एंटनी ने टेट्रा ट्रक के मामले में जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि ए के एंटनी जब टेट्रा ट्रक के बारे में संसद में बोल रहे थे, तब उन्होंने इस मामले की जानकारी संसद को क्यों नहीं दी कि एक जांच चल रही है. यह क्यों नहीं बताया कि टेट्रा ट्रक के बारे में पहले से शिकायत आ रही है. ए के एंटनी एक ईमानदार नेता माने जाते हैं, फिर भी उन्होंने जनरल वी के सिंह के प्रकरण पर इस तरह संसद में जवाब दिया, जैसे उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि टेट्रा ट्रक के सौदे में घपलेबाजी का आरोप है. लेकिन जब जनरल सिंह ने इस मामले को जनता के सामने रख दिया तो पूरी राजनीतिक जमात उनके पीछे लग गई, सांसद उन्हें बर्खास्त करने की मांग करने लगे.

लगता है, देश चलाने वालों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि जो भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और जो भ्रष्टाचार करेगा, उसे ईनाम दिया जाएगा. थलसेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह ने चौथी दुनिया के साथ एक इंटरव्यू में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था. चौथी दुनिया के एडिटर इन चीफ से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बताया था कि किस तरह एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने उन्हें घूस देने की पेशकश की थी. इस इंटरव्यू को देश के सारे चैनलों पर दिखाया गया. इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया. रक्षा मंत्री ने संसद में इस मुद्दे पर जनरल वी के सिंह के बयानों और आरोपों को सही बताया, लेकिन इस विवाद के दौरान कुछ नेताओं का आचरण ऐसा था, जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया. हैरानी तो तब हो गई कि जब कुछ नेता जनरल वी के सिंह पर पर्सनल अटैक करने लगे. ऐसा लगा कि नेताओं के बीच जनरल के ख़िलाफ़ बोलने की प्रतियोगिता हो रही है. इन नेताओं को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और टेट्रा ट्रक के सौदे में हुई घपलेबाजी की जांच की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ देने का फ़ैसला किया. सांसदों के ऐसे ही बर्ताव और बयानों से लोगों का संसद और राजनीति से विश्वास उठता है. शायद इन नेताओं को यह जानकारी नहीं है कि जब ये टीवी पर बोलते नज़र आते हैं तो लोग चैनल बदल देते हैं.

**सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला नहीं किया है कि जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि क्या है. यह मामला आज भी खुला है. विवाद जारी है. यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा है. रक्षा मंत्रालय ने उनके रिटायरमेंट की चिट्ठी नहीं भेजी है. रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि उसकी परेशानी यह है कि रिटायरमेंट की चिट्ठी में उनकी जन्मतिथि क्या लिखी जाए. सूत्र बताते हैं कि जो चिट्ठी तैयार की गई है, उसमें जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि वर्ष 1951 लिखी गई है. अगर यह चिट्ठी भेजी जाती है तो, इसका मतलब यह है कि सरकार ने जनरल वी के सिंह को समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया. रक्षा मंत्रालय की मुश्किल यह है कि एड्जूटैंट ब्रांच के दस्तावेज़ों में जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि आज भी 10 मई, 1951 है.**

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि सेना में हथियारों और ट्रकों को ख़रीदने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, यह काम रक्षा मंत्रालय का है. इसका फ़ैसला रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारी लेते हैं. इसलिए जो भी घोटाला होता है, उससे जुड़ा जो भी दलाली और बिचौलिए का धंधा है, उसके लिए रक्षा मंत्रालय में बैठे सिविलियन अधिकारी ज़िम्मेदार हैं. यह बात किसी से नहीं छिपी है कि देश में रक्षा सौदा किस तरह होता है, उसमें दलालों एवं बिचौलियों का क्या रोल है. वर्ष 2006 से ही सरकार ने सैन्य सौदे में बिचौलियों और दलालों की भूमिका ख़त्म कर दी है. यह तय हो चुका है कि जो भी हथियार या ट्रक ख़रीदे जाएंगे, वे सीधे उत्पादकों से लिए जाएंगे. जनरल वी के सिंह ने सिर्फ़ अपने कर्तव्य का पालन किया है. उन्होंने सैन्य सौदे में होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया है. अब यह सरकार की ड्यूटी है कि वह पूरे सिस्टम से भ्रष्टाचार को ख़त्म करे, सेना में भ्रष्टाचार के सभी मामलों की तहकीकात करे और रक्षा मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, लेकिन ठीक उल्टा हो रहा है. देश के थलसेना अध्यक्ष को सीबीआई से जांच के लिए कहना पड़ा है, इसलिए अब कई मामले सामने आएंगे और उन पर तहकीकात होगी. यही वजह है कि सीबीआई ने टेट्रा ट्रक बेचने वाली कंपनी वेक्ट्रा के ठिकानों पर छापेमारी की है. जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इस घोटाले के बारे में नई-नई जानकारियां आ रही हैं.

जब जनरल वी के सिंह के इंटरव्यू का यह विवाद शुरू हुआ, तब प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी को मीडिया में लीक कर दिया गया. सरकार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## तीन महीने पहले ही चौथी दुनिया ने टेट्रा ट्रक विवाद का खुलासा किया था

चौथी दुनिया ने तीन महीने पहले ही टेट्रा ट्रक विवाद को छापा था. यह सेना की इज्जत का सवाल है शीर्षक से प्रकाशित इस लेख में सवाल खड़ा किया गया था कि क्या जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि का विवाद उठाने के पीछे हथियार माफिया और दलालों का षड्यंत्र है. हाल की घटनाओं से यह साफ़ होता है कि जनरल वी के सिंह टेट्रा ट्रक की ख़रीद पर रोक लगाते ही कुछ अधिकारियों और हथियार माफिया के निशाने पर आ गए. इसलिए टेट्रा ट्रक का विवाद समझना ज़रूरी है. भारतीय सेना एक ट्रक का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम है टेट्रा ट्रक. भारतीय थलसेना टेट्रा ट्रक का इस्तेमाल मिसाइल लांचर की तैनाती और भारी-भरकम चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में करती है. इन ट्रकों का पिछला ऑर्डर फरवरी, 2010 में दिया गया था, लेकिन ख़रीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं तो आर्मी चीफ वी के सिंह ने इस सौदे पर मुहर लगाने से इंकार कर दिया. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी बीईएमएल लिमिटेड को जिस वक्त इन ट्रकों की आपूर्ति का ठेका मिला, तब भारतीय सेना की कमान जनरल दीपक कपूर के हाथ में थी. नियमों के मुताबिक़, हर साल आर्मी चीफ को इस डील पर साइन करने होते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी से लेकर मानकों के उल्लंघन तक की शिकायतों की वजह से जनरल वी के सिंह ने साइन नहीं किए. इसी डील पर साइन करने के लिए जनरल वी के सिंह को 14 करोड़ रुपये घूस देने की पेशकश की गई. क़ानून के मुताबिक़, टेट्रा ट्रकों की ख़रीददारी सीधे कंपनी से होनी चाहिए, लेकिन बीईएमएल ने यह ख़रीददारी टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड से की, जो न तो स्वयं उपकरण बनाती है और न उपकरण बनाने वाली कंपनी की सब्सिडियरी है. यह स्लोवाकिया की एक टेट्रा कंपनी से ट्रक खरीदती है.

हैरानी की बात यह है कि टेट्रा कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर रविंद्र ऋषि के पास हैं और वही वेक्ट्रा ग्रुप का मालिक भी है. अब सवाल यह है कि जब वह टेट्रा का मालिक है तो फिर उसे वेक्ट्रा के जरिए ट्रक ख़रीदने की क्या ज़रूरत है. समझने वाली बात यह है कि ट्रक की खरीददारी का सौदा ट्रक बनाने वाली कंपनी और भारत सरकार के बीच नहीं है. कुछ सवाल ऐसे हैं, जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए. रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को देना है. सैन्य सौदों में बिचौलियों को बाहर रखने के क़ानून का खुला उल्लंघन क्यों हुआ. क्या सरकार को यह पता नहीं था कि रविंद्र ऋषि निर्माता नहीं, एक दलाल है. इस पूरे घोटाले में कितना पैसा कमीशन के रूप में जा रहा है, उसे पता करना बड़ा ही आसान है. बस यह पता करना था कि रक्षा मंत्रालय इन ट्रकों के लिए रविंद्र ऋषि को कितना पैसा देता था और ट्रक निर्माता को कितना मिलता है. सरकार ने अब तक यह काम क्यों नहीं किया. रविंद्र ऋषि भारतीय मूल के हैं, लेकिन उनकी नागरिकता ब्रिटेन की है. वह डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए भारत में हैं. इसमें हिस्सा लेने वालों की बाक़ायदा पुलिस द्वारा जांच होती है. इसका मतलब है कि सरकार के पास रविंद्र ऋषि की पूरी जानकारी है.

सरकार देश को गुमराह कर रही है कि यह मामला नया है. दरअसल, बीईएमएल

(शेष पृष्ठ 2 पर)

गुजरात में पिछले सितंबर से डीजीपी का पद खाली पड़ा है. सितंबर 2010 में एस एस खंडेलवाल डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद अभी तक स्थायी तौर पर किसी को डीजीपी नियुक्त नहीं किया गया.



# दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

## गुजरात सरकार की नई परेशानी

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपीए सरकार के बीच तकरार होती रहती है. एक नया विवाद तब सामने आया, जब गुजरात के पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि वह गुजरात में डीजीपी नियुक्त करने के लिए हस्तक्षेप करें. गुजरात में पिछले सितंबर से डीजीपी का पद खाली पड़ा है. सितंबर 2010 में एस एस खंडेलवाल डीजीपी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसके बाद अभी तक स्थायी तौर पर किसी को डीजीपी नियुक्त नहीं किया गया और एडीजीपी चितरंजन सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. श्रीकुमार के अनुसार, नियमत: राज्य में डीजीपी का पद 6 महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, श्रीकुमार ने गृह मंत्री से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा है कि डीजीपी के रिक्त पद पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई है. अब गृह मंत्री को इसका जवाब देना है.

## रेल मंत्रालय के बाबू

ममता बनर्जी को नाराज करने के बाद दिनेश त्रिवेदी की रेल मंत्रालय से विदाई हो गई. उनकी जगह मुकुल राय को रेल मंत्री बनाया गया. मुकुल राय के रेल मंत्री बनने के बाद बाबुओं के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या वह मंत्रालय में काम कर रहे अधिकारियों में कुछ फेरबदल करेंगे. जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं तो उन्होंने अपने विश्वासपात्र बाबुओं को साथ काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वह दिल्ली से कोलकाता गईं तो उनमें से कई बाबुओं को अपने साथ ले गईं. इनमें रतन मुखर्जी, तपन राय, जे के साहा एवं गौतम सान्याल के साथ कुछ अन्य अधिकारी शामिल थे. बाद में तपन राय और रतन मुखर्जी अपने पुराने मंत्रालय में वापस आ गए थे. अब जबकि मुकुल राय रेल मंत्री बन गए हैं तो देखना यह है कि वह ममता बनर्जी के विश्वासपात्र अधिकारियों को अपने साथ रखते हैं या फिर दूसरे अधिकारियों को, जिन्हें वह पसंद करते हैं.

## सूचना आयोग और बाबू

सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद सेवानिवृत्त बाबुओं को सूचना आयुक्त बनाया जाना जारी है. सूत्रों के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिनों पहले सेवानिवृत्त हुईं मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी को राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया है. हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी भी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए पिछले साल सिविल सेवा से इस्तीफ़ा दे दिया था. इसे संयोग ही कहा जाए कि वह उर्वशी गुलाटी के पति हैं. हालांकि उर्वशी गुलाटी मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी का नाम घोषित नहीं किया है. वरीयता के आधार पर तो मुख्य वित्त आयुक्त राजकुमार उर्वशी गुलाटी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पी के चौधरी भी मुख्य सचिव पद के मुख्य दावेदारों में से एक हैं. चौधरी अभी केंद्र में डेपुटेशन पर हैं.

dilipcherian@gmail..com

# साउथ ब्लॉक

### अनूप श्रीवास्तव एएस बने

1981 बैच के आईएएस अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह संगीता गैरोला की जगह लेंगे. अनूप श्रीवास्तव इससे पहले राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे.

### राकेश भूषण और विजय भूषण जेएस बने

1986 बैच के आईएफएस अधिकारी राकेश भूषण सिन्हा को कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह अनिंदो मजूमदार की जगह लेंगे. इसी तरह विजय भूषण पटनायक को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में जेएस बनाया गया है.

### दिलीप कुमार और नवीन सोना निदेशक बने

1997 बैच के आईडीएएस अधिकारी दिलीप कुमार को पंचायती राज मंत्रालय में निदेशक बनाया जाएगा. वह पी के केसवन की जगह लेंगे. इसी तरह एन नवीन सोना को खाद्य एवं जन वितरण विभाग में निदेशक बनाया गया है.

### मुग्धा सिन्हा उप सचिव बनीं

1999 बैच की आईएएस अधिकारी मुग्धा सिन्हा को वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है. वह पहले वस्त्र मंत्रालय में ओएसडी थीं.

### सुधा योजना आयोग की सचिव बनेंगी

योजना आयोग में सदस्य सचिव के पद पर कार्यरत सुधा पिल्लई का कार्यकाल पूरा होने वाला है. इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें योजना आयोग का सचिव बनाया जा सकता है.

# भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जंग

पृष्ठ एक का शेष

ने इस पूरे विवाद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया, जहां सबसे बड़ा सवाल यह हो गया है कि जनरल वी के सिंह की चिट्ठी किसने लीक की. मीडिया और जनता का ध्यान बंटाने का नुस्खा भी काम नहीं आया, क्योंकि लगातार नए–नए खुलासे होते रहे. इस विवाद की जड़ में बस एक मूल सवाल है कि क्या हमारे देश में हथियारों की खरीददारी में दलालों और बिचौलियों को लूट मचाने की छूट है या नहीं. क्या हर सौदे में घोटाला हो रहा है, लेकिन मीडिया के कुछ हिस्से में यह चर्चा होने लगी कि जनरल वी के सिंह यह सब इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में जन्मतिथि का मुक़दमा हार गए हैं. मीडिया भी इस मामले में देश को गुमराह कर रहा है. हक़ीक़त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि पर कोई फ़ैसला ही नहीं दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला नहीं किया है कि जनरल की जन्मतिथि क्या है. बड़े आदर के साथ यह कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से यह मामला आज भी खुला है. विवाद जारी है. यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया है कि इस मामले पर सरकार और आप स्वयं फ़ैसला कर लें. रक्षा मंत्रालय ने जनरल वी के सिंह या आर्मी हेड क्वार्टर को उनके रिटायरमेंट की चिट्ठी नहीं भेजी है. रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि उसकी परेशानी यह है कि रिटायरमेंट की चिट्ठी में उनकी जन्मतिथि क्या लिखी जाए. सूत्र बताते हैं कि जो चिट्ठी तैयार की गई है, उसमें जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि वर्ष 1951 लिखी गई है. अगर यह चिट्ठी भेजी जाती है तो, इसका मतलब यह है कि सरकार ने जनरल वी के सिंह को समय से पहले ही रिटायरमेंट दे दिया. रक्षा मंत्रालय की मुश्किल यह है कि एडजूटैंट ब्रांच के दस्तावेज़ों में जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि आज भी 10 मई, 1951 है. याद रहे, एडजूटैंट ब्रांच ही सेना के दस्तावेज़ों और सैन्य अधिकारियों के रिकॉर्ड को रखने वाली आधिकारिक शाखा है. इसलिए न तो जन्मतिथि के मामले में जनरल वी के सिंह की हार हुई है और न यह विवाद अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन अब जो विवाद सामने आया है, वह जनरल वी के सिंह की जन्मतिथि के विवाद से कहीं आगे चला गया है. जो लोग जनरल वी के सिंह के बयानों और कोशिशों को किसी मोटिव से जोड़ रहे हैं, वे देशद्रोह का काम कर रहे हैं. सबसे अहम सवाल यह है कि जो जानकारी जनरल वी के सिंह ने प्रधानमंत्री को दी, उसमें कितनी सच्चाई है. क्या हमारी तोपों में गोले–बारूद नहीं हैं, क्या हम रात के अंधेरे में दुश्मन से लड़ नहीं सकते, क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और चीन से कमज़ोर है, अगर जंग हो जाए तो क्या कुव्यवस्था की वजह से हमें नुक़सान हो सकता है? प्रधानमंत्री को सामने आकर जनरल वी के सिंह के सवालों को जवाब देना चाहिए. अगर जनरल वी के सिंह की बातें ग़लत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और अगर उनकी बातों में जरा भी सच्चाई है तो प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्रालय में बैठे सारे अधिकारियों को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए.

देश बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है. एक तरफ इंडियन आर्मी का ईमानदार जनरल है तो, दूसरी तरफ सरकार है, राजनीतिक पार्टियां हैं और वे तमाम नेता हैं, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं. संसद में नेताओं ने इस तरह बयान दिए, जैसे जनरल वी के सिंह हिंदुस्तान में पाकिस्तान की तरह सत्ता पर बैठना चाहते हैं. पिछले सप्ताह हमने जनरल वी के सिंह का इंटरव्यू छापा था, जिससे साफ–साफ पता चलता है कि जनरल वी के सिंह एक ईमानदार ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र और समानता का सम्मान करने वाले जनरल हैं. देश के लोगों को ऐसे सेना अध्यक्ष पर गर्व होता है, जो नक्सली इलाक़ों में सेना के इस्तेमाल को मना कर देता है. आज़ादी के बाद जनरल वी के सिंह पहले ऐसे सेना अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जवानों का जीवन संवारा है. चाहे वह अफसरों जैसा राशन देने का मामला हो या फिर कपड़ों का. जनरल वी के सिंह यह सब इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी से प्यार है, बल्कि यह मामला सेना और देश के भविष्य से जुड़ा है. ऐसे सेना अध्यक्ष के ख़िलाफ़ नेताओं का एकजुट होना एक शर्मनाक घटना है. अच्छा तो यह होता कि सरकार और संसद जनरल वी के सिंह के साथ मिलकर सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करती, लेकिन सरकार में छिपे कुछ देशद्रोहियों ने प्रधानमंत्री को लिखी जनरल वी के सिंह की चिट्ठी पहले लीक कर दी और जनरल वी के सिंह पर आरोप मढ़ने की कोशिश की. रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि सरकार ने ग़रीबों का पेट काट कर एक लाख तिरानवे हज़ार करोड़ रुपये सेना को दिए हैं. इन पैसों को दलालों और बिचौलियों के हाथों में जाने से रोकने की ज़िम्मेदारी सरकार की है. रक्षा मंत्री के सिर पीटने और मामले को दबा देने से अब काम नहीं चलने वाला है. सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार के तंत्र को जड़ से नष्ट करने की ज़रूरत है.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

manish@chauthiduniya.com

## तीन महीने पहले ही चौथी दुनिया ने टेट्रा ट्रक विवाद का खुलासा किया था

पृष्ठ एक का शेष

द्वारा टेट्रा ट्रकों की ख़रीद का पूरा मामला संदेह के घेरे में है. एक अंग्रेजी अख़बार डीएनए के मुताबिक़, यह पूरा रैकेट 1997 से चल रहा है. बीईएमएल में उच्च पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी के हवाले से यह भी ख़बर आई कि अब तक कंपनी टेट्रा ट्रकों की डील से कुल 5,000 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. यह कारोबार टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड के साथ किया गया. इसे स्लोवाकिया की टेट्रा सिपॉक्स (एएस) की सब्सिडियरी बताया जाता रहा है. बीईएमएल के इस पूर्व अधिकारी के मुताबिक़, 5,000 करोड़ रुपये के इस कारोबार में 750 करोड़ रुपये बीईएमएल एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बतौर रिश्वत दिए गए. बात यहीं ख़त्म नहीं होती है. बीईएमएल के एक शेयर धारक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता के एस पेरियास्वामी राष्ट्रपति से हस्तक्षेप और सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं. वह कहते हैं, ख़रीद के लिए जितनी रक़म की मंजूरी दी जाती है, उसका कम से कम 15 फ़ीसदी हिस्सा कमीशन में चला जाता है. ऊपर से नीचे तक सबको हिस्सा मिलता है.

ट्रकों की संदेहास्पद डील को लेकर 8 मई, 2005 को मीडिया में ख़बर आई थी. डीएनए अख़बार ने एक और ख़ुलासा किया कि टेट्रा सिपॉक्स (यूके) लिमिटेड की स्थापना 1994 में ब्रिटेन में हुई थी. जोजफ मजिस्की और वीनस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इसके शेयर धारक थे. स्लोवाकिया के न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक़, टेट्रा सिपॉक्स (एएस) 1998 में अस्तित्व में आई. इसका मतलब यह हुआ कि 1997 में बीईएमएल ने ऐसी कंपनी की सब्सिडियरी के साथ समझौता किया, जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी. टेट्रा सिपॉक्स (यूके) की शेयर होल्डिंग में कई बार बदलाव हुआ, लेकिन स्लोवाक कंपनी के पास कभी इसका एक शेयर भी नहीं रहा. अब सवाल यह उठता है कि क्या आर्मी चीफ को पद से हटाने के लिए साज़िश रची गई, क्योंकि उन्होंने टेट्रा डील पर दस्तख़त नहीं किए थे? क्या बीईएमएल सेकेंड हैंड ट्रकों का आयात कर रही है और क्या स्लोवाकिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो गया है? क्या पुराने ट्रकों की मरम्मत को घरेलू उत्पादन के तौर पर दिखाया जा रहा है? रविंद्र ऋषि को इतने रक्षा सौदों का ठेका क्यों दिया जा रहा है? इस लॉबी के लिए सरकार में काम करने वाले लोग कौन हैं? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि टेट्रा ट्रक के अलावा किन–किन सौदों में रविंद्र ऋषि की हिस्सेदारी है?

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 04 अंक 05
दिल्ली, 09 अप्रैल–15 अप्रैल 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

*समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.*

# संसद को अरविंद केजरीवाल का जवाब

**लोकसभा में 162 ऐसे सांसद हैं, जिनके ख़िलाफ़ विभिन्न आपराधिक मामले लंबित हैं. अरविंद केजरीवाल द्वारा यह बयान दिए जाने के बाद लोकसभा एवं राज्यसभा के कुछ सदस्यों की ओर से उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया. अरविंद केजरीवाल ने 30 मार्च को इस नोटिस का जवाब संसद को भेजा. चौथी दुनिया के पास अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए जवाब की कॉपी है, जिसे यहां हू-ब-हू प्रकाशित किया जा रहा है.**

अरविंद केजरीवाल

मुझे आपकी तरफ़ से श्री राजनीति प्रसाद एवं प्रोफेसर रामकृपाल यादव द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने संसद का अपमान किया है. मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं कि मैंने अपने शब्दों या किसी कार्य से संसद का अपमान किया है. मैं संसद की बहुत इज़्ज़त करता हूं, संसद का बहुत सम्मान करता हूं, मैं संसद को जनतंत्र के मंदिर की तरह मानता हूं. इसीलिए मुझे अत्यधिक चिंता और दर्द है कि जनतंत्र के इस मंदिर को आएदिन अपने कृत्यों से अथवा अपने शब्दों से संसद के अंदर बैठे कुछ लोग अपमानित करते हैं. विभिन्न तथ्य और घटनाएं यह दर्शाती हैं कि संसद का अपमान संसद के बाहर के लोगों की बजाय संसद के अंदर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं. मैं संसद का सम्मान करता हूं, कई अच्छे सांसदों का सम्मान भी करता हूं, पर कुछ सांसदों का सम्मान करने में असमर्थ हूं.

अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई, जिसका नाम है पान सिंह तोमर. इस फिल्म में एक डायलॉग है-बीहड़ में बागी रहते हैं, डाकू तो संसद में रहते हैं. मैंने यह फिल्म तीन बार देखी. जब-जब हीरो यह डायलॉग बोलता है तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है. हर बार तालियां सुनकर बहुत पीड़ा हुई. ऐसा क्यों हुआ कि जब हीरो ने संसद में डाकुओं के होने की बात कही तो ऐसा लगा, मानो उसने इस देश की जनता के मन की बात कही हो. यह सोचने की बात है कि आख़िर ऐसा कैसे हुआ कि देश की जनता के मन में संसद में बैठे लोगों के लिए इतना गुस्सा और तिरस्कार है? संसद की ऐसी छवि बनाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है-इस देश की जनता या संसद में बैठे लोग? सांसदों का सम्मान इस बात से नहीं घटता-बढ़ता कि उनके बारे में क्या कहा जाता है. उनका सम्मान उनके आचरण और व्यवहार से होता है.

आज लोकसभा के अंदर 162 ऐसे सांसद हैं, जिनके ऊपर 522 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 76 के ख़िलाफ़ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं, 14 के ख़िलाफ़ हत्या के मामले दर्ज हैं, 20 के ख़िलाफ़ हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, 11 के ख़िलाफ़ ठगी के मामले दर्ज हैं और 13 के ख़िलाफ़ अपहरण के मामले दर्ज हैं. इसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं, जिन पर समय- समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं. जैसे-श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोझी, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री मुलायम सिंह यादव इत्यादि. यदि जन लोकपाल क़ानून होता तो कुछ और सांसदों पर भी आरोप तय हो सकता था. अब आप ही बताइए, क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है या घटती है? इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं, जिन्हें आप शादी-विवाह, त्योहार में अपने घर बुलाने से भी कतराएं. क्या ऐसे लोगों के संसद में बैठने से संसद का अपमान नहीं होता?

आख़िर ऐसे लोगों को टिकट क्यों दी गई? सभी पार्टियां बढ़-चढ़कर आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट दे रही हैं और हर आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों की संख्या पिछले चुनावों से अधिक होती है. जैसे 2004 में हुए चुनाव में 128 लोग लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, 2009 के चुनाव में यह संख्या बढ़ कर 162 हो गई. इस गति से वह दिन दूर नहीं, जब संसद में आपराधिक छवि के लोगों की संख्या बहुमत में होगी. तो जब किसी फिल्म के हीरो के यह कहने पर कि डाकू तो संसद में रहते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

संसद को इस हालत में पहुंचाने के लिए सभी पार्टियां ज़िम्मेदार हैं. 2009 में कांग्रेस ने आपराधिक छवि के 117 लोगों को टिकट दिया, जिनमें 44 लोग चुनकर आ गए. अन्य सभी पार्टियों ने भी बढ़-चढ़कर दागियों को टिकट दिया. इनमें कई लोग ऐसे हैं, जिन पर कोर्ट ने संगीन अपराधों के आरोप तय किए हैं. आख़िर इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया? इन पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या इन पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट देकर संसद का घोर अपमान नहीं किया? क्या इन पार्टियों को संसद का अपमान करने के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए?

कहा जा रहा है कि अभी तो इन सब पर आरोप हैं. कोर्ट में सभी आरोप सिद्ध नहीं हुए. अभी मामले चल रहे हैं. इस पर मेरा कहना है कि ये मामले तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं. एक मामला निपटने में इस देश में तीस साल से ज़्यादा समय लग जाता है. हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त और ढीली क्यों है? इसे दुरुस्त करने का काम भी तो सांसदों का ही था. सांसदों ने 65 साल में इसे दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्या जानबूझ कर नहीं किया? क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था को दुरुस्त कर देते और ये सभी मामले जल्द निपट जाते तो क्या यह सच नहीं कि इनमें से कई लोग जेल चले जाते? ऐसे में क्या इस शक को बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, तब तक हमारे देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त होगी ही नहीं? क्या इस शक को बल नहीं मिलता कि जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, तब तक इस देश से अपराध कम नहीं होगा? आप ही बताइए कि ऐसे सांसदों का मैं सम्मान कैसे करूं? यह कहना ठीक है कि इन लोगों पर अभी आरोप हैं. आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए. मामले अभी लंबित हैं. ऐसा हो सकता है कि बीस साल बाद जब कोर्ट का निर्णय आए तो ये सभी निर्दोष पाए जाएं. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बीस साल के बाद जब कोर्ट का आदेश आए तो इनमें से कई लोग दोषी पाए जाएं. अगर ऐसा होता है तो क्या यह अत्यंत चिंता का विषय नहीं है कि इतने वर्षों तक हमारी संसद में ऐसे हत्यारे, ठग और अपहरणकर्ता देश के क़ानून बनाते रहे? आप कहते हैं कि मैंने संसद का अपमान किया है. मैं संसद का बहुत सम्मान करता हूं, पर आप ही बताइए कि ऐसे सांसदों का सम्मान कैसे करूं?

एक वह संसद भी थी, जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन दुर्घटना होने पर अपना इस्तीफ़ा दे दिया था. ऐसी संसद के लिए सब कुछ क़ुर्बान करने को मन करता है. लेकिन जो संसद आज है, उसका सम्मान कैसे करूं?

29 दिसंबर, 2011 को संसद में लोकपाल बिल की चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सांसद श्री राजनीति प्रसाद जी ने मंत्री महोदय के हाथ से लोकपाल बिल छीनकर फाड़कर फेंक दिया. क्या इससे संसद अपमानित नहीं हुई? हम यदि संसद को जनतंत्र का मंदिर मानते हैं तो क्या मंदिर में गीता फाड़ने से भगवान का अपमान नहीं होता? हद तो तब हुई, जब एक भी सांसद ने खड़े होकर बिल को फाड़ने का विरोध नहीं किया. सभी सांसद मौन थे. संसद अध्यक्ष भी मौन थे. संसद के सम्मान की दुहाई देने वाले आख़िर मौन क्यों थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ. इस जनतंत्र के मंदिर में कई बार पहले भी बिल फाड़े जा चुके हैं, लेकिन कभी किसी को सज़ा नहीं दी गई.

क्या आपको नहीं लगता कि श्री राजनीति प्रसाद जी को संसद के अंदर बिल फाड़ने के लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए. ऐसी सज़ा दी जाए कि भविष्य में कोई सांसद संसद के अंदर बिल फाड़ने की हिम्मत न कर सके.

राज्यसभा में ऐसे कई उद्योगपति सांसद हैं, जिनका जनता या जनसेवा से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है. कई ऐसे उद्योगपति पैसे के बल पर विभिन्न पार्टियों से टिकट लेकर संसद में आते हैं. ऐसे लोग अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संसद का दुरुपयोग करते हैं. जैसे श्री विजय माल्या जी किंगफिशर के मालिक हैं. उन्होंने जनसेवा का कोई कार्य किया हो, ऐसा सुनने में नहीं आया. वह संसद की नागरिक उड्डयन स्थायी समिति के सदस्य हैं. इस समिति में बैठकर वह देश की नागरिक उड्डयन नीति बनाते हैं. ज़ाहिर है कि वह ऐसी ही नीतियां बनाएंगे, जिनसे किंगफिशर एयरलाइंस को भरपूर फ़ायदा हो. क्या यह सीधे-सीधे संसद का दुरुपयोग नहीं है? राज्यसभा में तो ऐसे ढेरों सांसद हैं, जो अपना उद्योग बढ़ाने के लिए संसद का सीधे-सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं. क्या संसद का इस तरह से दुरुपयोग संसद का अपमान नहीं है?

संसद में रिश्वत लेकर प्रश्न पूछने का मामला सामने आया. यह तो संसद का सबसे घोर अपमान था, लेकिन ऐसे सांसदों को महज़ उनकी सदस्यता से बर्खास्त करके छोड़ दिया गया. रिश्वत लेना या देना आपराधिक मामला बनता है. अपराध सिद्ध होने पर तो ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए था. इनकी सदस्यता बर्खास्त की गई, इसका मतलब इनके ख़िलाफ़ मामला साबित हो गया था. फिर इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? केवल सदस्यता बर्खास्त करके क्यों छोड़ दिया? संसद के इतने घोर अपमान के लिए अगर उस वक़्त उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी गई होती तो भविष्य में कोई सांसद इस तरह संसद का अपमान करने की कोशिश नहीं करता. चूंकि उस वक़्त उन सांसदों को हल्की सज़ा देकर छोड़ दिया गया, इसलिए कुछ वर्ष बाद ही जुलाई 2008 में खुलेआम सांसदों की ख़रीद फरोख्त का मामला सामने आया. जनतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनता ने सांसदों को खुलेआम बिकते हुए देखा. सारे देश की आत्मा रो पड़ी, जनतंत्र रो पड़ा, संसद रो पड़ी, लेकिन सरकार बच गई. एक भी सांसद को अभी तक सज़ा नहीं मिली. क्या यह किसी देशद्रोह से कम था? क्या सांसदों को ख़रीदना और सांसदों का बिकना देशद्रोह से कम है? कैसे करूं ऐसे सांसदों की इज़्ज़त?

ऐसा कितनी बार हुआ है कि संसद के अंदर माइक उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं. कुर्सियां उठाकर एक-दूसरे पर फेंकी जाती हैं. कैसे करूं ऐसे सांसदों का सम्मान? एक तरफ तो 8 बिल 17 मिनट में बिना चर्चा के पास हो जाते हैं, दूसरी तरफ़ आएदिन सांसदों के हो-हल्ला और शोरशराबे के कारण संसद का कामकाज़ ठप रहता है.

देश महंगाई और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के कत्ल हो रहे हैं. जनता कराह रही है. इन सारे मामलों पर या तो संसद मौन रही या संसद में भाषणों की राजनीति हुई. कई वर्षों से बनी हुई इन समस्याओं से जनता को आज तक निजात नहीं मिली. अमूमन इनमें से किसी भी समस्या पर संसद की आम सहमति नहीं हो पाती. मामले स्थायी समिति में लटकते रहते हैं. जनता कराहती रहती है.

लेकिन जब इन सांसदों से संबंधित मामला होता है तो तुरंत सभी पार्टियों में आम सहमति हो जाती है. इन्हीं में से एक सांसद श्री शरद पवार जी को किसी ने थप्पड़ मारा, (थप्पड़ मारना ग़लत था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए) तो सारे सांसद कराह उठे. सारी पार्टियों में आम सहमति थी. दो घंटे तक सभी नेताओं ने इसकी जमकर आलोचना की. जब-जब सांसदों के भत्ते, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की बात होती है तो सभी सांसदों में तुरंत आम सहमति हो जाती है. चोर की दाढ़ी में तिनका यह मुहावरा कह देने भर से सारी पार्टियां एकजुट हो गईं. इस छोटे से मुहावरे ने सांसदों को इतना आहत कर दिया कि कई घंटों तक संसद में इस पर चर्चा हुई. तो मन में एक विचार आता है-क्या कुछ सांसद जनता की बजाय अपने स्वार्थ की ज़्यादा चिंता नहीं करते?

संसद के साथ-साथ विधानसभाएं भी जनतंत्र का मंदिर हैं. ऐसे मंदिर में कुछ विधायक और उस राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर बैठकर खुलेआम अश्लील फिल्म देखते हैं, तो आप ही बताइए, कैसे सम्मान करूं ऐसे विधायकों का?

ऐसा नहीं कि इस संसद में अच्छे सांसद नहीं हैं. कई अच्छे सांसद भी हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं. पर ऐसे अच्छे सांसदों की आवाज़ें संसद के शोरशराबे में खोती जा रही हैं.

जिस कथन पर मुझे यह नोटिस दिया गया है, उस कथन में मैंने कुछ अहम प्रश्न उठाए हैं. जिस संविधान ने सांसदों को क़ानून बनाने का अधिकार दिया है, उसी संविधान ने जनता को सांसदों से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया है. प्रश्न उठते हैं कि जिस संसद में आपराधिक छवि के इतने लोग हैं, क्या वह संसद अपराध को ख़त्म करने के लिए कभी सख्त क़ानून बना पाएगी? जिस संसद में कई ऐसे लोग हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, क्या ऐसे में यह संसद भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सख्त क़ानून बना पाएगी, जिसके लागू होने से कुछ सांसदों के लिए ही परेशानी खड़ी हो जाए? जन लोकपाल बिल आंदोलन के दौरान इस देश की जनता एक सशक्त क़ानून की मांग लेकर सड़क पर उतरी, लेकिन जब सरकार और संसद सशक्त क़ानून देने से कतराते नज़र आने लगे तो जनता ने ये प्रश्न पूछने चालू किए. जनता के मन में प्रश्न है कि क्या जन लोकपाल बिल आएगा?

इन बातों से साफ ज़ाहिर है कि संसद का अपमान मैंने नहीं, बल्कि संसद के भीतर बैठने वाले कुछ लोग लगातार कर रहे हैं, जिन पर विश्वास करके इस देश की जनता ने जिन्हें अपना भविष्य सौंपा था. मैंने जो कुछ भी कहा, वे सिर्फ तथ्य थे. मैंने कुछ भी ग़लत नहीं कहा. मैंने तो सिर्फ़ जनता के प्रश्नों को उठाया है. यदि आपके क़ानून की नज़रों में मैं दोषी हूं तो मैं उस क़ानून के तहत सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं. यदि आप मुझे अपने क़ानून के तहत दोषी पाएं तो मेरा आपसे निवेदन है कि सज़ा सुनाने से पहले मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी बात कहने का मौक़ा ज़रूर मिलना चाहिए.

*feedback@chauthiduniya.com*

कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वह उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में विकास को अपना मुख्य एजेंडा नहीं बना सकती, क्योंकि इस मामले में मोदी बहुत आगे हैं.

दिल्ली, 09 अप्रैल–15 अप्रैल 2012 चौथी दुनिया

## एनसीटीसी

# इस जल्दबाज़ी की वजह क्या है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

**कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वह उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में विकास को अपना मुख्य एजेंडा नहीं बना सकती, क्योंकि इस मामले में मोदी बहुत आगे हैं. इसलिए कांग्रेस मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हुए दंगे, आगजनी, मुसलमानों पर अत्याचार, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाएगी. गुजरात में औद्योगीकरण के कारण किसानों और मछुआरों की जो आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय हुई है, कांग्रेस उसे भी अपने निशाने पर रखेगी. रही-सही कसर ये जांच एजेंसियां पूरी कर देंगी. वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अपनी बिसात दो साल पहले से ही बिछानी शुरू कर दी थी.**

रूबी अरुण

एनसीटीसी के गठन के पीछे क्या वाकई देश की सुरक्षा की चिंता है या फिर यह कांग्रेस की विपक्षी पार्टियों और नेताओं, ख़ासकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिकंजा कसने की कोई सियासत? आख़िर कांग्रेस और उसके मंत्री एनसीटीसी यानी आतंकवाद निरोधी ख़ुफ़िया केंद्र को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं? जब देश में पहले से ही इतनी जांच एजेंसियां मौजूद हैं तो फिर एक और नई एजेंसी की ज़रूरत क्यों आ पड़ी है? यह सवाल न सिर्फ़ विपक्षी पार्टियों, बल्कि सरकार में शामिल घटक दलों के बीच भी उमड़-घुमड़ रहा है. सवाल उठने लाज़िमी भी हैं और इसकी माकूल वज़हें हैं. जब देश में आईबी, एनआईए और रॉ जैसी एजेंसियां पहले से ही मौजूद हैं तो फिर एक और एजेंसी की ज़रूरत क्यों आ पड़ी? क्या सचमुच सरकार का मकसद इस आतंकवाद निरोधी ख़ुफ़िया केंद्र के ज़रिए देश से आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देना है या इसकी मार्फ़त सरकार के ख़िलाफ़ खड़े लोगों, नेताओं के साथ शह और मात का खेल खेलना है? इस एजेंसी के गठन से फ़िक्रमंद नरेंद्र मोदी भी हैं. उन्हें पता है कि इसकी गाज सबसे पहले उन पर ही गिरने वाली है. तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 16 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के गठन पर चर्चा को ही एजेंडा बनाने का पुरजोर आग्रह किया है. इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मोदी ने कहा है कि उन्हें आंतरिक सुरक्षा को लेकर होने वाले इस सम्मेलन के एजेंडा के बारे में गृह मंत्री पी चिदंबरम की ओर से सूचना मिली है. मोदी ने काफी निराशा और दु:ख के साथ कहा है कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि विशेष तौर से एनसीटीसी के गठन के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है. सिर्फ़ एक इसी मसले पर बैठक क्यों नहीं बुलाई गई है. नरेंद्र मोदी की यह फ़िक्र एनसीटीसी के गठन की असलियत और सरकार की नियत, सब कुछ बयान कर देती है.

दरअसल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों में इस साल के आख़िर में या अगले साल यानी 2013 के शुरुआती महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं. उत्तर प्रदेश में बुरी तरह पटखनी खाने के बाद इन प्रदेशों पर कांग्रेस की नज़र है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में भाजपा का शासन है. ज़ाहिर है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसा हश्र इन राज्यों में नहीं चाहेगी. ख़ासकर, गुजरात में. पर चूंकि वहां नरेंद्र भाई मोदी की हुकूमत चलती है और उनके राजकाज तथा प्रदेश का अविरल विकास करने के तौर तरीक़ों से गुजरात की जनता उनसे बेहद ख़ुश है, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए भी कांग्रेस को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे. सच्चाई यह भी है कि नरेंद्र मोदी शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता होने के साथ-साथ विवादित भी हैं और बतौर आरोपी उनका नाम कई दंगाई मामलों में शामिल भी हैं. उच्चतम न्यायालय ने भी विशेष जांच दल यानी एसआईटी से इस बात पर विचार करने को कहा है कि क्या गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में जीवित जलाए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की शिकायत पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 52 अन्य के ख़िलाफ़ आगे जांच ज़रूरी है, क्योंकि मोदी पर पीड़ितों को संरक्षण देने के बजाय दंगाइयों की भीड़ को और भी भड़काने के आरोप हैं. अब ज़ाहिर है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की इस दुखती रग को दबाना चाहेगी और इसकी ख़ातिर कांग्रेस को आतंकवाद निरोधी ख़ुफ़िया केंद्र जैसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात पश्चिम बंगाल में भी नज़र आने वाले हैं.

गृह मंत्री पी चिदंबरम द्वारा देश की सुरक्षा के प्रति गहरी चिंता दर्शाना भी विस्मय पैदा कर रहा है, क्योंकि मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भी गृह मंत्री ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए कोई ठोस पहल नहीं की, सिवाय लफ्फाजियों के . पी चिदंबरम के ही निर्देशन में, मुंबई पर आतंकी हमले के बाद देश से आतंकवाद के सफाए की ख़ातिर एफ़बीआई की तर्ज़ पर नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद और देश के लोगों को आश्वस्त किया था कि एनआईए को इतना मज़बूत बनाया जाएगा कि यह एजेंसी हिंदुस्तान में आतंकियों के मंसूबों को कभी परवान चढ़ने ही नहीं देगी. आतंकी घटनाओं से पहले ही कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन हुआ क्या? आज एनआईए अपने गठन के तीन साल बाद भी लावारिसों की हालत में है. उसे काम करने की बेसिक सुविधाएं भी मयस्सर नहीं हैं. एनआईए इस समय आतंकवाद से जुड़े 35 मामलों पर काम कर रही है, लेकिन अब तक सिर्फ़ एक मामला सुलझा है. हालांकि सरकार अभी तक एनआईए पर इस वित्तीय वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपये के ख़र्च का आंकड़ा पेश कर रही है, पर सच यही है कि यह एजेंसी आज महज़ एक सफेद हाथी ही साबित हो रही है. 2008 में हुए मुंबई हमले के बाद आतंकवाद रोधी मोर्चे पर इस एजेंसी ने जो कुछ किया है, वह सांकेतिक प्रभाव भी नहीं दे पाया है. ऊपर से एनआईए पर यह ठप्पा ज़रूर लग गया कि कांग्रेस सरकार इस जांच एजेंसी के तहत हिंदू और भगवा आतंकवाद को भारतीय जनमानस में प्रत्यारोपित कर रही है. मालेगांव बम विस्फोट, स्वामी असीमानंद एवं साध्वी प्रज्ञा जैसे अनेक मामलों को ले क र भाजपा और आरएसएस जैसी पार्टियां एनआईए को पहले से ही कठघरे में खड़ा कर चुकी हैं. काम के मामले में फिसड्डी साबित हुई इस एजेंसी के विस्तार की भी तैयारी की जा रही है. अब एनआईए न सिर्फ़ तीन नए कार्यालय खोलेगी, बल्कि संगठन के कर्मचारियों की संख्या 400 से बढ़ाकर लगभग 900 करेगी. एनआईए लखनऊ, कोच्चि और मुंबई में अपने कार्यालय खोलेगी. गृह मंत्रालय के इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने हाल ही में मंजूरी भी दे दी है.

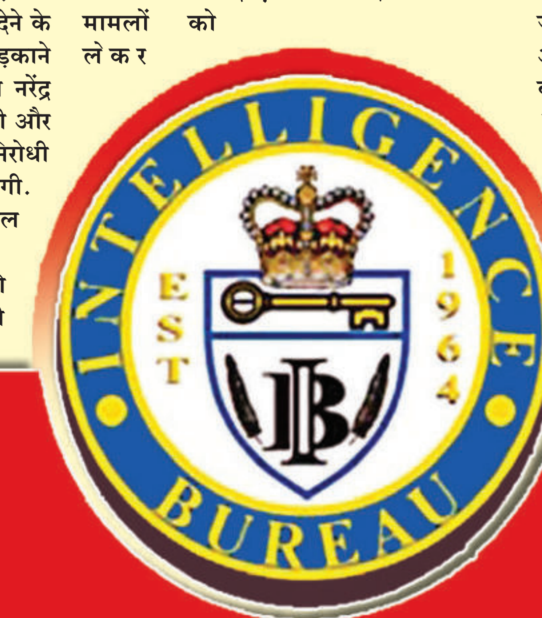



**सच्चाई यह भी है कि नरेंद्र मोदी शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता होने के साथ-साथ विवादित भी हैं और बतौर आरोपी उनका नाम कई दंगाई मामलों में शामिल भी हैं. उच्चतम न्यायालय ने भी विशेष जांच दल यानी एसआईटी से इस बात पर विचार करने को कहा है कि क्या गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में जीवित जलाए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की शिकायत पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 52 अन्य के ख़िलाफ़ आगे जांच ज़रूरी है, क्योंकि मोदी पर पीड़ितों को संरक्षण देने के बजाय दंगाइयों की भीड़ को और भी भड़काने के आरोप हैं. अब ज़ाहिर है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी की इस दुखती रग को दबाना चाहेगी और इसकी ख़ातिर कांग्रेस को आतंकवाद निरोधी ख़ुफ़िया केंद्र जैसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी. कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात पश्चिम बंगाल में भी नज़र आने वाले हैं.**

सवाल उठता है कि जब आतंक के ख़ात्मे के नाम पर एक एजेंसी का गठन किया जाता है और उसके विस्तार की भी तैयारियां की जाती हैं, तब उसी दरम्यान उसी काम के लिए आनन-फानन में दूसरे संगठन का गठन क्यों कर दिया जाता है? लेकिन जब हम सियासी गलियारों में धमक रखने वाले लोगों से बात करते हैं और एनआईए के अधिकार क्षेत्र और एनसीटीसी के काम करने के तरीक़े की विवेचना करते हैं, तो सारी बातें साफ़ हो जाती हैं. यह एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होगी. एनसीटीसी को ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम यानी यूएपीए से शक्ति हासिल होगी, जो केंद्र सरकार की एजेंसियों को गिरफ्तारी और जांच करने का अधिकार देता है. भारत सरकार ने अब तक यह व्यवस्था बरक़रार रखी है कि ख़ुफ़िया ब्यूरो को गिरफ्तारी और ज़ब्ती का अधिकार नहीं होगा. साथ ही ख़ुफ़िया ब्यूरो जो भी सूचनाएं एकत्र करता है, उन्हें वह राज्य पुलिस या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप देता है, जो जांच, गिरफ्तारी और अभियोग की कार्रवाइयां करते हैं. लेकिन अब, एनसीटीसी को ख़ुफ़िया ब्यूरो के अंतर्गत लाकर और उसे जांच एवं कार्रवाई का अधिकार देकर सरकार ने सभी शक्तियां इस जांच एजेंसी के पास संग्रहित कर दी हैं. ज़ाहिर है, इसके परिणाम अच्छे नहीं होने वाले हैं. यह केंद्रीय एजेंसी आतंकवाद से जुड़े किसी भी मसले में देश भर में कहीं भी जाकर तलाशी ले सकती है और गिरफ्तारी कर सकती है. जांच के दौरान यह राज्य की पुलिस को तो भरोसे में लेगी, लेकिन राज्य सरकार और राज्य पुलिस से इजाज़त लेना इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा. अब हर राज्य की पुलिस और अन्य ख़ुफ़िया एजेंसियों को आतंक से जुड़ी सभी गोपनीय जानकारी एनसीटीसी के साथ साझा करनी होगी. यक़ीनन यहां ये संभावनाएं पैदा होती हैं कि जो आईबी पहले से ही विपक्षियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, अब और भी ताक़तवर हो जाएगी. ऐसे में अधिकारों के दुरुपयोग होने की आशंकाएं बलवती हो जाती हैं. यही वज़ह है कि दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री पी चिदंबरम के ड्रीम प्रोजेक्ट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया. यह बात अलग है कि सरकार सपा और बसपा की मदद से अपनी बात मनवाने में सफल रही.

कांग्रेस की मुश्किल यह है कि वह उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में विकास को अपना मुख्य एजेंडा नहीं बना सकती, क्योंकि इस मामले में मोदी बहुत आगे हैं. इसलिए कांग्रेस मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हुए दंगे, आगजनी, मुसलमानों पर अत्याचार, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाएगी. गुजरात में औद्योगीकरण के कारण किसानों और मछुआरों की जो आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति दयनीय हुई है, कांग्रेस उसे भी अपने निशाने पर रखेगी. रही-सही कसर ये जांच एजेंसियां पूरी कर देंगी. वैसे देखा जाए तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ अपनी बिसात दो साल पहले से ही बिछानी शुरू कर दी थी, जब सोनिया गांधी ने गुजरात के पूर्व आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर को नेशनल एडवाइजरी कमिटी का मेंबर बनाया. साथ में सामाजिक कार्यकर्ता फराह नकवी और मिराई चटर्जी को भी जगह दी. फिर हर्ष मंदर को सोनिया गांधी ने फूड सिक्योरिटी कमिश्नर बना दिया. अपने इन सिपहसालारों के बूते सोनिया गांधी ने गुजरात के मुसलमान तबके, दंगे में यतीम हुए बच्चों और बेवाओं की खातिर काम कराना शुरू किया. वक़्त-बेवक़्त कांग्रेस से जुड़े समाजसेवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मोदी विरोधी काम जारी रखे और उनके ख़िलाफ़ याचिकाओं के ज़रिए माहौल बनाए रखा. गवाहों और कई अपुष्ट साक्ष्यों की मार्फ़त नरेंद्र मोदी और उनके बेहद ख़ास लोगों की भूमिका संदिग्ध भी नज़र आई, पर क़ानूनी दांव-पेंचों की वज़ह से न तो कांग्रेस के मंसूबे अभी तक पूरे हो सके, न मोदी की असलियत सामने आ सकी, पर शायद अब नरेंद्र मोदी और उनके नज़दीकी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ग़ैरक़ानूनी गतिविधियों का सबूत भी एनसीटीसी को ही जुटाना है और बग़ैर किसी की अनुमति लिए आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसे ही करनी है.

*ruby@chauthiduniya.com*

12 मई, 1998 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले.



## जल संसाधन मंत्रालय

# एनपीसीसी में यह क्या हो रहा है

**जल, थल और नभ, भ्रष्टाचार के कैंसर ने किसी को नहीं छोड़ा. जहां उंगली रख दीजिए, वहीं भ्रष्टाचार का जिन्न निकल आता है. बड़े घोटालों की बात अलग है. ऐसे सरकारी संगठन भी हैं, जिनके बारे में अमूमन आम आदमी नहीं जानता और इसी का फ़ायदा उठाकर वहां के बड़े अधिकारी वह सब कुछ कर रहे हैं, जिसे संस्थागत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता है. ऐसा ही एक मामला है एनपीसीसी का. पेश है चौथी दुनिया की ख़ास रिपोर्ट :-**

अभिषेक रंजन सिंह

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1957 में नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनपीसीसी) की स्थापना की थी. इसे स्थापित करने का मुख्य लक्ष्य था देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में जहां निजी कंपनियां नहीं जाती हैं, वहां निर्माण कार्य करना. एनपीसीसी ने अपने स्थापना काल से मौजूदा समय तक देश में कई बड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि एनपीसीसी का विवादों से भी पुराना नाता रहा है. मामला चाहे ताज कॉरिडोर के निर्माण का हो या किसी अन्य परियोजना का. देश में जब पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुईं तो केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने का प्रस्ताव दिया गया था. 12 मई, 1998 को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिले. इस फ़ैसले के बाद एनपीसीसी ने अपने सभी वर्गों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से 60 साल कर दी. हालांकि सरकार को यह महसूस हुआ कि इस निर्णय से देश की कमज़ोर कंपनियों के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. इसलिए उसने निर्णय लिया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस निर्णय की पुन: समीक्षा करें. चौथी दुनिया की तहक़ीकात में यह पता चला कि 19 जनवरी, 2007 को पीएसईबी (पब्लिक इंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड) ने एनपीसीसी में डायरेक्टर इंजीनियरिंग पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसके जॉब डिस्क्रिप्शन में यह लिखा गया था कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल होगी. उसके बाद 23 मार्च, 2007 को जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने पीईएसबी को सूचित किया कि एनपीसीसी में डायरेक्टर के लिए रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है. लिहाज़ा उसने इसमें आवश्यक सुधार करने का अनुरोध किया. यह सूचना प्राप्त होने के बाद पीईएसबी ने इंटरनल नोट अग्रसारित किया, जिसमें उसने बताया कि मंत्रालय ने यह सूचना दी है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल की जगह 58 साल की जाए. 26 मार्च, 2007 को जल संसाधन मंत्रालय ने एक ओ एम (ऑफिस मेमोरेंडम) 9/4/2006-पीएसयू/277 पीईएसबी को भेजा, जिसमें बताया गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की जाए. 30 मार्च, 2007 को पीईएसबी ने जल संसाधन मंत्रालय की बात मानते हुए एक रिवाइज्ड (पुनरीक्षित) विज्ञापन निकाला, जिसमें 19 जनवरी, 2007 का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया. इस नए विज्ञापन, संख्या 7/5/2007-पीईएसबी, 30 मार्च, 2007 में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल निर्धारित की गई. उसके बाद 29 और 30 मई 2007 को पीईएसबी ने डायरेक्टर इंजीनियरिंग पद का साक्षात्कार आयोजित किया, जिसमें ए के झांब का नाम शॉर्टलिस्ट कर जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ सचिव जल संसाधन मंत्रालय और अतिरिक्त सचिव एवं इस्टेवलिपमेंट ऑफीसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) को एसीसी एप्रूवल हासिल करने के लिए भेजा. उसके बाद 19 अगस्त, 2010 को चीफ मैनेजर (एच आर) ने एक प्रपोजल झांब के टेन्योर को एक्सटेंड करने के संबंध में अवर सचिव (जल संसाधन मंत्रालय) को 58 साल के बाद 2 साल सेवा विस्तार हेतु भेजा. ग़ौरतलब है कि इस पत्र को ए के झांब ने ही एप्रूव किया. उसके बाद जल संसाधन मंत्रालय ने अपनी सिफारिश पीईएसबी को भेज दी. उसके बाद 9 दिसंबर, 2010 और 5 जनवरी, 2011 को मंत्रालय ने पीईएसबी से ए के झांब का सेवा विस्तार करने हेतु पत्र भेजा, जिसका पत्रांक-9/1/2005/पीएसयू-1473, दिनांक 19.12.2010 और 9.1.2005-पीएसयू/18, दिनांक 5.1.2011 है. उसके बाद पीईएसबी ने इस विषय पर 19 जनवरी, 2011 को विमर्श किया, जिसमें सचिव, जल संसाधन मंत्रालय ने ए के झांब का पक्ष रखा, लेकिन पीईएसबी ने स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट (एसपीआर) देखने के बाद पाया कि ए के झांब का प्रदर्शन उसके मानदंडों के अनुसार सेवा विस्तार के लिए कम है. इसके अलावा पीईएसबी ने यह भी लिखा कि उनकी सेवा अवधि सिर्फ़ एक साल बाक़ी है. ग़ौरतलब है कि ए के झांब की जन्मतिथि 11 मार्च, 1953 है. बहरहाल, पीईएसबी बोर्ड ने यह पाया कि उनके सेवा विस्तार के प्रस्ताव की संस्तुति न की जाए, क्योंकि एनपीसीसी में उनकी कोई ख़ास उपलब्धियां नहीं हैं, जिस वजह से उनका सेवा विस्तार किया जाए. इसलिए पीईएसबी बोर्ड ने 31 मार्च, 2011 के बाद से उनके सेवा विस्तार की सिफारिश नहीं की. उसके बाद पीईएसबी ने 20 जनवरी, 2011 को इस विषय की जानकारी सेक्रेट्री जल संसाधन मंत्रालय को पीईएसबी यू ओ नं.-9/48/2010-पीईएसबी, दिनांक 20.1.2011 को भेज दिया. जब ए के झांब को यह ज्ञात हुआ कि पीईएसबी ने उनके सेवा विस्तार के मामले को अग्रसारित नहीं किया है, तब उन्होंने पुन: 28 जनवरी, 2011 को एक पत्र सचिव जल संसाधन विभाग को भेजा, जिसमें उन्होंने यह कहा कि एनपीसीसी में बोर्ड स्तर के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है, न कि 58 साल.

उल्लेखनीय है कि ए के झांब ने अपने सेवा विस्तार का प्रस्ताव 19 अगस्त, 2010 को अवर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय को भिजवाया था, जिसे उन्होंने ख़ुद एप्रूव किया था. ख़ैर, 28 जनवरी, 2011 को झांब द्वारा लिखे गए पत्र पर जल संसाधन मंत्रालय ने पुन: ग़ौर किया. जबकि पीईएसबी ने जल संसाधन मंत्रालय की सिफारिश 20 जनवरी, 2011 को नामंजूर कर दी थी. 14 फरवरी, 2011 को यह तय पाया गया कि ए के झांब का यह पत्र डीपीई को भेजा जाए और 17 फरवरी, 2011 को इस आशय का ड्राफ्ट भी बनाया गया. हालांकि ज्वाइंट सेक्रेट्री वॉटर रिसोर्स ने कहा, एडिशनल सेक्रेट्री हेड डिजायर टू गिव सम रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन, द फाइल इज अकार्डिंगली पुट अप. उसके बाद एडिशनल सेक्रेट्री वॉटर रिसोर्स ने लिखा कि सचिव जल संसाधन मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श हुआ और यह पाया गया कि इस मामले का जल संसाधन मंत्रालय में ही पुनरीक्षण किया जाए, क्योंकि इस मामले से जुड़े दस्तावेज़ मंत्रालय में ही उपलब्ध हैं. हालांकि उनकी यह दलील समझ से परे है और कई संदेह पैदा करने वाली है. इस तरह का मामला डीपीई के पास ज़रूर भेजना चाहिए था. बहरहाल, 10 मार्च, 2011 को एडिशनल सेक्रेट्री मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्स ने एक नोट बनाया, जिसमें लिखा कि रिकॉर्ड के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि एनपीसीसी बोर्ड स्तर में सेवानिवृत्ति की आयु कभी नहीं बदली गई. इस नोट को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री ने भी अपनी सहमति दी थी. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशनल सेक्रेट्री, सेक्रेट्री और जल संसाधन मंत्री ने 10 मार्च, 2011 को इस नोट पर हस्ताक्षर किए थे. उल्लेखनीय है कि जल संसाधन मंत्रालय ने ए के झांब (डायरेक्टर इंजीनियरिंग) को सीएमडी (एनपीसीसी) का अतिरिक्त प्रभार 2 दिसंबर, 2011 को तीन महीने के लिए दिया, जबकि इस बारे में विजिलेंस क्लीयरेंस भी सीवीसी से नहीं लिया गया और न ही डीओपीटी (एसीसी) से इस बारे में एप्रूवल लिया गया. इतना ही नहीं, ए के झांब को पुन: तीन महीने का अतिरिक्त कार्यभार 2 मार्च, 2012 को मिला. ऐसे में सवाल यह है कि किस वजह से उनका सेवा विस्तार किया जा रहा है, उसके बारे में पूरी तरह पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही है.

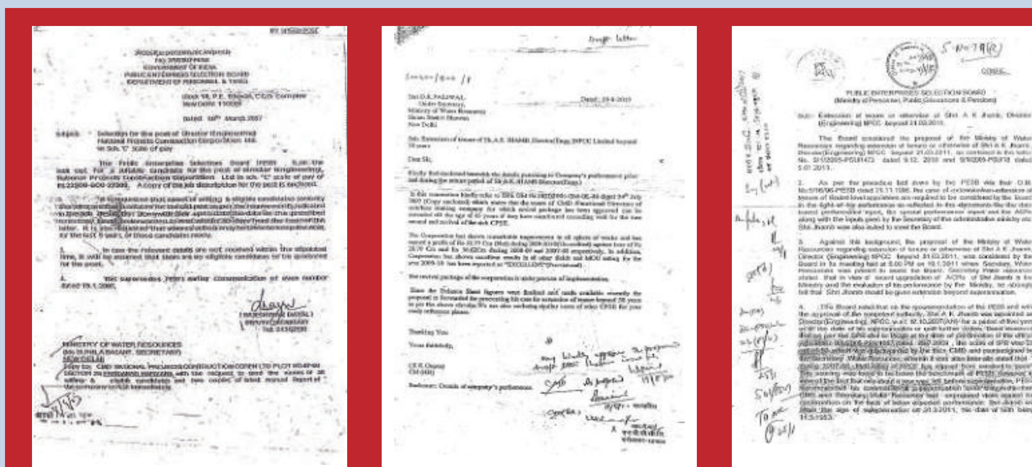


arsingh@chauthiduniya.com


## अल्पसंख्यक होने का एहसास कराया : एस आर हुसैन

सैयद रज़ा हुसैन, उम्र लगभग 50 साल, जो एनपीसीसी में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) के पद पर वर्ष 1983 से कार्यरत थे, ने चौथी दुनिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने एनपीसीसी में चल रहे गोरखधंधे और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जिस वजह से उन्हें 8 अगस्त, 2011 को बर्ख़ास्त कर दिया गया. बर्ख़ास्तगी के शिकार हुए सैयद रज़ा हुसैन एनपीसीसी स्टॉफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेट्री भी हैं. उनका कहना है कि यूनियन में वह अभी तक बने हुए हैं. बतौर महासचिव हुसैन ने एनपीसीसी में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया. हुसैन का कहना है कि विभाग ने मेरे ख़िलाफ़ जो चार्जशीट जारी की है, उसमें कहा गया है कि मैंने स्टॉफ यूनियन की आड़ में एनपीसीसी का नाम बदनाम किया है. हुसैन का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाज़ा यहां के नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है. क्या सच कहना और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करना गुनाह है. महीनों से वेतन से वंचित हुसैन का पूरा परिवार परेशान है. उनके तीन बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बग़ैर पैसों के उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा है. ऐसी हालत में भी हुसैन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है. उनका कहना है कि वह एनपीसीसी की सच्चाई देश की जनता के सामने लाएंगे. उनके मुताबिक़, उन्होंने पूर्व में भी प्रधानमंत्री को इस बारे में कई पत्र लिखे और आगे भी उन्हें पत्र लिखकर जानकारी देंगे. एनपीसीसी में वरीय अधिकारियों की मानवीय संवेदना किस तरह ख़त्म हो गई है, उसे विभाग में सहायक (कार्मिक व प्रशासनिक) के पद पर कार्यरत ख़ान ज़ियाउल्लाह ख़ान की आपबीती सुनकर समझा जा सकता है. वर्ष 2006 में उनका तबादला कॉरपोरेट ऑफिस नार्दन जोन में हुआ और अगस्त 2006 में उनका तबादला पुन: लखनऊ कर दिया गया. चार महीने के भीतर दोबारा तबादले का ऐसा प्रावधान समझ से परे है. ख़ान की मां और बहन मानसिक रोग से पीड़ित हैं. उनकी मां तो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी हैं. नियमानुसार इस तरह के रोगियों की देखभाल के दृष्टिकोण से उनके परिवारजनों, जो सरकारी सेवा में हैं, को मानवीय आधार पर परिवार से दूर नहीं भेजा जाता है. मां और बहन की उचित देखभाल हो, इसके लिए उन्होंने अपने वरीय अधिकारियों से विनती की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. सबसे ज़्यादा तकलीफ़ विभाग के कार्यकारी निदेशक की उस बात से हुई, जिसमें उन्होंने ख़ान से कहा कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, आपको मेरे पास नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक आयोग से विनती करनी चाहिए. उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वह भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक होने का एहसास करा रहे हैं. हुसैन के अनुसार, वर्ष 2006 में ख़ान को डेंगू हो गया. उसके बाद उन्हें कई तरह की बीमारियों ने भी अपना शिकार बनाया. इतना ही नहीं, फरवरी 2007 में उनके छोटे भाई की मौत एक हादसे में हो गई, बावजूद इसके विभाग ने उनका बकाया भुगतान नहीं किया. ख़ान जियाउल ख़ान ने इस बाबत कंपनसेशन के लिए एक रिट-7298/2008 दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की है.

आपका सपना एक छोटा सा फ्लैट हो या एक आलीशान विला
देना बैंक प्रस्तुत करता है ऐसा गृह ऋण
जो आपके सपनों को साकार करता है !

देना निवास गृह वित्त योजना

अधिक जानकरी के लिए हमारी निकटतमशाखा में संपर्क करें

बैंक अपनी सेवाएं हिन्दी में भी उपलब्ध कराता है.

देना बैंक DENA BANK (भारत सरकार का उद्यम) विश्वस्त पारिवारिक बैंक www.denabank.com

डिपॉज़िट प्रॉडक्ट्स | रिटेल लोन प्रॉडक्ट्स | इंश्योरेंस लिंक्ड प्रॉडक्ट्स | ई- प्रॉडक्ट्स

वैसे तो लगता है कि नीतीश कुमार के पास भारी बहुमत है, लेकिन 2010 के चुनाव के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो यह भ्रम दूर होता है. इस चुनाव में नीतीश कुमार को 31 फ़ीसदी वोट मिले थे यानी 69 फ़ीसदी लोगों ने उनके विरोध में वोट दिया था.

साक्षात्कार

# बड़े ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चलना मुश्किल

**83 वर्षीय सच्चिदानंद सिन्हा एक समाजवादी कार्यकर्ता, चिंतक एवं लेखक हैं. उस दौर में जब समाजवादी विचारधारा महानगरों एवं चर्चाओं तक सीमित रह गई हो, तब सच्चिदानंद बाबू की न सिर्फ़ लेखनी, बल्कि उनकी जीवनशैली भी समाजवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार करती नज़र आती है. आपातकाल ख़त्म होने और जनता पार्टी के बिखराव के बाद वह अपने गांव लौट गए. चाहते तो पटना या किसी अन्य शहर में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने गांव (मुज़फ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड अंतर्गत मणिका) में रहना पसंद किया. वह अकेले, बिना किसी नौकर की सहायता के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और अभी भी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर चल रहे जनांदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं. चौथी दुनिया संवाददाता शशि शेखर ने उनसे मणिका मुशहरी में विभिन्न मुद्दों पर एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:-**

***सोशलिस्ट पार्टी से लेकर आपातकाल का दौर, फिर समाजवादी जन परिषद और अब अपने गांव में. राजनीति और आंदोलन के एक लंबे दौर को कैसे देखते हैं आप?***

1977 की बात है, चुनाव होना था. जनता पार्टी का गठन हो रहा था. जार्ज फर्नांडिस सोशलिस्ट पार्टी का विलय जनता पार्टी में कर रहे थे. हम लोगों ने इस बात का समर्थन नहीं किया. हमने कहा कि हम जैसे लोग कहां जाएंगे. तब हमने नए समाजवादी आंदोलन की शुरुआत का निर्णय लिया. कर्नाटक के हमारे साथियों ने समता संगठन के नाम से नए आंदोलन की शुरुआत की. हम लोगों ने यह महसूस किया कि नई तकनीक समस्या का समाधान नहीं है. इसलिए हमने वैकल्पिक अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जो स्वदेशी हो. कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति, पश्चिम बंगाल में उत्तर बंग दलित आदिवासी संगठन, जनांदोलन समन्वय समिति का गठन किया गया. फिर 1995 में मुंबई की बैठक में समाजवादी जन परिषद की स्थापना की गई.

***तकनीक के इस दौर में आप तकनीक को नकार रहे हैं, आख़िर विकास कैसे होगा?***

ऊर्जा क्षेत्र को ही देखिए. चीन के मुक़ाबले भारत में मवेशियों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी चीन में गोबर गैस के 70 लाख प्लांट हैं, वहीं भारत में सिर्फ़ 7 लाख. हमारे पास स्थानीय संसाधनों की कमी नहीं है. आख़िर इससे विकास क्यों नहीं हो सकता. बिहार में या अन्य जगहों पर भी बड़ी ज़मीन वाले अपने खेत में ख़ुद खेती नहीं करते. बहुत से ज़मीन मालिकों ने खेती करना छोड़ दिया है. आख़िर सरकार ऐसी ज़मीनें चिन्हित करके ग़रीबों में बांट क्यों नहीं देती. हां, इसके बदले ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा भी दिया जाना चाहिए. दूसरी ओर विकास के नाम पर ज़मीन अधिग्रहण कर सरकार उद्योगपतियों को बांट देती है. क्या ग़रीबों एवं भूमिहीनों के बीच ज़मीन नहीं बांटी जा सकती है? जापान में फ्यूडल लॉ के तहत 7 एकड़ ज़मीन पर मालिकाना हक़ फिक्स कर दिया गया. देखिए, आज जापान कहां है.

***भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ और लोकपाल के मुद्दे पर पूरे देश में अभी एक आंदोलन चल रहा है. इसे कैसे देखते हैं आप?***

सवाल रीयल चेंज यानी असल बदलाव का है. संसद के भीतर के लोगों और संसद के बाहर खड़ी जनता के बीच यह लड़ाई है. इससे समाधान नहीं निकलेगा. असल समस्या कुछ और है. यह देश जितना बड़ा है, जितनी बड़ी आबादी है, जितना बड़ा ढांचा है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का सही ढंग से चलना ही मुश्किल है. लोकतंत्र के ढांचे को बहुत छोटी-छोटी इकाइयों में बांटना होगा. पंचायत और ग्रामसभा से भी छोटी इकाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता हो. उसी तरह अर्थतंत्र भी छोटी इकाई में हो. तकनीक और लोकतंत्र के गठबंधन ने अमीर-ग़रीब के बीच की खाई बढ़ाई, साथ ही पर्यावरण को भी नुक़सान पहुंचाया है. ग़ैर बराबरी से लोकतंत्र नहीं चलेगा.

***बिहार में विकास की बात काफी जोर-शोर से की जा रही है, सरकार उच्च विकास दर की बात कह रही है, आप क्या मानते हैं?***

एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, ऊर्जा क्षेत्र का. विकास के लिए ऊर्जा एक अहम मसला है. बिहार में ऊर्जा क्षेत्र की हालत क्या है? सड़कों की हालत देखिए. राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली सड़कों और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या केंद्रीय योजनाओं से बनी सड़कों के बीच तुलना कर लीजिए, हक़ीक़त समझ जाएंगे. मेरे घर के ठीक आगे की सड़क और मेन रोड की सड़क को ही देख लीजिए. मेरे घर के पीछे मणिका मन है. इसके विकास की बात मैं पिछले 5 सालों से सुन रहा हूं, अब तक कुछ नहीं हुआ. जो एस्बेस्ट्स पूरे विश्व में बैन हो चुका है, उसकी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी. जब हम लोगों ने विरोध किया तो मीडिया ने हमारे विरोध को जगह ही नहीं दी.

***सरकारी दावों और हक़ीक़त के बीच जो भी अंतर है, उसके पीछे क्या वजह हैं?***

नीतीश कुमार होशियार हैं. वह जानते हैं कि वोट कैसे मिलता है. लालू यादव की अव्यवस्था असहनीय थी. उनके समय में बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लड़ाई थी. नीतीश ने ईबीसी/महादलित कैटेगरी बनाकर लालू को शिकस्त दी. वैसे तो लगता है कि नीतीश कुमार के पास भारी बहुमत है, लेकिन 2010 के चुनाव के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो यह भ्रम दूर होता है. इस चुनाव में नीतीश कुमार को 31 फ़ीसदी वोट मिले थे यानी 69 फ़ीसदी लोगों ने उनके विरोध में वोट दिया था, लेकिन विरोधी मतों के बिखराव की वजह से नीतीश कुमार इतनी सीटें पा गए. विपक्ष के बिखराव से ही नीतीश कुमार सर्वाइव कर रहे हैं.

***क्या राजनीतिक विकल्प के अभाव का असर सरकार, शासन एवं प्रशासन की कार्यशैली पर भी पड़ रहा है?***

विकल्प का अभाव भी है और नीतीश कुमार अरोगेंट भी हैं. कुछ खास चुने हुए लोगों की ही सलाह मानते हैं और उसी के मुताबिक़ काम करते हैं. इसका नुक़सान तो हो ही सकता है. धीरे-धीरे फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ने लगा है. पंचायतों के अंदर लूटखसोट मची हुई है. इंदिरा आवास एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए केंद्र से पैसा आता है, जिसे पंचायत स्तर पर लूट लिया जाता है. गवर्नेंस कहां है. पंचायत का पैसा ठीक से नहीं बंट पाता. फिर कैसा और कहां का गुड गवर्नेंस. मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं, बिहार का विकास भी स्थानीय संसाधनों के सहारे ही संभव है. खाली और जिस ज़मीन पर खेती नहीं हो रही है, उसे ग़रीबों के बीच बांटा जाना चाहिए, लेकिन इसकी जगह बिहार सरकार किसानों की ज़मीन एस्बेस्ट्स फैक्ट्री और उद्योगपतियों को दे रही है. इस हिसाब से देखें तो विकल्प के अभाव से नुक़सान तो हो ही सकता है, लेकिन कोई उपाय भी नहीं दिख रहा. विकल्प जब तक नहीं बनेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता.

shashishekhar@chauthiduniya.com

अन्ना चर्चा समूह

# सरकारी लोकपाल कैसे धोखा है

अरविंद केजरीवाल

**कई लोग पूछ रहे हैं, लोकपाल बिल आ तो गया, अब अन्ना हज़ारे किस लिए लड़ रहे हैं?**

- सरकार ने जान बूझ कर लोगों में यह ग़लतफ़हमी पैदा की है. पहली बात तो यह है कि लोकपाल बिल अभी संसद में पारित नहीं हुआ है. अभी केवल लोकसभा में पारित हुआ है, राज्य सभा में अभी भी विचाराधीन है.
- लेकिन ज़्यादा गंभीर मामला यह है कि, जो लोकपाल बिल सरकार ने संसद में पेश किया है, वह बहुत ख़तरनाक है. यदि वो पास हो गया तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा.
- अन्ना ने सरकारी लोकपाल बिल में 34 संशोधन के सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने उनमें से केवल एक ही बात मानी है. अन्ना की बाक़ी सारी बातें नामंजूर कर दी गई.
- सबसे ख़तरनाक बात यह है कि, सरकार ने अपनी तरफ़ से इसमें कुछ ऐसी बातें डाल दी हैं, जिससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाएगा. इसलिए किसी भी हालत में इस बिल को रोकना ज़रूरी है.

**1. सरकारी लोकपाल पूरी तरह से सरकार के हाथों की कठपुतली होगी**

(क) लोकपाल का चयन सीधे सरकार के हाथों में होगा: लोकपाल की चयन समिति में पांच सदस्य हैं- प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, लोकसभा स्पीकर, चीफ जस्टिस और सरकार का चुना एक गणमान्य वकील. ज़ाहिर है कि इसमें से तीन लोग सत्ता पक्ष के हैं, तो लोकपाल सीधे-सीधे सरकार के हाथों की कठपुतली होगा. अन्ना ने सुझाव दिया था कि, चयन समिति में नौ लोग होने चाहिए- प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के दो जज, दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त. ज़ाहिर है कि अन्ना के द्वारा सुझाई चयन समिति सरकार के नियंत्रण से बाहर होती. अन्ना ने यह भी सुझाव दिया था कि, एक खोज समिति बनाई जाए, जिसमें-रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सतर्कता आयुक्त, रिटायर्ड सीएजी, रिटायर्ड चुनाव आयुक्त होते. या जनता से अच्छे लोगों के नाम मंगवाते. वेबसाइट पर डालकर उन नामों पर जनता की राय मांगते और आपस में आम सहमति से उन नामों का चयन करते. सरकार ने अन्ना की यह सारी मांगें ख़ारिज़ कर दी हैं. सरकार की चयन प्रक्रिया के हिसाब से सत्ताधारी पार्टी किसी भी भ्रष्ट और अपने वफादार व्यक्ति को लोकपाल बना सकती है.

(ख) लोकपाल को निकालना तो सरकार के नियंत्रण में होगा: सरकारी लोकपाल बिल के हिसाब से यदि लोकपाल भ्रष्ट होता है तो, केवल सरकार इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर सकती है. एक आम आदमी भ्रष्ट लोकपाल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा. जब तक सुप्रीमकोर्ट सरकार की शिकायत पर जांच करेगा उस दौरान सरकार लोकपाल के सदस्यों को सस्पेंड कर सकती है. यह बहुत ख़तरनाक है. मान लीजिए, लोकपाल ने किसी मंत्री के ख़िलाफ़ जांच शुरू कर दी तो, सरकार लोकपाल के उस सदस्य के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कोई झूठी शिकायत कर देगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा तब तक सरकार उस लोकपाल के सदस्य को सस्पेंड कर देगी. अन्ना ने सुझाव दिया था, कि भ्रष्ट लोकपाल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करने का अधिकार जनता को भी होना चाहिए. जब तक सुप्रीम कोर्ट जांच करता है, लोकपाल के सदस्य को सस्पेंड करने का अधिकार सरकार को कतई नहीं होना चाहिए. ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होना चाहिए. सरकार ने अन्ना की बात नहीं मानी, क्योंकि सरकार लोकपाल को अपने हाथ की कठपुतली बनाए रखना चाहती है.

(ग) लोकपाल के उच्च अधिकारियों का चयन सरकार करेगी: सरकारी लोकपाल बिल के मुताबिक़ लोकपाल के सभी उच्च अधिकारियों का चयन सरकार करेगी. अन्ना का कहना है कि अपने सभी अधिकारियों का चयन करने का अधिकार लोकपाल के पास होना चाहिए, लेकिन सरकार ने यह बात भी नहीं मानी.

(घ) सरकारी लोकपाल टीन का एक खोखला डिब्बा: दुनिया में पहली बार एक ऐसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी का गठन किया जा रहा है,जिसके पास न जांच करने की ताक़त होगी और न जांच करने की अपनी एजेंसी. सरकारी लोकपाल क़ानून के मुताबिक़ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ शिकायत की जांच लोकपाल को किसी सरकारी एजेंसी से करानी होगी. यह कैसी व्यवस्था हुई? सरकारी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सरकारी एजेंसी ख़ुद ही जांच करेगी? ज़ाहिर है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी और जांच में कुछ नहीं निकलेगा और सभी बड़े नेताओं और अफसरों को बचा लिया जाएगा. अन्ना का कहना था कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन सीबीआई अभी उन्हीं लोगों के क़ब्ज़े में है, जिनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं. सीबीआई का सरकार जमकर दुरुपयोग भी करती है. सीबीआई को चिदंबरम जैसे भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब-जब सरकार ख़तरे में होती है, तो सीबीआई का इस्तेमाल करती है. मसलन, मायावती और मुलायम के पीछे छोड़कर, उन्हें डराकर उनकी पार्टियों का सहयोग लेने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए अन्ना जी का कहना है कि, सीबीआई को सरकारी शिकंजे से निकालकर लोकपाल की जांच एजेंसी बनाया जाए, लेकिन सरकार की तो नीयत ही ख़राब है. वह किसी भी हालत में सीबीआई को अपने शिकंजे से मुक्त नहीं करेगी. इससे यह ज़ाहिर है कि लोकपाल पूरी तरह से सरकार के हाथों की कठपुतली होगा.

**2. सरकारी लोकपाल बहुत ही ख़तरनाक है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है**

(क) भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में वकील: सरकारी लोकपाल क़ानून के मुताबिक़ भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को कोर्ट में अपना बचाव करने के लिए सरकार मुफ्त में वकील देगी. पहली बार क़ानूनन इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए प्रावधान किया जा रहा है.

(ख) भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को कठोर सज़ा: यदि कोई व्यक्ति लोकपाल को भ्रष्टाचार के किसी मामले की शिकायत करता है और शिकायत में पयार्प्त सबूत नहीं होने या उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो, उसे एक साल तक कैद हो सकती है. अगर आज कोई व्यक्ति लोकपाल में भ्रष्टाचार की शिकायत करता है तो, अगले दिन ही उसके ख़िलाफ़ भ्रष्ट अफसर या नेता कोर्ट में केस दर्ज कर सकेगा. इसके लिए सरकार भ्रष्टाचारियों को मुफ्त में अलग से वकील देगी. बेचारा शिकायतकर्ता शिकायत करने के अगले दिन से ही अपने को बचाने के लिए कोर्ट में चक्कर काटने लगेगा.

(ग) सबसे ख़तरनाक बात: इन क़ानून के मुताबिक़ चंदा पाने वाली हर संस्था (चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं) लोकपाल के दायरे में आएंगी जैसेः- मंदिर, मस्ज़िद, गुरुद्वारे, चर्च, महिला मंडल, धार्मिक संस्था, रामलीला कमेटी, दुर्गा पूजा समिति, मदरसा, क्रिकेट क्लब, स्पोर्ट क्लब, युवा क्लब, मज़दूर-किसान संगठन, आंदोलन, प्रेस क्लब, सारे अस्पताल, सारी डिस्पेंसरी, आर.डब्ल्यू.ए., रोटरी क्लब, लाइंस क्लब इत्यादि. इस क़ानून के मुताबिक़ इन संस्थाओं में काम काज करने वाले सभी लोगों को सरकारी अधिकारी घोषित कर दिया गया है. अब तो इस क़ानून के मुताबिक़ मंदिरों में काम करने वाले सभी पंडित मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने वाले मौलाना, गिरजाघरों में बाइबल पढ़ने वाले सभी फादर, गुरुद्वारों के सभी ग्रंथी, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों केअध्यापक, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ये सभी सरकारी अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं. अब सरकार लोकपाल के ज़रिए कभी भी इनमें से किसी पर भी छापा मार सकती है. अपने को लोकपाल के चंगुल से बचाने के लिए इन सब को लोकपाल को रिश्वत की मोटी रक़म देनी पड़ेगी . मज़ेदार बात यह है कि, बाक़ी सारे देश को लोकपाल में डाल दिया है, लेकिन राजनैतिक पार्टियां इसके दायरे से बाहर हैं.

(घ) केंद्र सरकार के 60 लाख में से 56 लाख कर्मचारी लोकपाल के दायरे से बाहर होंगे:
जैसे-इनकम टैक्स इंस्पेक्टर , कस्टम अप्रैजर , रेलवे का टी.टी. इत्यादि . इनमें से कोई व्यक्तिगत रिश्वत लेता है तो, अब उसे जेल नहीं भेजा जा सकेगा. यानि केंद्र सरकार 56 लाख कर्मचारी रिश्वत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.

(च) अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर संसद में या विधान सभा में प्रश्न पूछता है या वोटिंग करता है तो उसकी जांच भी लोकपाल नहीं कर सकेगा.

(च) अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो, उसे नौकरी से निकालने का अधिकार उसी विभाग के मंत्री को होगा. अधिकतर मामलों में रिश्वत का हिस्सा मंत्रियों तक पंहुचता है. आज़ादी के बाद से आज तक किसी मंत्री ने अपने नीचे काम करने वाले किसी भ्रष्ट सेक्रेट्री को निकालने की इज़ाजत नहीं दी है तो, हम भविष्य में उनसे ऐसा करने कि उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ज़ाहिर है कि इस प्रावधान से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलेगा.

**3. भ्रष्टाचारियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की सुरक्षाः**

अगर कोई सूचना केअधिकार से सूचना मांगता है या भ्रष्टाचार केख़िलाफ़ कोई शिकायत करता है तो, उस पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है. पिछले एक साल में ऐसे 13 लोगों का क़त्ल कर दिया गया. सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ, सतीश शेट्टी, अमित जेठवा, दत्ता पाटिल, विट्ठल गिटे, सोलारंगा राव, शशिधर मिश्रा, विश्राम लक्ष्मण डोडिया, वैंकटेश, ललित कुमार मेहता, कामेश्वर यादव, शहला मसूद आदि ऐसे कई शहीदों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. अभी पिछले दिनों बागपत ज़िले में मनोज ने जब शिक्षा विभाग और खाद्य विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया तो तलवारों से उस पर हमला किया गया. इन सभी मामलों में स्थानीय पुलिस अक्सर भ्रष्टाचारियों केसाथ मिली होती है. एक तरफ़ तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को हमले बर्दाश्त करने पड़ते हैं, दूसरी तरफ़ पुलिस उन पर झूठे मुक़दमे लगाकर उन्हें प्रताड़ित करती है. मनोज और उनके परिवार के सदस्यों पर अनेक ऐसे झूठे मुक़दमे लगा दिए हैं. लोकपाल आने पर यदि कोई लोकपाल को शिकायत करेगा तो ज़ाहिर है कि उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा. अन्ना का कहना था कि, लोकपाल केपास ऐसे लोगों को संरक्षण देने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अन्ना की यह बात नहीं मानी.

**4. भ्रष्टाचार करने वालों को सज़ा :**

अभी क़ानूनन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अधिकतम सज़ा सात साल की है. अन्ना का कहना है कि भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाए, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी है. आज अक्सर यह देखने में आता है कि, कंपनियां रिश्वत देकर सरकार से तरह-तरह के फ़ायदे लेती है. अन्ना का कहना है कि अगर किसी कंपनी केख़िलाफ़ कोर्ट में भ्रष्टाचार साबित हो जाता है तो, उस कंपनी को भविष्य में कभी सरकारी ठेका न दिया जाए. भ्रष्टाचार के ज़रिए उस कंपनी ने सरकार को जो नुक़सान पंहुचाया उसकी पांच गुनी रक़म उस कंपनी से जुर्माने के रूप में वसूल किए जाए. सरकार ने अन्ना की यह बात नहीं मानी.

**5. लोकपाल के कर्मचारी अगर भ्रष्ट हो गए तो क्या होगा :**

सरकारी लोकपाल बिल के मुताबिक़ लोकपाल ख़ुद अपने भ्रष्ट कर्मचारियों केख़िलाफ़ जांच करेगा, इसमें शक पैदा होता है कि लोकपाल कहीं अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश न करे. इसकी वजह से लोकपाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकता है.
अन्ना का कहना था कि, लोकपाल के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र शिकायत आयोग बनाया जाए . जो सबके सामने ऐसी शिकायतों की सुनवाई कर लोकपाल के भ्रष्ट कर्मचारियों को दो महीने में नौकरी से निकाल दे. लोकपाल की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने केलिए अन्ना के जन लोकपाल में अन्य कई सुझाव दिए थे, लेकिन सरकार ने इनमें से कोई सुझाव नहीं माना.

**6. लोकपाल खाली बैठा रहेगा**

सरकारी लोकपाल बिल केमुताबिक़ यदि लोकपाल की नज़र में कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है , तो वह ख़ुद कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक कोई शिकायत न करे और शिकायत करने से लोग डरेंगे, क्योंकि शिकायतकर्ता पर तो अगले दिन ही केस कर दिया जाएगा. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी लोकपाल खाली ही बैठा रहेगा.

**7.आम आदमी भ्रष्टाचार झेलता रहेगा**

आम आदमी का भ्रष्टाचार और महंगाई से जीना मुश्किल हो गया है . अन्ना ने कहा था कि आम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए सिटिजन चार्टर लाओ. अगर किसी व्यक्ति द्वारा समय सीमा में काम नहीं किया जा रहा है तो लोकपाल उस विभाग के प्रमुख की तनख्वाह काटे, जो शिकायतकर्ता को मुआवज़े के तौर पर दी जाए. दो मामलों में भी यदि विभाग प्रमुख की तनख्वाह कट गई तो सारा विभाग ठीक से काम करने लगेगा, लेकिन सरकार जलेबी वाला सिटिज़न चार्टर बिल लाई है. सरकारी बिल के हिसाब से किसी विभाग में यदि काम कराना है, तो पहले वह आदमी संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, इसके बाद उसी विभाग में अपीलीय अधिकारी के पास जाएगा. उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी के पास जाएगा, फिर जन शिकायत आयोग में जाएगा, फिर लोकायुक्त के पास जाएगा. सरकार लोगों को परेशान करना चाहती है? सरकारी क़ानून में काम न होने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान इतना लचर है कि किसी पर जुर्माना लगेगा ही नहीं तो भला कोई काम क्यों करेगा ?

feedback@chauthiduniya.com

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

**सरकार ने अब खुली चुनौती दी है अन्ना के जनलोकपाल की कोई बात नहीं मानी जाएगी**
**सरकार का कहना है.**
**आप आंदोलन करते रहिये क़ानून बनाना हमारा काम है. हमें आंदोलन की कोई परवाह नहीं है.**
**अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसे में सरकार को कैसे सख्त क़ानून बनाने के लिए मनाया जाए?**
**हम सख्त लोकपाल के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.**
**अपनी अंतिम सांस तक हम लड़ते रहेंगे.**
**क्या आप भी समर्पित हैं?**

## भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चौथी दुनिया की मुहिम

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ चौथी दुनिया की एक और मुहिम. चौथी दुनिया के माध्यम से आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़ सकते हैं. अपनी राय, सवाल और सुझाव सीधे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और टीम अन्ना के सामने रख सकते हैं. चौथी दुनिया आपके सवाल और राय को सीधे पहुंचाएगा टीम अन्ना तक और उनके जवाब आप तक. आप हमें पत्र और ईमेल के ज़रिये अपनी बात और अपने सवाल भेज सकते हैं. चौथी दुनिया अख़बार और चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर लगातार हम इस कॉलम और अरविंद केजरीवाल का साक्षात्कार प्रकाशित और प्रसारित करते रहेंगे. आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया
*एफ-2, सेक्टर 11*
*नोएडा*
*उत्तर प्रदेश*
*पिन:201301*
*ईमेल: sawal@chauthiduniya.com*

राजीव गांधी ने इसे समझा, क्योंकि वह उस समय के युवा वर्ग का एक चेहरा बन गए थे. उनके द्वारा उठाए गए क़दमों एवं सुधारों से युवाओं को फ़ायदा हुआ.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

# दुष्टतापूर्ण नीति

भारत में तो एक तरह से यह स्थिति आ गई है कि शासन को भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ ही चला रहा है. कोई भी काम हो, अगर उसके अधिकारीगण कराना चाहेंगे तो फ़ौरन हो जाएगा, चाहे वह काम क़ानूनन वैध हो अथवा अवैध. कोई मिल, फैक्ट्री या कारखाना कितने ही वर्षों से नुक़सान में चल रहा हो, मज़दूर आवश्यक संख्या से बहुत ज़्यादा हों, यहां तक कि धीरे-धीरे मिल की सारी पूंजी समाप्त हो जाए, पर इन श्रमिक संघों के कान पर जूं नहीं रेंगेगी. पर यदि विवश होकर मालिक लोगों को नुक़सान उठाने में अपने आपको असमर्थ पाकर मिल जबरन बंद करनी पड़ी तो हाहाकर मचेगा कि ग़रीब मज़दूर बेकार हो गए हैं, तकलीफ पा रहे हैं. उनकी असहायावस्था एवं दारुण विपत्ति की कथा इतनी अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा में प्रस्तुत की जाएगी कि साधारणतया लोग दूसरे पक्ष के बारे में विचार करने का अवकाश ही नहीं पाएंगे. मालिकों की स्थिति क्या है, इस विषय पर विचार करना भी ज़रूरी है. मिल अथवा फैक्ट्री के नुक़सान उठाने पर आर्थिक सहायता का कोई स्रोत उनके पास नहीं. अपनी सारी मिल्कियत गिरवी रखने पर अथवा हर तरह की सिक्योरिटी पेश करने के बावजूद सरकार की ओर से उन्हें उधार पैसा मिलना कठिन है, ताकि वे मिल, फैक्ट्री अथवा उस कारखाने को चला सकें. रुपये के इस अभाव की पूर्ति होने पर शायद मिल या कारखाना अथवा फैक्ट्री फिर चल सकती थी. मिल बंद हो गई, मालिक दीवालिए घोषित हो गए. रुपये के अभाव में इसके सिवाय कोई चारा भी नहीं था.

मिल के बंद होते ही रुपये देने में उदासीन वही सरकार किसी श्रमिक संघ के कहने पर बिना सिक्योरिटी के रुपये लगाने को तैयार हो जाएगी. इस तरह से यह कारखाना, फैक्ट्री अथवा मिल बेकारी सहायता योजना के अंतर्गत संघ के हाथ चलाने के लिए दे देगी. ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं और हो भी रही हैं. यद्यपि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की निजी या व्यक्तिगत संपत्ति बिना उचित मुआवज़ा दिए सरकार नहीं ले सकती. फिर भी अनेक ऐसे लोग हैं, जिनकी व्यक्तिगत अथवा निजी संपत्ति सरकार ने बिना पूरा अथवा अधूरा मुआवज़ा दिए हड़प ली. कारण शायद यह हो कि इन उद्योगों के मालिकों की आवाज़ सत्ताधारियों तक पहुंच नहीं पाती. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस कार्यवाही को अवैध घोषित कर दिया तो सरकार ने तत्काल संविधान में ही संशोधन कर दिए. भारतीय संविधान का चतुर्थ संशोधन क़ानून इस हेतु ही बनाया गया, जिससे कि सरकार किसी की भी निजी संपत्ति अगर वह किसी प्रकार का उद्योग है तो बिना किसी कारण, बिना किसी तरह का मुआवज़ा दिए संचालन या नियमन करने के लिए 5 वर्ष तक अपने हाथ में ले सकती है. उद्योग नियमन विधेयक इसीलिए बनाए गए थे. कई अधिनियम भी बने, जिनसे भारतीय नागरिकों से मूलभूत अधिकार वापस ले लिए गए.

यह संघों का ही प्रभाव है कि प्रत्येक धनाढ्य को आज 70 से 75 प्रतिशत अपनी आय का भाग सरकार को समर्पित कर देना पड़ता है. संभव है कि एक दिन ये तमाम पूंजीपति भी अपना संघ क़ायम कर लें और हड़ताल कर दें कि हम शासन के लिए कर जमा कराने का जो दायित्व वहन कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे. न हम कमाएंगे, न हम टैक्स देंगे. आज जबकि संघों का इतना प्रताप है तो इस तरह की स्थिति आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं. ऐसा समय भी शीघ्र ही आने वाला है, जब सब श्रमिक मिलकर यह महसूस करने लगेंगे और व्याकुल होकर कहने लगेंगे कि पूंजीवादी तत्वों से प्रभावित इन संघों के संघर्ष से हमें बचाइए. पूंजीवादियों से भी अधिक हमें पूंजीवादी प्रवृत्ति से भरे हुए अपने संघों से ही अधिक डर है. अमेरिका जैसे विकसित देशों के श्रमिकों की यह उत्पीड़ित आवाज़ दिन-ब-दिन गंभीर रूप धारण कर रही है.

## धन की क़ीमत

सामूहिक पूंजीवाद का ज़िक्र काफी हो चुका. वैयक्तिक पूंजी या पूंजीवाद के महत्व का अवलोकन करना भी आवश्यक है. मान लीजिए, आपके पास थोड़ी-बहुत निजी पूंजी है तो यह भी आवश्यक है कि परिस्थिति का विवेचन उस पहलू से भी हो. संपत्ति का कोई निश्चय स्वरूप तो होता नहीं. आपके पास यदि कोई धन है तो सवाल यह है कि वह किस रूप में है? यदि वह मोटरगाड़ी के रूप में है, अन्न भंडार है, सोने के जेवर अथवा जवाहरात हैं या करेंसी नोट हैं? जो धन आपके पास है, उसकी क़ीमत तभी तक है, जब तक कि दुनिया उसे धन मानती है. अन्न भंडार के रूप में जो धन है, उसका सदैव मूल्य बना रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, टिकाऊ नहीं रहता. इसलिए उसी रूप में तो उसे आप हमेशा रख सकते नहीं, किसी न किसी रूप में उसे परिवर्तित करना ही पड़ेगा. चाहे उसे चांदी के रूप में बदल दीजिए अथवा सोने के रूप में, उसका मूल्य अन्न से कुछ ज़्यादा अरसे तक बना रहता है. अन्य तमाम वस्तुओं को धन के अंतर्गत तभी तक रखा जा सकता है, जबकि उसका कोई दूसरा ग्राहक मौजूद हो. मान लीजिए कि देश के प्रत्येक नागरिक के पास सोना-चांदी आदि फालतू द्रव्य के रूप में हों और अन्न-वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक साथ अपना सोना-चांदी बेचना चाहते हैं. कोई ख़रीददार नहीं है. उस हालत में उस द्रव्य की हैसियत क्या रहेगी? उसका क्या मूल्य होगा? उसे कोई कौड़ियों में भी नहीं पूछेगा. बात सीधी या हंसने की नहीं है. विश्व में ऐसी स्थिति अनेक देशों में हो चुकी है. एक प्याली चाय के लिए नोट या सेरों धातु देने पर भी उपलब्धि संभव नहीं थी.

## तो धन किसको समझें?

मानव के लिए जीवनोपयोगी सामग्री अन्न-वस्त्र इत्यादि धन है और चूंकि ये टिक नहीं सकते. अत: इन्हें लेकर सही माने में कोई व्यक्ति धनाढ्य नहीं बन सकता. अब तो सिर्फ़ सामाजिक मान्यता की ही बात रहती है. आजकल हम सब सोना-चांदी या करेंसी नोटों को धन मानते हैं और चूंकि सब या बहुसंख्यक सब यही मानते हैं तो वह धन है ही. आपके पास कुछ फालतू धन है. आप उसे सोने-चांदी के रूप में बदल कर रखते हैं या उसका ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे आगे आने वाले समय के लिए वह सुरक्षित रहे. ऐसे धन को लागत पूंजी या निवेश पूंजी कहते हैं. अगर आपके पास इस तरह से जमा की हुई या सुरक्षित पूंजी है तो उस पूंजी से जो आय होगी, वह आपकी अनर्जित आय है. समाजवाद में अनर्जित आय को अनुचित माना जाता है. भारत सरकार ने समाजवादी व्यवस्था को मान्यता देते हुए जो आयकर लगा रखे हैं, उनमें अर्जित और अनर्जित आय की दरों में फ़र्क़ है.

समाजवादी ध्येय की प्राप्ति के लिए भारतीय शासन ने एक नया टैक्स और लगाया है, जिसे संपत्ति कर कहते हैं. कई लोगों का कहना है कि ऐसा टैक्स विश्व के किसी दूसरे देश में नहीं लगाया गया. यह बात सही नहीं है. हालांकि ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में इस तरह का संपत्ति कर नहीं है, पर हालैंड, स्कैंडेनेविया, जर्मनी आदि देशों में इस तरह का संपत्ति कर कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है. इसके फलस्वरूप सामाजिक-आर्थिक समानता कुछ हद तक हासिल भी हो पाई है. मृत्यु कर विश्व के अनेक देशों में मौजूद है. इसका स्वरूप निश्चय ही सामाजिक व्यवस्था में समान वित्त वितरण का है. अब सवाल यह कि आपकी संपत्ति क्या है, उसका इन करों के लिए मूल्यांकन कैसे हो? जैसा कि मैंने कहा, आपकी संपत्ति तब तक ही संपत्ति है, जब तक लोग उसे धन मानें या उसका उस रूप में उपयोग हो.

अगर आपको अपना संपत्ति टैक्स चुकाने के लिए अपनी साइकिल या टाइपराइटर मशीन बेचनी है और इसी प्रकार देश के समस्त करदाताओं को अपनी-अपनी साइकिल या टाइपराइटर बेचने हैं तो कहिए क्या मूल्य होगा? पांच सौ रुपयों की लागत की चीज को कोई पचास में भी नहीं पूछेगा और कोई खरीददार नहीं मिलेगा. टैक्स चुकाने के लिए रुपयों का होना आवश्यक है. नतीजा होगा, 50 रुपये में या उससे भी कम में उसे आपको बेचना पड़ेगा. ग्रेट ब्रिटेन में बड़े-बड़े लार्डों के, रईसों के विशालकाय मकान, इस्टेट जो करोड़ों की लागत से बने थे, यों ही कौड़ियों के मोल बिके और जब सामाजिक परिस्थिति में समाजवाद का दौर आया तो हालत यह हो गई कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही धनाढ्य क्यों न हो, एक बड़ी कोठी या मकान रख नहीं सका. उसकी साफ-सफाई, रंगाई-पुताई कराने में या नौकरों के रखरखाव की व्यवस्था में इतना ज़्यादा ख़र्च होने लगा कि बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो गया. भारत में भी यही स्थिति है या होने जा रही है. बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं या ठाकुरों की कोठियां, गढ़ या महल सस्ती क़ीमतों में बिके और बिकाऊ हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में संपत्ति कर या मृत्यु कर देते हुए बड़ी-बड़ी हवेलियां रख सकना किसी भी व्यक्ति या परिवार की सामर्थ्य के बाहर की बात होगी.

feedback@chauthiduniya.com

*महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.*

मेघनाद देसाई

# राहुल गांधी को हार से सबक लेना चाहिए

बजट आ चुका है और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम भी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया है कि सहयोगी दलों द्वारा रोड़े अटकाए जाने के कारण वह कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं. अगर कांग्रेस को आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसे पुनर्विचार करना होगा कि राहुल गांधी को फिर से मौक़ा दिया जाए या फिर अपनी रणनीति बदली जाए. बॉलीवुड का एक उदाहरण है. जॉय मुखर्जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अपने पिता की फिल्म से की. शुरुआती दौर में वह सफल रहे, लेकिन अपनी सफलता को बरक़रार नहीं रख सके. शम्मी कपूर ने भी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत परिवार के सहयोग से की, लेकिन शुरुआती दौर में वह असफल रहे. उन्होंने संघर्ष जारी रखा और नासिर हुसैन की एक फिल्म ने उन्हें सफलता का स्वाद चखाया. बाद में शम्मी कपूर एक सफल अभिनेता साबित हुए. उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी को जॉय मुखर्जी बनना है या फिर शम्मी कपूर. राहुल गांधी ने ढेर सारे वादों के साथ राजनीति में प्रवेश किया. उन्हें उम्मीद थी कि वह काफी सफल होंगे. कुछ समय तक उनके काम की सराहना की गई. संभव है कि उनके चमचों ने ऐसी बात कही हो, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होता है. हमें उनसे यही पूछना है कि वह जॉय मुखर्जी बनना चाहते हैं या फिर शम्मी कपूर.

बेशक अखिलेश यादव जॉय मुखर्जी की तरह शुरुआत में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, यदि उनका परिवार उत्तर प्रदेश में इसी तरह चुनाव जीतना जारी रखता है. समाजवादी पार्टी की पहली सरकार को गुंडाराज कहा जाता रहा है. सुखबीर सिंह बादल ने भी इसी तरह अपने परिवार का सहारा लिया है. जगन रेड्डी अपना काम धीमी गति से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी. परिवार आपकी सहायता कर सकता है, आपको प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन आगे क्या करना है, कैसे करना है, यह तो ख़ुद तय करना होगा. वंशवाद द्वारा आप सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं. क्या राहुल गांधी शम्मी कपूर बन सकते हैं. बेशक राहुल का स्टाइल और संदेश सही नहीं कहा जा सकता है. कभी दाढ़ी के साथ और कभी क्लीन शेव वाला उनका चेहरा लोगों का दिल नहीं जीत पाया. उनका एंग्री यंगमैन की छवि बनाने का तरीक़ा पुराना हो गया है. यह साठ के दशक में चल सकता था. उनका ग़रीबी हटाने या ग़रीबों के लिए कुछ करने का संदेश भी पुराना है और उनकी दादी आजमा चुकी हैं. इन तरीक़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं. राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता तभी दिखाई पड़ेगी, जब वह अपनी पुरानी ग़लती से कुछ सीखेंगे. उन्होंने जो ग़लतियां विगत चुनाव के समय की हैं, उन्हें फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे. उन्हें नए तरीक़े अपनाने की ज़रूरत है. उन्हें देश के 35 साल तक के युवाओं के बीच अपनी पैठ बनानी चाहिए. यह युवा वर्ग वादों से नहीं मानने वाला है. उसे काम चाहिए, बदलाव चाहिए.

**बेशक अखिलेश यादव जॉय मुखर्जी की तरह शुरुआत में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं, यदि उनका परिवार उत्तर प्रदेश में इसी तरह चुनाव जीतना जारी रखता है. समाजवादी पार्टी की पहली सरकार को गुंडाराज कहा जाता रहा है. सुखबीर सिंह बादल ने भी इसी तरह अपने परिवार का सहारा लिया है. जगन रेड्डी अपना काम धीमी गति से कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी.**

राजीव गांधी ने इसे समझा, क्योंकि वह उस समय के युवा वर्ग का एक चेहरा बन गए थे. उनके द्वारा उठाए गए क़दमों एवं सुधारों से युवाओं को फ़ायदा हुआ. उनकी कमाई इस स्तर की हो गई कि वे अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अंडमान जा सकते थे. उनके परिवार वालों ने भी राजीव गांधी को समर्थन दिया. राहुल गांधी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं. उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सहयोगी लोग विदेशी सोच रखते हैं. केवल मतदान के समय अपना चेहरा दिखाते हैं और निजी ज़िंदगी को लोगों से दूर रखते हैं. मुझे विश्वास है कि अगर वह अपना तरीक़ा बदलें तो लोग उन्हें ज़्यादा चाहेंगे. पुराने कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को शाहबानो मामले में ग़लत सलाह देकर उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को बिगाड़ा और राहुल के सलाहकारों ने भी बटला हाउस प्रकरण में यही किया. यह सही है कि भारत के हर क्षेत्र में वंशवाद का प्रभाव है, चाहे वह उद्योग हो या बॉलीवुड या फिर राजनीति. राहुल गांधी का परिवार भी उतना ही पुराना है, जितना टाटा घराना उद्योग में है, लेकिन परिवार ही सफलता की गारंटी नहीं है. जॉय मुखर्जी के उदाहरण से इसे देखा जा सकता है. प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में किसी विशेष परिवार का होना सफलता की गारंटी नहीं कहा जा सकता. राजनीति इससे अलग नहीं है. अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है तो फिर स्वयं ही मेहनत करनी होगी. अगर राहुल सबक नहीं ले सके तो फिर कांग्रेस को कोई और रणनीति बनानी होगी.

feedback@chauthiduniya.com

# पाठकों की दुनिया

## सर्वश्रेष्ठ पत्र

### समाज का कर्तव्य

देश में अनेक मुद्दों को लेकर बहस होती है, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच एक ज्वलंत मुद्दा ऐसा भी है, जिसकी हमेशा से ही उपेक्षा की जाती रही है. यह मुद्दा है उन महिलाओं का, जो वेश्यावृत्ति के दलदल में जीने को मजबूर हैं. कुछ महिलाएं मजबूरी में इसे अपनाने को मजबूर हैं, तो कुछ को उनके रिश्तेदारों या अन्य लोगों द्धारा जबरन इस दलदल में धकेल दिया जाता है. समाज में ऐसी महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि इन्हें इस पेशे में लाने वाले लोग कथित सम्मान के भागीदार बने रहते हैं. इतना ही नहीं, इन महिलाओं के पास आने वाले सफ़ेदपोश भी अपना स्वार्थ पूरा होने पर इन्हें अप्रिय शब्दों से पुकारते हैं. ये महिलाएं भी हमारे समाज का अभिन्न अंग हैं और इनकी इस दशा के लिए समाज ही ज़िम्मेदार है. इसलिए यह समाज का कर्तव्य बन जाता है कि वह इनके उत्थान के लिए कार्य करे.

-सरफ़राज़ असलम, *इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश.*

### साहित्य दुनिया के नए रंग

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-साहिर लुधियानवी हर पल के शायर थे, पढ़ा. साहिर लुधियानवी के बारे में पढ़कर अच्छा लगा. साहित्य दुनिया में नित नए रंग देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत लुभाते हैं. आपसे अनुरोध है कि इसे बनाए रखें. उम्मीद है कि आगामी अंकों में भी हमें शायरों और लेखकों के बारे में इस तरह के लेख पढ़ने को मिलते रहेंगे. अगर आप लघु कथाएं, गीत, ग़ज़ल और कविताओं को भी अपने अख़बार में प्रकाशित करें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा.

-फ़ैज़ान, *दिल्ली.*

### धर्म के नाम पर अधर्म

देश में धर्म की आड़ में अनैतिक धंधा ज़ोर-शोर से चल रहा है. इसका एक उदाहरण है इच्छाधारी बाबा उर्फ़ शिवमूर्ति द्विवेदी. भगवा चोले की आड़ में देश भर में संगठित रूप से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में फंसे इस बाबा ने निचली अदालत द्धारा अपने ख़िलाफ़ तय किए गए आरोपों को ख़ारिज कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, पर इसे राहत नहीं मिली. 1998 से लेकर अब तक बाबा के विरुद्ध दिल्ली और नोएडा में देह व्यापार के कई मामले दर्ज किए गए. ऐसे बाबाओं के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग धर्म को बदनाम करते हैं.

-डेनिस, *मुंबई, महाराष्ट्र.*

### दोहरी नीति ख़त्म हो

भारतीय चुनाव में दोहरी नीति ख़त्म होनी चाहिए, जैसे वोटिंग के समय जो ज़्यादा वोट पाता है, उसे जीता हुआ मान लिया जाता है. यहां पर वोट ट्रांसफर नहीं होते यानी तीन नंबर वाला अपने वोट दूसरे को ट्रांसफर करे तो उसे नहीं माना जाता. फिर संसद या विधानसभा में यह ट्रांसफर का खेल क्यों होता है, जिससे सरकार ब्लैकमेल होती है. जो सबसे ज़्यादा सांसद लाए, उसे सरकार बनाने दिया जाए. फिर वह सरकार कैसे चलाए, यह वह जाने. छोटे दलों से गठबंधन के नाम पर ब्लैकमेल होना बंद होना चाहिए.

-अनिल सरन अग्रवाल, *ई-मेल से.*

### चुनाव विश्लेषण

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत का मुख्य श्रेय मुस्लिम वोटों को देना सरासर ग़लत है. चुनाव विश्लेषण देखने पर पता चलता है कि बसपा और सपा में सिर्फ़ कुछ प्रतिशत वोटों का अंतर है. समाजवादी पार्टी की जीत का मुख्य कारण मुस्लिम वोट नहीं, बल्कि ओबीसी और स्वर्ण समाज के कुछ हिस्से का बसपा से हटना बताया जाता है. मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्रीय और धार्मिक पार्टियों में विभाजित है.

-सिद्धार्थ, *ई-मेल से.*

### स्वयं को सुधारें

रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है. अतिक्रमण, बिना टिकट यात्रा करना, बिजली-पानी की चोरी, लूट, अपहरण और टैक्स चोरी आदि भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं. सिर्फ़ क़ानून बनाने से ही भ्रष्टाचार का समूल नाश संभव नहीं है. इसके लिए हमें स्वयं को सुधारना होगा और यह तभी संभव है, जब हम नैतिकता, ईमानदारी और सदाचार को अपने जीवन में स्थान दें.

-किशनलाल आर्य, *आगरा*

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जानेवाली 700 रुपए की किताबें

देश के जाने-माने पत्रकार एवं 'चौथी दुनिया' के सम्पादक संतोष भारतीय के संपादन में प्रकाशित 'दलित अल्पसंख्यक सशक्तीकरण' के वैश्विक प्रयासों का तथ्यात्मक दस्तावेज। यह पुस्तक प्रमाणित करती है कि दुनिया भर के गरीब, दबे-कुचले और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग समूहबद्ध होकर यदि शक्तिसम्पन्न होने का संकल्प लें तो वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव सामने आएँगे।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएँ इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

## जब तोप मुक़ाबिल हो

# जनता से टकराने की कोशिश मत कीजिए

संसद सर्वोच्च है, संसद पवित्र है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है और हिंदुस्तान में संसद आज आम आदमी के सुख, सुरक्षा और लोकतंत्र की गारंटी है. इसी संसद ने 1950 में एक संविधान बनाया था. 1950 के बाद संसद का यह धर्म था कि वह संविधान की मूल भावना की रक्षा करे. सवाल यह है कि क्या संसद ने 1950 में बने संविधान की आत्मा, संविधान की भावना की रक्षा की? इस सवाल का जवाब देश की जनता को तलाशना है और आज संसद में जो लोग हैं, उन्हें इस सवाल का जवाब देना है. एक विडंबना यह भी है कि संसद में ऐसे लोग ज़्यादा हैं, जो अपनी जवानी के दिनों में जनता के हित, हक़ और सुख के लिए लड़ते रहे हैं. ये नेता मुखर भी हैं, लेकिन इन नेताओं की आज की भाषा और तीस साल पहले की भाषा की तुलना करें तो पाएंगे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी पूरा रूपांतरण हो गया है, जिसे हम व्यक्ति का चरित्र बदलना कहते हैं, चरित्र बदल गया है. एक ज़माना था, जब मुलायम सिंह यादव, शरद यादव एवं शिवानंद तिवारी जैसे लोग आंदोलनों का हिस्सा हुआ करते थे और वे नारा लगाते थे, सच कहना अगर बग़ावत है तो समझो हम भी बागी हैं. यह और बात है कि उस समय यह नारा श्रीमती इंदिरा गांधी को ध्यान में रखकर लगाया जाता था. थोड़े दिनों तक उन्होंने इस नारे को या ऐसे ही नारों को राजीव गांधी को ध्यान में रखकर लगाया था. उनके इस नारे का साथ देश की जनता ने दिया और आज न केवल ये तीन नेता, बल्कि अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज जैसे लोग देश के बड़े नेताओं की श्रेणी में आ गए हैं. अब ये सब संसद में हैं. आशा यह करनी चाहिए कि ये संसद में होंगे और संसद में ज़्यादातर भाषण, ज़्यादातर क़दम जनता के हितों के लिए उठाए जाएंगे, पर पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि संसद में बहुत कुछ ऐसा होता है, जो जनता के हित के ख़िलाफ़ होता है. इसी दौरान संसद में लिब्रलाइजेशन पॉलिसी आई, बाज़ार शब्द घुसा, बाज़ार नियंत्रित नीतियां बनने लगीं. आज मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि यह पूरी संसद मार्केट रूल से गाइड हो रही है. सन् 1950 के संविधान, जिसमें समाजवादी अवधारणा, पंथनिरपेक्षता एवं लोक कल्याणकारी गणराज्य की बात की गई थी, समानता एवं भाईचारा जैसे आदर्श रखे गए थे, उन सारी चीजों को आज अगर तलाशें तो संसद के किसी कोने में न तो उसकी गूंज सुनाई देती है, न छाप दिखाई देती है. दिखाई क्या देता है? दिखाई देता है कि जनता अगर कहीं आवाज़ उठाती है तो उस आवाज़ के ख़िलाफ़ संसद में आवाज़ उठती है. जनता के हित में यह बाज़ार नहीं है, अब यह संसद में सुनाई नहीं पड़ता. महंगाई को लेकर सालों बीत जाते हैं, रस्मी तौर पर बहस होती है, लेकिन संसद चिंतित नज़र नहीं आती. भ्रष्टाचार को लेकर बहस होती है, लेकिन संसद परेशान नहीं होती, क्योंकि महंगाई और भ्रष्टाचार अब आज के सांसदों की चिंता रही नहीं, क्योंकि ये उन्हें परेशान नहीं करती, ये उससे परे चले गए हैं. जनता की आवाज़ अब संसद को हिलाती नहीं. क्योंकि जो लोग जनता की आवाज़ लेकर संसद के सामने प्रदर्शन करते थे, संसद को हिलाने का दावा करते थे, आज वही लोग संसद में बैठकर जनता को आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं.

ये लोग जब आंदोलन करते थे तो देश के लोगों को लगता था कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं और आज जब ये संसद में बोलते हैं तो जनता को लगता है कि ये तो कोई और लोग हैं. ये वे लोग नहीं हैं, जो हमारा नेतृत्व किया करते थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी के ऊपर देश को ठप्प करने का काम करते थे, आंदोलनों की अगुवाई करते थे. ऐसा कैसे हो गया कि जनांदोलनों को शरद यादव, मुलायम सिंह यादव एवं शिवानंद तिवारी जैसे लोग पसंद न करें. ऐसा कैसे हो गया कि देश की चिंता अब इन्हें नहीं रही. ऐसा कैसे हो गया कि जो सच्चाई की बात करे, उसे ये लोग देशद्रोही कहने लगें, बेईमान कहने लगें. दो घटनाएं प्रमुखता से याद आती हैं. अन्ना के आंदोलन में सारे देश के लोगों की भावना जुड़ गई थी, लेकिन सांसदों को लगा या कहें कि संसद को लगा कि यह जनता की भावना नहीं है. यह तो कुछ सिरफिरे लोगों की भावना है. देश में फैले भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को जनता अगर ठीक करने का आग्रह संसद से करे तो संसद को लगता है कि जनता का दिमाग़ ख़राब हो गया है. अगर जनता जन लोकपाल बिल के नाम पर अन्ना का समर्थन करे तो संसद को लगता है कि इससे देश में कामकाज रुक जाएगा. अन्ना ने कभी नहीं कहा कि जो जन लोकपाल वह प्रस्तुत कर रहे हैं, वही लागू हो. उन्होंने यह ज़रूर कहा कि उनके जन लोकपाल को सारे देश में बहस के लिए संसद अपनी तरफ़ से प्रसारित करे और संसद अपना बिल भी जनता के बीच बहस के लिए प्रसारित करे, लेकिन संसद ने दोनों में से कोई काम नहीं किया.

दूसरी घटना सेना अध्यक्ष जनरल वी के सिंह को लेकर है. जिस तरह संसद में ग़ैर ज़िम्मेदाराना कृत्य सांसदों का दिखाई पड़ा, उससे हम, जो संसद के बाहर हैं, हमें शर्म आई कि हम ऐसे लोगों को अपना नेता मानते हैं, जिन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है. सांसदों ने कहा, सेना अध्यक्ष का दिमाग़ ख़राब हो गया है, सेना अध्यक्ष राजनीति में आना चाहता है, सेना अध्यक्ष देश को बदनाम कर रहा है. यह कौन लोग कह रहे थे, जो ख़ुद संदेह और आरोप के दायरे में घिरे हुए हैं. सेना अध्यक्ष ने मुद्दा उठाया, सांसदों को यह भी चिंता नहीं हुई कि पता करें कि यह चिट्ठियों की कड़ी है या फिर अकेली चिट्ठी है. लेकिन कैमरा सामने आते ही सांसदों को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बोलना चाहिए, ताकि वे टीवी पर दिखाई दें, लेकिन वे नहीं जानते कि जितनी ग़ैर ज़िम्मेदारी की बातें उन्होंने की हैं, उससे देश की जनता में उनके प्रति प्यार नहीं बढ़ रहा है. उन्हें इस बात का एहसास शायद तब होगा, जब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका होगा. अब हमारे ये वीर सांसद वही बातें सुनना चाहते हैं, जो इनकी चापलूसी की हो, जो इनकी तारीफ़ की हो और जो कहे कि वाह, आपने तो मोहनदास करमचंद गांधी से भी बड़ी बात कह दी, डॉ. लोहिया से भी बड़ी बात कह दी, वे लोग किस खेत की मूली थे. आप ही हैं, जो हैं. शायद इसलिए ये सांसद अपनी उस ज़मीन से कट गए हैं, जिसने इन्हें संसद में भेजा है. क्या देश का नौजवान, जो बेकारी से कराह रहा है, वह इन सांसदों की या इस संसद की इज़्ज़त करेगा? इन सांसदों को तो यह भी पता नहीं है कि जब बाज़ार आधारित अर्थ नीति बनी थी तो उस समय देश के साठ जिले नक्सलवाद के प्रभाव में थे. आज जबकि ये सांसद बढ़-चढ़कर देश और देश के लोगों के गुस्से का मज़ाक उड़ा रहे हैं, देश के लगभग 260 जिले ऐसे हैं, जो नक्सलवाद के प्रभाव में हैं.

इसका मतलब कि जैसे-जैसे बाज़ार का प्रभुत्व देश की नीतियों पर बढ़ा, वैसे-वैसे देश के लोगों के हाथ में हथियार भी बढ़े. इसलिए बढ़े, क्योंकि भूख, बेकारी, पिछड़ेपन, अवसर न होने की निराशा लोगों के हाथ में हथियार पकड़ने के लिए तर्क दे गई. इसकी चिंता इन सांसदों को नहीं है. हमें इन सांसदों का एक भी भाषण याद नहीं है, जो इस चिंता को देश के सामने रखता हो. हो सकता है, ये सांसद ईमानदार हों, इन्होंने अपने रुख़ के लिए अंतरराष्ट्रीय हथियारों के दलालों से कोई पैसा न लिया हो. शायद नहीं लिए होंगे, क्योंकि यह विश्वास करना कठिन है कि शरद यादव, मुलायम सिंह यादव या शिवानंद तिवारी जैसे लोग पैसे ले सकते हैं. लेकिन हथियारों के दलाल तो चारों तरफ़ यही फैला रहे हैं कि जितने भी संभावित मुखर सांसद हो सकते थे, वे सब अब हमारे पक्ष में बयान देंगे और मौजूदा सेना अध्यक्ष को, जिसके ऊपर एक धब्बा नहीं है, उसे संपूर्ण तौर पर कालिख में पुता हुआ दिखाएंगे और जाने या अनजाने, इन सांसदों ने हथियार के दलालों की बातों को सच साबित किया. शायद अपने वक्तव्य की गंभीरता का एहसास संसद के इन महान सांसदों को नहीं है. इन सांसदों को हम बता दें कि अगर जनरल वी के सिंह के ऊपर एक भी आरोप होता तो सरकार उन्हें अब तक सूली पर चढ़ा चुकी होती यानी उसका बहाना लेकर उन्हें निकाल चुकी होती. इन सांसदों को यह नहीं लगता कि आरोपों से घिरे हुए आप ख़ुद हैं और आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जो ईमानदार है. आप सोचते हैं कि देश की जनता आपकी आरती उतारेगी, आपकी पूजा करेगी. शायद ऐसा अब नहीं होगा. अब जो नौजवान निर्णायक स्थिति में आ रहा है, वह दावों और भ्रम की भाषा से अलग हक़ीक़त देख रहा है कि वह जहां रह रहा है, वहां के क्या हालात हैं. आप जो बोलते हैं और वह जिस ढंग की ज़िंदगी जी रहा है, उसमें कोई तारतम्य है भी या नहीं. एक वरिष्ठ नेता ने संसद में बयान दिया, लगता है जनरल सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं. इसमें ग़लत क्या है? जनरल सिंह सेना अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अगर वह सेना अध्यक्ष न रहें, लोगों के बीच जाएं, लोग उनसे कहें कि आप चुनाव लड़ें और वह चुनाव लड़ने के लिए हां कर दें तो इसमें ग़लत क्या है? क्या इस संसद में वही जा सकते हैं, जिन पर आईपीसी की धाराएं लगी हों. अगर सांसदों को यह नहीं पता है तो हम दोबारा यह छापें कि कितने सांसदों के ऊपर आईपीसी की कितनी धाराओं के अंतर्गत कितने मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें वे बरी भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सज़ा भी हो सकती है. ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं, जिनमें सजाएं हुई हैं. बहुतों के साथी उसी आरोप में जेल गए हुए हैं, जो आरोप उनके ऊपर अभी लगे हैं. एक कहावत है हिंदुस्तान में, सूप तो सूप चलनी भी बोले.

> **अफसोस इस बात का है कि वे लोग, जो कभी जनता के आंदोलनों के अगुवा माने जाते थे, आज सत्ता की भाषा बोल रहे हैं. सत्तारूढ़ दल के लोग इतनी ग़ैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने में पता नहीं क्यों, संसद में हर कोई आगे आ रहा है. आज जो सेना की हालत है, वह दो सालों में नहीं हुई है. सेना की यह हालत नरसिम्हा राव के समय से शुरू हुई, जब सेना में खुले बाज़ार का प्रवेश हुआ, जब सेना में खुलेआम बाज़ार से सामान ख़रीदने की कोशिश हुई और नतीजे के तौर पर घनघोर रिश्वत दी गई. हर साल साठ हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च हुए सेना के हथियारों पर, तो फिर आज वायु सेना, जल सेना और थल सेना की यह हालत कैसे हो गई? यह सवाल इन सांसदों में चिंता नहीं पैदा करता.**

अफसोस इस बात का है कि वे लोग, जो कभी जनता के आंदोलनों के अगुवा माने जाते थे, आज सत्ता की भाषा बोल रहे हैं. सत्तारूढ़ दल के लोग इतनी ग़ैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाने में पता नहीं क्यों, संसद में हर कोई आगे आ रहा है. आज जो सेना की हालत है, वह दो सालों में नहीं हुई है. सेना की यह हालत नरसिम्हा राव के समय से शुरू हुई, जब सेना में खुले बाज़ार का प्रवेश हुआ, जब सेना में खुलेआम बाज़ार से सामान ख़रीदने की कोशिश हुई और नतीजे के तौर पर घनघोर रिश्वत दी गई. हर साल साठ हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च हुए सेना के हथियारों पर, तो फिर आज वायु सेना, जल सेना और थल सेना की यह हालत कैसे हो गई? यह सवाल इन सांसदों में चिंता नहीं पैदा करता. आपके ही साथी, आपके ही समर्थक, कोई न कोई विदेशों को सूचना सप्लाई करते हैं. यह जो सूचना सामने आई है, क्या दुश्मन के पास नहीं होगी? दुश्मन के पास इससे भी भयानक सूचनाएं होंगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय में चोरी हो जाती है. आपको चिंता नहीं होती कि कैसे विदेश मंत्रालय में चोरी हो गई. प्रधानमंत्री कार्यालय से वित्त मंत्री का खत लीक हो जाता है. आपको चिंता नहीं होती कि प्रधानमंत्री कार्यालय से कैसे खत लीक हो रहे हैं. कोई महकमा हमारा सुरक्षित नहीं है. जब एक खत सामने आता है, ईमानदारी भरा खत कि हमारे देश की हालत ख़राब है, ठीक कीजिए और वह उस स्थिति में आता है, जब राजनेता उस बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि देश का बड़ा अहित हो गया.

मैं आप महान सांसदों से और संसद के तमाम सांसदों से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वयं को ईश्वर मत समझिए, स्वयं को जनता की इच्छाओं के ऊपर मत समझिए, स्वयं को तानाशाह मत समझिए. वे दिन याद कीजिए, जब आप सड़कों पर नारे लगाते थे और पुलिस आपको पीटती थी. आज आप जनता को गोली मरवाने की नीति का समर्थन करने जा रहे हैं. आप अगर इस देश के लोगों की इच्छाओं के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो इस देश की जनता आज तो संसद को ठीक करने की मांग कर रही है, कल हो सकता है कि वह इस संसद को भंग करने की मांग करे. यह संसद जनता की आकांक्षाओं के लिए कभी बहस नहीं करती. आप इर्रेलिवेंट हो गए हैं. आपको तो यह भी पता नहीं है कि कौन सा क़ानून बनने जा रहा है, कौन सा क़ानून बनेगा. आपमें तो इतनी भी शर्म नहीं बची कि 29 तारीख़ को संसद इसलिए स्थगित हो गई कि 10 प्रतिशत लोग भी वहां नहीं पहुंचे. राज्यसभा स्थगित हो गई, लोकसभा में भी लोग नहीं. जिस चीज के लिए जनता आपको वहां भेजती है, जिसके लिए टैक्सपेयर का इतना पैसा आपके ऊपर ख़र्च होता है और आप संसद में बैठने में भी शर्म महसूस करते हैं और बाहर निकल कर जनता को आंखें दिखाते हैं. इस देश की सेना और जनता, दोनों ने हाथ मिला लिया है और उसकी नज़र आपके एक-एक क़दम के ऊपर है. मेरा अनुरोध है, संभलिए, संभलने का वक़्त ख़त्म हो रहा है. ठीक उसी तरह, जैसे मुट्ठी में बालू को बांधने का एक निश्चित तरीक़ा होता है और आप वह तरीक़ा भूल चुके हैं. जनता ख़तरनाक है, जनता के गुस्से से डरिए सांसद महोदय! इस पूरी संसद को हिंदुस्तान की जनता से, नौजवानों से, ग़रीबों और वंचितों से डरना चाहिए. अगर जरा भी शर्म होगी तो हो सकता है, अभी डेढ़ साल बाक़ी है, आप यह बताएं कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं. हमें निकालने की, हमें भंग करने की मांग मत करो. शायद जनता मान जाए. लेकिन अगर आपके यही तेवर रहे तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि यह जनता इस संसद को भंग करने की मांग उठाएगी और आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपको दिन में तारे दिखाई दे जाएंगे.


संपादक
editor@chauthiduniya.com

दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली इस ड्रेस की लंबाई दो मील है. इतनी लंबी ड्रेस बनाकर इस फैशन हाउस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड्र्स में अपना नाम दर्ज कराया.

दिल्ली, 09 अप्रैल-15 अप्रैल 2012 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

# सूचना आयोग ज़रूर जाएं

आरटीआई अधिनियम के तहत सभी नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार है, लेकिन आम तौर पर देखा जाता है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना न देने के हज़ार बहाने बनाते हैं. ऐसे में आख़िरी रास्ता बचता है सूचना आयोग का. ऐसी हालत में आवेदक केंद्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग में अपील या शिकायत कर सकता है. अपील और शिकायत में थोड़ा अंतर है. आपके आरटीआई आवेदन में जो सवाल पूछा गया है, उसका जवाब अगर ग़लत दे दिया जाता है और आपको विश्वास है कि जो जवाब दिया गया है वह ग़लत, अपूर्ण या भ्रामक है तो आप आयोग में अपील कर सकते हैं. जब आप किसी सरकारी महकमे में आरटीआई आवेदन जमा करने जाते हैं और पता चलता है कि वहां तो लोक सूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किया गया है या फिर आपसे ग़लत शुल्क वसूला जाता है तो ऐसे मामलों में आप सीधे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं. ऐसे मामलों में अपील की जगह शिकायत ही समाधान है. सूचना अधिकार क़ानून की धारा 18 (1) के तहत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और पूछताछ करे. इसके अलावा यदि किसी आवेदक को तय समय के अंदर सूचना नहीं मिलती है तो पहले उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील करनी चाहिए. अगर वहां से भी सूचना न मिले तो वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास द्वितीय अपील कर सकता है. इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा ऐसे क़दम उठाए जाने चाहिए, ताकि आरटीआई क़ानून के प्रावधानों का सही मायनों में पालन हो सके. मसलन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए. रिकॉड्र्स के रखरखाव और उसके प्रबंधन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए. संबंधित अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम के संदर्भ में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए. यही नहीं, वे इस क़ानून की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) का पालन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करें.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

**चौथी दुनिया**

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

## आवेदन का प्रारूप
(विद्युतीकरण का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन
महोदय,
ग्राम..........................में विद्युत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. उपरोक्त गांव के कितने घरों में बिजली का कनेक्शन है? प्रत्येक कनेक्शनधारी का नाम एवं पता बताएं.
2. उपरोक्त गांव जिस ब्लॉक में आता है, उसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? वर्षवार विवरण प्रदान करें.
3. क्या उपरोक्त ब्लॉक में विद्युतीकरण एवं उसके रखरखाव का कार्य किसी ठेकेदार/एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है? यदि हां, तो उससे संबंधित निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

(क) कार्य का नाम
(ख) कार्य का संक्षिप्त विवरण
(ग) कार्य के लिए स्वीकृत राशि
(घ) कार्य स्वीकृत होने की तिथि
(च) कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
(छ) कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
(ज) कार्य शुरू होने की तिथि
(झ) कार्य समाप्त होने की तिथि
(त) कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
(थ) कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है?
(द) कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
(ध) इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.
(न) उन सहायक एवं कार्यपालक अभियंताओं के नाम बताएं, जिन्होंने इन प्रत्येक कार्यों का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी. उनकेद्वारा कार्य के किस भाग का निरीक्षण किया गया?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.
यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम..........
पता..........
फोन नं..........
संलग्नक..........

# राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

**मेष** (21 मार्च से 20 अप्रैल)
धन से संबंधित तनाव में रहेंगे. कुछ पूर्व लंबित कार्य की सफलता का समाचार प्राप्त हो सकता है. सहकर्मी और अधिकारी का स्नेह प्राप्त रहेगा. रक्तचाप और हृदय से संबंधित रोगी अपने शरीर का ध्यान रखें. कोई नया संपर्क बनेगा, जो भविष्य के लिए एक बड़ी मदद साबित होगा.

**वृष** (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह आप धन संचय पर विशेष ध्यान रखेंगे. बहुत सारे नए कार्यों को लेकर उत्साहित रहेंगे. पारिवारिक सहयोग आपको अत्यधिक मिलेगा. किसी कार्य में आने वाली बाधा को लेकर विचलित न हों. वाहन लेने की योजना बना सकते हैं. पित्त विकार से संबंधित रोगी खानपान का ध्यान रखें.

**मिथुन** (21 मई से 20 जून)
संबंधों को सुधारने की कोशिश करेंगे और कामयाब रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से व्यापारी अच्छा समय महसूस करेंगे. किसी बुज़ुर्ग के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको परेशान करेगी. यात्रा की योजना बन सकती है. इस सप्ताह आपको मान-सम्मान भी प्राप्त होगा.

**कर्क** (21 जून से 20 जुलाई)
आप अपना आलसी रवैया त्याग दें. धन भी ज़रूरत के मुताबिक़ प्राप्त होता रहेगा. दौड़-भाग की वजह से आप इस सप्ताह थकावट महसूस करेंगे. ग़ैर ज़रूरी वस्तुओं पर व्यय न करें. संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा.

**सिंह** (21 जुलाई से 20 अगस्त)
अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए ज़्यादा चिंतित रहेंगे और उसका निर्वाह भी करेंगे. उपलब्धियां हासिल होंगी, लेकिन आप ज़्यादा प्रसन्न नहीं होंगे. आर्थिक रूप से सामान्य समय रहेगा. थोड़ा सतर्क रहें, अन्यथा कोई दुष्ट मित्र आपको नुक़सान पहुंचा सकता है.

**कन्या** (21 अगस्त से 20 सितंबर)
अपने रहस्य या मन में सोची रणनीति इस सप्ताह उजागर न करें, अन्यथा नुक़सान होगा. सामाजिक और पारिवारिक रूप से आप कोई बड़ा कार्य संपन्न करने की योजना बनाएंगे. व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग के लिए शुभ सप्ताह. माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

**तुला** (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आप इस सप्ताह बहुत व्यस्त रहेंगे. बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करेंगे और इसके पीछे वजह है प्रसिद्धि में वृद्धि. इस दौड़-भाग में स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें. भाई-बहनों का सहयोग बढ़ेगा. यथाशक्ति दान दें, आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे.

**वृश्चिक** (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप प्रगति की राह पर रहेंगे और धनोपार्जन अच्छा- खासा करेंगे. इस वजह से पारिवारिक सदस्यों की उम्मीद पूर्ण कर पाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. मधुमेह और उदर विकार वाले रोगी चिकित्सक से मिलें.

**धनु** (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आपकी आमदनी ख़ूब रहेगी और ख़र्च भी ख़ूब करेंगे. कोई अकस्मात यात्रा आपको धन दिला सकती है. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. परिवार में मांगलिक कार्य भी हो सकता है. स्वास्थ्य पर मिश्रित प्रभाव रहेगा. पूर्व में दिए गए क़र्ज़ वापस निकालने का प्रयास करेंगे.

**मकर** (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह आपके पूर्व में किए गए कार्य से संबंधित शाबाशी मिल सकती है. आप लोगों के दु:ख-सुख में हिस्सा लेंगे, जिससे आपके पूरे परिवार का सामाजिक कद बढ़ेगा. व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग ख़ुश रहेंगे. किसी दूसरे के दु:ख को देखकर डिप्रेशन में न जाएं, बल्कि उसे मदद करने का प्रयास करें.

**कुंभ** (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आप बनते कार्यों में रुकावट महसूस करेंगे. परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे. धन से संबंधित नुक़सान हो सकता है. कोई मित्र आपकी मदद करेगा. मेडिटेशन का सहारा लें.

**मीन** (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप इस सप्ताह उमंग में रहेंगे. बहुत सारे कार्य बनेंगे. पारिवारिक ज़िम्मेदारी बढ़ेगी. सफलता से आपके अंदर निखार आएगा. व्यवसाय और नौकरी दोनों में आप सफल रहेंगे. आर्थिक रूप से भी मज़बूत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

## ज़रा हट के

# 40 साल का इंतज़ार

बाग में खिलते हुए फूल कितने अच्छे लगते हैं, माली बड़ी हसरत से पौधे को इस इंतज़ार में रोपता है कि जल्द ही उसमें फूल खिलेगा. हर माली रोज़ सोचता है कि उसके बाग में रोज़ाना सुंदर-सुंदर फूल खिलें, ताकि उसका बाग सुंदर लगे. शायद ही किसी बागबान ने यह सोचा होगा कि उसकी यह हसरत 40 साल बाद पूरी होगी. लंदन के रॉयल बोटेनिक नामक बगीचे में एक खास किस्म के पौधे में लगे फूलों को खिलते देखने के लिए माली को 40 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ गया. मेक्सिको के जंगल से मिला यह पौधा लंबाई में आम पौधों जैसा है, लेकिन पूरा विकसित होने पर यह छह फीट लंबा हो जाता है. इसकी खासियत यह है कि जब यह अपनी लंबाई तक पहुंच जाता है, तभी इसमें फूल खिलते हैं और फूल खिलने के बाद यह पौधा मर जाता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# सबसे लंबी ड्रेस

शादी की ड्रेस बहुत ही सुंदर लगती है. उसकी लंबाई अन्य पोशाकों के मुक़ाबले अधिक लंबी होती है, लेकिन रोम के एक फैशन हाउस ने शादी की ऐसी ड्रेस बनाई है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. दुल्हन द्वारा पहनी जाने वाली इस ड्रेस की लंबाई दो मील है. इतनी लंबी ड्रेस बनाकर इस फैशन हाउस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉड्र्स में अपना नाम दर्ज कराया. यह ड्रेस बनाने में डिजाइनरों को 100 दिन लगे. इसका प्रदर्शन हवा के गुब्बारे में मॉडल को बैठाकर किया गया, जिसे देखने के लिए फैशन जगत के अलावा लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. चारों ओर इस ड्रेस की चर्चा हो रही है.

# हाथी से बड़ी कुर्सी

सारी कुर्सियां बैठने में लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ बहुत आरामदायक होती हैं. सभी कुर्सियों की लंबाई में कुछ ज़्यादा फ़र्क़ नहीं होता, साथ ही कुर्सी पर केवल एक आदमी बैठ सकता है. दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो हमेशा लीक से हटकर कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं. ब्रिटेन के एक व्यक्ति ने ऐसी कुर्सी बनाई है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. इस कुर्सी की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार है. दरअसल यह कुर्सी डबल डेकर बस से लंबी और हाथी के आकार से भी बड़ी है. इसमें एक साथ कई लोग आराम से बैठ सकते हैं. इसे बनाने में 21 दिनों से भी ज़्यादा का समय लगा है. यह माना जा रहा है कि यह विश्व में अब तक की सबसे बड़ी कुर्सी है. इसे एक तटीय शहर में सागर के किनारे रखा गया है. इस पर लोग बैठकर इसका लुत्फ ले रहे हैं.

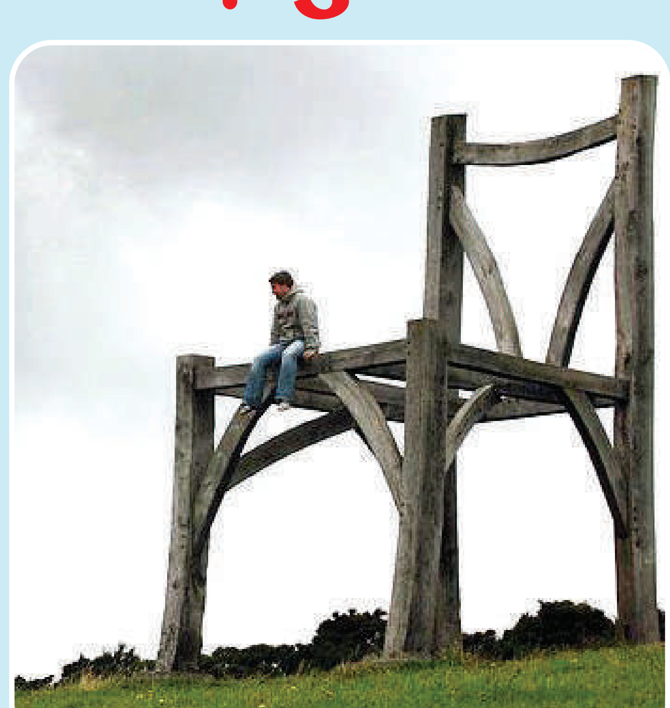

# परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन-2012
# राह आसान नहीं

राजीव कुमार

दक्षिण कोरिया के सिओल में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा परमाणु बम के प्रसार को रोकने और इसके वर्तमान ज़ख़ीरे को कम करने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़े. सभी देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी स्थिति में परमाणु बम की तकनीक आतंकवादियों के पास नहीं पहुंचनी चाहिए. अगर परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ में चला गया तो फिर दुनिया को नष्ट होने से नहीं रोका जा सकता है. इसलिए यह ज़रूरी है कि जिन देशों के पास परमाणु बम की तकनीक है, वह इस बात पर ध्यान दें कि इसके प्रसार को रोका जाए. इस बैठक में कहा गया कि परमाणु बम को ग़लत हाथों में जाने से रोकने के लिए सख्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों की आवश्यकता है. यह केवल किसी विशेष देश की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा. चरमपंथियों तक परमाणु हथियार की पहुंच रोकने के अलावा बैठक में इस बात को भी अहमियत दी गई कि वर्तमान समय में विभिन्न देशों के पास जो परमाणु हथियार हैं, उनकी संख्या में कमी की जाए. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका के पास आवश्यकता से अधिक परमाणु हथियार हैं. अगर इसमें कमी कर दी जाए तो भी वह अपनी और अपने सहयोगी राष्ट्रों की सुरक्षा कर सकता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने परमाणु हथियारों के ज़ख़ीरे को कम करेगा. अगर अमेरिका अपने परमाणु हथियार में कमी करता है तो दूसरे देशों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी. इससे परमाणु हथियारों के लिए जिस तरह की होड़ मची है, उसमें कमी होगी. अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी परमाणु सुरक्षा संबंधी ख़तरे को विश्व के समक्ष एक महत्वपूर्ण ख़तरा माना है तथा ख़तरे से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है. अमेरिका और रूस दोनों ने उत्तर कोरिया से कहा है कि उसे बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोक देना चाहिए. रूसी राष्ट्रपति देमेत्री मेदवेदेव से मुलाक़ात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उत्तर कोरिया अपना क़दम नहीं रोकता है तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस निर्णय का उल्लंघन होगा जिसके तहत उसके लिए इस तरह की मिसाइलों का परीक्षण निषिद्ध किया गया है. सुरक्षा परिषद के निर्णय की अवहेलना करने के बाद उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. दक्षिण कोरिया ने तो यहां तक कहा है कि अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रमों को नहीं रोकता है या लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण जारी रखता है तो मानवीय सहायता के तौर पर दी जाने वाली खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को भी रोका जाना चाहिए.

भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम के उद्देश्यों को विश्व के सामने रखा. उन्होंने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ज़ोर दिया. इस बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा कि परमाणु सुरक्षा को सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीक़ा तो यही है कि विश्व को परमाणु अस्त्रविहीन बना दिया जाए. उन्होंने कहा कि भारत पहले ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) तथा मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) के निर्देशों का पालन कर रहा है. उनका कहना था कि भारत कभी संवेदनशील प्रौद्योगिकी के प्रसार का स्त्रोत नहीं रहा है तथा हम उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली को और अधिक मज़बूत करने लिए प्रतिबद्ध है. मनमोहन सिंह ने भारत को परमाणु क्लबों का सदस्य बनाए जाने की मांग की है. उनकी मांग है कि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी), मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार अरेंजमेंट तथा ऑस्ट्रेलियाई ग्रुप का सदस्य बनाया जाए, ताकि भारतीय परमाणु कार्यक्रम में उच्च अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित हो तथा भारत की परमाणु निर्यात नियंत्रण प्रणाली को मज़बूत करने में मदद मिले. भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएइए) के परमाणु सुरक्षा कोष में 2012-13 के लिए 10 लाख डॉलर के योगदान की घोषणा की है.

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कई संकल्प लिए गए हैं, लेकिन संकल्प लेना और उस पर अमल करना दोनों अलग-अलग बात है. इससे पहले 2010 में यह सम्मेलन हुआ था. ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ी सफलता मिली है और कुछ देशों ने मानकों का पालन भी किया है. लेकिन इसे वास्तविक तौर पर सफलता नहीं कहा जा सकता है. उत्तर कोरिया ने इनकी बात मानने से मना कर दिया है. ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए है. भारत को परमाणु क्लब में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि भारत सुरक्षा के सभी मानदंडों का पालन कर रहा है. ऊर्जा आधुनिक समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है. परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों की कमी महसूस की जा रही है. अगर ऊर्जा के परंपरागत स्त्रोतों का लगातार दोहन किया गया तो अगले चालीस-पचास सालों में इसके भंडार ख़त्म हो जाने की उम्मीद है. इसके कारण परमाणु ऊर्जा का महत्व काफ़ी बढ़ गया है. विकासशील और अल्प विकसित देशों को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना अत्यावश्यक है. हालांकि इस पर निगरानी रखनी चाहिए. फुकुशिमा घटना के बाद परमाणु सुरक्षा पर ध्यान देना और अधिक ज़रूरी हो गया है. ऐसे में विकसित देशों की ज़िम्मेदारी है कि वे परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी रखें तथा बेहतर तकनीक उन देशों को मुहैया कराएं, जहां परमाणु कार्यक्रम चल रहा है. परमाणु बम के मुद्दे पर भी दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है. जब तक कुछ देशों के पास परमाणु बम होगा, तब तक उसके आसपास के देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम तकनीक हासिल करने की कोशिश करते ही रहेंगे. अमेरिका के पास जब यह तकनीक आई तो तत्कालीन सोवियत संघ इसके लिए प्रयास करने लगा और सफल भी हुआ. भारत ने जब परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बारे में अभी भी कहा जाता है कि अगर भारत के पास उस समय परमाणु बम होता तो संभव है कि चीन की भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती. इसी तरह ईरान के तीन पड़ोसियों भारत, चीन और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है. अघोषित रूप में इज़रायल के पास भी परमाणु बम है. ऐसे में ईरान परमाणु बम बनाने का प्रयास क्यों न करे. ऐसी ही स्थिति उत्तर कोरिया के साथ भी है. यदि परमाणु ख़तरे से विश्व को सुरक्षित रखना है तो फिर विश्व को परमाणु बम विहीन करना ज़रूरी है. इसलिए इस सम्मेलन में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना करना पड़ेगा. इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक और संकल्प लेना पड़ेगा. यह संकल्प होगा मानव हित को राष्ट्रीय स्वार्थ पर वरीयता देने का. जब तक राष्ट्रीय स्वार्थ को मानव हित के ऊपर रखा जाएगा, न तो पर्यावरणीय समस्या का समाधान होगा और न ही परमाणु सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा.

rajiv@chauthiduniya.com

# राष्ट्र हित पर भारी पड़ा कांग्रेस हित

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया, जिसमें श्रीलंका द्वारा लिट्टे के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई के समय मानवाधिकार हनन की निंदा की गई. 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 24 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया, जबकि 15 ने इसके विरोध में मतदान किया. इसके अलावा आठ देशों ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया. भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन किया. भारत ने जिस आधार पर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, वह चिंता का विषय है. भारत सरकार इस प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इसका समर्थन किया. इसकी वजह वैश्विक परिदृश्य में आया कोई बदलाव नहीं था, बल्कि सरकार पर सहयोगी दलों का दबाव था. द्रमुक सहित तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों ने सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया था. द्रमुक ने तो यहां तक कहा था कि अगर सरकार यूएनएचआरसी में लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती है तो वह अपने मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहेगा. इसका मतलब साफ था कि द्रमुक सरकार से समर्थन वापस ले लेगा. यूपीए सरकार किसी भी स्थिति में अपने सहयोगी दलों का समर्थन नहीं खोना चाहती है, क्योंकि इससे मध्यावधि चुनाव कराने की नौबत आ सकती है और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है. हाल में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है. कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है. अन्ना हजारे का आंदोलन भी कांग्रेस के विरुद्ध नज़र आ रहा है, क्योंकि टीम अन्ना के अनुसार कांग्रेस सशक्त लोकपाल नहीं लाना चाहती. इन सभी कारणों से डरी कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने श्रीलंका के विरुद्ध लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन करना उचित समझा. उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसके मत से देश का हित होगा या अहित. उसे तो बस इस बात की चिंता है कि किसी तरह वह अपना कार्यकाल पूरा कर ले. चुनाव के समय तक यह मुद्दा जीवित भी नहीं रहेगा और वैसे भी भारतीयों को इन बातों से बहुत ज़्यादा मतलब रहता कहां है? यूपीए सरकार की इस विदेश नीति से देश को किस तरह का नुक़सान झेलना पड़ सकता है, इसकी चिंता न प्रधानमंत्री को है और न विदेश मंत्री को.

इसे भारत की विदेश नीति का दरकना कहा जाना चाहिए. किसी देश की विदेश नीति राष्ट्र हित ध्यान में रखकर तय की जाती है, न कि सरकार बचाने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, लेकिन भारत ने जो किया है, उसे उसकी विफलता और कांग्रेस की सफलता के रूप में देखा जा सकता है. अब भारत सरकार अपनी इस कूटनीतिक असफलता के घाव को कम करने की कोशिश कर रही है. उसका कहना है कि वह श्रीलंका के साथ खड़ी है. पता नहीं, साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है. पहले तो उसे घायल करो और उसके बाद यह कहो कि मैं तो आपके साथ था. क्या करें, उस समय मेरा हाथ पता नहीं कैसे उठ गया, लेकिन मैंने सावधानी बरती थी. आपके सिर पर हमला नहीं किया था, जिससे आपकी मौत नहीं हुई. यही काम भारत सरकार कर रही है. प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को एक खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने प्रस्ताव की भाषा को परिवर्तित कराया. इसके अलावा यह भी लिखा है कि भारतीय प्रतिनिधियों को श्रीलंका के प्रतिनिधियों से सतत संपर्क बनाए रखने को कहा गया था. यूपीए सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसने मजबूरी में प्रस्ताव का समर्थन किया. भारत सरकार के कुछ मंत्रियों का कहना है कि इससे भारत-श्रीलंका के बीच के संबंध ख़राब नहीं होंगे. क्या यह व्यवहारिक है. एक ओर आप किसी देश की निंदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वह आपके साथ अच्छा संबंध बनाए रखे, जबकि आसपास के कई देशों ने उसका साथ दिया हो. ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया है. श्रीलंका ने भी भारत के इस दोहरे रवैये का जवाब दिया. उसने कहा कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. यूपीए सरकार ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है. वैसे भी भारत के अपने पड़ोसी देशों में अधिकांश के साथ अच्छे संबंध नहीं है. पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है. चीन के साथ सीमा विवाद है, साथ ही वह आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर भारत को अपना प्रतिद्वंद्वी समझता है. वह भारत को नीचा दिखाने का कोई भी मौक़ा नहीं छोड़ेगा. बांग्लादेश पर विश्वास नहीं किया जा सकता. वहां सत्ता बदलते ही भारत के प्रति नज़रिया बदल जाता है. ऐसे में श्रीलंका को नाराज़ करना, वह भी आंतरिक राजनीति के दलदल में फंसकर, सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है. भारत गुजराल सिद्धांत से भटकता जा रहा है. अगर इसी तरह सरकार बचाने के लिए राष्ट्र हित को दांव पर लगाया जाता रहा तो कुछ समय के बाद सारे पड़ोसियों से भारत के संबंध बिगड़ जाएंगे और वह अकेला पड़ जाएगा.

राजीव कुमार
rajiv@chauthiduniya.com

बेवल पंचायत

# ईमानदारी की क़ीमत चुकाता एक सरपंच

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

संजय ब्रह्मचारी उर्फ संजय स्वामी की आंखों में एक सपना था. वह सपना था, गांधी जी के सपनों को साकार करने का. दिल्ली एवं मुंबई में हमारी सरकार, लेकिन हमारे गांव में हम ही सरकार यानी हमारा गांव हमारी सरकार. 13 सितंबर, 2010 की रात हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले की बेवल पंचायत में इस सपने को साकार करने की एक शुरुआत हुई थी, जब संजय स्वामी ने ग्रामसभा की खुली बैठक में सरपंच पद का प्रभार काफी मशक्कत के बाद संभाला था. मशक्कत इसलिए, क्योंकि न हारा हुआ सरपंच और न प्रशासनिक अधिकारी ग्रामसभा की खुली बैठक में संजय स्वामी को प्रभार देना चाहते थे. उस वक़्त भी चौथी दुनिया ने इस ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. लेकिन सरपंच बनने के बाद जब संजय स्वामी ने ग्रामसभा की नियमित बैठक और पंचायत के कामों में पारदर्शिता लाने का काम शुरू किया, तब यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आई. इसमें राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल थे. नतीजतन, संजय स्वामी को परेशान किए जाने की तैयारी शुरू हो गई. झूठे मुक़दमे किए गए, आरोप लगाए गए. यह सब इसलिए भी हुआ, क्योंकि संजय स्वामी टीम अन्ना के आंदोलन में भी सक्रिय हैं और हिसार उपचुनाव में टीम अन्ना के साथ जोर–शोर से लगे हुए थे. उन्हें हत्या के प्रयास और बिजली चोरी जैसे मामलों में भी फंसाने की कोशिश की गई.

चौथी दुनिया से बातचीत में संजय स्वामी कहते हैं कि पुलिस ने मुझे झूठे मामले में फंसा दिया है, 307 के एक मामले में, इसलिए अभी छिपा हुआ हूं, वकीलों से सलाह ले रहा हूं. इस मामले की कहानी बताते हुए वह कहते हैं कि पूरे ज़िले में भैंस लूट का मामला चल रहा था, लोग अपना आक्रोश शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त कर रहे थे. पुलिस ने भीड़ हटाने के लिए वहां लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफ़ी लोगों को चोटें आईं. विरोध में लोगों ने पत्थरबाज़ी की, जिससे एक एसएचओ का माथा फूट गया. पुलिस ने यह कहकर कि संजय ब्रह्मचारी थे उसमें और उन्होंने एसएचओ को लाठी से मारा, धारा 307 लगा दी और उसमें यह भी जोड़ दिया कि हमने उनकी कार्बाइन लूट ली है. वह कहते हैं कि मेरा अधिकतर जीवन आश्रम में बीता है, हिंसा में हम विश्वास नहीं करते. संजय स्वामी आगे बताते हैं कि चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने में मुझे तीन महीने लगे, क्योंकि हमने जनता के सामने यह बात रखी थी कि हम जो भी करेंगे, पंचायत की खुली बैठक में करेंगे. चार्ज खुली बैठक में लिया जाएगा और प्रशासन खुली बैठक में चार्ज देने को तैयार नहीं था.

ज़ाहिर है, हरियाणा समेत हर राज्य में एक परंपरा सी है कि जब सरपंच चार्ज लेता है तो उसमें कोई डीटेल्ड बात नहीं होती है. वह एक बस्ता भरकर लाते हैं रिकॉर्डों का, जीता हुआ सरपंच उस पर दस्तखत कर देता है और चार्ज हैंडेड ओवर/टेकेन ओवर हो जाता है. कभी यह जानने की कोशिश नहीं की जाती कि गांव में कितने पैसे कहां लगे. संजय स्वामी ने जब चार्ज लिया, तभी पूर्व सरपंच द्वारा पांच लाख रुपये से ज़्यादा की लूट का पता चल गया. उन्होंने जनता को इस बारे में बताना शुरू किया कि आपके पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है, कौन इसे लूट रहा है, तो इससे प्रशासनिक अधिकारियों को दिक्कत हुई. सरपंच बनते ही संजय स्वामी की मुश्किलें शुरू हो गईं. वह कहते हैं कि क़ानून यह कहता है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो पंचायत के सारे खाते ब्लॉक में जमा हो जाने चाहिए. अब ब्लॉक से कैसे चेकबुक बाहर आई और किस तरह पूर्व सरपंच ने पैसा निकाल लिया. ज़ाहिर है, बीडीओ एवं अन्य अधिकारी जब तक शामिल न हों, तब तक ऐसा नहीं हो सकता. जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तो कुछ स्थानीय नेता एवं अधिकारी मेरे दुश्मन बन गए. संजय बताते हैं कि मुझे चार्ज तो दे दिया गया, लेकिन प्रशासन और अन्य लोगों द्वारा हमारे पंचों को भड़का दिया जाता था, ग्राम सचिव कई बार बदल दिए गए.

संजय बताते हैं, मुझे एक बार पूर्व सरपंच के कार्यकाल के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच के संबंध में ब्लॉक में बुलाया गया. षड्यंत्र के तहत मेरे साथ मारपीट की गई. उस समय वहां कोई अधिकारी उपस्थित नहीं था. मैं किसी तरह भागकर पुलिस के पास गया और रिपोर्ट दर्ज कराई. मैं जब गांव पहुंचा तो मालूम हुआ कि मेरे ख़िलाफ़ हरिजन एक्ट के अंतर्गत झूठा मुक़दमा ग्राम सचिव ने दर्ज करा दिया है. उन्होंने गांव की एक महिला को आगे करके उक्त मुक़दमा दर्ज कराया, जो चल रहा है. महिला ने आरोप लगाया कि मैं जब बीपीएल कार्ड के लिए महाराज की कुटिया में गई तो उन्होंने मुझे जातिसूचक शब्द कहे. इस सबके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, यह पूछे जाने पर

संजय कहते हैं कि जो महिला बीपीएल कार्ड के लिए मेरे पास आई, वह पहले से राजस्थान में एक बड़ी ज़मीन की मालिक है. उसमें एक राजनीतिक दबाव रहा, ये लोग किसी पार्टी के नहीं हैं, प्रशासनिक अधिकारी डीडीपीओ हैं. पांच लाख वाले मामले में कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है, उनके कहने पर ही यह काम हुआ. संजय बताते हैं कि महिला वाले मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है, क्योंकि उसमें दो–दो अधिकारी बदले गए, महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक का

**महेंद्रगढ़ हरियाणा के पिछड़े क्षेत्र में आता है और केंद्र सरकार एक विशेष योजना के तहत विकास के लिए 13 करोड़ रुपये सीधे ज़िले में भेजती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे उस पैसे की बंदरबांट हो जाती है, जो गांव के विकास के लिए ख़र्च होना चाहिए. संजय कहते हैं कि उस पैसे से कंप्यूटर ख़रीदे जाते हैं, ट्रैक्टर ख़रीदे जाते हैं, जबकि गांव में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है. कई गांव तो ऐसे हैं, जिनमें आधारभूत संरचना नहीं है. अधिकारी विकास पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ़ लूट-खसोट पर ध्यान देते हैं.**

**सरपंच बनने के बाद जब संजय स्वामी ने ग्रामसभा की नियमित बैठक और पंचायत के कामों में पारदर्शिता लाने का काम शुरू किया, तब यह बात कुछ लोगों को रास नहीं आई. इसमें राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल थे. नतीजतन, संजय स्वामी को परेशान किए जाने की तैयारी शुरू हो गई. झूठे मुक़दमे किए गए, आरोप लगाए गए. यह सब इसलिए भी हुआ, क्योंकि संजय स्वामी टीम अन्ना के आंदोलन में भी सक्रिय हैं और हिसार उपचुनाव में टीम अन्ना के साथ जोर-शोर से लगे हुए थे. उन्हें हत्या के प्रयास और बिजली चोरी जैसे मामलों में भी फंसाने की कोशिश की गई.**

भी दबाव था. दो–दो अधिकारी बदले जाने के बावजूद मामला बनता न देख पुलिस ने एफआर लगा दी.

संजय स्वामी कहते हैं कि तीसरा केस मुझ पर बिजली चोरी का लगाया गया. बिजली चोरी के केस में जिस उपकरण की बात की गई, वह मेरी कुटिया में नहीं है, मेरे यहां पंखा तक नहीं है. उस दिन मैं गांव में था ही नहीं. वह कहते हैं कि मैं उस दिन अपने गांव के कुछ मामलों के सिलसिले में चंडीगढ़ लोकायुक्त के यहां जा रहा था. मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ को रिप्रेजेंटेशन दिया कि मेरे ख़िलाफ़ ग़लत मामला बना दिया गया है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और 4000 रुपये का जुर्माना कर दिया. मैंने कहा कि आप विजिलेंस के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर जांच तो कर सकते हैं. उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ केस दर्ज करा दिया. जब मैं 307 और कार्बाइन वाले केस में कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो मेरे ख़िलाफ़ वारंट आ गया. मैंने अंतरिम जमानत के लिए भी कोशिश की, लेकिन मुझे जमानत नहीं मिली. जब भैंस वाली लड़ाई हुई थी, तब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था. आरोप संगीन होने की वजह से हाईकोर्ट ने मेरी अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया. इसलिए सरकार की नज़र में भगोड़ा हूं. कार्बाइन वाले केस में मेरे पास एक सीडी है, जिसमें कार्बाइन रिकवरी की बात एसएचओ ने स्वीकारी है. यह मामला बनाया हुआ है, ताकि मुझे फंसाया जा सके.

सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ , चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का हो या पंचायत स्तर का, आवाज़ उठाने पर सत्ता और प्रशासन में बैठे लोगों को क्यों परेशानी होती है. पंचायत या किसी भी संस्था में पारदर्शिता हो, पंचायत स्तर पर ग्रामसभा मज़बूत हो, जन भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, ऐसा काम अगर कोई सरपंच करता है या करना चाहता है तो इसमें दिक्कत क्या है. आख़िर क्यों ऐसी बातों को सत्ता प्रतिष्ठान स्वीकार नहीं करना चाहता. जहां सरपंच सूचनाओं को दबाते हैं, वहीं कोई ईमानदार सरपंच सूचनाओं को उजागर कर रहा है तो क्यों यह बात प्रशासन के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है. संजय बताते हैं, हमारे यहां कोई भी योजना हो, उसके अंदर लुकाछिपी का काम चलता है. कोई ऐसी योजना नहीं है, जिसमें पैसा नहीं खाया जाता. महेंद्रगढ़ हरियाणा के पिछड़े क्षेत्र में आता है और केंद्र सरकार एक विशेष योजना के तहत विकास के लिए 13 करोड़ रुपये सीधे ज़िले में भेजती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि कैसे उस पैसे की बंदरबांट हो जाती है, जो गांव के विकास के लिए ख़र्च होना चाहिए. संजय कहते हैं कि उस पैसे से कंप्यूटर ख़रीदे जाते हैं, ट्रैक्टर ख़रीदे जाते हैं, जबकि गांव में सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है. कई गांव तो ऐसे हैं, जिनमें आधारभूत संरचना नहीं है. अधिकारी विकास पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ़ लूट–खसोट पर ध्यान देते हैं.

shashishekhar@chauthiduniya.com

विदेशी अख़बारों से मिलने वाला पैसा तो और भी ज़्यादा होता है. हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के अख़बार कम बिकते हैं, लेकिन फिर भी लेखकों को मानदेय वहां ज़्यादा है.



# मानदेय का अर्थशास्त्र नहीं बदला

अनंत विजय

बात नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों की है. उस वक़्त मैं अपने शहर जमालपुर से दिल्ली आया था. अख़बारों में लिखना-पढ़ना तो अपने शहर से ही शुरू कर चुका था. लिहाज़ा दिल्ली आने के बाद जब बोरिया-बिस्तर लगा और पढ़ाई शुरू हुई तो उसके साथ-साथ अख़बारों के दफ्तर में इस उम्मीद में चक्कर काटने लगा कि कोई असाइनमेंट मिले, ताकि घर से मिलने वाले पैसों के अलावा कुछ और पैसों का इंतज़ाम हो सके. दिल्ली विश्वविद्यालय के पास के मुहल्ले विजय नगर में रहता था और वहां से सौ नंबर की बस पकड़ कर कनॉट प्लेस पहुंचता था, जहां हिंदुस्तान और इंडिया टुडे के दफ्तर थे. उसके अलावा रफी मार्ग स्थित इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बिल्डिंग में, जहां कई अख़बारों के दफ्तर थे, जाकर कुछ काम लेता था. छात्र जीवन के दौरान फ्रीलांसिंग से जितने भी पैसे मिल जाते थे, वे बोनस होते थे. उसी वक़्त देश की शीर्ष पाक्षिक पत्रिका में दो किताबों पर एक समीक्षा लिखने का अवसर मिला. अगर मेरी स्मृति साथ दे रही है तो यह वर्ष 1993 की बात है, मेरी लिखी समीक्षा उक्त पाक्षिक पत्रिका में छपी पूरे एक पन्ने में. बेहद ख़ुशी हुई. दिल्ली आने के बाद पहली बार किसी राष्ट्रीय पत्रिका में पूरे पन्ने पर जगह मिली, अख़बारों में तो लेख वग़ैरह छप ही रहे थे. दो महीने बीतने के बाद एक लिफ़ाफ़े में उक्त समीक्षा का मेहनताना आया, लिफ़ाफ़ा खोला तो उसमें एक हज़ार रुपये का चेक था. खुशी दोगुनी हो गई. उस वक़्त हज़ार रुपये बहुत हुआ करते थे. बाद में तो यह सिलसिला चल निकला और अख़बारों एवं पत्रिकाओं में लिखकर चेक आने की प्रतीक्षा करने लगा. हम तीन लोग एक फ्लैट में रहते थे. साथ रह रहे दोस्तों को भी मेरी डाक में आने वाले चेक का अंदाज़ा हो गया था और वे भी अख़बार-पत्रिकाओं के लिफ़ाफ़े का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि जिस दिन लिफ़ाफ़ा आता था, उस दिन जश्न तय होता था यानी किंग्सवे कैंप के सम्राट या विक्रांत होटल में जाकर खाना खाना.

अभी हाल में, तक़रीबन दो साल पहले उक्त पत्रिका में फिर से मेरे द्वारा लिखी गई एक पन्ने की समीक्षा छपी. दो महीने बाद फिर से चेक आया, लेकिन राशि वही एक हज़ार रुपये. अचानक मेरे दिमाग़ में एक बात कौंधी कि डेढ़ दशक बाद भी एक पृष्ठ समीक्षा लिखने के उतने ही पैसे, कोई बदलाव नहीं. फिर मैंने सोचना शुरू किया और अख़बारों-पत्रिकाओं से लेखकों को मिलने वाले मानदेय या मेहनताने पर विचार किया तो लगा कि तक़रीबन पंद्रह साल बाद भी लेखकों को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला है. मानदेय कमोबेश वही है, जो दस-बारह साल पहले था. इस बीच अख़बारों एवं पत्रिकाओं के मूल्य और उनमें छपने वाले विज्ञापनों की दरें कई-कई गुना बढ़ गईं, लेकिन लेखकों को मिलने वाले मानदेय में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ. दरअसल, फ्रीलांसरों के बारे में किसी ने सोचने की ज़हमत ही नहीं उठाई. लगा कि यह तो ज़रूरतमंद है, जितने पैसे दोगे, उतने में ही काम करेगा. नतीजा यह हुआ कि हिंदी में स्वतंत्र लेखन करने वालों को ज़रूरतमंद मान लिया गया. हिंदी के लेखकों को अख़बारों या पत्रिकाओं में लेख लिखने के एवज में जो पैसे मिलते हैं, वे बहुत ही कम हैं और लेखकों की प्रतिष्ठा के अनुरूप तो कतई नहीं है. अब तो कई अख़बारों में कम से कम लेखों का हिसाब रहने लगा है, नहीं तो कुछ दिनों पहले तक हालत यह थी कि संपादकीय विभाग या लेखा विभाग में बैठा बाबू जितने की पेमेंट लगा दे, उससे ही लेखकों को संतोष करना पड़ता था. अब भी कई अख़बारों एवं पत्रिकाओं में हज़ार शब्दों के एक लेख के लिए लेखकों को पांच सौ से लेकर सात सौ रुपये तक ही दिए जा रहे हैं, लेकिन लेखक लिख रहे हैं और ख़ुशी-ख़ुशी लिख रहे हैं. हिंदी में न कहने की प्रवृत्ति अथवा यूं कहें कि साहस नहीं है. उन्हें लगता है कि अगर मना किया तो ये पांच सौ रुपये भी मिलने बंद हो जाएंगे.

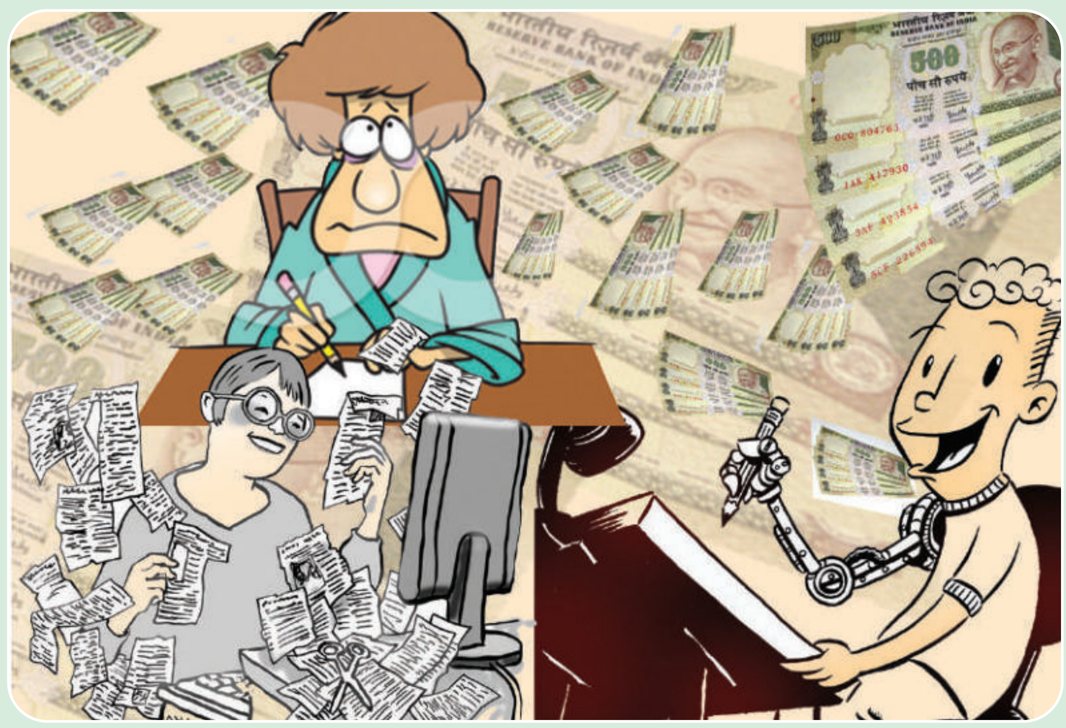

इस पूरे वाकए को बताने के पीछे मेरा मक़सद उस सवाल से टकराने का है, जो बार-बार मेरे जेहन में कौंध रहा है. सवाल यह है कि क्या हिंदी का लेखक सिर्फ़ लिखकर अपना जीवनयापन कर सकता है. अगर हम यह मान भी लें कि किसी लेखक का हर दिन कोई न कोई लेख किसी अख़बार में छपता है, हालांकि यह मुमकिन है नहीं, फिर भी मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेख के पारिश्रमिक को अगर हम बहुत ऊपर भी रखें और प्रति लेख पंद्रह सौ रुपये मानें, तब भी महीने के 45 हज़ार होते हैं. क्या महानगर में सिर्फ़ 45 हज़ार रुपये के बूते जीवन चल सकता है? अभी के जो हालात हैं, उसमें तो लगता है कि हिंदी का पूर्णकालिक लेखक अपने लेखन के बूते सरवाइव कर ही नहीं सकता है. अगला सवाल यह उठता है कि हिंदी की हालत ऐसी क्यों है, जबकि हिंदी का बाज़ार और उसमें देशी-विदेशी निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे अगर हम वजह ढूंढते हैं तो वहां तस्वीर बेहद धुंधली सी नज़र आती है. हिंदी के बढ़ते बाज़ार के बावजूद लेखकों को उचित पारिश्रमिक न मिल पाने का कारण सिर्फ़ वह मानसिकता है, जो यह सिखाती है कि स्वतंत्र रूप से लिखने वालों को ज़्यादा पैसा क्यों दिया जाए. ये तो ज़रूरतमंद लोग हैं, जितना दिया जाएगा, याचक की तरह ले लेंगे और एहसान भी मानेंगे.

अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो वहां के पत्र-पत्रिकाओं में लेखकों को मिलने वाले पैसे हिंदी की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं और भुगतान भी व्यवस्थित है. अंग्रेजी अख़बारों में संपादकीय पृष्ठ पर एक लेख छपने के बाद कम से कम पांच हज़ार रुपये मिलते हैं और अगर कोई सेलेब्रिटी राइटर है तो पारिश्रमिक की सीमा वह ख़ुद तय करता या करती है. विदेशी अख़बारों से मिलने वाला पैसा तो और भी ज़्यादा होता है. हिंदी की तुलना में अंग्रेजी के अख़बार कम बिकते हैं, लेकिन फिर भी लेखकों को मानदेय वहां ज़्यादा है. दरअसल, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के कर्ता-धर्ता अब भी औपनिवेशिक ग्रंथि से मुक्त नहीं हो पाए हैं और अंग्रेजी उनके लिए अब भी मालिकों की भाषा है. लिहाज़ा अगर अंग्रेजी में लेखकों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो वे यह कहकर अपने कम देने को जायज़ ठहराते हैं कि वह अंग्रेजी है, वहां आय ज़्यादा है, लेकिन उस वक़्त वे यह भूल जाते हैं कि हिंदी में पिछले दस सालों में हर अख़बार के दर्जनों संस्करण शुरू हुए, प्रसार संख्या एवं विज्ञापनों में कई गुना इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन नहीं बढ़ा तो सिर्फ़ लेखकों का मानदेय.

अब वक़्त आ गया है कि हिंदी पत्र-पत्रिकाएं चलाने वाले लोग या फिर संपादक अपने लेखकों को दिए जाने वाले मानदेय पर एक नज़र डालें और उसमें समय के साथ सुधार करें. इससे लेखकों का तो भला होगा ही, ख़ुद हिंदी भाषा के साथ जुड़ने की लोगों की ललक भी बढ़ेगी. मैं एक किस्सा कई बार सुना चुका हूं, एक संपादक ने एक लेखक को एक पुस्तक समीक्षा के लिए अनुरोध पत्र भेजा और उनसे पूछा कि क्या पुस्तक उन्हें भेज दी जाए. लेखक महोदय ने उत्तर दिया, समीक्षा के लिए पुस्तक भेज दें, उस पर लिखकर ख़ुशी होगी, लेकिन अगर पुस्तक के साथ मानदेय का चेक भी हो, तो समीक्षा हुलस कर लिखूंगा. यह किस्सा बहुत कुछ कह देता है. आमीन.

*(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)*
anant.ibn@gmail.com

# जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही

फ़िरदौस ख़ान

पाकिस्तान की मशहूर शायरा परवीन शाकिर के कलाम की ख़ुशबू ने न केवल पाकिस्तान, बल्कि हिंदुस्तान की अदबी फ़िज़ा को भी महका दिया. वह अपना पहला काव्य संग्रह आने से पहले ही इतनी मशहूर हो चुकी थीं कि जहां भी शेरों-शायरी की बात होती, उनका नाम ज़रूर लिया जाता. उनका पहला काव्य संग्रह ख़ुशबू 1976 में प्रकाशित हुआ. इसके बाद उनके एक के बाद एक कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए. सद बर्ग 1980 में प्रकाशित हुआ, जबकि 1990 में उनके दो काव्य संग्रह ख़ुद कलामी और इनकार प्रकाशित हुए. इसके बाद 1994 में उनका काव्य संग्रह माह-ए-तमाम प्रकाशित हुआ. फिर कफ़-ए-आईना और गोशा-ए-चश्म प्रकाशित हुए. 24 नवंबर, 1952 को पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी परवीन शाकिर को अपने वालिद शाकिर हुसैन से बेपनाह मुहब्बत थी. उनके नाम में भी उनके पिता का नाम शाकिर हमेशा शामिल रहा. कराची के सैयद कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने कराची विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया. इसके बाद उन्होंने बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली. उन्होंने पीएचडी भी की. नौ साल तक उन्होंने अध्यापन किया. इसके बाद 1986 में वह इस्लामाबाद में कस्टम विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त हुईं.

उन्होंने युवावस्था से ही लिखना शुरू कर दिया था. पाकिस्तान के उर्दू एवं अंग्रेजी अख़बारों में उनके कॉलम छपते थे. पहले वह बीना नाम से लिखती थीं. उनकी शायरी ने बहुत कम अरसे में ही उन्हें उस बुलंदी पर पहुंचा दिया, जिसके लिए न जाने कितने शायर तरसते हैं. उनकी ग़ज़लें लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं, जहां से वे लौटना ही नहीं चाहते. लोग अपने महबूब को ख़त लिखते समय उसमें उनके शेअर लिखना नहीं भूलते. यही तो उनकी क़लम का जादू है:-

***चेहरा मेरा था निगाहें उसकी***
***ख़ामोशी में भी वो बातें उसकी***
***मेरे चेहरे पे ग़ज़ल लिखती गईं***
***शेअर कहती हुई बातें उसकी***
***ऐसे मौसम भी गुज़ारे हमने***
***सुबहें जब अपनी थीं, शामें उसकी***

परवीन शाकिर का कलाम महबूब को बेपनाह चाहने के जज़्बे से लबरेज़ है. इस जज़्बे में नज़ाकत भी है और नफ़ासत भी:-

***जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही***
***हो गई रात तेरे अक्स को तकते-तकते***
***मैंने फिर तेरे तसव्वुर के किसी लम्हे में***
***तेरी तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से***

परवीन शाकिर की शादी डॉ. निसार अली से हुई. उनका एक बेटा है सैयद मुराद अली. परवीन शाकिर की शादी कामयाब नहीं रही और उनका तलाक़ हो गया. इस रिश्ते की टूटन का एहसास उनके कलाम में भी झलकता है:-

***बिछड़ा है जो एक बार तो मिलते नहीं देखा***
***इस ज़ख्म को हमने कभी सिलते नहीं देखा***
***इस बार जिसे चाट गई धूप की ख्वाहिश***
***फिर शाख़ पे उस फूल को खिलते नहीं देखा***

उनकी शायरी में एक औरत की मुहब्बत, उसके ख्वाब और उसका दर्द झलकता है. यह कहना क़तई ग़लत न होगा कि उनका कलाम ज़िंदगी के अनेक रंगों को अपने में समेटे हुए है. उसमें मुहब्बत का रंग भी शामिल है तो जुदाई का रंग भी. ख़ुशी का रंग भी झलकता है तो दु:खों का रंग भी नज़र आता है:-

***कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने***
***बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की***
***वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया***
***बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की***
***तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे***
***तुझ पे गुज़रे न क़यामत शब-ए-तन्हाई की***

उनकी ग़ज़लों की तरह उनकी नज़्में भी बेहद लोकप्रिय हुईं. चंद अल्फ़ाज़ में गहरी से गहरी बात को बड़ी आसानी से कह जाने का हुनर उन्हें बख़ूबी आता था. ऐसी ही उनकी एक नज़्म चांद है:-

***एक से मुसाफ़िर हैं***
***एक सा मुक़द्दर है***
***मैं ज़मीं पर तन्हा***
***और वो आसमानों में***

बस इतना याद है, भी उनकी लोकप्रिय नज़्मों में शुमार की जाती है:-

***दुआ तो जाने कौन सी थी***
***ज़ेहन में नहीं***
***बस इतना याद है***
***कि दो हथेलियां मिली हुई थीं***
***जिनमें एक मेरी थी***
***और इक तुम्हारी***

उनके कलाम में एक ऐसी औरत का दर्द झलकता है, जो मुहब्बत से महरूम है. अपनी नज़्म मुक़द्दर में वह इसी दर्द को बयां करती हैं:-

***मैं वो लड़की हूं***
***जिसको पहली रात***
***कोई घूंघट उठाके यह कह दे***
***मेरा सब कुछ तेरा है, दिल के सिवा***

उनकी ऐसी ही एक और नज़्म है ड्यूटी, जिसमें वह एक ऐसी औरत के दर्द को पेश करती हैं, जिसका पति उसका होकर भी उसका नहीं है. औरत इस सच को जानते हुए भी इसे सहने को मजबूर है:-

***जान!***
***मुझे अफ़सोस है***
***तुमसे मिलने शायद इस हफ्ते भी न आ सकूंगा***
***बड़ी अहम मजबूरी है***

***जान!***
***तुम्हारी मजबूरी को***
***अब तो मैं भी समझने लगी हूं***
***शायद इस हफ्ते भी***
***तुम्हारे चीफ की बीवी तन्हा होगी***

ज़िंदगी में मुहब्बत बार-बार नहीं मिलती. इसलिए इसे सहेज लेना चाहिए. इसी बात को वह अपनी एक नज़्म एक दोस्त के नाम में बख़ूबी पेश करती हैं:-

***लड़की!***
***ये लम्हे बादल हैं***
***गुज़र गए तो हाथ कभी नहीं आएंगे***
***उनके लम्स को पीती जा***
***क़तरा-क़तरा भीगती जा***
***भीगती जा तू, जब तक इनमें नमी है***
***और तेरे अंदर की मिट्टी प्यासी है***
***मुझसे पूछ कि बारिश को वापस आने का रस्ता***
***न कभी याद हुआ***
***बाल सुखाने के मौसम अनपढ़ होते हैं***

इस हरदिल अज़ीज़ शायरा को ज़िंदगी ने बहुत कम सांसें दीं. 26 दिसंबर, 1994 को उनकी कार एक बस के साथ टकरा गई. इस हादसे में उनकी मौत हो गई. जिस दिन उनकी मौत हुई, उस रोज़ बारिश भी बहुत हो रही थी. लग रहा था, मानो बादल भी उनकी मौत पर मातम कर रहे हों. अपने कलाम के रूप में परवीन शाकिर आज भी ज़िंदा हैं और लोग हमेशा उनकी ग़ज़लों को गुनगुनाते रहेंगे.

firdaus@chauthiduniya.com

## किताब मिली

**पुस्तक का नाम**
हिमांशु जोशी की यादगारी कहानियां

**लेखक**
हिमांशु जोशी

**प्रकाशक**
हिन्द पॉकेट बुक्स

**मूल्य**
135 रुपये

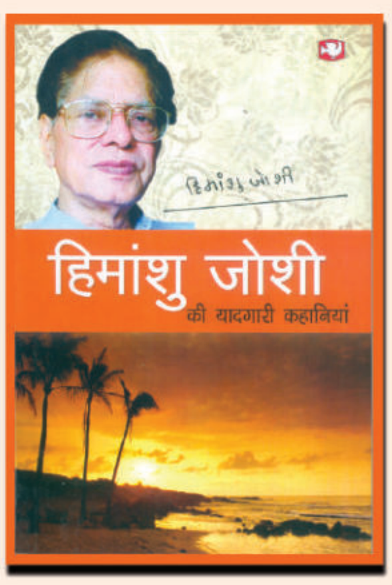


यह किताब हिमांशु जोशी की कहानियों का संग्रह है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

सैमसंग के बीम प्रोजेक्टर फोन में 4.0 इंच स्क्रीन के साथ 1 गीगाहर्ट का ड्यूअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी मोटाई 12.5 एमएम है.



# सैमसंग बीम प्रोजेक्टर फोन

मोबाइल फोन बाज़ार में फीचर और क़ीमत को लेकर तो हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती ही रहती है, मगर इसके साथ ग्रहकों को कुछ नया देने की होड़ भी लगी हुई है, शायद यही कारण है कि सैमसंग अपने हर नए हैंडसेट में कुछ न कुछ नया ज़रूर लाता है. ऐसा ही एक नया प्रयोग किया है सैमसंग ने, अपने बीम प्रोजेक्टर फोन को लाकर. हालांकि इससे पहले भी इंटेक्स और स्पाइस जैसी घरेलू हैंडसेट निर्माता कंपनियां अपने प्रोजेक्टर फोन भारत में लांच कर चुकी हैं मगर वे उतने कामयाब नहीं हो सके हैं. सैमसंग का बीम प्रोजेक्टर फोन बस कुछ ही दिनों के अंदर भारतीय बाज़ार में आने वाला है, मगर इसके फीचर्स की चर्चा हैंडसेट बाज़ार में जोरों पर हैं. सैमसंग के बीम प्रोजेक्टर फोन में 4.0 इंच स्क्रीन के साथ 1 गीगाहर्ट का ड्यूअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और इसकी मोटाई 12.5 एमएम है. फोन का डिस्प्ले 480x800 रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है. इसके अलावा बीम प्रोजेक्टर फोन की सबसे खास बात यह है कि इसका प्रोजेक्टर केवल 15 ल्यूमेन्स की पॉवर से 50 इंच की बड़ी स्क्रीन बनाता है. फोन को इनडोर के साथ-साथ आउटडोर में भी प्रयोग कर सकते हैं. सैमसंग बीम प्रोजेक्टर फोन की अनुमानित क़ीमत 25,000 रुपए है. सैमसंग बीम प्रोजेक्टर फोन एंड्रॉएड 2.3 जिंजरब्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है. इसमें 5 मेगापिक्सल ऑटोफोकस कैमरा है जिसमें फ्लैश की सुविधा दी गई है. इसके साथ ही 1.3 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है. इसमें 786 एमबी रैम, 8जीबी इंटरनल मैमोरी और 32 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी है. यह ब्लूटूथ और वाईफाई को सपोर्ट करता है. इसमें 3.5 एमएम इयरफोन जैक दिया गया है और इस खास फोन में 2000 एमएएच बैटरी लगी है. बाज़ार में इसकी अनुमानित क़ीमत 25,000 रुपए है.

नई दिल्ली में फुजी फिल्म की ब्रांड एंबेसडर एवं बॉलीवुड अभिनेत्री मिनिषा लांबा ने डिजिटल कैमरे की नई रेंज पेश की . फोटा–सुनील मल्होत्रा

# भरोसे का दूसरा नाम अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स

**बिहार और झारखंड के लोगों को चीज़ों की अच्छी परख है. यहां के लोगों ने बहुत जल्द अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ अपना रिश्ता बनाना शुरू कर दिया है.**

EARTH INFRASTRUCTURES LTD. Innovation beyond imagination.

दिल्ली एवं एनसीआर में प्यारा सा घर. एक ऐसा सपना, जिसे हर कोई संजोता है. लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं. ज़्यादातर लोगों के सामने भरोसे का संकट पैदा हो जाता है. दिल्ली एवं एनसीआर की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कौन सही सलाह देगा और कौन सही मकान देगा. कहेगा कुछ और देगा कुछ. यह ऐसी समस्या है, जिससे ज़्यादातर लोग रोज़ रूबरू होते हैं. ऐसे ही लोगों के लिए अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने एक आसान रास्ता निकाला है. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कहता है, वही अपने ग्राहकों को देता है. ग्रीन बिल्डिंग्स का सपना भी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरा कर रहा है. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट सिद्धार्थ कटयाल के अनुसार, मास्टर प्लान 2031 के ज़रिये नोएडा को हरे-भरे शहर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है. इस बात का पता इसी से चलता है कि तीन फ़ीसदी अतिरिक्त ज़मीन को सिर्फ़ हरे-भरे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स के निर्माण को बढ़ावा देने जैसे क़दम पर्यावरण संरक्षण के लिहाज़ से सराहनीय हैं. मास्टर प्लान द्वारा नोएडा में ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण में काफ़ी तेज़ी आ सकती है. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने हाल में ग्रेटर नोएडा के टेकजोन में प्लाट नंबर एक पर अर्थ बीटा टेक लांच किया है. यह बग़ैर फर्निश किया हुआ विश्व स्तर का ऑफिस स्पेस है. अर्थ बीटा के बारे में सिद्धार्थ कटयाल का कहना है कि हम हमेशा अपने ग्राहकों को आधुनिक और उन्नत तकनीक वाली बिल्डिंग मुहैया कराने पर ज़ोर देते हैं. विश्व स्तर पर अपनी विशेषताओं, लोकेशन और कनेक्टिविटी के साथ अर्थ बीटा टेक एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट में एमबीए कराने वाली एमिटी यूनिवर्सिटी ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड को नॉलेज पार्टनर बनाया है. इसका मक़सद साथ मिलकर रियल एस्टेट सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देना है. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने बिहार और झारखंड के लोगों की सुविधा के लिए पटना एवं रांची में भी अपना कार्यालय खोला है. दोनों प्रदेशों में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है. अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जोनल हेड रजनी यादव का मानना है कि बिहार और झारखंड के लोगों को चीज़ों की अच्छी परख है. यहां के लोगों ने बहुत जल्द अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ अपना रिश्ता बनाना शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने सम्मानित ग्राहकों को पूरा सम्मान दें और उनकी सारी ज़रूरतों को समय सीमा के अंदर पूरा करें. उन्होंने कहा कि हम अपने ग्राहकों से किया हर वादा पूरा करते हैं.

रजनी यादव, जोनल हेड अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# द नेटवर्क विजार्ड

आज की दुनिया में संचार जीवन का अहम अंग है. इंटरनेट संचार के सबसे तीव्र माध्यमों में से एक है. जेब्रोनिक्स ने इसे हर तरह के यूजर्स के लिए आसान बनाने के लिए हाई परफॉर्मेंस वायरलेस उत्पाद नेटविज-द नेटवर्क विजार्ड- लांच किया है. इन उत्पादों से उपभोक्ताओं की ज़िंदगी में राउटर्स और गेटवेज की भूमिका नए सिरे से परिभाषित होने जा रही है. ये कई तरह के नए अनूठे एप्लीकेशंस, फीचर्स के ज़रिए इंटरनेट इस्तेमाल की तमाम संभावनाओं का विस्तार कर देते हैं और अल्टीमेट होम नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं. नेटविज - द नेटवर्क विजार्ड तीन वायरलेस राउटर और एक वारयलेस डोंगल की एक उत्पाद श्रृंखला है. पीसी हो, लैपटॉप या फिर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन, नेटविज सीरीज वायरलेस राउटर इन सभी को इंटरनेट से निर्बाध कनेक्ट करता है. राउटर्स के तीन मॉडल हैं, एनडब्ल्यूजेड-डब्ल्यूआ 150ए, एनडब्ल्यूजेड-डब्ल्यूआ 150ए थ्री जी, एनडब्ल्यूजेड-डब्ल्यूआ 150ए एडीएसएल. जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पहला मॉडल एन सीरीज का वायरलेस राउटर है. दूसरा मॉडल यूएसबी पोर्ट से लैस है, जो थ्री जी मॉडल से अटैच करने के लिए है. तीसरा मॉडल एक एडीएसएल मॉडम के साथ आता है. ये तीनों मॉडल पैरेंटल कंट्रोल, आसान कनेक्टिविटी के लिए डब्ल्यूपीएस, आसान मेल रिपोर्टिंग, सिक्योर कनेक्शन, डीएमजेड- डी मिलिट्राइज्ड जोन और इसके अलावा भी कई नए फीचर्स से लैस हैं. यूएसबी डोंगल एनडब्ल्यूजेड-यूडी 150 ए एक एन सीरीज उत्पाद है. यह डब्ल्यूपीएस, सिक्योर कनेक्शन, यूएसबी 2.0 सहित कई खूबियों से लैस है. यह स्टेशन मोड के साथ-साथ एक्सेस प्वाइंट मोड में भी काम कर सकता है. जेब्रोनिक्स 3जी वाई-फाई राउटर एनडब्ल्यूजेड-डब्ल्यूआ 150ए 3 जी मोबाइल उपभोक्ताओं की इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने के लिए वायरलेस नेटवर्क सेट करने की ज़रूरत पूरी करता है. 3जी डोंगल इंस्टॉल करने यूजर काफी कम समय में सिक्योर वायरलेस नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. वायरलेस नेटवर्क के भीतर कहीं भी एकदम सुविधाजनक तरीक़े से इंटरनेट कनेक्शन शेयर किया जा सकता है. राउटर इस्तेमाल करना और इसका सेटअप एकदम आसान है. यह अपने आप यूएसबी डिवाइस डिटेक्ट कर वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन कायम कर देता है. तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर, पीडीए और वाई-फाई फोन एक साथ एक ही वायरलेस 3जी कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं. सफर के दौरान इंटरनेट एक्सेस के लिए कोई झंझट झेलने की ज़रूरत नहीं है. अब आप कहीं भी इंटरनेट शेयर कर सकते हैं. बस संबंधित थर्ड पार्टी 3जी इंटरनेट डोंगल पर कोई इंटरनेट प्लान एक्टिवेट करने की ज़रूरत है. नेटविज रेंज के उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पाद अब एडॉप्टर, केवल और मैनुअल्स जैसे एसेसरीज के साथ उपलब्ध हैं. कंपनी ने उत्पादों में डिजाइन का भी एक पुट जोड़ा है. हमें यह नई अल्टीमेट नेटवर्किंग मशीन उपभोक्ताओं को उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला सुरक्षित और भरोसेमंद सामाधान पेश करती है, जिसके ज़रिए वे अल्टीमेट होम नेटवर्क बना सकते हैं. अनूठी खूबियों से लैस नए राउटर तमाम अग्रणी आईटी स्टोर्स पर 1100 से 3150 रुपये की क़ीमत पर उपलब्ध हैं.

# लॉजिटेक का नया वेबकैम

**बाज़ार में कई वेब कैमरे उपलब्ध है मगर कम क़ीमत में लॉजिटेक का सी310 वेबकैम आपके लिए सबसे फ़ायदे का सौदा होगा क्योंकि इसमें वीडियो कालिंग के दौरान 720 पिक्सल की हाइडेफिनेशन इमेज क्वालिटी मिलती है.**

अगर आपके सगे संबधी कहीं विदेश में रहते है तब तो उनके क़रीब आने के लिए आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वेबकैमरा ज़रूर होना चाहिए. फेसबुक हो या फिर गूगल हर कहीं वीडियो चैटिंग का ऑप्शन मौजूद है.

इन सर्विसेज़ से वीडियो चैटिंग कर लंबी दूरी को आसानी से ख़त्म किया जा सके. जितनी अच्छी क्वालिटी का वेबकैमरा होगा उतनी ही अच्छी तस्वीरें देखी जा सकती है. वैसे तो पीसी बाज़ार में कई वेब कैमरे उपलब्ध है मगर कम क़ीमत में लॉजिटेक का सी310 वेबकैम आपके लिए सबसे फ़ायदे का सौदा होगा क्योंकि इसमें वीडियो कॉलिंग के दौरान 720 पिक्सल की हाइडेफिनेशन इमेज क्वालिटी मिलती है. लॉजिटेक के नए वेबकैम में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. इसके अलावा वेब कैम की मदद से आप अपने फेसबुक और यूट्यूब एकाउंट की फोटो भी कैप्चर कर सकते है वो भी बस एक क्लिक मात्र से, अन्य फीचर्स में कैमरे की मदद से लिए गए वीडियो में कई शानदार इफेक्ट दिए जा सकते हैं, लॉजिटेक का नया सी310 वेब कैमरा मात्र 1,449 रुपए में उपलब्ध है.

# एंड्रॉएड बेस सिडॉन लक्ज़री कार

एंड्रॉएड फोन के बारे तो आपने सुना होगा मगर क्या कभी एंड्रॉएड कार के बारे में सुना है, ताइवान की कार कंपनी लक्जन मोटर ने दुनिया की पहली एंड्रॉएड बेस कार लांच की है. लक्जन 5 नाम की इस प्रीमियम सिडॉन कार को कंपनी ने एचटीसी के साथ मिलकर बनाया है. ताइवान बेस मोबाइल फोन निर्माता एचटीसी द्वारा बनाए गए थिंक सिस्टम से लक्जन कार में यूजर अपने एचटीसी फोन को कार के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं. इसे कार में लगी 9 इंच की स्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है. थिंक सिस्टम के द्वारा यूजर न सिर्फ़ कार से कॉल अटेंड कर सकता है बल्कि कार के कंसोल में लगी स्क्रीन में फेसबुक, मेल भी भेज सकते हैं. कार में लगी 9 इंच की टच स्क्रीन काफी स्मूथ वर्क करती है जिससे यूजर कार चलाते समय आसानी से फोन कॉल रिसीव कर सकता है. इसके अलावा कार के थिंक सिस्टम में जीपीएस नेविगेशन और हैंडस फ्री ब्लूटूथ की सुविधा मौजूद है. एंड्रॉएड इंटरफेस से लैस लक्जरी सिडॉन कार को एंड्रॉएड बेस बनाने में काफी तकनीकी बदलाव भी किए है. कार की क़ीमत लगभग 12,12272 रुपये से लेकर 15,81225 रुपये के बीच हैं.

**ताइवान बेस मोबाइल फोन निर्माता एचटीसी द्वारा बनाये गए थिंक सिस्टम से लक्जन कार में यूजर अपने एचटीसी फोन को कार के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं. इसे कार में लगी 9 इंच की स्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है.**

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

## लॉयनल मेसी

# फुटबॉल का स्वर्णिम युग या सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ?

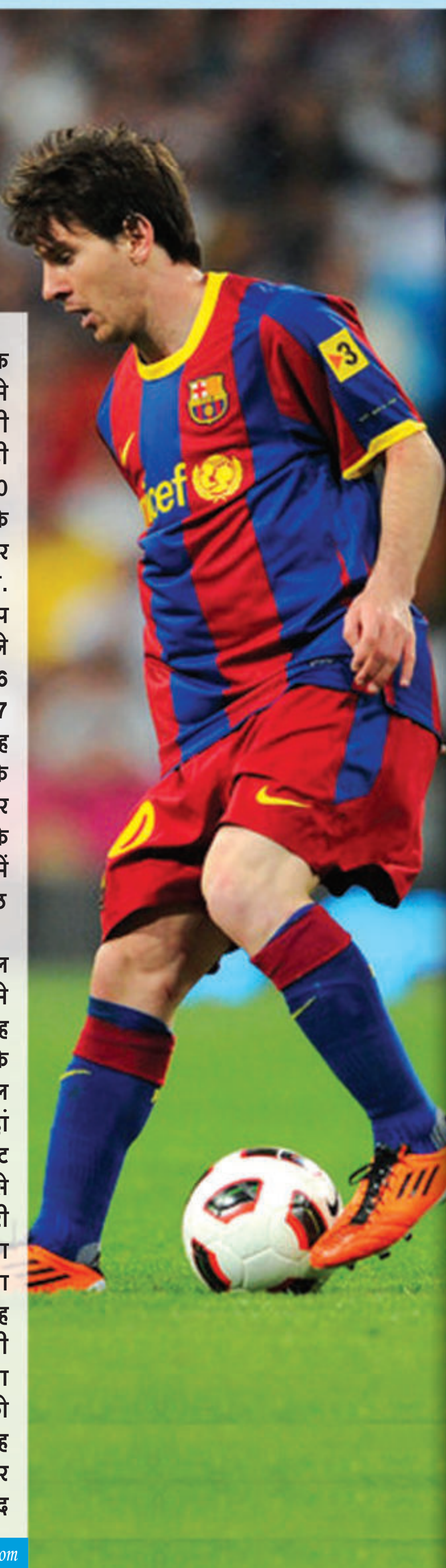


नवीन चौहान

फुटबॉल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वैज्ञानिक किसी खिलाड़ी के अद्‌भुत खेल का कारण जानना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने लॉयनल मेसी के दिमाग़ का परीक्षण करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि मेसी अभी 25 साल के भी नहीं हुए हैं और उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है. उन्होंने अपना नाम फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में होना सुनिश्चित कर दिया है. इसका श्रेय उनके बेहतरीन खेल, उनकी विध्वंसक ड्रिबलिंग, तकनीक, फुटवर्क और मैच दर मैच गोल दाग़ने की बढ़ती बेतहाशा भूख को दिया जा सकता है. हाल में मेसी ने 234वां गोल करके बार्सिलोना की ओर से सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है. उसी दौरान चैंपियंस लीग के एक मैच में 5 गोल करने का एक नया कीर्तिमान भी बना डाला. इसके बाद बार्सिलोना टीम के कोच जोसेफ ग्वारडिओला ने कहा था कि हम हर मायने में एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खेल के साक्षी बन रहे हैं. वह जो कुछ भी करते हैं, उसे हर तीसरे दिन दोहराते हैं. मुझे उन लोगों के लिए दुख है, जो उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं, मगर यह नौजवान सर्वश्रेष्ठ है.

मेसी ने पांच साल की उम्र में फुटबॉल का ककहरा अपने पिता से सीखना शुरू किया. अर्जेंटीना में एक लोकल क्लब ग्रैंडोली में उनके पिता कोच थे. यही मेसी का पहला क्लब था. 1995 में वह अपने गृहनगर रोसेरियो के न्यूवेलओल्ड बॉयस क्लब में शामिल हुए. मगर 11 साल की उम्र में मेसी ग्रोथ हार्मोन डिफीसियेंसी से ग्रसित हो गए. उस समय उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे. उनके खेल से प्रभावित होकर एफसी बार्सिलोना के खेल निदेशक ने ट्रायल के दौरान मैदान में ही काग़ज़ उपलब्ध न होने की वजह से पेपर नेपकिन पर ही क़रार कर डाला और तब एक महान खिलाड़ी के निर्माण की कहानी शुरू हुई.

महज़ 17 साल की उम्र में एल्बेसिटी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए किए गोल ने उन्हें बार्सिलोना के लिए सबसे कम उम्र में गोल करने वाला खिलाड़ी बना दिया था. मेसी ला-लीगा में खेलने वाले तब सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे. मेसी ने 2005 में नीदरलैंड में हुए फीफा अंडर-20 विश्वकप में गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल पुरस्कारों के साथ अर्जेंटीना को विश्वकप विजेता बना कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी. वर्ष 2006 में मेसी अर्जेंटीना की ओर से फीफा विश्वकप खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. मेसी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गोल फीफा विश्वकप 2006 के अभ्यास मैचों के दौरान किया था. अब तक मेसी ने 67 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 22 गोल ही किए हैं, जबकि वह 2008 बीजिंग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य थे, मगर उनकी ये उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य रूप से उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किए जाने के लिए नाकाफ़ी हैं. वह वर्तमान में खेल रहे खिलाड़ियों में सबसे बेहतर हैं. उन्हें फीफा ने तीन बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है.

अगर महानता का पर्याय कहे जाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी पेले, मैराडोना, रोनाल्डो, जिडान जैसे खिलाड़ियों से मेसी की तुलना की जाए तो शायद यह समय सही नहीं है, क्योंकि मेसी अभी अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर से गुज़र रहे हैं. वह अब तक दो फुटबॉल विश्वकप में शिरकत कर चुके हैं, मगर उनका प्रदर्शन वहां औसत दर्जे का रहा है. हम मेसी की शारीरिक बनावट और खेल की वजह से उनकी तुलना हमवतन मैराडोना से करते हैं. मैराडोना ने ख़ुद ही मेसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है. स्पेनिश प्रेस ने तो मेसी को मेसीडोना की संज्ञा तक दे दी है, मगर मेसी ने अपनी नए मैराडोना की उपाधि को अतिशयोक्ति साबित नहीं होने दिया. वह लगातार अच्छा खेल रहे हैं. इस बारे में उनके साथी खिलाड़ी चार्ल्स पुयोल कहते हैं, फुटबॉल के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेसी न कर सकें. भगवान ने मेसी को अच्छा फुटबॉल खेलने की नेमत बख़्शी है और वह इसका पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं. वह खेलते जा रहे हैं और गोल पर गोल करते जा रहे हैं और प्रशंसक इसका आनंद उठा रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

## बॉक्सिंग

# मेरीकॉम और सरिता देवी का गोल्डन पंच

भारतीय महिला मुक्केबाज़ एमसी मेरीकॉम और सरिता देवी ने मंगोलिया में संपन्न हुई छठी एशियाई महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को दो स्वर्ण पदक जिता दिए. चैंपियनशिप में भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल आठ पदक जीतने में कामयाब रहा. स्पर्धा में सबसे ज़्यादा पदक चीन के नाम रहे. भारत को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. पांच बार की विश्व चैंपियन मेरीकॉम ने 51 किग्रा वर्ग के फाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन और 2010 एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता चीन की रेन चानचान को 14-8 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. 60 किग्रा वर्ग में सरिता देवी ने पिछले वर्ष की विजेता तजाकिस्तान की चोरिएवा मावजुना को 16-9 से हराया. महिला बॉक्सरों के इस प्रदर्शन से पहली बार ओलंपिक में शामिल की गई महिला बॉक्सिंग में भारतीय जीत की संभावनाओं को बल मिला है.

## क्रिकेट

# आयरलैंड और अफ़ग़ानिस्तान टी-20 विश्वकप में

आयरलैंड ने अफ़ग़ानिस्तान को यूएई में हुए विश्व टी-20 क्वालीफायर टूर्नामेंट में पांच विकेट से हराकर ख़िताब अपने नाम कर लिया है. आयरलैंड और अफ़ग़ानिस्तान ने लगातार दूसरी बार टी-20 विश्वकप के लिए क्वालीफाई किया है. पिछली बार दोनों टीमों ने वेस्टइंडीज में हुए टी-20 विश्वकप के मेन ड्रॉ में जगह बनाई थी. अब ये दोनों टीमें सितंबर 2012 में श्रीलंका में होने वाले टी-20 विश्वकप में टेस्ट टीमों से दो-दो हाथ करती नज़र आएंगी. पिछली बार वेस्टइंडीज में हुए टी-20 विश्वकप में दोनों टीमों का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था. दोनों एक भी मैच जीतने में सफल नहीं हो पाई थीं. इस बार आयरलैंड की टीम 2011 के 50-50 विश्वकप में किए अपने बेहतरीन प्रदर्शन को टी-20 विश्वकप में दोहराने की कोशिश करेगी.

# दादा फिर कप्तान बने

सौरव गांगुली एक बार फिर कप्तान बन गए हैं. उन्हें मौजूदा आईपीएल सीजन में कैंसर से लड़ रहे युवराज सिंह की ग़ैर मौजूदगी में पुणे वॉरियर्स टीम का कप्तान घोषित किया गया है. गांगुली पहले कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की कप्तानी कर चुके हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया आईपीएल -2012

| | |
|---|---|
| अप्रैल 4 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस |
| अप्रैल 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स |
| अप्रैल 6 | मुंबई इंडियंस बनाम पुणे वॉरियर्स<br>राजस्थान रॉयल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब |
| अप्रैल 7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स<br>डेक्कन चार्जर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| अप्रैल 8 | राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स<br>पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम किंग्स इलेवन पंजाब |
| अप्रैल 9 | डेक्कन चार्जर्स बनाम मुंबई इंडियंस |
| अप्रैल 10 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स<br>दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| अप्रैल 11 | मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स |
| अप्रैल 12 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर<br>किंग्स इलेवन पंजाब बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया |
| अप्रैल 13 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स |
| अप्रैल 14 | दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम डेक्कन चार्जर्स<br>पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| अप्रैल 15 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स |
| अप्रैल 16 | मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स |
| अप्रैल 17 | राजस्थान रॉयल्स बनाम डेक्कन चार्जर्स<br>रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया |
| अप्रैल 18 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| अप्रैल 19 | डेक्कन चार्जर्स बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स, चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया |
| अप्रैल 20 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
| अप्रैल 21 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया |
| अप्रैल 22 | मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स इलेवन पंजाब<br>डेक्कन चार्जर्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| अप्रैल 23 | राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
| अप्रैल 24 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स,<br>कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| अप्रैल 25 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम मुंबई इंडियंस<br>रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| अप्रैल 26 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| अप्रैल 27 | दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम मुंबई इंडियंस |
| अप्रैल 28 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब,<br>कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
| अप्रैल 29 | दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| अप्रैल 30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| मई 1 | डेक्कन चार्जर्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया<br>राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स |
| मई 2 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम किंग्स इलेवन पंजाब |
| मई 3 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम मुंबई इंडियंस |
| मई 4 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| मई 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया |
| मई 6 | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| मई 7 | दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| मई 8 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम राजस्थान रॉयल्स<br>डेक्कन चार्जर्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब |
| मई 9 | मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
| मई 10 | राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| मई 11 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
| मई 12 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस |
| मई 13 | राजस्थान रॉयल्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया<br>किंग्स इलेवन पंजाब बनाम डेक्कन चार्जर्स |
| मई 14 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस,<br>कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| मई 15 | दिल्ली डेयर डेविल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब |
| मई 16 | मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| मई 17 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम चेन्नई सुपर किंग्स |
| मई 18 | डेक्कन चार्जर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स |
| मई 19 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली डेयर डेविल्स<br>पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स |
| मई 20 | डेक्कन चार्जर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस |

## प्लेऑफ मुक़ाबले

| | |
|---|---|
| मई 22 | क्वालीफायर 1-पहले नंबर की टीम बनाम दूसरे नंबर की टीम |
| मई 23 | एलिमिनेटर -तीसरे नंबर की टीम बनाम चौथे नंबर की टीम |
| मई 25 | क्वालीफायर 2- एलिमिनेटर का विजेता बनाम क्वालीफायर 1 में हारी टीम |
| मई 27 | फाइनल क्वालीफायर 1 का विजेता बनाम क्वालीफायर 2 का विजेता |

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

सुभाष घई की फिल्म परदेस से अपना करियर शुरू करने वाली महिमा को बाद में बॉलीवुड में टिके रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा.

# डायना की चाहत

एक अंग्रेजी कहावत है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ज्वॉय फॉरएवर. ऐसी ही कई दूसरी ब्यूटीफुल कुड़ियों की तरह ग्लैम डॉल डायना भी बिग और स्मॉल स्क्रीन से ग़ायब होने के बावजूद लोगों से जुड़ी रहती हैं. अपनी समाजसेवा से, अवॉर्ड शोज में अपनी प्रस्तुति से, कभी वाकपुटता से और कभी पब्लिक फंक्शंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर. अच्छी बात तो यह है कि डायना ग्लैम वर्ल्ड से दूर रहने के बावजूद उतनी ही फिट एवं चार्मिंग दिखती हैं, जितना लोग उन्हें हमेशा देखना चाहते हैं. अपनी इस फिटनेस का राज वह ख़ुद बताती हैं, मैं जमकर एक्सरसाइज़ करती हूं, जिसमें कार्डियो एवं स्ट्रेचिंग खास हैं. मेरी डाइट भी हेल्दी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन शामिल रहते हैं. मैं हैवी मील के बजाय थोड़ा-थोड़ा खाना पसंद करती हूं. आजकल गर्मी काफी है, इसलिए लिक्विड यानी पानी, जूस एवं दही वग़ैरह ज़्यादा लेती हूं. मुझे चेस खेलने का बहुत शौक है. ज़्यादा वक़्त मैं किताबें पढ़ने में बिताती हूं. मुझे आध्यात्मिक किताबें बेहद पसंद हैं. पाउलो कोल्हो मेरे फेवरिट राइटर हैं. डायना ख़ुद को पांच साल बाद कहां देखना चाहेंगी? इस सवाल पर वह कहती हैं कि पांच साल बाद भी मैं ख़ुद को यही काम करते हुए देखना चाहती हूं, जो मैं आज कर रही हूं. मुझे अपना काम बहुत प्यारा है. शो होस्ट करने और कॉरपोरेट इवेंट्स के सिलसिले में अक्सर देश-विदेश घूमती रहती हूं. मैं लोगों से पर्सनली जुड़ना चाहती हूं. मैं हमेशा अपने चैरिटी वर्क से जुड़ी रहना चाहती हूं, ताकि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सकूं.

**डायना ख़ुद को पांच साल बाद कहां देखना चाहेंगी? इस सवाल पर वह कहती हैं कि पांच साल बाद भी मैं ख़ुद को यही काम करते हुए देखना चाहती हूं, जो मैं आज कर रही हूं. मुझे अपना काम बहुत प्यारा है. शो होस्ट करने और कॉरपोरेट इवेंट्स के सिलसिले में अक्सर देश-विदेश घूमती रहती हूं.**

# शादी नहीं, पहले फिल्म

अपनी शादी को लेकर काफी बवाल मचा चुके सैफ-करीना ने आख़िरकार फिल्म एजेंट विनोद की रिलीज के वक़्त साफ कर दिया कि वे फ़िलहाल शादी नहीं कर रहे हैं. अब यह बात ज़ाहिर हो गई कि उन्होंने यह मैरिज स्टंट अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल किया. सैफ अली ख़ान का कहना है कि लोग उनके और करीना के कारण ही इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करेंगे कि हम रीयल लाइफ में कपल हैं, बल्कि एक फिल्म का हिट या फ्लॉप होना उसकी कहानी और प्रमोशनल इवेंट में कुछ कमी पर ही निर्भर करता है. सैफ का कहना है कि वह नहीं मानते कि उनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर इसलिए उतनी सफल नहीं हुई, क्योंकि वे रीयल लाइफ कपल हैं. फिल्में उनकी या करीना की वजह से नाकाम नहीं हुईं. उनकी फिल्में न चल पाने के पीछे ख़राब पटकथा और रिलीज का ग़लत समय जैसे कारण शामिल हैं. उन्होंने कहा, हम इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि वास्तविक जीवन के रिश्ते को फिल्माते वक़्त पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए. इस रिश्ते को बड़े पर्दे पर घिसे-पिटे तरीक़े से पेश नहीं किया जाना चाहिए. सैफ कहते हैं, फिल्म एजेंट विनोद की पटकथा और किरदार दमदार हैं. इसमें हम दोनों के रोल इस तरह रचे गए हैं कि लोग केवल फिल्मी किरदारों को देखेंगे और यह भूल जाएंगे कि हमारी जोड़ी फिल्मी पर्दे के बाहर कैसी है. सैफ ने उन ख़बरों को ख़ारिज किया कि उन्होंने करीना के कहने पर आगामी फिल्म रेस-2 की पटकथा में इसलिए बदलाव किया, क्योंकि उसमें उनके कुछ गर्मागर्म दृश्य थे. बकौल सैफ, करीना बहुत अच्छी कलाकार हैं और सिनेमा से प्यार करती हैं. वह एक समझदार लड़की भी हैं. वह मुझसे कभी नहीं कहेंगी कि फलां पटकथा बदल दो या फलां किरदार मत निभाओ.

**सैफ का कहना है कि वह नहीं मानते कि उनकी जोड़ी फिल्मी पर्दे पर इसलिए उतनी सफल नहीं हुई, क्योंकि वे रीयल लाइफ कपल हैं. फिल्में उनकी या करीना की वजह से नाकाम नहीं हुईं. उनकी फिल्में न चल पाने के पीछे ख़राब पटकथा और रिलीज का ग़लत समय जैसे कारण शामिल हैं.**

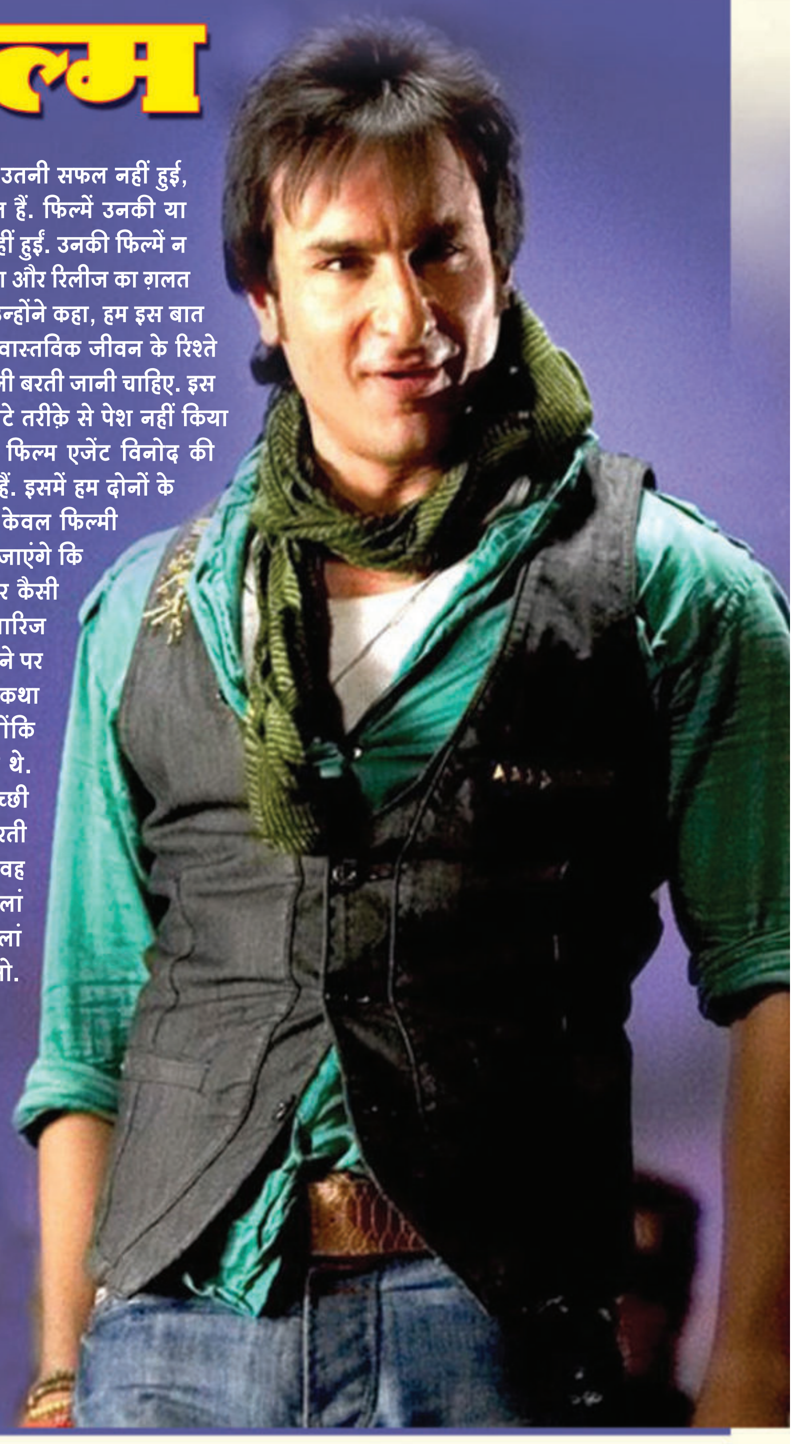

# महिमा की वापसी

बॉलीवुड में इन दिनों वापसी का दौर है. रवीना टंडन ने अभिनय की दुनिया में वापसी की तो करिश्मा कपूर ने भी एक फिल्म साइन कर ली. उनके दौर की एक अन्य अभिनेत्री महिमा चौधरी भी वापस आ गई हैं और इन दिनों मुम्भाई नामक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं. पिछले दिनों जब मुम्भाई के निर्माता ने महिमा के सामने फिल्म का प्रस्ताव रखा तो उन्हें अपना रोल पसंद आया और वह फ़ौरन मान गईं. फिल्म में महिमा के अलावा आर्य बब्बर, ओमपुरी और संजय कपूर हैं. सुभाष घई की फिल्म परदेस से अपना करियर शुरू करने वाली महिमा को बाद में बॉलीवुड में टिके रहने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा. जब उन्हें लगा कि करियर में कुछ बाक़ी नहीं रहा तो उन्होंने बॉबी मुखर्जी से विवाह कर लिया. महिमा चौधरी ने घर तो बड़े शौक से बसाया था, लेकिन जल्दी ही उसमें दरार पड़ गई. हालांकि यह तो बहुत पहले से सुनने में आ रहा था कि उनकी अपने पति बॉबी मुखर्जी के साथ बन नहीं रही है. दोनों की शादी क़रीब 6 साल पहले हुई थी और उनकी एक बेटी अरायना भी है. बॉबी एक फेमस आर्किटेक्ट हैं और महिमा के भाई के अच्छे दोस्त भी. वैसे इस शादी से पहले उनका एक डिवोर्स हो चुका था. महिमा के क़रीबी बताते हैं कि जब दोनों की मुलाक़ात हुई, तब महिमा लिएंडर पेस से अपने ब्रेकअप की वजह से अपसेट थीं और बॉबी में उन्हें एक अच्छा दोस्त नज़र आया. वैसे दोनों अपने-अपने स्तर पर अपने बीच की दूरी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके झगड़ों का कोई हल निकल नहीं रहा था. ऐसे में महिमा को लगा कि उनके लिए अलग रहना बेहतर है. इसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया. हालांकि यह अभी पता नहीं लगा है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है या नहीं.

**महिमा चौधरी ने घर तो बड़े शौक से बसाया था, लेकिन जल्दी ही उसमें दरार पड़ गई. हालांकि यह तो बहुत पहले से सुनने में आ रहा था कि उनकी अपने पति बॉबी मुखर्जी के साथ बन नहीं रही है. दोनों की शादी क़रीब 6 साल पहले हुई थी और उनकी एक बेटी अरायना भी है.**

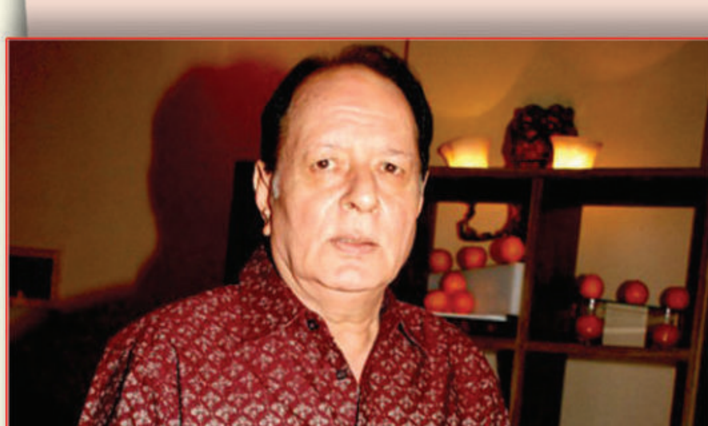

## नवीन निश्चल (जन्मदिन-11 अप्रैल)

# ग़रीबों का राजेश खन्ना

नई पीढ़ी ने उन्हें खोसला का घोसला जैसी फिल्म में एक ईमानदार कलाकार की भूमिका निभाने वाले शख्स के रूप में देखा, लेकिन अपने ज़माने में ग़रीबों का राजेश खन्ना नाम से मशहूर अभिनेता नवीन निश्चल की हैसियत कहीं बड़ी थी. पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से अदाकारी के गुर सीखने वाले नवीन इस संस्थान के पहले छात्र थे, जिन्हें स्वर्ण पदक मिला. 1970 में रेखा के साथ आई उनकी फिल्म सावन-भादो ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कामयाबी हासिल की और वह रातोंरात स्टार बन गए. उन्होंने धुंध, परवाना, विक्टोरिया नंबर 203 और बुड्ढा मिल गया समेत क़रीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया. बुड्ढा मिल गया फिल्म का उनका गीत-रात कली एक ख्वाब में आई आज भी सुना जाता है. नवीन निश्चल की आख़िरी फिल्म ब्रेक के बाद थी. नवीन निश्चल का पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण रहा और उसका असर भी उनके करियर पर पड़ा. उनकी दोनों पत्नियों से नहीं पटी. उनकी दूसरी पत्नी गीतांजली ने 2006 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. नवीन और उनके भाई प्रवीण पर उसने प्रताड़ना का आरोप लगाया था. इससे नवीन को गहरा धक्का पहुंचा था. नवीन का कहना था कि उनकी दूसरी पत्नी बेहद मूडी थी और उन्हें घर से भी बाहर निकाल चुकी थी. गीतांजली की भी यह दूसरी शादी थी. फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर नवीन की पहली पत्नी थीं. नवीन का नाम जब एक फिल्म अभिनेत्री से जोड़ा जाने लगा और बात हद से आगे बढ़ गई तो नीतू ने उनसे तलाक ले लिया. फिल्मी सफर में नवीन निश्चल का अपना दौर रहा और उनके चाहने वाले भी ख़ूब थे. नवीन ऐसे समय यह दुनिया छोड़ गए, जब एक अभिनेता के रूप में हिंदी सिनेमा उनका बहुत अच्छा उपयोग कर सकता था. जहां तक भूमिकाओं का सवाल है, वर्तमान दौर में सत्तर के दशक के फिल्मी सितारे अपने अभिनय जीवन के बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं. भले ही वे अब फिल्मों के नायक न बनाए जाते हों, पर उनमें से ज़्यादातर अभिनेता मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले युवा सितारों से फिल्म को अपने पक्ष में छीन रहे हैं.

नवीन निश्चल का फिल्मी जीवन मध्यमार्गी रहा. न वह बहुत बड़े सितारे बन पाए और न कभी ऐसा हुआ कि वह गुमनामी के अंधेरे में खो गए हों. उनके दौर के राजेश खन्ना, शशि कपूर, जीतेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा आदि ने लगभग उसी समय स्टारडम पा लिया था और इन सितारों के सामने नायक की भूमिका में स्टारडम पाना आसान नहीं था. सावन-भादो (1970, निर्देशक मोहन सहगल) जैसी हिट फिल्म से शुरुआत करके अगले पांच सालों तक नवीन को ठीक-ठीक सी फिल्में मिलीं, जिनमें परवाना (1971, निर्देशक ज्योति स्वरूप), बुड्ढा मिल गया (1971, निर्देशक हृषिकेश मुखर्जी), हंसते जख्म (1973, निर्देशक चेतन आनंद), धुंध (1973, निर्देशक बी आर चोपड़ा) और पैसे की गुड़िया (1974, निर्देशक ब्रज) प्रमुख हैं. विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा और एक से बढ़कर एक जैसी पूर्णतया व्यवसायिक श्रेणी एवं कई अभिनेताओं वाली फिल्में उन्हें इस काल में मिलीं और उन्होंने सफलता भी पाई. सत्तर का दशक ख़त्म होते-होते नवीन निश्चल को भी रहस्य-रोमांच वाली तथाकथित हॉरर फिल्मों में खींच लिया गया. 1980 में लेख टंडन की एक बार कहो, 1982 में बी आर इशारा की लोग क्या कहेंगे, 1980 में ही रवि चोपड़ा की द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में उन्हें मिलीं. उन्होंने कभी अपने अभिनय करने का तरीक़ा नहीं बदला और वह सौम्य-सहज चरित्रों के लिए उपयोगी बने रहे. उनका अभिनय निखरा राजू बन गया जेंटलमैन (1992, निर्देशक अज़ीज़ मिर्ज़ा) जैसी फिल्म से. उनकी इसी सौम्यता को सही ढ़ंग से प्रस्तुत किया टीवी धारावाहिकों ने, जिनमें देख भाई देख और फरमान प्रमुख हैं. देख भाई देख ने उनके अंदर कॉमेडी करने की संभावना भी जगाई, मगर उनके अभिनय जीवन का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन रिजर्व था खोसला का घोसला में एक वरिष्ठ रंगकर्मी बापू की भूमिका के लिए. यही एक भूमिका चिल्ला-चिल्ला कर कहती है कि आज वह सत्तर के दशक के अपने साथी कलाकारों, जो उस समय सुपर स्टार थे और आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, को जमकर टक्कर दे सकते थे. काश कि हिंदी सिनेमा खोसला का घोसला के बाद उनकी इस विकसित अभिनय प्रतिभा का भरपूर उपयोग कर पाता. दुनिया जब-जब खोसला का घोसला देखेगी, तब-तब नवीन निश्चल की याद आएगी. 19 मार्च, 2011 को दिल का दौरा पड़ने से नवीन का निधन हो गया, लेकिन उनके प्रशंसक-परिचित उन्हें हमेशा याद रखेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## फिल्म प्रीव्यू

### बिट्टू बॉस

कभी अजय देवगन के सचिव रहे कुमार मंगत ने अजय के सहयोग से स्वयं को निर्माता के रूप में स्थापित किया और उन्हें नायक के तौर पर लेकर कई फिल्मों का निर्माण किया. यशराज की बैंड बाजा बारात के बाद शादियों पर फिल्म बनाने की होड़ सी लग गई है. उसी की अगली कड़ी है निर्माता कुमार मंगत एवं अभिषेक पाठक की अगली फिल्म बिट्टू बॉस. छोटे पर्दे पर काम कर चुके अभिनेता पुलकित सम्राट इस फिल्म के ज़रिए बड़े पर्दे पर प्रवेश करने जा रहे हैं. एकता कपूर के टेलीविजन शो से करियर की शुरुआत करने वाले पुलकित बॉलीवुड में बिट्टू बॉस से अपना डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में उनका किरदार एक वीडियोग्राफर का है, जो शादियों में वीडियो बनाता है. उनका साथ दे रही हैं अमृता पाठक. बिट्टू बॉस एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसकी नायिका अमृता पाठक कुमार मंगत की बेटी हैं. उन्होंने पहले भी बॉलीवुड में अमृता को प्रवेश कराया था, लेकिन वह स्थान बनाने में नाकाम रहीं. अपनी बेटी को स्थापित करने के लिए कुमार मंगत ने इस बार बॉक्स ऑफिस पर आजमाया हुआ फार्मूला चुना है. उन्हें उम्मीद है कि इस फिल्म से अमृता बॉलीवुड में अपना मुक़ाम हासिल करने में कामयाब होंगी. फिल्म के निर्देशक एवं कहानीकार हैं सुपवित्र बाबुल.

# चौथी दुनिया महाराष्ट्र

दिल्ली, 09 अप्रैल-15 अप्रैल 2012

www.chauthiduniya.com


## चौथी दुनिया का एक साल का सफ़र

# कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास

प्रवीण महाजन

साप्ताहिक चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के प्रकाशन को 9 अप्रैल 2012 को एक वर्ष पूरे हो गए. इस दौरान हमारा यही प्रयास रहा कि चौथी दुनिया पत्रकारिता के मानदंडों और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी में खरा उतरे. हम पाठकों की कसौटी पर कितना खरा उतरे, यह तो सुधी पाठक ही बता सकते हैं, लेकिन हमारा मक़सद है- भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आम जनता के हक़ की लड़ाई लड़ना. उक्त उद्देश्य के साथ हमने प्रकाशन सामग्री का चयन किया. यह बात हमारे हर अंक में परिलक्षित होती है. इसके अलावा सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक क्रिया-कलापों व समसामयिक घटनाओं पर भी हमने दृष्टिपात किया. किसी भी मामले को उठाते समय चौथी दुनिया की भूमिका तटस्थ रही है. किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा गया और न ही पक्षपात किया गया. जो तथ्य सामने आए, उन्हें पाठकों तक पहुंचाया गया. एक नज़र चौथी दुनिया के एक वर्ष के सफ़र पर डालते हैं. आम आदमी की समस्याओं से जुड़ाव का पता चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के 11 से 17 अप्रैल के पहले अंक से चलता है, जिसकी पहली स्टोरी थी- विदर्भ सावधान, यह सुसाइड जोन है, जिसमें विदर्भ के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया. इस ख़बर में यह पड़ताल करने की कोशिश की गई है कि विदर्भ का किसान किस तरह सरकार के आधे-अधूरे प्रयासों के कारण कर्ज़ बाज़ारी के चक्रव्यूह में फंसता है और उस पर प्रकृति की मार, प्रशासनिक अनास्था आदि के कारण आत्महत्या करने को मज़बूर होता है. उसके अगले अंक 18 से 24 अप्रैल में महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में सत्तापक्ष-विपक्षी दलों की आपसी जुगलबंदी पर प्रकाश डाला गया. महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र, सब कुछ फिक्स्ड है शीर्षक से प्रकाशित स्टारी में. इसमें बताया गया कि हमारे विधायक-मंत्री गण विधानसभा के अंदर किस तरह टाइम पास करते हैं. 25 अप्रैल से 1 मई के अंक में जहां महाराष्ट्र की मराठी जनता की आकांक्षा को एक मराठी भाषी प्रधानमंत्री चाहिए स्टारी में व्यक्त किया गया, वहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साक्षात्कार- पारदर्शिता की पटरी पर विकास व 1 मई महाराष्ट्र दिवस पर विशेष सिर्फ ताकत बढ़ाने की सियासत के रूप में राज्य की राजनीतिक दशा-दिशा का विश्लेषण किया गया है. 2 से 8 मई के अंक में अमरावती ज़िले के किसानों पर दृष्टिपात किया गया है. अब प्यासे मरेंगे अमरावती के किसान में बताया गया है कि इंडिया बुल्स नामक कंपनी कैसे खेतों के हक़ के पानी पर डाका डाल रही है. 9 से 15 मई की चौथी दुनिया में नक्सल समस्या को रेखांकित करते हुए-नाजुक हाथों को लाल सलाम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. इसके अलावा विकास से बहुत दूर पारधी समाज, विदर्भ के किसानों का मनोविज्ञान भी साथ में हैं. 16 से 22 मई के अंक में कपास पणन महासंघ बर्ख़ास्तगी पर बवाल रिपोर्ट में महासंघ के बेकाम होने का ज़िक्र है और उस समय सरकार ने उसे बर्ख़ास्त करने का मन बना लिया था, लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते वह अपने निर्णय पर अमल नहीं कर सकी.

नागपुर बना बाघपुर रिपोर्ट में उप राजधानी को टाइगर हब बनाने की चर्चा का ज़िक्र किया गया है. 23 से 29 मई के अंक में बिजली की कमी या लापरवाही. उच्च शिक्षण संस्थानों का फर्ज़ीवाड़ा, आशियाने को तरसते पत्थर तराशने वाले, जैतापुर पर घमासान और जैतापुर पर उठे सवाल शीर्षकों से प्रकाशित रिपोर्टों में बिजली वितरण कंपनी, शिक्षा संस्थान संचालकों के छात्रवृति घोटाले और परमाणु संयंत्र के मुद्दे पर जैतापुर वासियों के संघर्ष को दर्शाया गया है. 30 मई से 5 जून के अख़बार में पर्यावरण पर विशेष फोकस किया गया है. सरकार नहीं जानती विकास क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना-समाधानों पर ग़ौर करने की ज़रूरत रिपोर्ट में सरकार की विकास नीति पर आक्षेप किया गया है और योजनाओं को बनाते समय, उससे पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान करने का सुझाव दिया गया है. 6 से 12 जून के अंक में गिराटा गांव- किसानों के साथ धोखा रिपोर्ट में बैंकों की कर्ज नीति के दोषों को दर्शाया गया है, तो बीपीएल कार्ड सूची- पूरी दाल ही काली है रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह योजना के पात्र लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है और अपात्र योजना का लाभ ले रहे हैं. 13 से 19 जून को आखिर जागे सांसद-मंत्री, विदर्भ ताप बिजली परियोजनाओं की पुनर्समीक्षा होगी रिपोर्ट में यवतमाल में आयोजित पानी परिषद में सत्ताधीशों की घोषणाओं का विश्लेषण किया गया है. साथ ही नागपुर स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय में इंस्पेक्टर राज में लिए जा रहे ग़ैरक़ानूनी निर्णय का खुलासा किया गया है. 20 से 26 जून को शराब और उसके लत से ग्रसित लोगों की मानसिकता पर प्रकाश डालती रिपोर्ट शराबियत ख़तरनाक बीमारी, सीमाएं टूट रही हैं प्रकाशित की गई. इसके अलावा नागपुर के गांधीसागर तालाब पर तालाब मांगे खून स्टोरी में बताया गया है कि, किस तरह एक ऐतिहासिक तालाब आत्महत्या के लिए कुख्यात हो गया. चौथी दुनिया के 27 जून से 3 जुलाई के अंक में शिक्षा की समस्याओं को विशेष तौर पर रेखांकित करती हुई-सरकार ने रोके शिक्षा के द्वार और फीस पर अंकुश आसान नहीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. 4 से 10 जुलाई में विदर्भ की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना के पहलुओं को टटोला गया है. इस पर संपूर्णता की ओर विदर्भ का स्वप्न और वो शर्मनाक 25 साल, किसी और का न हो ऐसा हश्र गोसीखुर्द परियोजना की दास्तान को उजागर करती है, तो साथ ही जे.डे. हत्याकांड- बेशर्म सरकार, निर्लज्ज पुलिस में सरकार व घटनाक्रम को लेकर बार-बार बदलते बयान पर टिप्पणी की गई है. 11 से 17 जुलाई के अंक में राजनीति में स्वार्थी तत्वों के बढ़ते वर्चस्व पर आघात करते हुए- स्वार्थतंत्र में लोकतंत्र गुम लिखा गया है. 18 से 24 जुलाई के अंक में कन्या भ्रूण हत्या पर माता हुई कुमाता और नकोशियों का दर्द आलेख में अनचाही पुत्रियों यानी नकोशियों के मुद्दे को चौथी दुनिया राज्य में विस्तार से उठाने वाला पहला अख़बार था. इसके साथ ही रेव पार्टी मुंबई-पुणे और अब सारे देश में युवा पीढ़ी में नशे के बढ़ते क्रेज को रेखांकित किया गया है. बढ़ता अंग्रेजी क्रेज, घटता मराठी मोह में मराठी भाषा की उपेक्षा पर टिप्पणी की गई है. 25 से 31 जुलाई के अंक में वामपंथी दलों की

शेष पृष्ठ 18 पर

**आम आदमी की समस्याओं से जुड़ाव का पता चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के 11 से 17 अप्रैल के पहले अंक से चलता है, जिसकी पहली स्टोरी थी- विदर्भ सावधान, यह सुसाइड जोन है, जिसमें विदर्भ के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया. इस ख़बर में यह पड़ताल करने की कोशिश की गई है कि विदर्भ का किसान किस तरह सरकार के आधे-अधूरे प्रयासों के कारण कर्ज़ बाज़ारी के चक्रव्यूह में फंसता है और उस पर प्रकृति की मार, प्रशासनिक अनास्था आदि के कारण आत्महत्या करने को मज़बूर होता है. उसके अगले अंक 18 से 24 अप्रैल में महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में सत्तापक्ष-विपक्षी दलों की आपसी जुगलबंदी पर प्रकाश डाला गया. महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र, सब कुछ फिक्स्ड है शीर्षक से प्रकाशित स्टारी में. इसमें बताया गया कि हमारे विधायक-मंत्री गण विधानसभा के अंदर किस तरह टाइम पास करते हैं.**

DML DAILY MULTIMEDIA LTD.

BODY ART
PERMANENT Tattoo
Flat 60% off
800 Rs. per sq. inch
Rs. 320 per sq. inch
Female Artist: Manisha
9167763369 / 9930756810
Plot No 542, Room No D1, Near Oxford School, Charkop, Kandivali (W), Mumbai 52

DML DAILY MULTIMEDIA LTD.

ESTD 1962
Aalis SHOES
upto 50% off &
Rs. 299 /- and Rs. 399 /-
on selected ladies footwears
7, Jai Mahal, 502, Linking Road, Khar (W), Mumbai 52

महानगर पालिका क्षेत्र में भी इस आवास योजना की तस्वीर अलग नहीं है. वहां भी इस योजना का बंटाधार अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण हो रहा है.

## महाराष्ट्र हलचल

केम्द्र सरकार द्वारा सोने के आयात और उत्पादन शुल्क में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी करने पर कैंडल मार्च निकाल कर विरोध करते अकोला के सर्राफा व्यवसायी.

बुलढाना ज़िले की मेहकर तहसील में श्री स्वामी समर्थ महाराज की पालकी शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालु.

वाशिम ज़िले की कारंजालाड तहसील में स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना के तहत आयोजित कार्यकम में महिला बचत गट की सदस्यों को धनादेश प्रदान करते नगराध्यक्ष संजय काकड़े व उपाध्यक्ष एजाज खां और उपस्थित महिला सदस्य.

नागपुर ज़िला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष सौ. संध्याताई गोतमारे का पदभार ग्रहण करने पर स्वागत करते जि.प. सदस्य.

अमरावती ज़िले के शिराला गांव से ताल–मृदंग बजाते व भजन गाकर संतनगरी शेगांव जाते श्रद्धालु.

ज़िंदगी की आपाधापी में चुस्त-दुरुस्त रहने के लिए मूल स्थित रामलीला भवन के प्रांगण पर सामूहिक योगाभ्यास करते लोग.

यवतमाल ज़िले में दो ग्रामसेवकों की संदेहास्पद मौत होने की जांच करने की मांग को लेकर मोर्चा निकालते ज़िले के ग्रामसेवक.

गोंदिया ज़िले के काचेवानी गांव में अदानी फाउंडेशन द्वारा आयोजित महिला सम्मेलन को संबोधित करती जि.प. सदस्य राजलक्ष्मी तुरकर व उपस्थित महिलाएं.

## चौथी दुनिया का एक साल का सफ़र

# कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास

पृष्ठ 17 का शेष

परिस्थिति पर–एक बार फिर चाहिए– वामपंथ व समाजवाद में प्रकाश डाला गया है. 1 से 7 अगस्त के चौथी दुनिया में आतंकवाद बनाम सरकारवाद–कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं रिपोर्ट में राज्य में हो रहे सतत आतंकवादी हमलों और उससे निपटने की सरकारी नीति पर विचार–विमर्श किया गया है. इसके अलावा शिक्षा सहयोग बीमा योजना में चल रहे आर्थिक कदाचार और सरकारी स्कूल का अस्तित्व संकट में शासन–प्रशासन की उदासीनता को प्रकट किया गया. 8 से 14 अगस्त में नागपुर की जल समस्या पर विशेष रूप से ग़ौर करते हुए प्यासा रह जाएगा नागपुर– बिछ रही है पाइप लाइन रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है. 15 से 21 अगस्त के अंक में ख़तरे में बांध रिपोर्ट में राज्य के बांधों पर नक्सली और आतंकवादी हमलों की खुफिया एजेंसियों की आशंकाओं का विश्लेषण किया गया है. साथ ही शिक्षा पर ग़रीबों का हक़, भारत को लहूलुहान करने की साज़िश पर लिखा गया है. 22 से 28 अगस्त को नए भू– अधिग्रहण अधिनियम पर दृष्टिपात किया गया है–छलावा न हो– भू–अधिग्रहण और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों द्वारा आयोजित बंद को गढ़चिरोली ज़िले के आदिवासियों द्वारा चुनौती दिए जाने का अवलोकन किया गया है. 29 अगस्त से 4 सितंबर के चौथी दुनिया में मावल में हुए गोलीकांड पर सरकारी गोली के निशाने में पर किसान, आश्रमशालाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए सरकारी आश्रम शाला रामभरोसे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. 5 से 11 सितंबर में राहुल के दौरे से क्या बदल जाएंगे मावल के हालात में मावल गोलीकांड में सत्तारूढ़ दल द्वारा की जा रही राजनीति का विवेचन किया गया है. इसके अलावा उफान पर है शराब का सुरूर में सरकार की आबकारी नीति का पोस्टमार्टम किया गया है. राजनीति पर ज़िला परिषद चुनाव की किलेबंदी और अजीत पवार को कब समझा आएगी हैं. 12 से 19 सितंबर के चौथी दुनिया में अभियंता दिवस पर विशेषतौर पर अभियांत्रिकी के पितामह डॉ. विश्वेश्वरैया के जीवन पर प्रकाश डाला गया है. इसके अलावा किसानों पर बिजली की मार और घर बचा लो नितिन जी रिपोर्ट महावितरण कंपनी की किसानों के प्रति असंवेदनशील रवैये को उजागर किया गया है तथा भाजपा की अंतर्कलह को रेखांकित किया है. 19 से 25 सितंबर के अंक में महाराष्ट्र को खोखला करता भ्रष्टाचार और बृहन्मुंबई की परिसंपत्तियां ख़तरे में में बढ़ते भ्रष्टाचार व मुंबई मनपा प्रशासन की लापरवाही से परिसंपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ों के ग़ायब होने के मामले को जनता के सामने लाया गया है. 26 सितंबर से 2 अक्टूबर को बिजली प्रकल्प सोखेंगे नदियों का पानी–विदर्भ में पावर प्रोजेक्टों की बाढ़ रिपोर्ट में सरकार की विदर्भ के प्रति ग़ैरज़िम्मेदार तरीके से पावर प्लांटों को मंजूरी दिए जाने के मामले को लक्षित किया गया है. साथ ही बीपीएल सूची में निरंतर जारी गड़बड़ियों को पुनः सामने लाया गया है. दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर– नगर पालिका चुनाव में राजनीतिक दांव–पेंच का उल्लेख किया गया है. 3 से 9 अक्टूबर में शिक्षण संस्थाओं ने अनुदान लूटा में बोगस छात्रों के नाम पर सरकारी खजाने को लूटने का ज़िक्र है. चुनावी राजनीति पर गठबंधन मजबूरी–प्रभाग रचना से कई नेताओं का भविष्य अधर मे रिपोर्ट प्रकाशित की गई है. विदर्भ के अनुशेष पर केलकर समिति–जनसुनवाई के नाम पर रस्म अदायगी और इसके साथ ही शिक्षा पर माफिया राज–डी.वाई. पाटिल ग्रुप की हक़ीक़त को निष्पक्षता के साथ पाठकों के सामने रखा गया है. 10 से 16 अक्टूबर के अंक में चिंता वोटों की, किसानों की नहीं रिपोर्ट में भू–विकास बैंक की आर्थिक बदहालियत का कौन ज़िम्मेदार हैं, इस पर से पर्दा उठाया गया है. वन मज़दूरों की भविष्य निधि संकट में–चंद्रपुर के वन्य मज़दूरों की कई सालों से भविष्य निर्वाह निधि को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हजम करने के मामले का खुलासा किया गया है. एसआईटी के दोषी अधिकारियों को सजा मिले में एसआईटी की कार्रवाई की ख़ामियों पर आक्षेप किया गया है. 17 से 23 अक्टूबर के अंक में नदी जोड़ परियोजना–किसान खुशहाल होंगे रिपोर्ट में नदियों के पानी का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इसका ज़िक्र किया गया है. आज देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से नदियों के जोड़ने पर अपनी नीति स्पष्ट करने को कहा है. 24 से 30 अक्टूबर के चौथी दुनिया में कुपोषण का दुष्चक्र–योजनाओं में लूट में कुपोषित बच्चों, महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की विफलता के कारणों को रेखांकित किया गया है. 31 अक्टूबर से 6 नवंबर में शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार– चालीस लाख फर्ज़ी छात्र मिले में, छात्र गणना के मामले पर विचार व्यक्त किए गए हैं. साथ ही अधिकारियों की लापरवाही से बिजली संकट गहराया में यह उजागर किया गया है कि, किस तरह अधिकारी जब चाहे बिजली संकट को बढ़ा देते हैं और बिजली दर बढ़ाने का दबाब बनाते हैं. 7 से 13 नवंबर में

घर को आग लग गई, घर के चराग से में रथयात्रा के साथ नागपुर पधारे भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा व्यक्त विचारों पर टिप्पणी की गई है. 14 से 20 नवंबर में ग़रीबो के प्रति शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता पर सवाल खड़े करते हुए लिखा गया–कौन दूर करेगा ग़रीबों का दर्द. शिक्षा माफिया पर नकेल, स्कूलों में बायोमेट्रिक हाज़िरी होगी सरकार की नीति की सराहना की गई है. 21 से 27 नवंबर के अंक में नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते है आलेख में भाजपा नेता की आस और मराठी जनता की अपेक्षा को रेखांकित किया गया है. इसके साथ ही राज्य के बीड़ी मज़दूरों की दुर्दशा पर बीड़ी मज़दूरों का भविष्य अंधकार में रोशनी डाली गई है. 28 नवंबर से 4 दिसंबर में लवासा को मंजूरी, जनता के साथ धोखा में किस तरह सरकार लवासा के मामले में क़ानून भूलकर मंजूरी दिलाने में जुटी रही है, इस ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया गया है. साथ ही सैकड़ों लोग बचा रहे करोड़ों की वन संपदा आलेख में लोणारा गांव वासियों की पर्यावरण व वन संपदा के लिए संघर्षरत रहने की कथा व्यथा है. 5 से 11 दिसंबर के अंक में सरकार व प्रशासन से सवाल किया गया है– किसान आत्महत्या कब रुकेगी? उप राजधानी के सफाई कर्मियों की व्यथा व्यक्त की गई है, सफाई कर्मियों की सुध कौन लेगा? इसके अलावा सहकारी बैंकों का गोरखधंधा उपराजधानी में शीतकालीन सत्र के निहितार्थ, किसान आंदोलन का राजनीतिकरण न हो पर प्रकाश डाला गया है. 12 से 18 दिसंबर के चौथी दुनिया में विदर्भ के किसानों का भविष्य अंधकारमय, कर्ज में डूबी विदर्भ की महानगर पालिकाएं, नागपुर बस नाम की उपराजधानी, कोयले का खनन अभयारण्य के लिए ख़तरा आदि आलेख उल्लेखनीय रहे हैं. 19 से 25 दिसंबर में प्रफुल्ल भी भूले किसानों को, गन्ना अपना–सौतेला धान, अनुदान लूटने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं?, सिकलसेल– बीमारों की सुध नहीं ले रही सरकार और ज़मीन घोटाला– बिल्डर–ठकेदार और प्रशासन का गठजोड़ आदि में आम आदमी के प्रति शासन–प्रशासन के रुख और उसमें चल रहे भ्रष्टाचार को रेखांकित किया गया है. 26 दिसंबर से 1 जनवरी के अंक में नागपुर में अधिकतर निर्माण ग़ैरक़ानूनी– करोड़ों का घोटाला में रियल स्टेट व्यवसाय के नाम पर हो रहे गोरखधंधे पर प्रकाश डाला गया है. इसके अलावा नक्सली कर रहे महिलाओं की भर्ती व वालमार्ट मॉल का निर्माण शुरू–एफडीआई पर रोक कितनी कारगर में सरकारी नीति पर प्रहार किया गया है. 2 से 8 जनवरी में किसानों को भीख नहीं कपास चाहिए में सरकार की पैकेज नीति पर सवाल खड़े किए गए हैं. इसके साथ ही दलित राजनीति– श्रेय लेने की होड़ मची में इंदु मिल प्रकरण पर प्रकाश डाला गया है. 9 से 15 जनवरी के अंक में विधानमंडल का शीतसत्र– विदर्भ की झोली में क्या आया? में विधानमंडल के सत्र में सरकार के कामकाज का लेखाजोखा किया गया है. इसके अलावा करोड़ों का स्टार बस घोटाला, साहूकारों ने हड़पी हज़ारों एकड़ ज़मीन और आश्रमशाला बना भ्रष्टाचार का केंद्र आदि आलेख भी हैं. 11 से 22 जनवरी में राज्य सरकार की नई वस्त्रोद्योग नीति, विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के साथ धोखा का विवेचन किया गया है. नदियों में बह गए 200 करोड़ रुपये में सरकार की नदियों के प्रदूषित होने के प्रति उदासीनता पर नज़र डाली गई है, तो करोड़ो का बिजली घोटाला और पानी के बदले ज़हर पी रहे हैं हज़ारों परिवार में आम आदमी की दुश्वारियों को रेखांकित किया गया है. 23 से 29 जनवरी के अंक में महानगर पालिका–ज़िला परिषद चुनाव की राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन किया गया है, बागी बिगाड़ेंगे खेल, गठबंधन पर संशय बरकरार, पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में घुसपैठ की सुरक्षा पर दृष्टिपात किया गया है. 30 जनवरी से 5 फरवरी के चौथी दुनिया में मंत्रियों की लापरवाही से विकास कार्य ठप में बताया गया है कि निधि उपलब्ध होने पर भी हमारे मंत्री उसको साल भर में ख़र्च नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें वित्तीय नियोजन की दृष्टि का अभाव रहता है और करोड़ों की रक़म बेकार पड़ी रहती है. इसके साथ ही 50 फ़ीसदी लड़कियां एनीमिया की शिकार, होमगार्ड के जवान उपेक्षा के शिकार हैं और महाराष्ट्र के नौकरशाह भ्रष्ट हैं आलेख भी हैं. 6 से 12 फरवरी में मनपा चुनाव की राजनीति पर बागियों ने बढ़ाई नेताओं की परेशानी, रेल प्रशासन मस्त, यात्री हलकान–पश्चिमी विदर्भ के चार रेलवे स्टेशन बंद, शिक्षा माफियाओं को नेताओं का संरक्षण और क्या विदर्भ की महिलाएं ला पाएंगी बदलाव आदि आलेख हैं. 13 से 19 फरवरी में बारामती–बंधुआ मज़दूरों की सुध कौन लेगा में आज भी इस कुप्रथा के जारी रहने पर रोशनी डाली गई है. इसके अलावा अच्छी शिक्षा के नाम पर करोडों की लूट में नर्सरी व केजी कक्षा में एडमिशन के नाम पर चालू कॉन्वेंट के गोरखधंधे पर प्रहार किया गया है. महाराष्ट्र के उद्योग कर्नाटक की राह पर, नकली बीजों से हज़ारों किसान बर्बाद, दिल से नहीं दिमाग से वोट करें पर भी टिप्पणियां की गई हैं. 20 से 26 फरवरी के अंक में वक्फ़ की ज़मीन पर कॉरपोरेट घरानों का कब्ज़ा और एमईटी बना भुजबल के गले की फांस में पावर–पैसे के गोलमाल पर से पर्दाफाश किया गया है. 27 फरवरी से 4 मार्च में इन माननीयों को शर्म नहीं आती में विलासराव देशमुख द्वारा मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग कर फिल्म निर्माता सुभाष घई को ज़मीन आवंटित करने पर न्यायालय की तल्ख टिप्पणियों के आलोक में सत्ताधीशों के मनमानी निर्णय पर फोकस किया गया है. मल्टीप्लेक्स से डूबा करोड़ों का टैक्स, अमरावती विभाग में पदोन्नति घोटाला और किसानो पर थोपी गई पैसेवारी ब्रिटिशकालीन पैसेवारी पद्धति से किसान परेशान में बताया गया है कि कैसे अंग्रेजों की शोषण नीति को बरकरार रखा गया है. 5 से 11 मार्च के अंक में चुनाव नतीजों की उलटबांसी शुरू में मनपा–जिप चुनाव के बाद राजनीति गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है. एक पत्र ने उड़ाई बड़े–बड़ों की नींद– अरबों की बिजली में करोड़ों का घोटाला , मनरेगा जी का जंजाल बनी और शहीदों की उपेक्षा में संबंधित विभाग व योजनाओं की ख़ामियों को उजागर किया गया है. 12 से 18 मार्च के अंक में एक सब्जी बेचने वाले के करोडपति बनने की कथा, कृपाशंकर पर राजकीय कृपा का आलेख पाठकों की दृष्टि से रोचक रहा है. भीषण जल संकट के मुहाने पर विदर्भ–मराठवाड़ा, नक्सलियों के समक्ष नतमस्तक प्रशासन और नोट छापने वाली पुरानी मशीनें कहां गई आलेख भी उल्लेखनीय रहे. 19 से 25 मार्च के चौथी दुनिया में अब इंडिया बुल्स ने छीना नासिक के किसानों का पानी में बताया गया है कि, किस तरह एक निजी कंपनी सत्ता के संरक्षण में राज्य के हितों को नुक़सान पहुंचाने का प्रपंच करती है. इसके साथ ही करोड़ों के पैकेज के बावजूद किसान बदहाल, पैकेज का खेल फेल में किसानों से सरकारी छल की दास्तान दी गई है. 25 मार्च से 1 अप्रैल के एक अंक में क़ानूनी फंदे में एक और दिग्गज में क़ानून से खुद को ऊपर समझने वाले एक राजनेता के कारनामों का उल्लेख है. इसके अलावा राजनीति पर दो दिग्गजों के मिलन पर डिनर डिप्लोमेंसी है तो किसानों के नाम पर चल रही बीमा योजना पर जनता बीमा योजना का फ़ायदा किसे और रामनवमी के अवसर पर विशेष है, राम होने का मर्म. पूरे एक साल के चौथी दुनिया के महाराष्ट्र संस्करण के अंकों का अवलोकन करने के दौरान यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि, हमने जो कुछ लिखा है वह निडरता से सच्चाई के पक्ष में लिखा है. किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल का आइना बन कर नहीं रहे हैं. हमारी कलम सभी पर सामान रूप से चली है. किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह रखे बिना लिखा गया है. यह सब हो सका है चौथी दुनिया के सुधी पाठकों, हॉकरों, एजेंटों और विज्ञापनदाताओं के असीम सहयोग और आशीर्वाद से. इसलिए हम संत कबीर के शब्दों में कह सकते हैं–कबीरा खड़ा बाज़ार में, मांगे सबकी ख़ैर। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।। हम बाज़ार में खड़े हैं निर्लिप्त भाव से. हमारी किसी से कोई दोस्ती–दुश्मनी नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

# निधि है, लेकिन घरकुल नहीं

अकोला ज़िला प्रशासन के निकम्मेपन के कारण यहां के ग़रीब जन को घरकुल (आवास) योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार की ओर से योजना के तहत घरकुल निर्माण के लिए करोड़ों की राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन जिस विभाग के जरिए यह कार्य होना है, उसके अधिकारी समय पास करते नज़र आते हैं, मानों उनका काम से कोई वास्ता ही न हो. इसका ख़ामियाज़ा उन हज़ारों पिछड़े ग़रीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें यह आस है कि सरकारी मदद से उन्हें सपनों का घर न सही, लेकिन रहने के लिए एक अदद घर मिल जाएगा. वैसे उनकी यह आस पूरी होती नज़र नहीं आती है. सरकार ने अनुसूचित जाति और नवबौद्ध घटकों के कल्याण के लिए विशेषतौर पर आवास योजना बनाई है. इस योजना के तहत सरकार घरकुल बनाकर अनुसूचित जाति व नवबौद्धों को आवंटित करेगी. योजना का उद्देश्य यह है कि विकास से वंचित ग़रीबों को उनका हक़ दिलाने के लिए और उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए. सरकार द्वयह योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से संचालित कर रही है. योजना का लाभ पाने वाले अनुसूचित जाति व नवबौद्धों का चयन बीपीएल सूची के क्रमांक अनुसार किया जाता है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए 70 हज़ार रुपये, नगर पालिका के लिए डेढ़ लाख रुपये और महानगर पालिका क्षेत्र में घरकुल निर्माण के लिए पौने दो लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है. आकोला ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष 2010–11 के लिए 2,419 घरकुलों का निर्माण करने को शासन से मंजूरी प्रदान की गई थी, जिनमें 1300 घरकुलों का निर्माण हुआ है, बाकी का काम प्रलंबित है.उसी तरह वर्ष 2011–12 के लिए शासन ने ग्रामीण भाग में 4,500 घरकुलों को बनाने की मंजूरी दी थी, जिनमें से 3,778 का निर्माण कार्य शुरू है और बाकी का तो कार्य भी शुरू नहीं हुआ है.

> सरकार ने अनुसूचित जाति और नवबौद्ध घटकों के कल्याण के लिए विशेषतौर पर आवास योजना बनाई है. इस योजना के तहत सरकार घरकुल बनाकर अनुसूचित जाति व नवबौद्धों को आवंटित करेगी. इस योजना का उद्देश्य यह हैं कि, विकास से वंचित ग़रीबों को उनका हक़ दिलाने के लिए, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए. सरकार यह योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के माध्यम से संचालित कर रही है.

विशेष बात यह है कि, जिन घरकुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनका आवंटन भी अब तक नहीं किया गया है और जिन घरकुलों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है पता नहीं कब उनका काम शुरू करने का मुहूर्त प्रशासन निकालेगा. इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र के लिए वर्ष 2010–11 में 41 घरकुलों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अंतिम चरण की 10 प्रतिशत राशि न मिलने के कारण काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है. वर्ष 2011–12 में ज़िले में 1000 घरकुल बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्रशासन के सामने रखा था और इसके लिए साढ़े सात करोड़ रुपये की राशि भी सरकार द्वारा जारी की गई थी. इस मामले में ज़िला व तहसील प्रशासन भी पूरी तरह सुस्त नज़र आता है. ज़िले की मात्र तेल्हारा व अकोट नगर पालिका ने इस कार्य में प्रगति की है बाकी जगहों पर नगर पालिका मुख्य अधिकारी द्वारा अब तक सर्वेक्षण फाइल ज़िला प्रशासन के पास नहीं भेजी गई है. नतीजतन ज़िला समिति से अब तक घरकुल निर्माण को मंजूरी नहीं दी गई है. इसका मतलब तो यही हुआ कि, योजना के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों की निधि उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के कारण इस योजना का लाभ पिछड़े ग़रीब लोगों को नहीं मिल रहा है. महानगर पालिका क्षेत्र में भी इस आवास योजना की तस्वीर अलग नहीं है. वहां भी इस योजना का बंटाधार अधिकारियों के निकम्मेपन के कारण हो रहा है. महानगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में मंजूर किए गए 44 घरकुलों का निर्माणकार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि वर्ष 2011–12 में एक हज़ार घरकुलों में से सिर्फ 112 को मंजूरी प्रदान की गई है, उनका निर्माणकार्य शुरू करने का मुहूर्त प्रशासन अब तक नहीं निकाल पाया है. इस संबंध में, जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, तो पता चला कि योजना के लिए निधि उपलब्ध है, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया है. काम शुरू नहीं हो पाने का कारण बताने में वे टालमटोल करते दिखाई दिए. इसमें सबसे बड़ा कारण तो प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता नज़र आती है. इसके साथ ही समयबद्ध कार्य न होने से प्रति घरकुलों की लागत बढ़ने की बात भी कही गई. इसके अलावा राजनीतिक अड़ंगेबाजी होने की बात भी दबी जुबान अधिकारियों ने कही. इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, सरकार चाहे योजना कितनी अच्छी क्यों न बनाए, जब तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं चाहेंगे उस पर काम नहीं होगा. इस प्रशासनिक उदासीनता का ख़ामियाज़ा ज़िले के हज़ारों ग़रीब पिछड़े अनुसूचित जाति व नवबौद्धों को भुगतना पड़ रहा है. इन हालात में भला ग़रीबों का उद्धार कैसे होगा?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## अमरावती मनपा का नया उपक्रम

# जोशी- द्वारकानाथ मॉल

मेघनाथ अरोड़ा

अमरावती महानगर पालिका ने अपने निर्माण से लेकर अभी तक शहर के सौंदर्यीकरण के बहाने छह बड़े-बड़े मार्केट बनाए हैं और दुर्भाग्य से सभी विवादग्रस्त रहे हैं. पिछली महानगर पालिका वर्ष 2007 से वर्ष 2012 तक अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाकर भी द्वारकानाथ/जोशी मॉल का उद्घाटन समारोह आयोजित करने मे सफल नहीं हो पाई. अब चुनाव संपन्न होने के बाद नवगठित महानगर पालिका पर नवनिर्वाचित 87 नगरसेवक व 5 मनोनीत नगरसेवक सत्ता पर विराजमान हैं. इन नवसत्ताधारी नगरसेवकों से अमरावती की जनता को शहर को स्वच्छ-सुंदर बनाने के साथ कई अपेक्षाएं भी हैं, जिनमें एक महिला के लोकप्रिय पुरानी मार्केट की जगह निर्मित द्वारकानाथ/जोशी मॉल के शीघ्र शुभारंभ होने का सपना है. नजूल शिट क्र. 68 डी भू.क्र. 81 पर महिलाओं में ख़रीददारी के लिहाज से लोकप्रिय एक बहुत पुरानी मार्केट हुआ करती था, जो जोशी मार्केट के नाम से प्रसिद्ध था. अमरावती के वीर-सेनानी, स्वतंत्र सैनिक व समाजसेवक वीर वामनराव जोशी के नाम पर उस मार्केट का निर्माण वर्षों पहले किया गया था, जिसमें 36 दुकानदार तल मंजिल पर थे और 13 लीजधारक पहली मंजिल पर. सभी को पुनः विस्थापित करते हुए नये मॉल के निर्माण की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी. उसके पश्चात जोशी मार्केट के मुख्यद्वार के साथ सरकार की ज़मीन पर नजूल शिट क्र. 68 डी के भू.क्र. 75/2 से 75/15 पर बनी पक्की दुकानें जिसे लाला द्वारकानाथ अरोड़ा मार्केट के नाम से जाना जाता था, उसका समावेश नये मॉल में करने का प्रस्ताव मनपा में पारित किया गया था. अंततः सभी दुकानदारों को अस्थायी व्यवस्था के रूप मे राजापेठ स्थित महानगर पालिका के निर्माणाधीन मार्केट में स्थानांतरित किया गया और 18 माह के भीतर इस नए जोशी/द्वारकानाथ मॉल को पूर्ण करने की घोषणा की गई. मार्च 2006 में एक दस्तावेज़ बनाकर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट किया गया. एग्रीमेंट में नवनिर्मित मार्केट 12 से 18 माह के भीतर बनाकर तैयार करने से लेकर, माहवारी भाड़ा व निर्माण की रक़म तक तय कर दी गई थी. इस दस्तावेज़ की आत्मिक शर्त थी कि, नए मॉल के निर्माण के बाद उन्हीं दुकानदारों को वहां पुनः स्थापित किया जाएगा, जो वहां पहले से मौजूद थे और ठेकेदार का उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रहेगा. दुकानदारों के वर्तमान अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और सिर्फ़ मासिक भाड़े की दर प्रत्येक 15 वर्ष के बाद 5 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. नागपुर की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सौ. एस. महुगांवकर द्वारा तैयार नक्शे की प्रति भी एग्रीमेंट के साथ जोड़ी गई थी. महानगर पालिका ने टेंडर निकालकर बीओटी तत्व पर एस. नवीन बिल्डर्स पी.एम. चोरड़िया (जेवी) वीनस पार्क, शेगांव नाका, अमरावती को मॉल निर्माण का ठेका दिया गया और इस कंपनी ने नागपुर के आर्किटेक्ट कोकाटे एसोसिएट्स, 20 बजाज नगर, नागपुर द्वारा 7 जून 2006 को तैयार नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया. इसी बीच वर्ष 2007 में ज़िलाधिकारी से द्वारकानाथ मार्केट की ज़मीन महानगर पालिका द्वारा भू.क्र. 75/2 से 75/15 तक पाने की कार्रवाई शुरू की गई. यह भूखंड 14 दुकानदारों से पावर ऑफ अटार्नी लेकर मांगा गया था. वास्तव में 1620 वर्ग फुट प्लॉट का यह भूखंड श्रीनाथ को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी को ज़मीन की पूरी क़ीमत अदा करने पर ज़िलाधिकारी ने वर्ष 2025 तक के लिए लीज पर दिया था. सोसाइटी को दरकिनार कर दुकानदारों को इस मॉल में दुकानें देने का काम महानगर पालिका प्रशासन अब कर रहा है. इससे नवनिर्मित मॉल को लेकर एक और नया विवाद शुरू हो गया है. चर्चा है कि ज़िलाधिकारी इस नए विवाद पर गुप्त रूप से जांच करा रहे हैं. महानगर पालिका को ज़मीन सम्बंधी लीज प्राप्त हुई है या नहीं, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है. शायद इसी कारण से जोशी/द्वारकानाथ मॉल का शुभारंभ होने में देर हो रही है. निर्माण की वैधता पर प्रश्नचिन्ह ठेकेदार ने कई बार नक्शे में परिवर्तन किया और सैंया भये कोतवाल तो, अब डर काहे का. कहावत को चरितार्थ करते हुए निर्माण कर डाला. आयुक्त का अंतिम आदेश 30 जून 2009 को जारी हुआ था और नक्शा हुक्मनामा क्र. 376 दिनांक 4 जुलाई 2009 को मंजूर किया गया था. ठेकेदार के अनुसार उसने अपने एग्रीमेंट में निश्चित समयानुसार दंड से बचने के लिये निर्माण पूर्ण करके महानगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया है. उधर महानगर पालिका प्रशासन, सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग और सहायक संचालक, नगर रचना विभागों में आपस में अनेक मुद्दों पर असहमति बनी हुई है. इस मॉल के निर्माण की वैधता और ज्यादा लागत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. अभी तक उसको निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है. नई स्थायी समिति गठन पश्चात नये सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद नये सिरे से एग्रीमेंट होने की संभावना है. इस मामले से जुड़े पक्षकारों ने न्याय के लिए उच्च न्यायालय के द्वार पर कई बार दस्तक दे चुके हैं. विधायक रावसाहब शेखावत इस मॉल का मुद्दा विधानसभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन लगता है कि विवादों में उलझे इस मॉल के उद्घाटन का मुहूर्त मनपा प्रशासन नहीं निकाल पाया है. इसलिए जोशी/द्वारकानाथ मॉल कितना बना है कितना अनबना है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हैं.

**दुकानदारों के वर्तमान अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा और सिर्फ़ मासिक भाड़े की दर प्रत्येक 15 वर्ष के बाद 5 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी. नागपुर की प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सौ. एस. महुगांवकर द्वारा तैयार नक्शे की प्रति भी एग्रीमेंट के साथ जोड़ी गई थी. महानगर पालिका ने टेंडर निकालकर बीओटी तत्व पर एस. नवीन बिल्डर्स पी.एम. चोरड़िया (जेवी) वीनस पार्क, शेगांव नाका, अमरावती को मॉल निर्माण का ठेका दिया गया और इस कंपनी ने नागपुर के आर्किटेक्ट कोकाटे एसोसिएट्स, 20 बजाज नगर, नागपुर द्वारा 7 जून 2006 को तैयार नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया.**

feedback@chauthiduniya.com

# संक्षिप्त समाचार

## नौकरी के लिए बहू ने सास की हत्या की

अक्सर यह देखा गया है कि, दहेज के लिए सास बहू को जलाती रही है, लेकिन पुणे शहर में इसके उलट एक घटना घटी. बहू ने सास को ही मारकर ठिकाने लगा दिया. यह घटना पुणे शहर के कोथरूड़ इलाक़े के निवासी सेलारका परिवार में घटी. यहां एक बहू ने नौकरी करने की अनुमति न देने पर पिछले माह अपनी सास 62 वर्षीय शोभा लक्ष्मीकांत सेलारका की हत्या कर दी. जांच के दौरान पुलिस ने मृतका की बहू श्वेता उदय सेलारका को गिरफ्तार किया. पुलिस उपायुक्त ज्ञानेश्वर फडतरे के मुताबिक़ हत्या की आरोपी बहू श्वेता एक बीमा कंपनी में अंशकालीन नौकरी करती थी. आगे वह पूर्णकालिक नौकरी करने की इच्छुक थी और उसे कई जगह से ऑफर भी मिले थे. बाहर पूर्णकालिक नौकरी करने के लिए, जब उसने अपनी सास शोभा सेलारका से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया. इस पर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ, लेकिन सास ने अपना निर्णय नहीं बदला. इससे श्वेता अपनी सास से नाराज़ थी. बीच-बीच में विवाद भी होता रहता था. पिछले माह की 13 तारीख़ को दोपहर में अपनी साढ़े तीन साल की बेटी जस्मीन को पड़ोस में खेलने के लिए भेज दिया. उसके पश्चात घर वापस आकर सास को उसकी आईब्रोज बढ़ने की बात कही. सास ने इस पर उससे आईब्रोज बनाने को कहा तो, वह तैयार हो गई. उसने सास को आईब्रोज बनाने के बहाने कुर्सी पर बिठाया. उसके बाद बहू ने सास के सिर पर लोहे से हमला किया, जिससे शोभा सेलारका के सिर पर गंभीर चोट आई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई. घटना की जांच के दरम्यान पुलिस को बहू श्वेता पर संदेह हुआ और, जब उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की गई तो, उसने हक़ीक़त उगल दिया.

## नागपुर शिक्षा बोर्ड का अजब कारोबार

क्या कोई मृत प्राध्यापक परीक्षा की कॉपियां जांच सकता है? यह सवाल चंद्रपुर ज़िले की वरोरा के लोग कर रहे हैं. दरअसल वरोरा नगर में स्थित एक कनिष्ठ महाविद्यालय में कार्यरत एक प्राध्यापक की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई थी, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य ऑफिसों के साथ ही नागपुर शिक्षा बोर्ड को भी दी गई थी. उसके बावजूद बोर्ड ने मृत प्राध्यापक के नाम कक्षा 12वीं की कॉपियां मूल्यांकन के लिए भेज दिया. इस पर जब उक्त उत्तर पुस्तिका कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य ने बोर्ड को प्राध्यापक की मौत हो जाने की जानकारी पुनः देते हुए वापस करने की कोशिश की तो, बोर्ड के अधिकारियों ने अपनी ग़लती मानने की बजाय उलटा प्राचार्य को ही तुगलकी फ़रमान जारी कर दिया गया. आदेश में कहा गया कि वे किसी तरह इन उत्तरपुस्तिकाओं की जांच करके निर्धारित समयावधि में बोर्ड के पास भेजें. बोर्ड के इस क़दम से कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य परेशान हो उठे. परेशानी का कारण यह था कि एक तो, जिस विषय की उत्तरपुस्तिका जांचने के लिए भेजी गई वह विषय प्राचार्य का था ही नहीं. इसलिए जांच में गड़बड़ी हो गई तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? यदि किसी से उत्तरपुस्तिकाओं की जांच करा ली जाती है तो, उसके पश्चात उसका पारिश्रामिक व भत्ता वगैरह किसे भुगतान किया जाएगा, क्योंकि पारिश्रामिक व भत्ते उसी व्यक्ति के नाम से जारी किए जाते हैं, जिसके नाम पर उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए जारी की गई हैं. यह बात नागपुर शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को कौन समझाए?

## झोपड़पट्टी में रहते हैं 10 फ़ीसदी पुलिसकर्मी

राज्य की बॉलीवुड की चकाचौंध भरी मुंबई नगरी की सुरक्षा का भार ढोने वाले पुलिस वालों की हालत कैसी है शायद यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे. हाल ही में अदालत के समक्ष यह तथ्य उजागर हुआ कि, मुंबई की सुरक्षा करने वाले 10 प्रतिशत पुलिस यहां की झोपड़पट्टियों में रहते हैं. झोपड़पट्टियों में रहने वाले पुलिस वालों में 81 पुलिस निरीक्षक और 4426 हवलदार शामिल हैं. दरअसल यह बात तब सामने आई, जब झोपड़पट्टी वासियों को पानी का कनेक्शन न दिए जाने का मामला अदालत पहुंचा. इस मुद्दे पर झोपड़ पट्टी वासियों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही जल अधिकार समिति ने सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी हासिल की. मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह व न्यायाधीश आर.वी. मोरे की खंडपीठ को जल अधिकार समिति ने बताया कि, जिन अवैध झोपड़पट्टी इलाक़ों में मुंबई पुलिस के 10 प्रतिशत कर्मचारी रहते हैं, वहां महानगर पालिका प्रशासन सामान्य प्रक्रिया के तहत पानी (नल) का कनेक्शन दे रहा है, जबकि अन्य झोपड़पट्टी इलाक़ों को अवैध बताकर वहां के निवासियों को पानी कनेक्शन देने से इंकार कर दिया जाता है. खंडपीठ ने जल अधिकार समिति की दलीलों को सुनने के बाद अगली सुनवाई में राज्य सरकार को इस मसले पर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है.इस खुलासे से मुंबई की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की दुर्दशा का भी पता चलता है कि सरकारी नौकरी करने के बाद भी अवैध झोपड़पट्टी इलाक़ों में उन्हें रहना पड़ रहा है.

## नागपुर मनपा की ग़रीबों से सीनाजोरी

नागपुर महानगर पालिका प्रशासन का अजब हाल है. जिनकी करोड़ों की कमाई है, उन पर कम संपत्ति कर लगाया जाता है, जबकि महीने में हज़ार-दो हज़ार कमाने वाले झोपड़पट्टी वासियों पर 15000 रुपये तक संपत्ति कर ठोंका जा रहा है. मनपा के कर बिलों को देखकर ग़रीब झोपड़पट्टी वासियों की सांसे फूल रही हैं. पीड़ित जब मनपा प्रशासन से उसकी ग़लती बताता है तो, उसको उलटा दंडात्मक कार्रवाई व नीलामी की धमकी देकर वसूली की जा रही है. प्रभाग 37 में पडोले नगर स्थित झोपड़पट्टी वासियों को कुछ इस तरह से संपत्ति कर का बिल भेजा गया है- रमेश ढोरे को 37,784 रुपये, कमलेश कुमार साहू को 8,066 रुपये, श्यामराव गणवीर को 32,583 रुपये, विलास लांडगे को 19,004 रुपये, अंजाबाई भगत को 30,384, मारोती थोटे को 36,442 रुपये का बिल भेजा गया है. इस क्षेत्र के अन्य झोपड़पट्टी वासियों को भी बढ़े हुए बिल भेजे गए हैं. यहां के निवासियों का कहना है कि पिछले कई सालों से मनपा प्रशासन ने कोई बिल नहीं भेजा था. अचानक इस साल इतनी राशि के बिल भेज दिए, जितनी हमारी साल भर की कमाई नहीं है. बिलों को देखकर झोपड़पट्टी वासी हैरान हैं. यहां के लोगों ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पुनः संपत्ति का सर्वेक्षण कराने और बकाया कर पर लगाए जा रहे ब्याज पर छूट देने की मांग की है.

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## ये क्या हो रहा है...

# दादा की दबंगई से महंगाई डायन खुश

प्रणव दा के बजट से कसमसा रही राज्य की जनता पर एक और आर्थिक मार पड़ गई है. वहीं अजीत दादा ने भी अपने बजट में दबंगई दिखाई. दादा की दबंगई से जहां, जनता परेशान है, वहीं महंगाई डायन ज़ोर-ज़ोर से खिलखिला कर हंसते हुए इठला रही है. जनता को लगा था कि, केंद्रीय बजट में जो मार उन पर पड़ी है, उसका दादा ख़्याल रखेंगे, लेकिन लगता है कि दादा महानगर पालिका और ज़िला परिषद के चुनावों की खुमारी से बाहर नहीं आए है. इसलिए तो उन्होंने मान लिया कि पांच साल के लिए हमारा दबदबा क़ायम हो गया है, अब विधानसभा चुनाव के पहले जनता के हित में सोचेंगे, तब तक जनता इस बजट की बेरहम मार को भूल चुकी होगी. जनता को भूलने की आदत जो है. दादा का यह बजट आम आदमी को राहत नहीं पहुंचाया. दादा ने आम ज़रूरतों की चीजों को कर मुक्त रखा है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के कारण आम ज़रूरत की वस्तुओं की क़ीमत में इजाफ़ा अपने आप हो जाता है. पहले प्रणव दा के और अब अजीत दादा के बजट से राज्य की जनता पर दोहरी मार पड़ी है. नागपुर वासियों पर मनपा ने भी अपना बोझ करों में वृद्धि कर डाल दिया है. दादा आखिर यह हो क्या रहा है? आप कहते हैं कि, महंगाई की डायन और मुटियाने के लिए आपने आम सहमति से यह बजट बनाया है. फिर कांग्रेस क्यों लाल-पीली हो रही है? वह रसोई गैस के सिलेंडर में कर वृद्धि किए जाने पर आपसे नाराज़ क्यों है? मुख्यमंत्री साहिब, बिक्रीकर रदद् करने की बात क्यों कर रहे हैं? कहीं यह आपसी द्वंद का बजट तो नहीं है? आम आदमी को अपना पेट भरने के लिए रोज़ कुंआ खोदना पड़ता है.

नेताओं की तरह उनकी किस्मत नहीं है. आम आदमी जब हर रोज़ काम करता है, तब कहीं जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है. इसलिए वह महंगाई डायन के बढ़ते स्वरूप से भयभीत रहता है. कहीं उसके नौनिहालों के हाथों से सत्ताधीशों की चेरी महंगाई डायन निवाला न छीन ले. वह इस बात को लेकर कर हैरान है कि, जो नेता चुनाव के समय उसकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर दिखाई दे रहे थे, उसके भले की बात कर रहे थे, उसका उद्धार करने के सपने दिखा रहे थे, वे चुनाव ख़त्म होते ही उसे भूल गए. ठेंगा दिखा दिया, मुंबई नगरिया पहुंच कर आपने, आम आदमी को. वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. पीने का पानी तक उसे आसानी से नहीं मिल पा रहा है. बढ़ती महंगाई के कारण उसे अपनी कमाई शून्य नज़र आती है. सत्ताधीशों को संसद हो या विधानसभा, हर जगह सब्सिडी पर खाने को हर सामान मिल जाता है, जनता को तो हर ज़रूरी चीज का जुगाड़ अपनी गाढ़ी कमाई से ही करना पड़ता है. इस महंगाई की मार के कारण न वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की सोच पा रहा है और न उनको ढंग से खाना खिला पा रहा है. इसलिए ग़रीब कुपोषित हैं और उनके लिए बनी योजनाओं से नेता-अफसर पोषित हैं. दादा आखिर राज्य में यह हो क्या रहा है, महंगाई डायन खुश और आम आदमी परेशान क्यों है?

महाराष्ट्र ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

# आंबेडकर से दूर जाते रिपब्लिकन नेता

**रामदास आठवले तो कभी-कभार अपनी पीड़ा व्यक्त भी कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर तो कुछ इस तरह से घायल हुए हैं कि, उनके मुंह से उफ, तक नहीं निकल पा रही है. अपनी इस हालत के लिए ये नेता ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. इसलिए तो, जिन रिपब्लिकन के हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए थी, वह टुकड़े-टुकड़े में विभाजित है, जबकि उसके वोटरों के दम पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना-भाजपा सत्ता का उपभोग कर रही है.**

राजेश नामदेव

राज्य की राजनीतिक क्षितिज में अपनी अमिट छाप छोड़ने को आज भी राज्य के रिपब्लिकन नेता को सहारे की ज़रूरत है. बार-बार सत्तारूढ़ गठबंधन से ठगे जाने के बाद रामदास अठावले ने पुरानी बातों को भुलाकर विपक्षी गठबंधन शिवसेना-भाजपा से गठजोड़ किया था, लेकिन आज यहां भी वे ख़ुद को ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहे हैं. उनकी अपेक्षाएं पूरी होने की बजाय महायुति में उपेक्षा का अहसास अब अधिक होने लगा है. इसके बावजूद अब उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि, वे कहां जाएं? वे अपने दर्द को छुपा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दर्द देने वाले सहयोगियों को एकदम से छोड़ भी नहीं पा रहे हैं. कुछ ऐसी ही हालत सत्तारूढ़ आघाड़ी के प्रसंस्करण महाआघाड़ी में शामिल हुए डॉ. प्रकाश आंबेडकर की भी है. इन दोनों को तात्कालिक ज़रूरत के अनुसार राज्य के सत्तारूढ़ व विपक्षी गठबंधन ने बख़ूबी इस्तेमाल किया और जब, उन्हें सत्ता में भागीदारी देने की बारी आई तो ठेंगा दिखा दिया. इस अपमान पर रामदास अठावले तो कभी-कभार अपनी पीड़ा व्यक्त भी कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश आंबेडकर तो कुछ इस तरह से घायल हुए हैं कि, उनके मुंह से उफ, तक नहीं निकल पा रहा है. अपनी इस हालत के लिए ये नेता ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. इसलिए तो, जिन रिपब्लिकन के हाथ में सत्ता की चाबी होनी चाहिए थी, वह टुकड़े-टुकड़े विभाजित है, जबकि उसके वोटरों के दम पर कांग्रेस-राकांपा और शिवसेना-भाजपा सत्ता का उपभोग कर रही हैं. पिछले एक-डेढ़ साल से रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले शिवसेना-भाजपा के साथ पूरे राज्य में शिवशक्ति-भीमशक्ति का राग अलापते फिरते रहे. हर ज़िले में जाकर महायुति की शक्ति का प्रदर्शन किया. हुंकार भरते रहे कि यह गठबंधन सिर्फ मनपा-विधानसभा चुनाव के लिए न होकर लोकसभा चुनाव तक क़ायम रहेगा. इतना ही नहीं यह महायुति राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील रहेगी. इस महायुति को नेताओं के नाम आधार पर एटीएम तक पुकारा जाने लगा. ए फॉर अठावले, टी फॉर ठाकरे और एम फॉर मुंडे को मिलाकर यह रचना की गई. एटीएम यानी नोट उगलने वाली मशीन. ऐसा लगा कि महायुति का यह एटीएम राज्य की सत्तारूढ़ दल का अच्छा विकल्प बन कर उभरेगा और सत्तारूढ़ गठबंधन के होश उड़ा देगा. शिवसेना-भाजपा नेताओं ने रामदास अठावले के बुझे हुए ख्वाबों को खूब हवा दी. शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने यहां तक घोषणा कर दी कि, वह अपने कोटे से रामदास अठावले को राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन नगर पालिका, महानगर पालिका और ज़िला परिषद चुनाव के बाद ही रामदास अठावले को अपने ठगे जाने का अहसास होने लगा.

मुंबई महानगर पालिका में दलित मतों के दम पर शिवसेना-भाजपा की सत्ता तो लौट आई, लेकिन रामदास अठावले के दल का एक भी उम्मीदवार नगरसेवक नहीं बना. महायुति की सत्ता शिवसेना-भाजपा ने आपस में बांट लिया और रामदास अठावले को पछताने के लिए छोड़ दिया. इस दशा के लिए अठावले के समर्थक उनके ख़िलाफ़ फिर बोलने लगे. जब समय आया राज्यसभा चुनाव का तो, शिवसेना से संकेत मिले कि, इस बार गुरूजी मनोहर जोशी की जगह रामदास अठावले को राज्यसभा में भेजा जाएगा. अठावले भी यह मानकर खुश थे कि, शिवसेना अपना वादा निभाने के प्रति गंभीर है, लेकिन जैसे-जैसे राज्यसभा चुनाव के दिन नज़दीक आने लगे तो, शंकाएं बढ़ने लगीं. इसकी वजह यह थी कि अठावले, जहां उद्धव ठाकरे से मिल कर खुद को उम्मीदवार घोषित करने की मंशा लिए घूम रहे थे, वहीं शिवसेना के कार्यकारी अधिकारी मुंबई मनपा की सत्ता मिलने के बाद इतने बिजी हो गए कि, रामदास अठावले की कॉल सुनने को भी उनके पास फुर्सत नहीं थी. इधर रामदास अठावले भाजपा-शिवसेना के नेताओं से मिलने को दौड़धूप कर रहे थे तो, वहीं शिवसेना ने अनिल देसाई को राज्यसभा भेज कर रिपब्लिकन नेता व उसके समर्थकों को करारा झटका दे दिया. इससे आहत रामदास अठावले भाजपा से आस लगाई, लेकिन नितिन गडकरी से मुलाक़ात के बाद वह भरोसा भी टूट गया. गडकरी ने भविष्य में मदद करने का भरोसा ज़रूर दिलाया. अब शिवसेना की वादा ख़िलाफ़ी से नाराज व अपमानित अठावले ने साफ कर दिया है कि, इस माह होने वाले पांच मनपा चुनावों में वह अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे. वह मालेगांव, भिवंडी-निज़ामपुर, लातूर, चंद्रपुर व परभणी मनपा के चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे. इसका मतलब साफ है कि, जिस ज़ोश के साथ शिवसेना ने शिवशक्ति -भीमशक्ति के नारे को बुलंद किया था, उसके बुलबुले को मुंबई की सत्ता मिलते ही फोड़ दिया गया. इसलिए शिवसेना-भाजपा-रिपब्लिकन पार्टी की महायुति वर्ष 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक टिकी रहेगी, यह कहना मुश्किल है. यहां तक कि भाजपा के शिवसेना के साथ बने रहने पर भी अटकलें लगाई जाने लगी है. इसका मतलब यह है कि, शिवसेना ने इस महायुति को अपने अहंकार व स्वार्थ के चलते बलिदान करने का मन बना लिया है. अब उद्धव ठाकरे या उनका कोई समर्थक शिवशक्ति-भीमशक्ति का नारा लगाते दिखाई नहीं देता है. शिवसेना की इस चाल से एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि, वह अपने सहयोगी दलों को हमेशा दोयम दर्जा देती है और अपना पिछलग्गू बनाकर ही रखना चाहती है. इसलिए उसके मतभेद तेज़ी से भाजपा के नेताओं के साथ भी बढ़ते जा रहे हैं. भाजपा भी शिवसेना के विरोध के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से संबंध बढ़ाना तेज़ कर दिया है. उसे मनसे के साथ भविष्य में फ़ायदा नज़र आने लगा है. हालांकि रामदास अठावले की समझ में यह नहीं आ रहा है कि, वे अब जाएं तो कहां जाएं? महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना-भाजपा-रिपब्लिकन की महायुति के मुक़ाबले कांग्रेस-राकांपा ने महाआघाड़ी बनाई थी और उसमें डॉ. प्रकाश आंबेडकर, जोगेंद्र कवाड़े की नेतृत्व वाली रिपब्लिकन को जोड़ा था, तब कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रकाश आंबेडकर से वादा किया था कि, उन्हें राज्यसभा अपने खेमे से भेजेंगे. मनपा चुनाव में कांग्रेस-राकांपा-रिपब्लिकन की महाआघाड़ी तो मुंबई की सत्ता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जहां भी सत्ता मिली कांग्रेस-राकांपा ने अपने गणित के अनुसार बंदरबांट कर ली. महाआघाड़ी में भी अब प्रकाश आंबेडकर की कोई पूछ-परख नहीं है. कांग्रेस ने भी राज्यसभा में आंबेडकर को भेजने के वादों को भुला दिया और विलासराव देशमुख व राजीव शुक्ला को पुनः भेज दिया है. अब महायुति से अपमानित रामदास अठावले और महाआघाड़ी में उपेक्षा से परेशान डॉ. प्रकाश आंबेडकर में फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि, अठावले अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं और आंबेडकर चुप्पी साध कर अपमान का ज़हर पी रहे है. अब यह वक्त आ गया है, जब रिपब्लिकन नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि, उसकी हालत ऐसी क्यों है? क्यों राज्य की बड़ी पार्टियां उन्हें चुनाव के समय पुचकार कर अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद अपमानित कर छोड़ देती हैं? जिस रिपब्लिकन ऑफ इंडिया को डॉ. बाबा साहब आंबेडकर ने स्थापित किया था, वह आज टुकड़े-टुकड़े क्यों है? नेताओं का आपसी ईगो पार्टी से ऊपर क्यों है? जिस दलित जनता को एक सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है, उसकी पीड़ा कोई समझने वाला क्यों नहीं है? आज डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है. कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उनके आदर्शों-सिद्धांतों व विचारों को आधार बना कर भाषण दिए जा रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन एकता कहीं नज़र नहीं आ रही है. दरअसल, रिपब्लिकन नेता अपने ईगो के कारण त्याग करने को तैयार नहीं हैं. वे आपसी समन्वय स्थापित करने को तैयार नहीं हैं, लिहाज़ा रिपब्लिकन जनता भ्रमित है कि, वह किसे अपना नेता मानें, जहां सभी अपने को नेता बताते हों. नेताओं के अहंकार के टकराने से सबसे अधिक नुक़सान पहुंचा है तो, डॉ.बाबासाहब आंबेडकर के रिपब्लिकन आंदोलन को. ये नेता कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना-भाजपा को गालियां भी देंगे और उनसे दोस्ती भी करेंगे. इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि, इनमें एकता नहीं है. पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ऐसा लगा था कि, रिपब्लिकन नेताओं ने एकता का जो आगाज किया है, वह प्रतिफलित होगा,लेकिन चुनाव होने से पहले ही सबका ईगो जाग उठा था और एकता के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए. यही वह वजह है कि बार-बार कांग्रेस-राकांपा व शिवसेना से अपमानित होने बाद भी उनके सहारे की ज़रूरत रिपब्लिकन नेताओं को पड़ती है. गुटों में बंटी रिपब्लिकन पार्टी आज राज्य में नाम की रह गई है, जबकि राज्य में सबसे अधिक पिछड़े, दलित, आदिवासी मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है. इसके बावजूद भी वे सत्ता से दूर हैं. सत्ता के नज़दीक जाने के लिए उन्हें कांग्रेस-राकांपा या शिवसेना-भाजपा जैसे राजनीतिक दलों के सहारे की ज़रूरत महसूस हो रही है. उनके ईगो की लड़ाई में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के सिद्धांतों व विचारों की हत्या रोज़ होती है. हालांकि जयंती पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की तस्वीर को आदरांजलि में कुछ हार व फूल चढ़ा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि, सारे रिपब्लिकन नेता एकजुट होकर उनके सपने को साकार करें. राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस हो या शिवसेना या फिर राकांपा जैसे दलों से सौदा करना उचित रहेगा या स्वाभिमान के साथ अपने दम पर लड़ना उचित रहेगा, यह तय करना है रिपब्लिकन जनता को. जनता ही स्वार्थ में अंधे कथित रिपब्लिकन नेताओं की आंखों से अहंकार की पट्टी खोल सकती है. इसलिए रिपब्लिकन जनता को यह निश्चित करना होगा कि, वह डॉ. बाबासाहब की खांचों में बंटी छवि को एक करे और नए प्रभात का स्वागत करे.

feedback@chauthiduniya.com

**मनपा चुनाव में कांग्रेस-राकांपा-रिपब्लिकन की महाआघाड़ी तो मुंबई की सत्ता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन जहां भी सत्ता मिली कांग्रेस-राकांपा ने अपने गणित के अनुसार बंदरबांट कर ली. महाआघाड़ी में भी अब प्रकाश आंबेडकर की कोई पूछ-परख नहीं है. कांग्रेस ने भी राज्यसभा में आंबेडकर को भेजने के वादों को भुला दिया और विलासराव देशमुख व राजीव शुक्ला को पुनः भेज दिया है. अब महायुति से अपमानित रामदास अठावले और महाआघाड़ी में उपेक्षा से परेशान डॉ. प्रकाश आंबेडकर में फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि, अठावले अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं और आंबेडकर चुप्पी साध कर अपमान का ज़हर पी रहे हैं. अब वह वक्त आ गया है, जब रिपब्लिकन नेताओं को यह सोचना पड़ेगा कि उसकी हालत ऐसी क्यों है?**

# चौथी दुनिया बिहार झारखंड

दिल्ली, 09 अप्रैल-15 अप्रैल 2012 www.chauthiduniya.com

# नीतीश को लाल सलाम

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

वाम दलों ने कहा है कि, नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए. नीतीश कुमार के कुछ साथी भी उन्हें ऐसी ही सलाह देते हैं. तीसरे मोर्चे का सपना देखने वाले भी यही चाहते हैं कि, जदयू भाजपा का साथ छोड़ दे, लेकिन सवाल यह है कि, अगर ऐसा हुआ तो फिर रास्ता किधर जाएगा. नीतीश कुमार को भाजपा का साथ छोड़ने की बात कहने वाले ऐसे लोग हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका देखना चाहते हैं. देश का मौजूदा राजनीतिक माहौल ऐसे लोगों के तर्कों का वजन बढ़ाता है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या अब वह समय आ गया है, जब नीतीश कुमार ऐसा कोई बड़ा कदम उठाएं. भाकपा के महाधिवेशन में दो बातें साथ-साथ चल रही थी. पहली वाम दलों एकता की और दूसरी नीतीश के भाजपा से दूरी बनाने की. लाल रंग में तीन दिनों तक रंगी पटना लगातार इन दो सवालों पर जारी गंभीर मंथन का गवाह बनी. भाकपा महासचिव ए बी बर्धन ने कहा कि, मंदिर व मस्ज़िद के नाम पर टकराव कराने वाली पार्टी भाजपा का साथ देकर किसी का भला नहीं हो सकता है. नीतीश कुमार को भाजपा से किनारा कर लेना चाहिए, उन्होंने कहा कि पांच राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, उससे यह साफ हो गया है कि जनता ने कांग्रेस और भाजपा को दरकिनार कर क्षेत्रीय दलों को गले लगाया है. अब क्षेत्रीय दलों को तय करना है कि, उसे किसके साथ रहना है. देखा जाए तो बर्धन ने आगे की राजनीति के साफ संकेत दे दिए हैं. किसी जमाने में लालू प्रसाद के लिए भी भाकपा ने अपना दरवाजा खोला था. अब दांव नीतीश कुमार पर लगाया जा रहा है. वाम दलों की इस पहल पर जदयू से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं. उन्हें लगता है कि उनके नेता ने प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है. वाम दलों ने जिस तरह से नीतीश को न्योता दिया है, उससे देर सवेर राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को लेकर होने वाली गोलबंदी के संकेत मिलने लगे हैं. जदयू प्रवक्ता व विधान पार्षद नीरज कुमार के अनुसार बर्धन के बयान से यह साफ हो गया कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां व कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होने लगे हैं. ग़रीबों, मज़दूरों व अल्पसंख्यकों के लिए नीतीश कुमार के कार्यक्रमों ने वाम दलों को भी प्रभावित किया है. जानकारों का मानना है कि बर्धन ने जो संकेत दिए हैं, वह आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति की दशा व दिशा तय कर सकता है. गठबंधन राजनीति के दौर में ऐसे नेता की ज़रूरत ज्यादा होती है, जो सभी घटकों को मान्य हो. नीतीश कुमार इस दिशा में तेज़ी से क़दम बढ़ा रहे हैं. दरअसल देखा जाए तो जदयू ने धीरे-धीरे ही सही भाजपा के साथ अपनी दूरी बढ़ानी शुरू कर दी है. अभी राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट के लिए तो नीतीश कुमार ने भाजपा को आर-पार की बात भी कह दी थी. जानकार तो यहां तक कहते हैं कि निर्दलीय के तौर पर अशफ़ाक करीम का नामांकन भी नीतीश कुमार का ही खेल था. अशफ़ाक करीम का नामांकन करा कर नीतीश कुमार भाजपा को दबाव में लाना चाहते थे और वह इसमें सफल भी हुए. राष्ट्रीय नेतृत्व के लाख चाहने के बावजूद भाजपा तीसरा उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई. इससे पहले यूपी चुनाव में जदयू अकेले मैदान में उतरी और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी उसका भाजपा के साथ कोई तालमेल नहीं हुआ है. इसके अलावा प्रदेश जदयू मुख्यालय से सभी ज़िलाध्यक्षों को कहा गया है कि, जहां भी भाजपा के विधायक हैं, उन क्षेत्रों में पार्टी के संगठन को मज़बूत करने की क़वायद तेज़ी से शुरू कर दी जाए. जदयू चाहता है कि भाजपा के पकड़ वाले इलाक़ों में भी मज़बूत संगठन बने. कुल मिलाकर जदयू आहिस्ता-आहिस्ता अपनी तैयारियों में जुटी है. देश व प्रदेश दोनों की ज़रूरतों के हिसाब से फ़ैसले लिए जा रहे हैं. बिहार दिवस मनाने के बहाने दिल्ली में नीतीश कुमार ने बड़ा जलसा किया, लेकिन भाजपा को इससे अलग रखा गया. भाजपा के नेता कहते हैं कि बिहार दिवस अकेले नीतीश कुमार व जदयू का नहीं था. भाजपा को भी उसमें शामिल करना चाहिए था, ताकि गठबंधन को लेकर सही संदेश जाए. हालांकि, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इन सारी घटनाओं के बावजूद भाजपा के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से रिश्ता तोड़ने का कोई फ़ैसला ज़ल्दबाजी में नहीं लेंगे. वह निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के परिणामों का इंतज़ार करेंगे. अगर एनडीए की सरकार बनी, तो गठबंधन चलता रहेगा और न बनी तो 2015 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नवीन पटनायक की तरह अलग हो सकते हैं. लेकिन यह क़दम भी इस समय प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर ही वह उठाएंगे. हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में एक चांस ज़रूर लेंगे. वाम दल जिस तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, अगर वह अस्तित्व में आया तो सारे समीकरण ख़ुद-बख़ुद बदल जाएंगे. अपने राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाकपा ने, जिस तरह नीतीश कुमार के लिए दरियादिली दिखाई उससे जदयू खेमा अतिउत्साह में आ गया है. देश में क्षेत्रीय दलों के प्रति उभर रहा समर्थन भी तीसरे मोर्चे का रास्ता साफ कर रहा है. वाम दलों की दोस्ती मुलायम सिंह के साथ एक बार फिर पटरी पर आ गई है. बिहार में उसने नीतीश को भाजपा से अलग होने की सलाह दी है. जदयू ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है और यह तभी संभव है, जब भाजपा से उसका रिश्ता टूटे. बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में जदयू, सपा व वाम दलों का गठबंधन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है. जदयू से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सपा से दोस्ती कर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के माय समीकरण को भी तहस नहस कर सकते हैं. लालू प्रसाद की असक्रियता के कारण पहले से ही कमज़ोर पड़ चुका राजद और भी कमज़ोर होता जा रहा है. ऐसे में माय समीकरण को तोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन यह सब बातें तो अभी संभावनाओं की गोद में है. सबसे बड़ी बात यह हुई हैं कि वाम दलों ने आपस में दोस्ती की पहल की है और नीतीश का साथ देने की पेशकश की है. ये दोनों बातें राष्ट्रीय व प्रदेश की राजनीति के लिए काफी अहम है. अगर बातें इसी दिशा में आगे बढ़ती गईं, तो नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में दख़ल बढ़ना तय है.

**वाम दलों की दोस्ती मुलायम सिंह के साथ एक बार फिर पटरी पर आ गई है. बिहार में उसने नीतीश को भाजपा से अलग होने की सलाह दी है. बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश में जदयू, सपा व वाम दलों का गठबंधन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है. जदयू से जुड़े सूत्र बताते हैं कि सपा से दोस्ती कर नीतीश कुमार लालू प्रसाद के माय समीकरण को तहस-नहस कर सकते हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

पंचायत चुनाव का सच

# मुखिया और उपप्रमुख से त्रस्त हैं उपमुखिया और वार्ड सदस्य

चंद्रेश शर्मा

झारखंड में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तेज़ी से विकास का ग्राफ बढ़ना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं हो रहा है. क्षेत्र की जनता ने जिस उत्साह से पंचायती राज चुनाव में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा है. जनता की कसौटी पर मुखिया, प्रमुख और ज़िला परिषद सदस्य खरा नहीं उतर रहे हैं. बाकी कसर यहां के नौकरशाहों ने पूरी कर दी है. पंचायत चुनाव से पूर्व सिर्फ नौकरशाहों पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगता था, लेकिन मौजूदा पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधि गांधी और जेपी के आदर्शों को भूलकर भ्रष्टाचार में शामिल हैं. चतरा सदर प्रखंड का एक पंचायत है गोइंडी. इस पंचायत के मुखिया हैं एकबाल अंसारी, उपप्रमुख हैं राजेंद्र साव व पंचायत सचिव हैं सुरेश ठाकुर. इनकी तिकड़ी ने लूट का ऐसा खेल शुरू किया है, जिसने भ्रष्टाचार के सभी रिकार्ड तोड़ दिए हैं. आरोपों के मुताबिक़ इन पंचायत प्रतिनिधियों ने पैसों की खातिर सिद्धांतों को [illegible] के मृत मंगरा भुईयां के नाम से इंदिरा आवास के 45 हज़ार रुपये की निकासी कर आपस में बांट लिया. मुखिया एकबाल अंसारी की दबंगई देखिए, उसने उपमुखिया और वार्ड सदस्यों से बिना विचार विमर्श किए योजनाओं को मंज़ूरी दे दी. इस बावत वार्ड सदस्य बसारत अंसारी और विनय वैद्य ने चौथी दुनिया को बताया कि गोइंडी गांव के मुकेश कुमार गुप्ता ने अपने निजी आवास का प्रथम तल इंदिरा आवास के पैसे से बना लिया. इस काम में मुखिया और पंचायत सचिव के सहयोग से पैसे का भुगतान करा लिया गया.

इस बारे में जब ग्रामीणों ने मुखिया से शिकायत की तो, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, जहां शिकायत करना है करो, क्योंकि मुकेश मेरा कार्यकर्ता है. उपमुखिया आरती देवी का आरोप है कि, उपप्रमुख राजेंद्र साव की पत्नी एक साथ दो लाभ के पद पर कार्य कर रही हैं. ख़बरों के मुताबिक़ वह आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के अलावा जनवितरण प्रणाली की दुकानदार भी हैं. ग्रामीणों की मानें तो, मुखिया की तिकड़ी ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में पंचायत में 11 इंदिरा आवासों के चयन में भारी अनियमितता बरती. वार्ड सदस्य बसारत अंसारी का आरोप है कि, उन्होंने इंदिरा आवासों का चयन कर लिया गया. बसारत मियां का कहना है कि इस बारे में, जब मुखिया से शिकायत की गई तो, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं में ग्राम सभा की कोई आवश्यकता नहीं है. उनके अनुसार मुखिया पंचायत का मालिक होता है, लिहाज़ा उसकी जो मर्जी होगी वह करेगा. मुखिया के इस दबंगई से हलकान वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया है कि डीप बोरिंग, जलछाजन योजना, किसानों को बंटने वाले यूरिया खाद और बल्ब वितरण में भी भारी अनियमितता बरती गई है. आरोपों के मुताबिक़ मुखिया एकबाल अंसारी द्वारा अपने समर्थकों को जबरन रेवड़ियां बांटी जा रही हैं. वार्ड सदस्य विनय वैद्य का आरोप है कि मुखिया ने योजनाओं में अवैध पैसा वसूलने के लिए दलालों को भी नियुक्त कर रखा है, जिसमें सागर सिंह की भूमिका प्रमुख है.

वार्ड सदस्यों का कहना है कि मुखिया समर्थक विनोद कुमार सिंह कसियाडीह विद्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा भवन निर्माण में जमकर अनियमितता बरती जा रही है. प्राक्कलन के मुताबिक़ विद्यालय भवन के निर्माण में चिमनी ईंट लगाया जाना है, जबकि यहां बंगला ईंट लगाया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि विनोद कुमार सिंह कभी भी विद्यालय नहीं आते, लेकिन अध्यक्ष नईम अंसारी की मिली भगत से वह अपनी हाज़िरी बना लेते हैं. अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हुए मुखिया एकबाल अंसारी ने चौथी दुनिया को कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ साज़िश रची जा रही है. वहीं दूसरी तरफ उप मुखिया और वार्ड सदस्यों ने प्रशासन से भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया, उपप्रमुख और पंचायत सचिव पर कार्रवाई की मांग की है.

उपमुखिया - आरती देवी | वार्ड सदस्य - बसारत अंसारी और विनय वैद्य

feedback@chauthiduniya.com

## कैल्शियम व पौष्टिक आहार का सेवन ज़रूरी

डॉ. उदय शंकर प्रसाद

ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होने के कारण और बचाव के संदर्भ में समस्तीपुर के प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं. प्रस्तुत है बातचीत के मुख्य अंश.

**प्र. आमतौर पर इस तरह की बीमारी होने के कारण क्या हैं.**

अधिकतम पैंतीस वर्षों के बाद मनुष्य के शरीर में बोन स्टॉक जब कम होने लगता है, तब हड्डियां के कमज़ोर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. शरीर की हड्डियां इस क़दर कमज़ोर हो जाती हैं कि, हल्की चोट या गिरने से भी उसके फ्रैक्चर होने का ख़तरा बढ़ जाता है. यह एक साइलेंट किलर डिजीज है, इसलिए मनुष्य के शरीर में इसका लक्षण स्पष्ट नहीं दिखता है. हालांकि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद इसकी प्रक्रिया तेज़ होने के कारण उनमें पुरुषों की अपेक्षा इस रोग के होने का ख़तरा अधिक रहता है.

**प्र. ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव कैसे संभव है.**

दूध, सोयाबीन, बादाम, मछली सहित अन्य संतुलित कैल्शियम व पौष्टिक युक्त खाद्य पदार्थों के साथ-साथ सूर्य की तेज किरणों का प्रतिदिन 15-20 मिनट तक सेवन करने से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है.

**प्र. इस बीमारी के मरीजों को क्या-क्या परहेज़ करना चाहिए.**

इस बीमारी के तत्काल बाद चिकित्सक की सलाह लेते हुए, उनकी सलाह के मुताबिक़ परहेज़ करना बेहद ज़रूरी है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# गया मंत्री पर भारी सिविल सर्जन

सुनील सौरभ

बिहार में धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि, यहां अब जनता का नहीं, बल्कि अफसरों का राज है. यहां नीचे से ऊपर तक सरकारी अधिकारियों की मनमानी के कारनामे रोज़ाना लोगों के बीच आ रहे हैं. हद तो तब हो गई, जब विधान सभा में विभागीय मंत्री की घोषणा के बाद भी एक ज़िले का सिविल सर्जन (असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) का निलंबन नहीं हो सका और वह अपने पद पर बने हुए हैं. यह मामला है गया ज़िले का. पिछले वर्ष जून महीने में गया ज़िले के 676 स्वास्थ्य कर्मियों के सामूहिक स्थानांतरण में अनेक अनियमितताओं की शिकायत विभाग के उच्चाधिकारियों, मंत्री और पटना हाईकोर्ट तक की गई. कई विभागीय उच्चाधिकारियों और मंत्री अश्विनी चौबे ने भी माना कि गया के सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार स्वास्थ्य कर्मियों के सामूहिक स्थानांतरण में गड़बड़ियां की हैं और आधा दर्जन से अधिक लोगों को इस माध्यम से फ़र्ज़ी बहाली करने का प्रयास किया गया. स्थानांतरित स्वास्थ्य कर्मियों के लंबे आंदोलन से भी सिविल सर्जन पर कोई असर नहीं हुआ तो, लाचार होकर सभी पटना हाईकोर्ट चले गए. हाईकोर्ट ने भी माना कि, गया के सिविल सर्जन ने स्थानांतरण में गड़बड़ी की है और इसे रद्द करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति जस की तस है. इस मामले पर विधान सभा में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए गत 29 फरवरी 2012 को स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि गया के सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है. मंत्री जी की इस घोषणा को क़रीब एक महीने होने जा रहा है, लेकिन सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार आज भी अपने पद पर बने हुए हैं. इतना ज़रूर हुआ कि हाईकोर्ट ने, जब इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दो सप्ताह का समय देते हुए की गई कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया तो, आनन-फानन में 20 मार्च 2012 को सभी स्वास्थ्य कर्मियों के स्थानांतरण निरस्त करने का आदेश विभागीय प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा के आदेश पर सिविल सर्जन ने निकाल दिया. वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में अवमानना से बचने के लिए विभाग के प्रधान सचिव ने गया के सिविल सर्जन पर प्रपत्र (क) में आरोप गठित करने का आदेश दे दिया है. इसके तहत ज़िला पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है, लेकिन प्रधान सचिव ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का स्थानांतरण ज़िला पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया है. मतलब यह कि इस गड़बड़ी में ज़िलाधिकारी को भी लपेटा गया है. जानकारों का कहना है कि विभाग की ओर से प्रपत्र (क) की सिर्फ कागज़ी खानापूर्ति कर हाईकोर्ट को इसकी सूचना दी जाएगी. पूरे प्रकरण में आज तक विभागीय मंत्री अश्विनी चौबे कमज़ोर पड़े हुए हैं और सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार भारी पड़ते हुए अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं.

**हाईकोर्ट ने भी माना कि, गया के सिविल सर्जन ने स्थानांतरण में गड़बड़ी की है और इसे रद्द करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी स्थिति जस की तस है. इस मामले पर विधान सभा में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुए गत 29 फरवरी 2012 को स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि गया के सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया गया है. मंत्री जी की इस घोषणा को क़रीब एक महीने होने जा रहा है, लेकिन सिविल सर्जन डॉ. दिलीप कुमार आज भी अपने पद पर बने हुए हैं.**

feedback@chauthiduniya.com

# समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बहाली में फ़र्ज़ीवाड़ा

प्रकाश कुमार

समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वर्ष 1981 से 1984 के बीच की गई बहाली में फ़र्ज़ीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है. इसकी जांच केंद्रीय सतर्कता आयोग कर रहा है. आयोग ने जांच का ज़िम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपर महाप्रबंधक (ग्रामीण) कौशिक सिन्हा को सौंपा है. ग़ौरतलब है कि समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने वर्ष 1981 में क्लर्क कम कैशियर के लिए विज्ञापन निकाला था. यह परीक्षा नेशनल बैंकिंग ऑफ प्रबंधन ने ली थी. विज्ञापन में यह साफ कहा गया था कि समस्तीपुर ज़िले के मूल निवासी ही, इसमें शामिल हो सकते हैं. दूसरे ज़िले के मूल निवासी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन बैंक ने मूल निवासी प्रमाण पत्र के बदले आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली कर ली. बहाल कर्मियों में अधिकांश दूसरे ज़िले के हैं. बताया जाता है कि नेशनल बैंकिंग ऑफ मैनेजमेंट ने समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए 318 अभ्यर्थियों का चयन किया था, जिसमें 32 की बहाली की गई. समस्तीपुर के मूल निवासी के बदले दूसरे ज़िलों के निवासी को बहाल करने का मामला तब उजागर हुआ, जब चांदचौर मथुरापुर निवासी वकील राम पुनीत चौधरी ने सूचना के अधिकार के तहत सारे कागज़ातों को बैंक से हासिल कर लिया. श्री चौधरी ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास भेज कर जांच कराने का भी आग्रह किया है. सीबीआई ने उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर प्रथम दृष्टया गड़बड़ी मानते हुए आवेदक को केंद्रीय सतर्कता आयोग में जाने की सलाह दी. उसके बाद वकील राम पुनीत चौधरी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सामने पूरे मामले को रखा. शिकायत पत्र में कहा गया था कि, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा की गई बहाली में समस्तीपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय किया गया है. विज्ञापन में डोमिसाइल को ही बहाल करने की बात कही गई थी, जबकि बहाली में इसकी अनदेखी की गई. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर इसकी जांच का ज़िम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना के अपर महाप्रबंधक ग्रामीण कौशिक सिन्हा को सौंपा है. श्री सिन्हा ने बताया कि जांच करने से संबंधित पत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त हुआ है. इसकी जांच शुरू कर दी गई है. ग़ौरतलब है कि वर्ष 1981 में जो लोग कैशियर कम क्लर्क के पद पर बहाल हुए थे, उनमें से अधिकांश वर्तमान में विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं. सही तस्वीर तो जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जांच प्रकिया शुरू हो जाने बाद हड़कंप मच गया है.

**शिकायत पत्र में कहा गया था कि, समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा की गई बहाली में समस्तीपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय किया गया है. विज्ञापन में डोमिसाइल को ही बहाल करने की बात कही गई थी, जबकि बहाली में इसकी अनदेखी की गई. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर इसकी जांच का ज़िम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना के अपर महाप्रबंधक ग्रामीण कौशिक सिन्हा को सौंपा है.**

feedback@chauthiduniya.com

खगड़िया नगर परिषद चुनाव

# ज़मीन थाहने में जुटे दिग्गज

मनेंद्र कुमार

नगर परिषद चुनाव की क़वायद शुरू होते ही खगड़िया में राजनीतिक दांव-पेंच का खेल शुरू हो गया है. कई दिग्गज, जो पांच वर्षों से ख़ामोश थे, अब वे जनता से लगातार संपर्क में हैं. सभी भावी उम्मीदवार जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हैं. वहीं पिछले चुनाव में विजयी हुए वार्ड पार्षद जनता को विकास की कहानी बयां कर रहे हैं. जबकि, पिछली बार पराजित उम्मीदवार वार्ड की समस्या को उजागर करने में लगे हैं. खगड़िया नगर को 26 वार्डों में बांटा गया है. शहर के विकास के बारे में नगर सभापति मनोहर कुमार यादव का कहना है कि उनके पांच वर्षों के शासन में सभी वार्डों का विकास हुआ है. शहर के हर गली मुहल्ले में पीसीसी सड़क का निर्माण, नाला का निर्माण, रोशनी की व्यवस्था तथा ग़रीब लोगों के लिए सहायता राशि समेत वृद्धापेंशन, विकलांगों को पेंशन और विधवा पेंशन का लाभ मिला है. कोई भी ज़रूरतमंद लोग इससे वंचित नहीं है. उनका कहना है कि, तालाब, घाट, पोखर तथा पार्क योजनाओं का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया है. जल्द ही इस पर काम शुरू होने की संभावना है. उनके अनुसार सभी वार्डों में बीपीएल सूची संतोषजनक है. हालांकि, 10 प्रतिशत ग़रीब लोग इससे वंचित है. उन्हें भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं वार्ड नं. 26 के पार्षद अमित कुमार उर्फ पप्पू का कहना है कि बीते पांच वर्षों का कार्य संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नगर सभापति का चुनाव लड़ा, लेकिन 12-14 मतों के अंतर से हार गया. अमित कुमार ने वर्तमान सभापति पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में सिर्फ एक ही सड़क का निर्माण शुरू हुआ है. नगर सभापति के विकास के दावों का खोखला बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर में लगाए गए वेपर लाइट की गुणवत्ता ठीक नहीं है. उनके मुताबिक़ नगर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, जो लगभग तय है. वहीं नगर परिषद उपसभापति विनय कुमार पटेल का कहना है कि मैं वार्ड नं. 3 का वार्ड पार्षद हूं और मेरे वार्ड में लगभग एक करोड़ रुपये का विकास कार्य मेरे प्रयासों से किया गया है. विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर नाला और सड़कों का निर्माण हुआ है. इसके अलावा नगर में सभी ग़रीब लोगों को विविध पेंशन योजनाओं का लाभ मिला है. बेरोज़गार युवाओं को ऋण मुहैया कराया गया तथा सड़कों पर रोशनी की उचित व्यवस्था की गई है. लिहाज़ा आगामी नप चुनाव में उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है. वार्ड नं. 3 से ही पिछले चुनाव में हारे सुमन कुमार पटेल का कहना है कि अमीर लोगों को वीपीएल सूची में शामिल किया गया है, जबकि पूर्व में पीला कार्ड धारक को एपीएल सूची में रखा गया था. किरासन तेल के आवंटन में मनमानी हो रही है. उनके मुताबिक़ वीपीएल सूची त्रुटिपूर्ण है. मौजूदा वार्ड पार्षद मनमाने ढंग से वोटरों के नाम दर्ज करा रहे हैं. इसलिए क्षेत्र की जनता नाराज़ है और इस बार चुनाव में ज़रूर बदलाव होगा. वार्ड 19 की पार्षद हेमा भारती का कहना है कि चुनावी समर में इस बार भी जीत मेरी पक्की है, क्योंकि 35 वर्षों से जर्जर डाकघर सड़क का निर्माण उन्होंने कराया. इसके अलावा पूरे वार्ड क्षेत्र में नाला, पीसीसी सड़क सहित विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए. उनके अनुसार पिछले चुनाव में जातीय समीकरण उनके पक्ष में न होने के बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की थी. इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नगर की जनता जाति-बिरादरी की भावना से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट करते हैं. वहीं वार्ड पार्षद विजय यादव का कहना है कि, उनके क्षेत्र में विकास का कोई भी कार्य लंबित नहीं है. श्री यादव का दावा है कि उन्होंने पांच वर्षों में लगभग 1 करोड़ रुपये की लागत से दर्जनों योजनाओं को पूरा किया. उनके मुताबिक़ हर गली मुहल्ले में सड़क, नाली और विवाह भवन का निर्माण कराया गया है. वहीं इस बार चुनावी समर में वार्ड नं. 16 की पार्षद रिंकु कुमारी पुन: चुनाव जीतने के लिए प्रयासरत हैं. उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में 4 लाख रुपये की लागत से सिर्फ़ चार योजनाओं को ही स्वीकृति मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं से कई कार्य हुए है. जबकि वार्ड नं. 9 के वार्ड पार्षद रुस्तम अली का कहना है कि मेरे द्वारा दिए विकास प्रस्ताव पर कोई अमल नहीं हुआ है. नतीजतन 5 वर्षों में सिर्फ दो सड़कों का ही निर्माण हुआ है. उनके अनुसार क्षेत्र में केरोसिन तेल का आवंटन कम होने से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं वार्ड नं. 11 की वार्ड पार्षद नूतन देवी का कहना है कि, नगर सभापति द्वारा व्यापक पैमाने पर कार्य किया गया है. क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजनाओं की स्वीकृति मिली. इसके अलावा गली- मुहल्लों में जर्जर हो चुकी सड़कों का निर्णाण कराया गया है. वार्ड पार्षद रविश चंद्र का कहना है कि हमलोगों की जीत पुन: पक्की है, क्योंकि क्षेत्र में सड़क का निर्माण, 4 नालों का निर्माण, रोशनी की व्यवस्था, पेंशन योजनाओं की स्वीकृति समेत दर्जनों कार्य कराए गए हैं. इसलिए जनता इस बार भी उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद देगी. विकास कार्यों की सराहना करते हुए पूनम देवी का कहती हैं कि एपीएल/बीपीएल सूची त्रुटिपूर्ण है और केरोसिन तेल वितरण में भी मनमानी की जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में डी.डी.टी का छिड़काव नहीं होता है, शहर में नालों के जाम रहने से गंदगी का अंबार लगाया हुआ है. उनके अनुसार सिर्फ सड़क निर्माण से ही विकास का ढिंढोरा पीटा नहीं जा सकता. उनके अनुसार क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, जो ज़रूरी भी है. बहरहाल, तमाम सियासी लोग आगामी नगर परिषद चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दांव-पेंच लगाना शुरू कर चुके हैं. वहीं पिछले चुनाव में शिकस्त खाए उम्मीदवार भी इस बार पूरे दम-खम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं. यही कारण है कि जहां मौजूदा वार्ड पार्षद विकास कार्यों की कहानी कह रहे हैं, वहीं पराजित उम्मीदवार उनकी ख़ामियां गिनाकर जनता का रुख बदलने में जुटे हैं.

मनोहर कुमार यादव | अमित कुमार | विनय कुमार पटेल | सुमन कुमार पटेल | हेमा भारती | विजय यादव | रुस्तम अली | रिंकु कुमारी | नूतन देवी

रविश चंद्र

feedback@chauthiduniya.com

# वास्तु विहार ने सस्ता घर का सपना साकार किया

कम पैसे वालों को भी अपना मकान हो, यह सपना वास्तु विहार के प्रबंध निदेशक विनय तिवारी ने जब देखा तो लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कम समय में लोगों के घर का सपना साकार होने लगा तो देखने वाले देखते ही रह गए. बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के 22 शहरों में फ्लैट, डुप्लेक्स, बंगला और हाईब्रिड का निर्माण कर वास्तु विहार ने अब तक दस हज़ार परिवारों को सात लाख रुपये तक की क़ीमत से लेकर 72 लाख रुपये तक के मकान का स्वामित्व प्रदान किया है. वास्तु विहार के प्रबंध निदेशक विनय तिवारी बताते हैं कि, वास्तु विहार की ओर से एक महत्वाकांक्षी परियोजना दिल्ली हाट शीघ्र ही शुरू होने वाली है. दिल्ली हाट विभिन्न प्रदेशों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ से लेकर 20 एकड़ के क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा. श्री तिवारी के अनुसार इसमें सड़क, नाला, अहाता, गोदाम , जलापूर्ति तथा बिजली सहित अन्य आधारभूत सरंचना का विकास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि वास्तुविहार ने घर व टाउनशिप के अलावा रिसोर्ट का भी निर्माण कराया है, जिसमें गया का संबोधि रिसोर्ट, छपरा के सब्बलपुर में आइलैंड रिसोर्ट प्रमुख है. श्री तिवारी मानते हैं कि अगर इंसान मज़बूत इरादों के साथ कोई संकल्प लेता है तो, वह ज़रूर पूरा होता है. आम आदमी के घर के सपने को पूरा कर श्री तिवारी संतोष का अहसास करते हैं. वह कहते हैं कि अपनी छत हर इंसान का सपना होता है. इस सपने को पूरा करने में अगर मैं थोड़ा भी सहयोग कर पा रहा हूं तो अपने को भाग्यशाली मानता हूं. उन्होंने कहा कि उनका मिशन आगे भी जारी रहेगा और वास्तु विहार का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा.

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001-2008 CERTIFIED COMPANY

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इंतेजारूल हक़

मोतिहारी नगर परिषद

# पार्षदों व नपकर्मियों का दुकानों पर कब्ज़ा

भ्रष्टाचार के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मोतिहारी नगर परिषद एक बार फिर परिषद की आवंटित दुकान को लेकर चर्चा में है. परिषद के अधिकांश दुकानों पर पार्षदों, पूर्व पार्षदों व परिषद के अधिकारियों का कब्ज़ा है और सरकार व विभाग जानकर भी अनजान बनी हुई है. उक्त दुकानों को खाली कराने को लेकर कई बार सामान्य बैठक में कुछ पार्षदों ने मामला उठाया भी, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्राप्त ख़बर के अनुसार सभापति प्रकाश अस्थाना, वार्ड पार्षद नसीमा खातून, धीरज, रोहित शर्मा, विनोद श्रीवास्तव, सुधीर कुमार, रंजीत कुमार उर्फ भोला, वीणा रानी, नप कर्मी अजय गुप्ता समेत दो दर्जन वार्ड पार्षदों के संबंधियों के नाम से दुकानें आवंटित की गई हैं. इन दुकानों को कई पूर्व वार्ड पार्षदों ने अलग से ही दूसरे के हाथों बेच भी दिया है और मोटी रक़म की उगाही की है. नगर विकास विभाग की अधिसूचना के अनुसार, कोई भी किरायेदार अपनी मर्जी से किसी को दुकान बेच नहीं सकता है और उसके छोड़ते ही उस पर नगर परिषद का अधिकार हो जाता है, लेकिन यहां इसके विपरीत काम किया गया है. सुशासन की सरकार व नगर विकास विभाग भले ही यह दावा करे कि, इन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद, जहां ब्लेक लिस्टेड आर्टिटेक द्वारा काम लिया जाता है, वहीं बग़ैर नक्शा के भी आसानी से मकान बनाए जाते हैं. सरकार द्वारा दिए गए एक पत्र में आर्टिटेक राकेश रंजन पर ब्लैक लिस्टेड होने का आरोप है और फिर भी उनसे काम लिया जाता है. हद तो तब हो गई, जब हाल ही में 75 लाख रुपये की लागत से बना नगर परिषद कार्यालय के कई कमरे में मौसम की पहली बरसात में ही पानी टपकने लगा. उप सभापति का कार्यालय भी इससे अछूता नहीं था. हालांकि तेरह लाख रुपये इसके रखरखाव पर भी ख़र्च किए गए, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है. जाली हस्ताक्षर कर राशि भुगतान का मुद्दा भी यहां हमेशा उठता है, लेकिन इसकी जांच कराने की बजाय उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. गर्मी से निजात दिलाने के लिए नप द्वारा लगाया गया पियाऊं का मामला हो या फिर वार्डों में लगाए गये चापाकल का. यहां चबूतरे का निर्माण हुआ भी नहीं और राशि की उगाही कर ली गई. यह मामला निगरानी विभाग में भी लंबित है. नगर वासियों को सुविधा देने व करदाताओं की सेवा के लिए स्थापित नगर परिषद करदाताओं व नगर वासियों का विकास तो नहीं कर पाया, लेकिन यहां के अधिकारी व पार्षद खूब चांदी काट रहे हैं. नगर परिषद कर्मी अजय गुप्ता के रिश्तेदार के नाम से नगर परिषद की आवंटित दुकान में मोबाइल का शो-रूम बनाया गया है, जबकि अन्य वार्ड पार्षदों द्वारा अपने-अपने संबंधियों के नाम से दुकान आवंटित कर नगरवासियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है. इतना ही नहीं नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामले में एक नया इतिहास रच रहा है. सभापति, उप सभापति व कार्यपालक पदाधिकारी के ख़र्चों पर अगर नज़र डालें कई मामले उजागर होते हैं. वहीं नगर परिषद के आय-व्यय पर नज़र डालें तो, यहां भी अनेक चौंकाने वाले मामले आते हैं. आमदनी अठन्नी व ख़र्च रुपये की तर्ज पर इस वर्ष का बजट सदन में पेश किया गया था. कुल मिलाकर नगर परिषद व सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं. ग़ौरतलब है कि कई पार्षद लगातार कई बैठकों में नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है. मोतिहारी नगर परिषद क्षेत्र में कुल अड़तीस वार्ड हैं और तमाम वार्डों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है. इस बाबत नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र मंडल से सवाल पूछा गया तो, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.

**सरकार द्वारा दिए गए एक पत्र में आर्टिटेक राकेश रंजन पर ब्लैक लिस्टेड होने का आरोप है और फिर भी उनसे काम लिया जाता है. हद तो तब हो गई, जब हाल ही में 75 लाख रुपये की लागत से बना नगर परिषद कार्यालय के कई कमरे में मौसम की पहली बरसात में ही पानी टपकने लगा. उप सभापति का कार्यालय भी इससे अछूता नहीं था. हालांकि तेरह लाख रुपये इसके रखरखाव पर भी ख़र्च किए गए, लेकिन उसका भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है.**

feedback@chauthiduniya.com

# एक नज़र

## लोजपा नेताओं पर लाठीचार्ज

छात्र संघ का चुनाव कराने सहित राज्य हित से जुड़े कई मुद्दों पर छात्र लोजपा द्वारा विधान सभा घेराव के मौके पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं, जिसमें कई नेता बुरी तरह से घायल हो गए. घायल होने वालों में पार्टी के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा, महासचिव रोहित कुमार सिंह, छात्र नेता उपेंद्र यादव, रंजन ओझा व मधुकर प्रमुख हैं. पीएमसीएच में भर्ती इन नेताओं को देखने पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान भी आए. पासवान के मुताबिक़ राज्य सरकार निरकुंश हो गई है. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे उनके नेताओं को बेरहमी से पीटा. रोहित सिंह ने बताया कि पार्टी व राज्य के लिए अगर जान भी देनी पड़ेगी तो, मैं पीछे नहीं हटूंगा. इस मौके पर पार्टी नेता शैलेंद्र सिंह और ललन चद्रवंशी भी मौजूद थे.

## टूटी हड्डियों को जोड़ना आसान हुआ

पटना में आयोजित सीसीटी 2012 में हड्डी से संबंधित रोगों पर विशेषज्ञों के बीच गहन विचार-विर्मश हुआ. मुंबई से आए डॉ. डी.डी तन्ना ने कहा कि टूटी हड्डियों के इलाज़ के लिए अब कई आधुनिक उपकरण उपलब्ध हो गए हैं. डॉ. जेफरी ने इस मौके पर कहा कि बिहार में जो आबादी है और जिस संख्या में यहां दुर्घटनाएं हो रही हैं उस अनुपात में यहां ट्रामा सेंटर का आभाव है. आयोजन सचिव डॉ. अमूल्य कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन से यहां चिकित्सकों को काफी कुछ सीखने को मिला है. ग़ौरतलब है कि इस समारोह में आधुनिक आधुनिक उपकरण के बारे में खुलकर चर्चा हुई और इसे काफी पसंद किया गया. डॉ. अमूल्य सिंह ने बताया कि हड्डी रोग और इसके इलाज़ से संबंधित नए रिसर्च को समझना और ग़रीब रोगियों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का एजेंडा हमलोगों के सामने है. हमलोगों की पूरी कोशिश है कि बिहार के मरीजों को इलाज़ के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े. इस आयोजन में एरिस्कोन फर्मा भी काफी सक्रिय रही.

– चौथी दुनिया ब्यूरो

## गोगरी में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित

गोगरी अनुमंडलअंतर्गत माधवपुर मैदान में माधवपुर और परवत्ता कन्हैयाचक के बीच 20-20 क्रिकेट मैच का शुभांरभ कांग्रेस के युवा नेता अखिल कुमार राय ने फीता काटकर किया. क्रिकेट जगत में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि, खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है. इसके अलावा यह स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है. माधवपुर क्रिकेट टीम के कप्तान दीपक कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 14.4 ओवर मे 98 रन बनाए. गौरव कुमार के नेतृत्व में खेलने उतरी कन्हैयाचक की पूरी टीम 15 ओवर में 82 रनों पर सिमट गई. माधवपुर के गौरीशंकर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया. वहीं बेलदौर प्रखंड के गांधी खेल मैदान में आयोजित तीसरे लीग मैच में बेलदौर ने उदाकिशनगंज टीम को 8 रनों से शिकस्त देकर सेमी फाइनल में पहुंची. चौथम प्रखंड अंतर्गत करूआ मोड़ स्थित दुर्गा मंदिर प्रागंण में नेहरू युवा क्लब द्वारा तीन दिवसीय खेल का आयोजन किया गया. बालक वर्ग के लिए फुटबॉल प्रतियोगिता एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

– गीता कुमार

## एकल विद्यालय अभियान प्रारंभ

हंटरगंज प्रखंड स्थित उच्चविद्यालय प्रांगण में हंटरगंज थाना प्रभारी सुनीत कुमार सिंह द्वारा दीप जलाकर एकल विद्यालय का शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि विद्यालय द्वारा बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिया जाता है और उनका गुणात्मक विकास किया जाता है. समारोह में स्थानीय सांसद प्रतिनिधि अरूण चौरसिया, एकल विद्यालय के प्रखंड व्यवस्थापक लालू यादव, संतोष कुमार यादव, भरत सिंह, ऋषि कुमार सहित काफी संख्या में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया.

## मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप

हंटरगंज प्रखंड अंतर्गत गेंजना पंचायत के पंचायत सचिव यदुनंदन सिंह पर मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. यह आरोप वार्ड सदस्य रिंकी देवी ने लगाया है. चौथी दुनिया को उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण योजना में प्रखंड कार्यालय द्वारा सीमेंट का वितरण किया जाना था, जिसका उठाव पंचायत सचिव यदुनंदन सिंह ने किया. हालांकि, इसका कोई लाभ लाभुकों को नहीं मिला और सीमेंट को खुले बाज़ार में बेच दिया गया. आरोप के मुताबिक पंचायत के आठ लाभुक क्रमश: अशोक यादव का 50 बैग, नंदू यादव का 50 बैग, बिरजू यादव का 50 बैग, गनपत यादव का 55 बैग, कृष्णा यादव का 35 बैग, बिगन यादव का 40 बैग, उर्मिला देवी का 60 बैग और कपिल यादव को मिले 50 बैग की निकासी कर ली गई. इस बावत मुखिया उपेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले की जांच कराने का अनुरोध प्रखंड विकास पदाधिकारी छुटेश्वर दास से की गई है.

## शिवालय बना आकर्षण का केंद्र

हंटरगंज प्रखंड के हिरींग गांव में स्थापित भगवान शिव का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आर्कषण का केंद्र बन गया है. महाशिवरात्रि के अवसर पर काफी संख्या में झारखंड और बिहार के श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की अराधना की. इस शिवालय का निर्माण हिरींग गांव के निवासी तथा झुमरीतिलैया महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य स्व. डॉ. गणेश नारायण सिंह ने सन् 1982 में करवाया था. यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए काफी मशहूर है. ग़ौरतलब है कि पूर्व प्राचार्य स्व. डॉ. गणेश नारायण सिंह द्वारा ही झारखंड के चतरा ज़िला अंतर्गत इटखोरी में मां भद्रकाली मंदिर परिसर में विवाह मंडप का निर्माण कराया गया है.

– अमरेंद्र प्रताप सिंह

21 मार्च 1916 को जन्में कमरूद्दीन किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का बचपन का नाम है.

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

# राजो सिंह के सपनों को वारिस का इंतज़ार

**सत्ता के साथ साझेदारी में समझदारी की राजनीति करने वाले राजो सिंह प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे. उसके बाद वह मुखिया बने और फिर सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद वह सांसद बने. शेखपुरा ज़िला की राजनीति में राजो सिंह की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से समझा जा सकता है कि, उनके दरबार में उच्चाधिकारियों से लेकर सत्ता के मंत्रिमंडल सदस्यों तक की चौकड़ी लगती थी और ज़िले में मुखिया से लेकर विधायक-सांसद तक चुनाव जीतने के लिए राजो सिंह के आशीर्वाद को जीत का पैमाना मानते थे.**

अरूण साथी

सत्ता की हनक क्या होती है, इसका अहसास मगध क्षेत्र की जनता सहित पूरे बिहार को राजो सिंह ने कराया था. अपने इलाक़े में उन्होंने विकास की ऐसी कहानी लिखी कि, इस भौगोलिक भूखंड की पहचान ही राजो बाबू से जुड़ गया. चुनावी राजनीति में अपराजेय और विधायी कार्यों में दक्ष राजो सिंह की कमी आज भी लोगों को अखरती है, क्योंकि उनकी विरासत को संभालने का काम अधूरा पड़ा है और विकास को लेकर उनकी परिकल्पना योग्य उत्तराधिकारी की तलाश कर रही है.

शेखपुरा ज़िला राजो बाबू के नाम से ही पहचाना जाता है. कांग्रेस के पूर्व सांसद एवं शेखपुरा ज़िला के संस्थापक कहे जाने वाले स्व. राजो सिंह को यहां के लोग राजो बाबू के नाम से ही जानते हैं. उनकी कार जब राजो सिंह को लेकर पटना से चलती थी, तो ज़िले के चौक–चौराहे पर मालाएं लेकर लोग अपने नेता के आने का इंतज़ार करते थे. राजो सिंह जब अपने क्षेत्र के गांवों का दौरा करते थे, तो ग्रामीण महिलाएं घूंघट काढ़े घरों से निकल पड़ती थीं. दरअसल राजो सिंह ने जनता को यह महसूस कराया कि विकास का रास्ता पटना से ही निकलता है और पटना में जिसकी जैसी ताकत होती है, वह अपने इलाक़े का इसी अनुपात में कायाकल्प कर सकता है. यही वजह थी कि, शेखपुरा के लोगों ने राजो सिंह को दिल खोलकर ताकत दी और राजो सिंह ने भी आजीवन उन्हें निराश नहीं किया.

सत्ता के साथ साझेदारी में समझदारी की राजनीति करने वाले राजो सिंह प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे. उसके बाद वह मुखिया बने और फिर सक्रिय राजनीति में उतरने के बाद वह सांसद बने. शेखपुरा ज़िला की राजनीति में राजो सिंह की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से समझा जा सकता है कि, उनके दरबार में उच्चाधिकारियों से लेकर सत्ता के मंत्रिमंडल सदस्यों तक की चौकड़ी लगती थी और ज़िले में मुखिया से लेकर विधायक–सांसद तक चुनाव जीतने के लिए राजो सिंह के आशीर्वाद को जीत का पैमाना मानते थे. वर्ष 1972 से राजनीति का सफ़र शुरू कर राजनीति में नए कृतिमान स्थापित करने वाले राजो सिंह की 9 सितंबर 2005 में गोली मार कर हत्या दी गई. अपराधियों ने उन्हें आज़ाद हिंद आश्रम में ही गोली मारी जहां वह अधिकारियों के साख विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. राजो सिंह के अवसान की यह कहानी वर्ष 2001 में शुरू हुई, जब राजो सिंह के सहयोगी एवं बरबीघा के विधायक रहे महावीर चौधरी की जगह उनके पुत्र अशोक चौधरी विधायक बने और फिर कारा राज्य मंत्री बन बरबीघा की राजनीति की कमान संभाली. अशोक चौधरी ने वर्ष 2001 में बरबीघा की हक़मारी का आरोप लगाते हुए राजो सिंह के वर्चस्व को चुनौती दी. सियासी रंजिश के इस खेल में 26 दिसंबर 2001 को टाटी नरसंहार का रूप लिया, जिसमें ज़िला परिषद सदस्य अनिल महतो, राजद नेता काशी पहलवान सहित कई लोगों को बरबीघा–शेखपुरा पथ पर राजो सिंह के गांव के निकट दिनदहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया. मारे गए सभी लोग कारा राज्य मंत्री अशोक चौधरी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहे थे. इस नरसंहार ने ज़िले की राजनीति को नई करवट दी और राजो सिंह समेत उनके पूरे कुनबे को इस मामले में नामज़द करार दिया. इस मामले में उनके मंत्री पुत्र संजय सिंह, भतीजा मृत्युंजय सिंह, दिवाकर सिंह, उदयशंकर सिंह, अरूण सिंह, पौत्र कन्हैया सिंह, समधी वृजनंदन सिंह, कृष्णनंदन सिंह, श्याम सिंह एवं नब्बे वर्षीय मुखिया बांके सिंह को नामज़द किया गया. कभी राजद नेता लालू प्रसाद के क़रीबी रहे राजो सिंह की तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से बढ़ती नज़दीकियों को लेकर उनकी राजनीति प्रतिद्वंदिता इस क़दर पलटी की वर्तमान मंत्रिमंडल के कई नेता शेखपुरा पहुंच कर राजनीतिक रोटियां सेंकनी शुरू कर दी. शेखपुरा में राजो सिंह द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किए गए सूचना पटों को तोड़ दिया गया. इस मामले में सांसद सहित नामज़द लोगों को जेल में रहना पड़ा और परिणामत: 15 अक्टूबर 2010 को मुंगेर कोर्ट में पेशी के दौरान संजय सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

वर्तमान में उनकी पुत्रवधु सुनीला देवी दो बार विधायिक रहने के बाद, इस बार चुनाव हार गईं और राजनीति में महज खानापूर्ति करने के लिए रह गई हैं. इस चुनाव में जहां सुनीला देवी कांग्रेस की टिकट पर शेखपुरा विधान सभा से चुनाव लड़ रही थी, वहीं उनके पुत्र सुदर्शन बरबीघा विधान सभा से लोजपा की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे. हालांकि दोनों सीटों पर मां–बेटे को हार का सामना करना पड़ा. फिलहाल ज़िले की राजनीति में विपक्ष किसी भी मोर्चे पर खड़ी नहीं दिखती. वहीं कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले इस ज़िले में पार्टी का कोई नामलेवा नहीं है. ग़ौरतलब है कि राजो सिंह के हत्या में पूर्व कारा राज्य मंत्री अशोक चौधरी को भी नामज़द किया गया था. उसके बाद से आज तक कांग्रेसियों के बीच बनी खाई फ़िलहाल पटने का नाम नहीं ले रहा. मिसाल के तौर पर कभी खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही कहने वाले राजो सिंह की हत्या के बाद शेखपुरा कांग्रेस कार्यालय में राजो सिंह की प्रतिमा को अनावरण के लिए कपड़ों से ढंक कर रखा गया है, लेकिन एक दशक बाद भी किसी कांग्रेसी नेता को यह सुध नहीं आई कि वह स्व. राजो सिंह की प्रतिमा का अनावरण करा सकें. राजो सिंह राजनीति की, जो विरासत छोड़ गए उसे संभालने वाला कोई नहीं है. विकास के साथ सत्ता का जो मंत्र राजो सिंह पढ़ते थे, उस पर अमल करने वाला कहीं नज़र नहीं आता. शेखपुरा व बरबीघा सहित पूरे मगध को इंतज़ार है, उस हाथ कि, जो उनके विरासत को संभाल सके.

feedback@chauthiduniya.com

## ॥ नेताजी कहिन ॥

जिन्हें राजो बाबू की विरासत संभालनी थी, वे संजीदा नहीं हैं. राजो बाबू सदन के कार्यकाल का पूरा उपयोग करते थे. बावजूद इसके उनके परिजनों ने कोई सीख नहीं ली. राजो बाबू की कृपा से ललन सिंह व रमेंद्र कुमार जैसे नेताओं ने राजनीतिक फ़सल काटी, लेकिन इनलोगों ने उनके प्रति कोई सम्मान नहीं जताया.

– नीरज कुमार *(जदयू विधान पार्षद)*

किसी वटवृक्ष के नीचे दूसरे वृक्ष का पनपना अपवाद ही होता है. राजो बाबू जैसे महान व्यक्तित्व की विरासत को संभालने के प्रति उनके समर्थक गंभीर नहीं रहे, लेकिन इतना तय है कि राजो बाबू ने विकास का जो सपना देखा था, वह हर हाल में पूरा होगा.

डॉ. सूर्यमणि सिंह
(वरिष्ठ कांग्रेसी नेता)

राजो सिंह एक अपराजेय योद्धा थे ,उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस्ट का कोई विकल्प नहीं होता. जहां तक उनकी विरासत का सवाल है, तो उनके परिजनों से कहीं ज्यादा बिहार के हर ज़िले में उन्हें चाहने वाले लोग उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं.

सुधीर शर्मा
(प्रवक्ता, भाजपा)

# बिस्मिल्ला खां का ग़लत नाम पढ़ रहे हैं बच्चे

कहने को हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन लगता है कलम वही है, स्याही बदल गई है. पक्षी यह समझते हैं कि गगन बदल गया है. मानव यह समझते हैं कि चमन बदल गया है, लेकिन श्मशान की यह खामोशी कहती है लाश वही है कफ़न बदल गया है. डॉ. राही मासूम रज़ा कि ये पंक्तियां मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार पर पूरी तरह सटीक बैठती है. बिहार के बारह लाख से अधिक बच्चों के भविष्य संवारने का सपना संजोए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना द्वारा प्रकाशित दसवीं की कक्षा के हिंदी पुस्तक गोधूलि भाग–2 में भारत रत्न बिस्मिल्ला खां के नाम के साथ खिलवाड़ किया गया है. बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम कमरूद्दीन है, जबकि इसे टेक्स्टबुक पब्लिसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार ने अपने संस्करण में अमीरूद्दीन के नाम से प्रकाशित किया है. दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले पूरे बिहार के लगभग 12 लाख छात्र उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम कमरूद्दीन की जगह अमीरूद्दीन पढ़कर गुमराह हो रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि बिहार के बक्सर ज़िले के डुमरांव में बख्श खां के घर 21 मार्च 1916 को जन्में कमरूद्दीन किसी साधारण व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का बचपन का नाम है. बीटीसी के दसवीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधूलि भाग दो के प्रथम संस्करण (वर्ष 2010–11) नौबत खाने में इबादत के पृष्ठ संख्या 92 से 97 में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम 12 बार अमीरूद्दीन प्रकाशित किया गया है, जबकि वेबसाइट तथा अन्य किताबों में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां के बचपन का नाम कमरूद्दीन लिखा गया है. विश्व में अपनी शहनाई की धुन से सबको मुरीद बनाने वाले उस्ताद आज अपने पैतृक राज्य बिहार में ही ग़लत नाम से नवाज़े जा रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की बिहार टेक्स्टबुक पब्लिसिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह पुस्तक निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत भी है. ऐसे में प्रदेश में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे भारत रत्न के बचपन का नाम ग़लत पढ़ रहे हैं. ज़ात हो कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां अपने जन्म के छह वर्षों तक डुमरांव में रहने के बाद काशी(बनारस) में नानी के घर चले गए. बाद में उन्होंने अपने परदादा सलार हुसैन से शहनाई की वारीकियां सीखी थी. एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सौ वर्ष पूरे होने पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां को अपने राज्य का होने पर गर्व महसूस करते हैं, वहीं सरकारी पदाधिकारियों व उनके मातहतों की लापरवाही की वजह से भारत रत्न बिस्मिल्ला खां के नाम के साथ खिलवाड़ कर उनके सम्मान को ठोस पहुंचाई जा रही है. ऐसे में बिहारी छात्रों के सामने ग़लत सूचना प्रस्तुत किए जाने से उन्हें भ्रमित होना पड़ा रहा है. इस पूरे मामले पर बिहार राज्य टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशुतोष ने भी ग़लत नाम छपने की बात स्वीकार करते हुए कहा की अगले संस्करण में इसे सुधार दिया जाएगा.

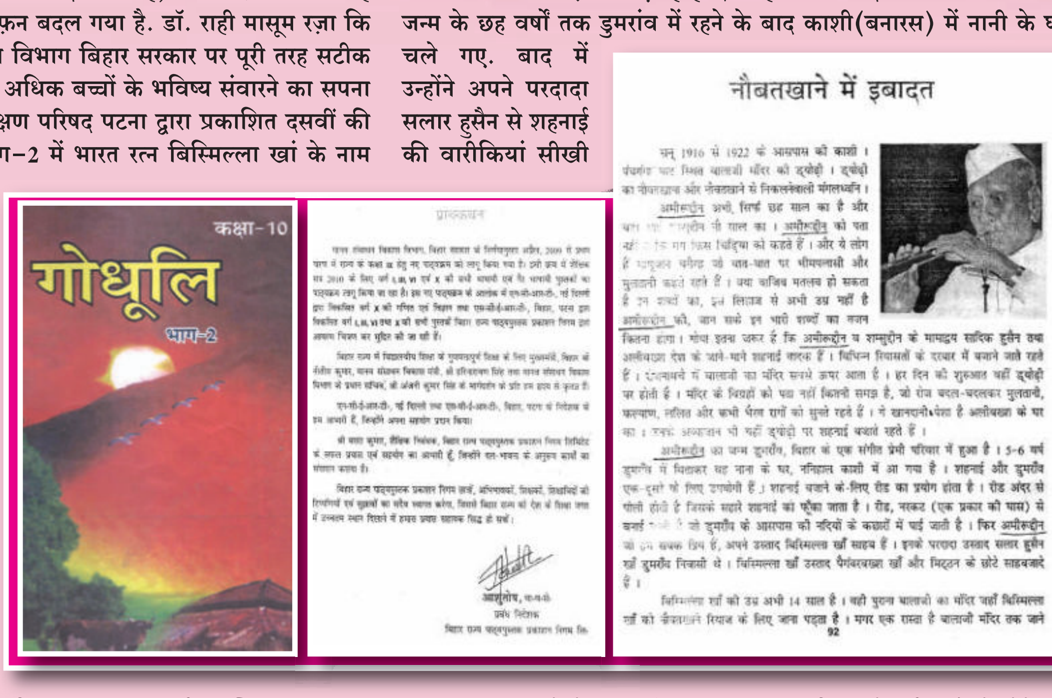


सुमरजीत
feedback@chauthiduniya.com

इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च
हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेउर, पटना-२
(बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार तथा आइ.ए.पी.से मान्यता प्राप्त)
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया से संबंधन प्राप्त

We Impart:-

POST GRADUAGE COURSES:
MPT Master of Physiotherapy
MOT Master of Occupational Therapy
MPO Master of Prosthetic & Orthotic
MASLP Master of Audiology & Speech Language Pathology
BPT Bachelor of Physiotherapy
BOT Bachelor of Occupational Therapy
BPO Bachelor of Prosthetic & Orthotic
BASLP Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology
BMRT Bachelor of Radio Imaging Technology
BMLT Bachelor of Medical Laboratory Technology
B.Ed. (Special Education)
B.Ophth. Bachelor of Ophthalmology

संस्थान द्वारा संचालित निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
- स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
- टीकाकरण
- फिजियोथेरापी
- अकुपेशनल थेरापी
- स्पीच थेरापी
- नेत्र जाँच
- सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो,लकवा,गठिया,हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
- हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जाँच एवं उपचार हियरिंग-एड
- मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जाँच एवं उपचार
- कृत्रिम हाथ,पैर,कैलीपर,पोलियो के जूते,वैशाखी, सर्वाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
- लाचार विकलांगों को तिपहिया-साकिल तथा व्हीलचेयर
- विकलांगों की शल्य चिकित्सा,सर्जिकल करेक्शन
- रियायती दर पर पैथोलोजिकल जाँच,एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य

1 Yr. ABRIDGED DEGREE For DPT & DOT

DIPLOMA COURSES:
DPT Diploma in Physiotherapy
DPO Diploma in Prosthetic & Orthotic
DMLT Diploma in Medical Lab. Tech
D-X-Ray Diploma in x-ray Technology.
DHM Diploma in Hospital Management
DOTA Diploma in Operation Theater Assistant
DECG Diploma in E.C.G.

certificate courses:
CMD Certificate in Medical Dressing
Foundation Course for Teachers in Disability

Form & Prospectus:- Available at the institute counter against payment of Rs. 300/-. Send a DD of Rs. 350/-only for postal delivery, in favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna-2

Eligibility:- For Post Graduate Courses-Degree in the same. 10+2 with science for Under Graduate & Diploma Courses. For B.Ed. Degree in any Subject.

Admission Going On...

डा.अनिल सुलभ
निदेशक-प्रमुख

फोन न. : 0612-2253290, 2252999, फैक्स: 0612-2253290,email. iiher_beur@gmail.com, www.iiher.org

चौथी दुनिया
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
दिल्ली, 09 अप्रैल-15 अप्रैल 2012
www.chauthiduniya.com

# वज़ीरेआला के आला अफसर

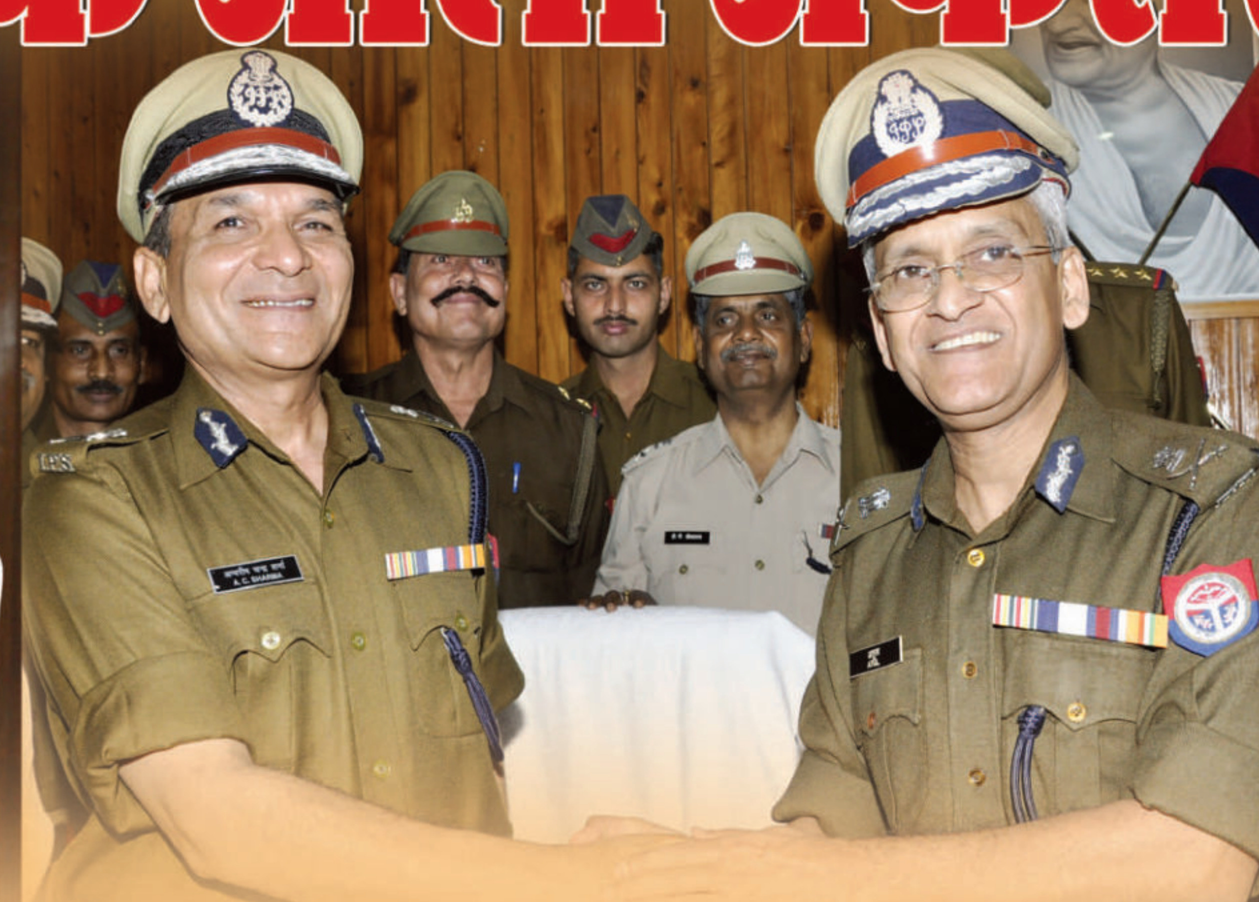

अजय कुमार

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही कई तरह के बदलाव किए हैं. इसके तहत साफ़ सुथरी छवि वाले अधिकारियों को भविष्य में किसी प्रकार से प्रशासनिक आधार पर अपमानित नहीं होना पड़ेगा और न ही कोई इस बात का सरकार पर आरोप लगा सकेगा कि पुरानी सरकार के लोगों को तैनाती दी जाने लगी है, इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एनेक्सी के पंचम तल से लेकर जनपदों तक में तैनात अधिकारियों के बारे में इस बात की जानकारी दी है कि तमाम ईमानदार अधिकारियों को निष्पक्षता से काम करने के कारण कष्ट उठाना पड़ता है और वे अधिकारी जो एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे, उन्हें कितना महत्व मिला. इसी के तहत पंचम तल पर तैनात प्रमुख सचिव नेतराम, रविंद्र सिंह, कुंवर फतेह बहादुर, डीएस मिश्रा, आरपी सिंह, सचिव चंद्रभानु, नवनीत सहगल को हटाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री को जब इस बात की जानकारी हुई कि पंचम तल के प्रमुख सचिव आरपी सिंह तथा सचिव चंद्र भानु निष्पक्ष एवं नियमानुसार कार्य कर रहे थे तो उन्होंने इन दोनों अधिकारियों से मनचाही पोस्टिंग पर जाने की जानकारी कराई. आरपी सिंह ने नियोजन विभाग में जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें प्रमुख सचिव नियोजन बना दिया गया तथा चंद्रभानु ने व्यापार कर में जाने की इच्छा जताई, लेकिन वहां पहले से अधिकारी के तैनात होने के कारण दूसरी जगह बताने को कहा गया. इसके बाद सरकार ने चंद्रभानु को सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद् बना दिया. वहीं स्वच्छ छवि के अनुराग यादव को लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा शशांक शेखर को पूर्व सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को एक झटके में समाप्त करने का फ़ैसला किया गया. शेष अधिकारियों को प्रतीक्षारत सूची में डाल दिया गया. जहां तक ज़िलों के प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले का सवाल है तो इसमें भी फ़ैज़ाबाद के जिलाधिकारी को कानपुर का जिलाधिकारी, इलाहाबाद के जिलाधिकारी को सीतापुर का जिलाधिकारी, मेरठ के जिलाधिकारी को इलाहाबाद का जिलाधिकारी बनाए जाने जैसे उदाहरण भी देखने को मिले. जबकि प्रतीक्षारत बलविंदर कुमार को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद बनाया गया. इसी तरह आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों में भी सरकार ने अपनी नीति का अनुपालन किया है. अखिलेश यादव ने अपनी टीम में उन चुनिंदा स्वच्छ छवि के अफसरों को शामिल किया है. जो प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त करें. कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों में विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री के पास 61 विभाग मौजूद हैं. जिन्हें वह स्वयं डील करेंगे. मुख्यमंत्री के पास फाइलें ले जाने का जिम्मा तेज़ तर्रार आईएएस अनीता सिंह को सौंपा गया है. जिन वरिष्ठ अफसरों को विभागों की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें सीएम के सचिव आलोक कुमार द्वितीय को कर एवं निबंधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, प्राथमिक एवं वैकल्पिक शिक्षा, उच्चशिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण, सूचना, केंद्र सरकार से संबंधित समन्वय कार्य, लघु उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, व्यावसायिक शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, संस्थागत वित्त, भूत्व एवं खनिकर्म, कांशीराम शहरी विकास योजना विभाग हैं. वहीं विशेष सचिव पंधारी यादव के जिम्मे गृह, सतर्कता, अपराध अनुसंधान, अभिसूचना, राजनीतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा, कारागार, होमगार्ड्स, प्रोटोकाल, आवास, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, संस्कृति, नागरिक उड्डयन, नियुक्ति एवं कार्मिक, पर्यटन, सचिवालय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, राज्य संपत्ति और गोपन विभाग दिए गए हैं. इसके अलावा विशेष सचिव जुबैर बिन सगीर को अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ, हज, राष्ट्रीय एकीकरण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कार्यक्रम क्रियान्वयन, धर्मार्थ कार्य, विकलांग कल्याण, बैंकिंग, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, ग्राम्य विकास एवं समन्वय, कृषि, कृषि विपणन एवं निर्यात, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, मातृ एवं शिशु कल्याण, रेशम, उत्तरांचल समन्वय, भाषा, उद्यान एवं खाद्य संस्करण, अंबेडकर ग्राम विकास, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, भूमिक विकास एवं जल संसाधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, खाद्य एवं रसद, परती भूमि विकास, बाह्य, सहायतित परियोजना, समाज कल्याण विभाग जैसे विभागों को सौंपा गया है तथा विशेष सचिव शंभू सिंह यादव के पास परिवहन, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, वन, पर्यावरण, न्याय, विधायी, संसदीय कार्य, नियोजन, लोक निर्माण, सहकारिता, पंचायती राज, आबकारी और मद्यनिषेध, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग हैं. मुख्यमंत्री के ओएसडी जगदेव सिंह के पास राजस्व, राजस्व अभाव एवं सहायता पुनर्वास, निर्वाचन, वैकल्पिक ऊर्जा, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत, सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ , श्रम, सचिवालय के विभिन्न प्रकोष्ठों का समन्वय कार्य, सामान्य प्रशासन, लघुसिंचाई, विवेकाधीन एवं पीड़ित कोष, घोषणा प्रकोष्ठ, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, प्रांतीय रक्षक दल, हथकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, वस्त्र उद्योग, सार्वजनिक उद्यम, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं ग़रीबी उन्मूलन विभाग है. पुलिस विभाग को चुस्त दुरूस्त करने के लिए अंबरीश चंद्र शर्मा को पुलिस महानिदेशक बनाया है. उनके सामने प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बनाये रखने की बड़ी चुनौती है. हालांकि डीजीपी का कहना है कि प्रदेश के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी. अपराधी या तो जेल जाएंगे या प्रदेश से बाहर होंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार में जावेद उस्मानी मुख्य सचिव बनाए गए हैं. हालांकि ईमानदार छवि के जावेद उस्मानी 16 अफसरों को सुपरसीड कर मुख्य सचिव की कुर्सी तक पहुंचे हैं. उस्मानी ने जिन 16 अफसरों को सुपरसीड किया है, उनमें आरके शर्मा, विजय कुमार शर्मा, अरूण कुमार विट, जगन मैथ्यूज, नीता चौधरी यूपी में नियुक्त हैं, लेकिन दूसरे आईएएस अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में सेवा कर रहे हैं. इसी प्रकार अनूप मिश्र ने भी जिन 28 अफसरों को सुपरसीड किया था, उसमें 1974 बैच के पुलक चटर्जी, प्रभात चतुर्वेदी, रीता मेनन, 1975 बैच की जयति चंद्रा, के चंद्रमौली, 1976 बैच के नसीम अहमद जैदी, प्रोमिला शंकर, रवींद्र कुमार शर्मा, प्रदीप कुमार मिश्रा, विजय कुमार शर्मा, अरूण कुमार मिश्र, पी उमाशंकर, अरूण कुमार विट, 1977 बैच के निदेश कुमार मित्तल, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, शेखर अग्रवाल, मुहम्मद हलीम खां, लोरेटा मेरी वास, प्रदीप कुमार सिन्हा, वी. वेंकटाचलम, जगन मैथ्यूज, नीता चौधरी 1978 बैंच के जावेद उस्मानी, सौरभ चंद्रा, आलोक रंजन, लव वर्मा, केके सिन्हा, प्रेम नारायण हैं, जिनमें कुछ अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

सुपरसीड करने की परंपरा कोई नई नहीं है. इसके पहले भी बसपा सरकार में डीएस बग्गा कांशीराम के चहेते होने के कारण इस कुर्सी से नवाजे गए, वहीं अखंड प्रताप सिंह, नीरा यादव जैसे अफसर सपा सुप्रीमो के विश्वासपात्र होने के नाते मुख्यसचिव की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे. जावेद उस्मानी ऐसे पहले अल्पसंख्यक मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने 1977 में सिविल सर्विसेज परीक्षा में टॉप किया था. उन्होंने आईएएस परीक्षा की तैयारी संयोगवश अनूप मिश्र के साथ ही की थी. दोनों एक ही बैच के अफसर हैं. उनकी ईमानदार छवि और कार्य कुशलता की चर्चा बुद्धिजीवियों के बीच होती है. काफ़ी सोच समझकर ही सपा सरकार ने वरिष्ठ अफसर का चयन किया है. जावेद उस्मानी का कहना है कि प्रदेश के विकास को बढ़ाने में जो भी अड़चनें होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा. टीम भावना के साथ कार्य किया जाएगा. जिससे अधिकारियों का मनोबल ऊंचा हो सके. ग़लत कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, प्रदेश में शांति और व्यवस्था तथा अमन चैन के लिए पुलिस महानिदेशक के साथ मिलकर काम होगा. इस बात की पुरज़ोर कोशिश की जाएगी प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन मिले. बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य

शेष पृष्ठ 18 पर

## सरकार की नई तबादला नीति

अखिलेश यादव सरकार ने पिछले शासन की तबादला नीति को खारिज करते सर्, 2012-13 के लिए नई तबादला नीति की घोषणा कर दी है, जो तत्काल लागू भी हो गई है. इस नीति से मंत्रियों को तबादलों के लिए अधिकृत कर दिया गया है. मंत्रियों को उनका अधिकार वापस मिल गया है. नई नीति में तबादलों के कुछ आधार तय किए गए हैं, वे सार्थक तभी होंगे, जब उन पर सही तरह अमल हो. इसके तहत एक ज़िले में लगातार छह वर्ष तक और मंडल में दस वर्ष तक काम करने वाले समूह क तथा ख के अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा. इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है. तबादला नीति के तहत मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेजा जा चुका है. शासन द्वारा जारी नई स्थानांतरण नीति के तहत विकलांग श्रेणी को मुक्त रखा गया है. नई नीति के तहत आच्छादित होने वाले प्रकरणों की सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है. समूह ख के अधिकारियों के तबादले विभागाध्यक्ष के अधीन होंगे. विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर विचलन किया जा सकता है. इसके अलावा जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री कभी भी किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण के आदेश दे सकते हैं. समूह ग एवं घ के कर्मचारियों के लिए विभागीय मंत्री तबादले का अनुमोदन करेंगे. तबादले की अंतिम तिथि 30 जून 2012 है. इसके बाद कोई भी तबादला मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाएगा. समूह क के अधिकारियों का तबादला उनके गृह मंडल में नहीं किया जाएगा. इसी प्रकार समूह ख के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में नहीं किया जाएगा, लेकिन यह प्रतिबंध केवल जनपद, स्तरीय कार्यालय में ही लागू होगा. नई तबादला नीति के मुताबिक स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा और तबादला नीति के इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के ख़िलाफ़ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. जो अधिकारी स्थानांतरित कर्मचारियों को अवमुक्त नहीं करेंगे. उनके ख़िलाफ़ भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण न कर लें. स्थानांतरण नीति में सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष और सचिव संघ का पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के लिए मुक्त रखा गया हैं. उनमें ज़िला शाखाओं के अध्यक्ष और सचिव भी शामिल हैं. बहरहाल अखिलेश यादव सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में सुधार का जो भरोसा दिलाया है, इसे तभी पूरा किया जा सकता है जब नौकरशाही बदलाव के लिए तत्पर होगी.

## आवश्यकता है

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया को उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों एवं ज़िलों में आवश्यकता है संवाददाताओं, विज्ञापन प्रतिनिधियों एवं प्रसार व्यवस्थापकों की. अनुभवी एवं कार्यरत लोगों को वरीयता दी जाएगी. सम्मानजनक वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय. इच्छुक लोग पूर्ण विवरण के साथ अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं:-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11
नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष -0120-6451999, 6452888, 6450888
Email -advt.uttarpradesh@gmail.com

रिंकू सिंह लोकसेवा आयोग से चयनित होने के बाद 24 नवंबर 2008 को मुजफ्फरनगर में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे.

संगोष्ठी में वरिष्ठ आलोचक प्रो. वारिस किरमानी ने कहा कि हिंदुस्तानी कहानी के मयार में बेदी के अफ़साने विश्वस्तरीय हैं.



# वज़ीरआला के आला अफसर

पृष्ठ 17 का शेष

# पिता हेडमास्टर तो बेटा मास्टर

दर्शन शर्मा

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों से दो टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पूर्ण बहुमत दिया है, इसके मद्देनज़र सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनने और उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुशासित तरीक़े से काम करना चाहिए. ताकि सरकार के प्रति जनता की आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आए और आने वाले दिनों में वह जनता के हितों को सर्वोपरि मानती रहे, इसी में सरकार और पार्टी का हित है. ढाई घंटे चली इस पाठशाला में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे. मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण के बाद से सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करने की सलाह दी जिससे पार्टी की ग़लत छवि जनता में बने. उन्होंने प्रदेश के मंत्रियों से हर क़ीमत पर विवादों से बचने की सलाह दी. उन्होंने मंत्रियों को अनुशासन की घुट्टी पिलाते हुए कहा कहा कि सरकार अनुशासन और कार्य के मामले में ऐसा उदाहरण पेश करे, जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार आदर्श रूप में देखी जाए और अन्य राज्य इसका अनुशरण करें. प्रदेश में सरकार बनने के बाद मंत्रियों के स्वागत समारोह में होने वाली घटनाओं और विभागीय कार्यों के बारे में सुधार करने के संकेत दिए. उन्होंने युवा मुख्यमंत्री की सरकार को बेदाग़ बनाने के गुर सिखाए. उन्होंने कहा कि यदि छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी बातें एक दिन पार्टी के लिए अहितकर होंगी. यह उचित नहीं है. इसका नुक़सान सभी को किसी न किसी रूप में उठाना पड़ेगा. ऐसे में बेहतर होगा सभी लोग जनता के प्रति सौ फ़ीसदी जवाबदेह हो और जनता के हितों को ध्यान में रख कर कार्य करें ताकि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले सकें. प्रदेश की जनता के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार रहें, तभी प्रदेश की प्रगति होगी और सरकार की जनता में अच्छी छवि बनेगी. साथ ही जनता एवं सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा. कार्यकर्ता गांव-गांव जाएं और जनहित के कार्य करें, उनका विश्वास जीते. लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं हैं. सारे जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मिलकर कार्य करें. जिससे आगे चलकर अच्छे परिणाम मिलेंगे. लोकसभा चुनावों में हमें 80 सीटें जीतनी होंगी. शायद यह पहला अवसर था जब किसी बैठक के बाद प्रदेश के मंत्री अपनी गाड़ियों में बैठकर प्रस्थान कर गए. इस मौक़े पर मंत्रियों से बैठक में हुई चर्चा की जानकारी चाहने वालों को निराशा ही हाथ लगी.

देश के सबसे बड़े सूबे के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ग़रीब, मजदूर, किसान, शासकीय कर्मचारी, शिक्षक और आम जनता सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आतुर दिख रहे हैं. उनकी पूरी कोशिश है कि पिता के नक्शेक़दम पर चलते हुए पार्टी का नाम रोशन करें. उन्होंने प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए संबंधित विभाग से एक माह में नीति पर रिपोर्ट मांगी है. साथ ही ज़ोर देकर कहा है कि सरकार किसी भी क़ीमत पर किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी. यह बात उन्होंने एनेक्सी भवन स्थित कार्यालय में गेहूं ख़रीद, खरीफ की फ़सल हेतु खाद बीज की व्यवस्था तथा सहकारिता विभाग के सबंध में आयोजित बैठक में कही. मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की ख़रीद के लिए सभी ज़रूरी प्रबंध समय से पूरे किए जाने चाहिए. मंडी परिषद् यह सुनिश्चित करें कि किसानों को समर्थन मूल्य से कम मूल्य कतई न मिले. साथ ही अनाज के सुरक्षित भंडारण की मुकम्मल व्यवस्था के भी उपाय किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया है कि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज, बिजली एवं पानी मुहैया होना चाहिए. उन्होंने प्राथमिक सहकारी समितियों और ज़िला सहकारी बैंकों में व्यापक सुधार के निर्देश दिए. एक हज़ार करोड़ के केंद्र सरकार के पैकेज को शीघ्र प्राप्त करने की मंत्रणा भी उन्होंने की. ज़िला सहकारी बैंकों में किए गए कंप्यूटरीकरण में हुई अनियमितताओं पर चिंता जताई. अखिलेश यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है. चूंकि मायावती ने जून 2009 में एक आदेश पारित कर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मंत्रियों से संबंधित जानकारियां राज्यपाल की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा लिखे गए पत्र, हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति आदि की जानकारी देने से इंकार कर दिया था. आरटीआई कार्यकर्ताओं और एनजीओ के काफ़ी हल्ला मचाने के बाद भी इन आदेशों को मायावती सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था. अब जनविश्वास पैदा करने के लिए प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया है कि मंत्रियों और अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक की जाएगी. उन्हीं क़दमों से जनता के बीच सपा सरकार की अच्छी छवि निखरकर सामने आएगी. मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए मंत्रिपरिषद् के गठन में सभी समुदायों से मिले समर्थन का भी पूरा ध्यान रखा है. उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद् में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ही दलित, ब्राह्मण और वैश्य समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है. उन्होंने एक महिला विधायक को मंत्री बनाया है. अखिलेश का संकल्प है कि वह डॉ. लोहिया और जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाएंगे. वह शिक्षा की तस्वीर, बिजली का उत्पादन और आपूर्ति सुधारने और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने, प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कटिबद्ध है.

feedback@chauthiduniya.com

## लोकसभा चुनाव
## जीत की उम्मीद में मुलायम

उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं. कल तक जो नेता और दल मुलायम को चुका हुआ मानते थे, अब वही मुलायम से क़रीबी बढ़ाने की कोशिश में हैं. मौक़े का फ़ायदा उठाने में माहिर नेताजी भी बदले हालात से खुश हैं. उन्हें लगता है कि वर्ष 1996 में प्रधानमंत्री बनने का जो सपना अधूरा ही रह गया था उसे वर्ष 2014 में या उससे पहले पूरा किया जा सकता है. जो लोग विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी को बीमार मानते थे, वह हैरान हैं कि मुलायम इतने चुस्त-दुरूस्त कैसे दिखने लगे हैं. कहते हैं कि समय साथ होता है तो बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं. ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है. ऐसे सुनहरे मौक़े का भला कोई कैसे फ़ायदा उठाना नहीं चाहेगा. ख़ासकर तब तो ज़रूर जब ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो. यही वजह है कि आत्ममुग्ध मुलायम लोकसभा चुनाव के समय से पहले हो जाने की संभावना जताने लगे हैं. वह जानते हैं कि अभी बात नई-नई है. जनता को समाजवादी पार्टी में अच्छाईयां नज़र आ रही हैं. ऐसा समय हमेशा नहीं रहने वाला है. इसीलिए वह सपा सरकार की छवि बरकरार रखने के लिए भी सक्रिय हैं. राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनावी घोषणापत्र पर तेजी से अमल करने की सलाह देकर मुलायम ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं. यादव ने समाजवाद के प्रणेता डॉ. राम मनोहर लोहिया की 102वीं जयंती पर लखनऊ में आयोजित एक समारोह में जब कहा कि प्रदेश में छह माह में परिवर्तन दिखना चाहिए और साल भर में घोषणापत्र लागू हो जाना चाहिए क्योंकि लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं तो उनके समर्थकों और विरोधियों सभी के माथे पर बल पड़ गए. इस हक़ीक़त से इंकार भी नहीं किया जा सकता है, इस समय सपा के पास वो सब कुछ है जिसके बल पर वह देश को मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा सकती है.

मध्यावधि चुनाव की संभावना व्यक्त करने से पूर्व मुलायम ने केंद्र सरकार में सपा की भागीदारी की बात को जिस तरह से नकारा था, तब भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पाप की गठरी अपने कंधों पर नहीं ढोना चाहती है. इस समय मुलायम की उंगलियां घी में हैं. एक तरफ़ वह कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को समर्थन देकर अपनी राह आसान कर रहे हैं दूसरी तरफ़ कांग्रेस को फटकार भी लगा रहे हैं. उन्हें पता है कि अगर वह यह कहेंगे कि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखने के लिए वह कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं तो इससे उनका वोट बैंक कतई प्रभावित नहीं होगा. बस, इसी एक मंत्र के सहारे वह अपनी राजनीतिक नैया को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. वैसे इंकार इस बात से भी नहीं किया जा सकता है कि मुलायम के लिए केंद्र की लाचार और कमजोर सरकार ज़्यादा मुफ़ीद रहती है, वह अपनी बात उससे जैसे चाहें पूरी करवा सकते हैं. इसी के सहारे वह केंद्र से प्रदेश के लिए अधिक से अधिक पैसा बटोर लेना चाहते हैं. उन्हें पता है कि भले ही केंद्र से मदद के मामले में बसपा सरकार को मुंह की खानी पड़ी हो लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा नहीं होगा. हो सकता है जल्द ही केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के लिए किसी पैकेज की घोषणा कर दे. बताते हैं कि केंद्र से मदद के लिए सपा सरकार नहीं समाजवादी पार्टी मोर्चा लेगी. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने बीते कई वर्षों से केंद्र में लंबित प्रदेश के प्रस्तावों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है. केंद्र से मदद के लिए रास्ता सुलभ हो इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौकरशाहों की टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है. केंद्र के पास पड़े प्रस्तावों की ताजा स्थिति का आकलन किया जा रहा है जिससे की मनमोहन सरकार पर दबाव बनाया जा सके. केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मुलायम उत्तर प्रदेश के समाजवादी सांसदों के साथ अन्य दलों के सांसदों को भी अपने साथ लाना चाहते हैं, वह यह प्रयोग अपनी पिछली सरकारों में भी कर चुके हैं. बहरहाल, सपा प्रमुख ने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छह महीने के भीतर प्रदेश में दिखने तथा महसूस किया जाने वाला परिवर्तन लाने की चुनौती देते हुए चुनाव घोषणापत्र पर अमल करने की नसीहत दी और कहा कि लोहिया वादाख़िलाफ़ी को भी भ्रष्टाचार मानते थे. इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पिछली बार हमारी सरकार पर यही आरोप लगा था, बावजूद इसके कि सरकार ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम किया था. उन्होंने इसी क्रम में कहा कि मध्य प्रदेश और बिहार की सरकारें वही कार्यक्रम लागू कर रही है जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू किए थे. सपा प्रमुख मुलायम ने भले ही मध्यावधि चुनाव का शिगूफ़ा छोड़ा हो, लेकिन उनके विरोधी इस बात को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं हैं. कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने मुलायम के बयान पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार बहुमत में है, उसको कोई ख़तरा नहीं है. ऐसे में मुलायम मध्यावधि चुनाव की संभावना किस आधार पर जता रहे हैं, यह समझ से परे है. भाजपा के प्रवक्ता विजय पाठक का इस संबंध में कहना था कि समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, वह कांग्रेस से दूरी बनाकर नहीं चल सकती. अन्यथा, इसके प्रमुख की आय से अधिक संपत्ति की फाइल आगे बढ़ जाएगी.

**अजय कुमार**
feedback@chauthiduniya.com

# जस्टिस काटजू ने ली मीडिया की क्लास

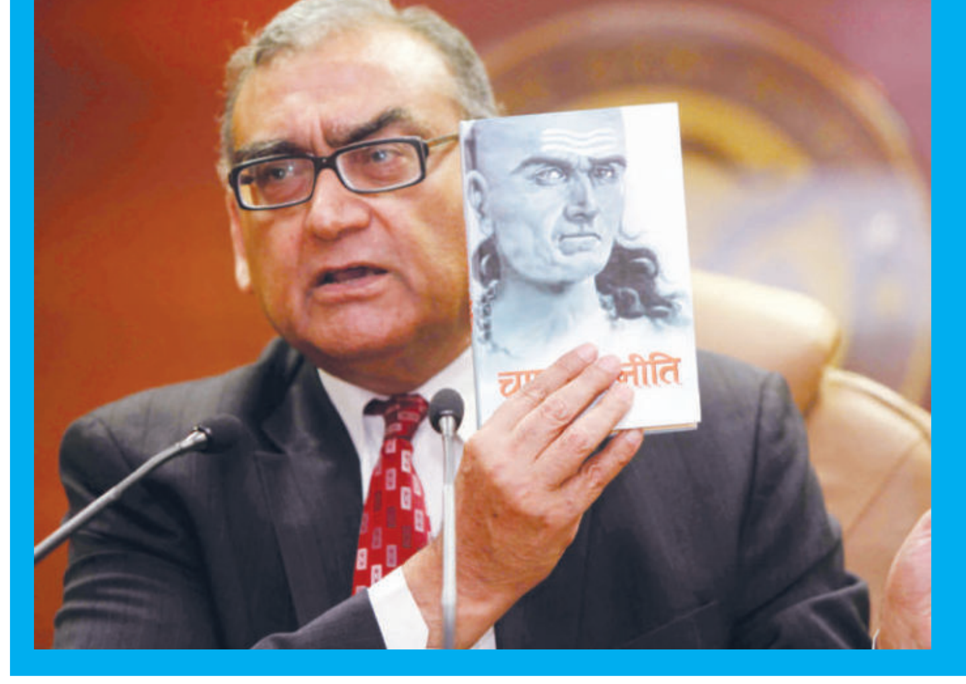

27 मार्च का दिन लखनऊ के पत्रकारों के लिए अच्छा नहीं गुजरा. हमेशा दूसरे की क्लास लेने वाली मीडिया की ही इस दिन क्लास लग गई. मीडिया की क्लास के गुरू थे भारतीय प्रेस परिषद् के इतिहास के सबसे अधिक चर्चित चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू (अवकाश प्राप्त) प्रेस की स्वतंत्रता हनन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए चार दिवसीय दौरे पर लखनऊ पधारे थे. उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की. इस दौरान अपनी बेबाक छवि के चलते काटजू ने ख़ूब सुर्ख़ियां बटोरी. एक ओर मीडिया के ग़ैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार के लिए उन्होंने फटकार लगाई तो दूसरी तरफ़ मीडिया कर्मियों के साथ नाइंसाफी करने वालों को भी वह खरी-खोटी सुनाने से नहीं चूके. वह अन्ना हजारे से लेकर मायावती और आरटीआई सहित कई मुद्दों पर बोले. कुछ मीडियाकर्मी अपनी हद भूलकर काटजू से ही सवाल-जवाब करने लगे तो वहीं काटजू की प्रेस वार्ता के दौरान सूचना निदेशक की उपस्थिति को देखकर मीडिया कर्मियों ने अच्छा-खासा हंगामा किया. वह पत्रकारों के व्यवहार को देखकर हतप्रभ भी लगे. फिर भी उन्होंने अपनी बात रखी. जस्टिज काटजू इस दौरान प्रेस काउंसिल की ताक़त बताने से भी नहीं चूके. उन्होंने यह कह कर खलबली मचा दी कि प्रेस परिषद का मुख्यमंत्रियों पर अंकुश है. किसी भी समय राष्ट्रपति से कहकर मुख्यमंत्री को हटावा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं. मीडिया समाज का आईना होता है, उसे जस्टिस काटजू ने कई बार आईना दिखाया. ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा की जा रही निगेटिव रिपोर्टिंग से वह ख़ासे ख़फ़ा दिखे. उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने यूपी सरकार के शपथ लेते ही कह दिया कि प्रदेश में गुंडाराज आ गया. सरकार को कुछ समय तो काम करने के लिए मिलना ही चाहिए था. नई सत्ता आई है, मुखिया युवा है, आधुनिक विचारों से प्रेरित हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें काम करने का मौक़ा दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रेस काउंसिल का कोई नियंत्रण नहीं है. प्रधानमंत्री से कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी काउंसिल के अधीन लाने के लिए वह क़दम उठाएं. बेबाक टिप्पणी के लिए पहचाने जाने वाले काजटू ने समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन को भी आड़े हाथों लिया. उनका कहना था कि अन्ना हजारे में वैज्ञानिक सोच नहीं हैं. अभी तक मैं उनके आंदोलन पर चुप रहा हूं, लेकिन लगता है कि कुछ बोलना चाहिए. उनके अपने विचार थे कि जिस जनलोकपाल की बात की जा रही है, वह यदि बन गया तो सरकारें काम नहीं कर पाएंगी. कर्मचारियों के ख़िलाफ़ शिकायतें निपटाने के लिए 50-55 हज़ार लोकपाल बनाने पड़ेंगे. बात को आगे बढ़ाते हुए वह बोले कि जन सूचना अधिकार क़ानून (आरटीआई) को भी ख़त्म कर देना चाहिए. उसने सरकार की नाक में दम कर रखा है. इसके ग़लत इस्तेमाल से देश की आधी ब्यूरोक्रेसी तबाह है. आधा समय तो लोगों के ग़लत और औचित्यहीन सवालों के जवाब देते ही निकल जाता है. पत्रकारों के हितों की बात करते हुए पूर्व जस्टिस काटजू ने कहा कि अब हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर 16 नवंबर को देश के सात पत्रकार सम्मानित होंगे. इसमें फोटो जर्नलिस्टों को भी शामिल किया जाएगा. काटजू ने कहा कि काउंसिल ने प्रदेश सरकार से कहा है कि पत्रकारों को पेंशन और परिवारों को बीमा मुहैया कराया जाए. यूपी में पत्रकारों और अख़बारों के सम्मान के लिए जल्द विज्ञापन और पत्रकार समिति का गठन होगा. समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार होंगे, जबकि सचिव पद पर ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाएगा. जस्टिज काटजू ने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ़ करते हुए कहा कि वह युवा और नई सोच के व्यक्ति हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को चाणक्य नीति और महाभारत का शांति पर्व पढ़ने की सलाह दी, जिसमें लिखा है कि अच्छा शासन कैसे चलाया जाए. जस्टिज काटजू ने अपने दौरे के दौरान पत्रकारों के उत्पीड़न के सौ से अधिक मामलों की सुनवाई की.

**अजय कुमार**
feedback@chauthiduniya.com

# उत्तर प्रदेश को भूले राहुल भैया

विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने यूपी को लेकर काफ़ी आत्मीयता दिखाई थी. चुनावी सभाओं में कई बार उन्होंने दोहराया कि वह राज्य की तस्वीर बदलने आए हैं. कांग्रेस चाहे हारे या जीते मैं यहां आता रहूंगा. मुझे यहां आने से कोई नहीं रोक सकता. पिछले 22 सालों में उत्तर प्रदेश की दुर्दशा के लिए उन्होंने गैर-कांग्रेसी सरकारों को कोसा. प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने जनता से पांच वर्ष मांगे तो केंद्र ने कई घोषणाएं करके जनता को खुश करने की कोशिश की. मुस्लिम आरक्षण, सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशें लागू करने जैसे तमाम वायदे किए. बुंदेलखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात कही, लेकिन जनता ने राहुल को नकार दिया और अखिलेश पर भरोसा जताया. बस, फिर क्या था राहुल जनता से किए वायदे भूल गए तो केंद्र ने भी आंखे फेरने में देरी नहीं की. वह चुनाव बाद यूपी का रास्ता ही भूल गए हैं. कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी के नतीजे तो काफ़ी दुख देने वाले रहे. जिस तरह से कांग्रेस की यहां फजीहत हुई इससे तो यही लगता है कि वर्ष 2014 के आम चुनाव में सोनिया और राहुल अपनी सांसदी बचाए रखने के लिए राज्य से बाहर किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं. इसकी वजह उत्तर प्रदेश के प्रति दस जनपथ का विश्वास कम हो जाना है.

कांग्रेस के युवराज ने चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली में ही हार के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हुए अपने कृत्यों की इतिश्री कर ली थी. उन्होंने हार की तो ज़िम्मेदारी ले ली लेकिन उत्तर प्रदेश आकर उन मतदाताओं को धन्यवाद देना ज़रूरी नहीं समझा जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था. कांग्रेस की हार का सबसे अधिक आघात बुंदेलखंड को लगा. चुनावी मौसम में राहुल एंड कंपनी ने बुदेलखंड की जनता से वादा किया था कि उनके यहां केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोला जाएगा, लेकिन हार से बौखलाई कांग्रेस ने बुंदेलखंड में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय खोलने के अपने वादे को ठंढ़े बस्ते में डाल दिया. बजट में विश्वविद्यालय के लिए कोई राशि ही नहीं आवंटित की गई. न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण सरकार की तरफ़ से आया. राहुल ने भी अपनी सरकार से यह पूछना उचित नहीं समझा कि क्यों बुंदेलखंड में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया. राहुल और कांग्रेस जिस तरह से अपने वायदे से पीछे हटे हैं इससे तो यही लगता है कि राहुल प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए नहीं अपनी सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. वह प्रदेश के विकास को लेकर जो चिंता जता रहे थे, वह नाटक था. दरअसल वह उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर काबिज होना चाहते थे, इसीलिए वह जनता को बरगला रहे थे. आश्चर्य होता है कि जिस घोषणा के बल पर कांग्रेस तत्कालीन बसपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, उसको लेकर उसकी सोच पूरी तरह से राजनीतिक थी. राहुल ने बुंदेलखंड की दुर्दशा के लिए मायावती सरकार को कसूरवार ठहराया था, लेकिन उनकी सोच में भी खोट था, यह बात अब साफ़ हो रही है. हो सकता है राहुल के दिल की बात बुंदेलखंडवासियों ने पहले ही पढ़ और समझ ली हो, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की ज़रूरत न समझी हो. राहुल और कांग्रेस ने जब केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी तब उन्होंने यह भी कहा था कि प्रदेश सरकार इस काम में सहयोग नहीं दे रही है. फिर भी वह इस विश्वविद्यालय की स्थापना करके ही रहेंगे. इतना ही नहीं झांसी स्थित राष्ट्रीय घास एवं पशुचारा अनुसंधान संस्थान की अतिरिक्त ज़मीन भी विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए तो विश्वविद्यालय का विचार ठंढ़े बस्ते में जाने में देर नहीं लगी. वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस अपने वायदे से मुकरी हो. ऐसा ही कुछ हाल अमेठी और रायबरेली में भी देखने को मिलता है. अब तो यहां की जनता कांग्रेसी वायदों से ऊब सी गई है. इसी कारण कांग्रेस को अबकी अपने गढ़(रायबरेली-अमेठी)में भी हार का मुंह देखना पड़ा. उत्तर प्रदेश बदलने के नारे के साथ यूपी की जंग में कूदी कांग्रेस की हार ने इसके नेताओं को औकात बता दी है. नेहरू-गांधी परिवार के पूरे कुनबे के पसीना बहाने के बाद भी जनता कांग्रेस के प्रति ज़रा भी नहीं पसीजी. बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा करने वाले कांग्रेसी नेताओं की जुबान अब सिल गई है. दिग्विजय सिंह एक तरह से यूपी छोड़कर भाग गए हैं, वहीं प्रदेश नेतृत्व हार के कारणों की तलाश अभी तक पूरी नहीं कर पाया है. बसपा, भाजपा, पीस पार्टी और अन्य छोटे-छोटे दलों तक में हार को लेकर मंथन चल रहा है, वहीं एक-दूसरे को नीचा दिखाने को आतुर रहने वाले कांग्रेसी हार के कारणों की समीक्षा के लिए बैठक तक नहीं कर पा रहे हैं. चुनावी मौसम में दिन में सैकड़ों सभाएं और रोड शो कर चुके राहुल तो अब तक हार के सदमें से उबर ही नहीं पाए हैं. राजनीतिक पंडित कांग्रेस की समीक्षा बैठक नहीं होने का कारण अविश्वास की कमी को बताते हैं. कई नेता तो दबी जुबान से यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने हार की ज़िम्मेदारी ले तो ली है, अगर कांग्रेस जीतती तो राहुल को इसका श्रेय जाता तो हार कि लिए भी वही ज़िम्मेदार हैं. कांग्रेसी समीक्षा बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं इसकी बानगी रायबरेली में देखने को मिली, जहां बात गाली-गलौज से हाथापाईं तक पहुंच गई. काफ़ी मशक्कत के बाद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के एल शर्मा की मौजूदगी में एक पूर्व विधायक ने गुस्से में आकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख को ही पीट दिया. लालगंज इलाक़े के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयशंकर सिंह ने पूर्व विधायक अशोक सिंह उनके पुत्र अविनाश सिंह और भाई के ख़िलाफ़ रायबरेली के भोदकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर जता दिया कि पार्टी के भीतर अनुशासन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. यह स्थिति तब ही आती है जब कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास अपने नेतृत्व से उठ जाता है. जैसा की आजकल कांग्रेस में हो रहा है, इसका नेतृत्व लगातार विवादित और कमजोर होता जा रहा है, जो नेतृत्व अपनी पार्टी को जीत दिलाने में नाक़ाम साबित होता है उसकी पकड़ पार्टी पर कमज़ोर हो जाती है. आज सोनिया और राहुल कमजोर साबित हो रहे हैं, ऐसी ही स्थिति का सामना पूर्व में इंदिरा गांधी को करना पड़ा था, तो अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव गांधी भी ऐसी विषम स्थितियों से बच नहीं पाए थे. वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो उसके बाद जो हालात बने इससे वह ठगी सी रह गईं. उनके राजनीतिक करियर पर सवाल खड़े किए जाने लगे. बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, राज मंगल पांडे जैसे तमाम नेताओं ने इंदिरा से बगावत करके अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था. इसी प्रकार वर्ष 1984 में मां इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजनीति के मैदान में क़दम रखने वाले उनके पुत्र राजीव गांधी को वीपी सिंह के कारण काफ़ी परेशानी और जिल्लत झेलनी पड़ी थी. इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए. कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन की उपाधि मिली लेकिन वह बोफोर्स तोप ख़रीद के विवादों में ऐसे घिरे की फिर उबर नहीं पाए. कांग्रेस चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई. पार्टी में उनका मुखर विरोध होने लगा.

ऐसे ही हालात एक बार फिर दिख रहे हैं. बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेसियों का सोनिया परिवार से विश्वास उठता जा रहा है. कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका के एक माह के सघन प्रचार के बाद भी पार्टी रायबरेली की पांच विधानसभा सीटें हार गई. चुनाव के दौरान मंच पर गुस्से में विपक्षी दलों पर गरजने वाले तथा सपा का कथित घोषणा-पत्र फाड़ने वाले राहुल का यूपी में इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है. बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, जब राहुल भैया यहीं रहने और मेल-मुलाकात बनाए रखने के बड़े-बड़े वायदे करते थकते नहीं थे. चुनाव नतीजे आने के बाद प्रदेश मुख्यालय एक तरह से भूतों का डेरा बन गया है. कोई यह बताने वाला नहीं है कि 2009 के लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस की गाड़ी पटरी पर ठीक-ठाक गति से चल पड़ी थी, वह वर्ष 2012 आते-आते पटरी से उतर कैसे गई. यूपी कांग्रेस के मुख्यालय जाओ तो वहां पार्टी का हाल बताने वाला कोई नहीं मिलता. दिग्विजय सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, श्री प्रकाश जायसवाल, पीएल पुनिया, रीता बहुगुणा जोशी सब भूमिगत हो गए हैं. कांग्रेस की अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने हार की नैतिक ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए त्यागपत्र आलाकमान को भेज दिया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान त्यागपत्र स्वीकारने या नकारने के बारे में कोई फ़ैसला अभी तक नहीं ले पाया है. चर्चा यह भी है कि कोई दूसरा नेता प्रदेश कांग्रेस की बागडोर संभालने को तैयार ही नहीं है. इसका कारण वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव हैं. कांग्रेसी नेताओं को पता है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, हार का ठीकरा उसके सर फोड़ दिया जाएगा. ऐसे में कोई क्यों आगे आए. इससे बड़ी बात यह है कि यहां चलनी राहुल और सोनिया की ही है. बाक़ी तो सब तमाशबीन बने रहने को मजबूर होंगे. कांग्रेसी इस बात से अंजान नहीं है कि टिकट वितरण में मनमानी और भाई भतीजावाद, केंद्र सरकार की नाक़ामी और राहुल की कच्ची राजनीतिक समझ ने कांग्रेस का कबाड़ा कर दिया. कांग्रेसी तो यहां तक कहते हैं कि भले ही राहुल कुछ न करते लेकिन यदि वह केंद्र के भ्रष्टाचार पर दो शब्द भी बोल देते तो उनपर लोग विश्वास कर लेते, लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया. वह जनता को बेवकूफ समझते रहे और जनता ने उन्हें बेवकूफ बना दिया. कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो उसे इस हार से सबक लेना ही होगा. उसे उन नेताओं को किनारे करना होगा जो यह मान कर चलते हैं कि जनता बेवकूफ होती है. कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए. इसके अलावा उन नेताओं के विरूद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए जो केंद्र में मंत्री और सांसद बने बैठे हैं, लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र की जनता का विश्वास खो चुके हैं. जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं किया इसका कारण तलाशना चाहिए न कि हक़ मारकर या उसके अधिकारों में कटौती करके जनता का विश्वास जीता जा सकता है. कांग्रेस को बताना ही होगा कि वह बुंदेलखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात से पीछे क्यों हट गई, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग के बारे में वह कितनी आगे बढ़ी है. प्रदेश की जनता के लिए उसके दिमाग़ में कोई विजन है भी या वह हवा में तीर चला रही है. राहुल अब न दलितों के यहां खाना खाने पहुंच रहे हैं, न ही गांवों में पंचायत लगा रहे हैं. खेतों में घूमने का भी उनका मन नहीं करता है. प्रदेश की जनता राहुल के आने की आस लगाए बैठी है. हो सकता है कुछ दिनों बाद राहुल फिर से वैसे ही जनता से साथ घुलते-मिलते नज़र आएं जैसे पहले नज़र आते थे, आखिर वर्ष 2014 के चुनाव भी तो उन्हें जीतना है, वर्ना वह पीएम कैसे बनेंगे.

**अजय कुमार**
feedback@chauthiduniya.com

# ईमानदारों पर तालिबानी क़हर

उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई है. कड़क छवि वाली मुख्यमंत्री रही मायावती की जगह सत्ता के शीर्ष पर एक ताजा-तरीन चेहरा लोगों के दिलों को छू रहा है, लेकिन उनकी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है कि सब सरकारें एक जैसी होती हैं. अगर ऐसा न होता तो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लखनऊ में अनशन पर बैठे एक अधिकारी की बात सुनने की बजाए उसे पुलिस के मार्फत जबर्दस्ती मानसिक चिकित्सालय नहीं भेज दिया जाता, लेकिन डॉक्टरों ने उक्त अधिकारी को मानसिक रोगी मानने से इंकार कर दिया. ऐसा ही एक वाकया मायावती राज में भी देखने को मिला था, तब डीआईजी अग्निशमन डीडी मिश्रा ने विभागीय भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ अपना आक्रोश मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किया था. मिश्र एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, इसलिए मायावती सरकार उनके ऊपर कोई और आरोप तो नहीं लगा पाई थी, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताकर मानसिक अस्पताल में भर्ती ज़रूर करा दिया था. उनको किसी से मिलने-जुलने की छूट नहीं दी गई थी.

उस समय समाजवादी पार्टी ने बसपा सरकार के इस कृत्य की न केवल भर्त्सना की थी, बल्कि ख़ूब हायतौबा भी मचाई थी. तब प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने पूरे मामले की जांच के निर्देश ज़रूर दे दिए थे, लेकिन अधिकारी के विरूद्ध अमानवीय व्यवहार करने वालों के ख़िलाफ़ कोई क़दम नहीं उठाया गया. भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले एलाइड सेवा के पीसीएस समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही. रिंकू की ग़लती बस इतनी थी कि वह आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार का ख़ुलासा करना चाहते थे, जो लखनऊ में विधान भवन के सामने अपने पूरे परिवार के साथ धरना दे रहे थे, उनके ऊपर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है. रिंकू सिंह लोकसेवा आयोग से चयनित होने के बाद 24 नवंबर 2008 को मुजफ्फरनगर में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे. प्रोबेशन के दौरान किसी अधिकारी को वित्तीय चार्ज नहीं मिलता है. इसलिए रिंकू को भी वित्तीय चार्ज नहीं मिला था. इस दौरान उन्हें वृद्धावस्था पेंशन एवं कॉलेजों में अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति आदि में क़रीब 50 करोड़ रुपए की धांधली की शिकायत मिली. इस पर रिंकू ने कैशबुक और अनुप्रयोग धनराशि का हिसाब मांगा तो उन पर जानलेवा हमला हो गया जिसमें उनकी एक आंख फोड़ दी गई, लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी. उन्होंने आरटीआई के तहत जिलाधिकारी, विभागीय निदेशक एवं प्रमुख सचिव से जानकारी मांगी, लेकिन हर तरह से उनके हाथ मायूसी ही लगी. इतना ही नहीं उनका तबादला अंबेडकर आईएएस/पीसीएस ट्रेनिंग लखनऊ में कर दिया गया. इसी बीच अन्ना हजारे ने 25 मार्च को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दिल्ली में अनशन करते हुए अपने अनुयायियों से ज़िलों में अनशन की बात कही तो रिंकू भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लखनऊ आकर अनशन पर बैठ गए. उनका साथ देते हुए उनके माता-पिता और छोटी बहन, ताऊ, बुआ, जेएनयू के छात्र प्रवीण के अलावा डीएस कॉलेज, डिग्री कॉलेज खेर, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर के भी कुछ छात्र आए थे. एलाइड सेवा के अधिकारी के धरना देने की ख़बर से लखनऊ प्रशासन में हड़कंप मच गया.

कई अधिकारी उन्हें मनाने के लिए पहुंच गए, लेकिन इन अधिकारियों के पास भी रिंकू के लिए आश्वासन के अलावा कुछ नहीं था. यह अधिकारी आश्वासन के सहारे रिंकू का धरना ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो रात के अंधेरे में क़रीब डेढ़ बजे पुलिस उन्हें मानसिक रोगी क़रार देकर उठा ले गई. पुलिस और प्रशासन रिंकू को ठीक वैस ही मानसिक रूप से बीमार घोषित करना चाहता थे जैसे कुछ माह पूर्व उसने डीआईजी अग्निशमन डीडी मिश्रा को घोषित किया था. पूरे प्रकरण में अच्छी बात यह रही कि धरती के भगवान कहलाए जाने वाले डॉक्टरों ने कोई चूक नहीं की. उन्होंने साफ़ कह दिया कि रिंकू मानसिक रोगी नहीं हैं, जिसके बाद पुलिस को उनका ब्लड प्रेशर गिरने की नई कहानी बनानी पड़ी. जिस तरह से ईमानदार अधिकारियों की जान ले ली जाती है, उन्हें तालिबानी तरीक़ों से प्रताड़ित किया जाता है, इससे तो यही लगता है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आसान नहीं है. इसमें ख़तरा ही ख़तरा है.

**संजय सक्सेना**
feedback@chauthiduniya.com

# जो सुना, देखा और महसूस किया वही कलमबंद किया

लखनऊ के जयशंकर प्रसाद सभागार में आयोजित राजेंद्र सिंह बेदी का व्यक्तित्व और कृतित्व विषयक संगोष्ठी में उर्दू के वरिष्ठ विद्वान प्रो. शारिब रूदौलवी ने प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र सिंह बेदी के उर्दू साहित्य में योगदान पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए. चार दिवसीय आयोजन के तीसरे दिन उन्होंने कहा कि असल नई कहानी का आगाज राजेंद्र सिंह बेदी से माना जाना चाहिए. प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने दूसरे रचनाकारों की तरह अपने ऊपर ऐसा कुछ हावी नहीं होने दिया, जिसके उनकी लेखनी से जो रचनाएं जन्मी, वह अलग पुट लिए हुई थीं यह उनकी कहानियों को पढ़ने पर महसूस होता है. संगोष्ठी में वरिष्ठ आलोचक प्रो. वारिस किरमानी ने भाग लेते हुए कहा कि हिंदुस्तानी कहानी के मयार में बेदी के अफ़साने विश्वस्तरीय हैं. उर्दू के वरिष्ठ कथाकार आबिद सुहैल ने बेदी के बारे में बताया कि बेदी की कहानियां उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में रखे जाने की हक़दार हैं. वरिष्ठ शायर एवं उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष मलिकजादा मंजूर अहमद बोले, बेदी, मंटो और कृष्णचंदर सरीखे कथाकारों के कारण ही उर्दू साहित्य विश्व स्तर को छू पाया है. लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभागाध्यक्ष अनीस अशफाक़ ने कहा कि उर्दू अदब में मंटो और बेदी दो ऐसे रचनाकार हैं, जिनसे ज़िंदगी के अफ़सानों को अदब का अफ़साना बनाने का हुनर सीखा जा सकता है. संगोष्ठी में जहां कुतुबुल्लाह ने बेदी की तीन कहानियों को केंद्रित करते हुए कहा कि यह बेदी का अलग आर्ट था, जो अवाम के चेहरे को महसूस करते थे. डॉ. सबीहा अनवर ने विचार रखे कि बेदी की कहानियां हमारी ज़िंदगी की कहानियां हैं. गर्मकोट की शम्मी हो या लालवंत की राजो, उन्हें पढ़कर लगता है कि इन किरदारों के बिना नगमा पूरा ही नहीं होता. एक तरह से उनके किरदार सोते जहनों को जगाने वाले हैं. उर्दू-अरबी-फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति अनीस अंसारी ने कहा कि बेदी के काम में शोरगुल नहीं है. वह कम शब्दों में बड़ी चीजें कहते हैं. संचालन कर रहे प्रो. इर्तिजा करीम ने कहा कि बेदी ने लेखन की शुरूआत मोहनसिन लाहौरी नाम से की. उन्होंने अदब के साथ फिल्मी दुनिया में मुकम्मल जगह बनाई. वहीं शफीक अहमद ने दाग़, मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती जैसी फिल्मों में योगदान का जिक्र किया. डॉ. मुश्ताक ने कहा कि बेदी ने जो सुना, देखा और महसूस किया वही, कलमबंद किया.

**दर्शन शर्मा**
feedback@chauthiduniya.com

# मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की मुहिम

सत्ता रूढ़ सपा सरकार के आने से मुस्लिम महिलाओं में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलने लगी है. मुलायम के घोषणा पत्र में मुस्लिम लड़कियों को तीस हज़ार रुपये दिए जाने की घोषणा से मुस्लिम समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति ललक बढ़ गई है. यह अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में भी चर्चा का विषय रहा. अखिल भारतीय मुस्लिम महिला शैक्षिक सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओं में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पढ़ लिखकर काबिल बनने पर ज़ोर दिया गया. मिल्लत एकेडमी के तत्वावधान में बिजनौर के राजा का ताजपुर में आयोजन हुआ, जहां जामैतुल फैसल में विभिन्न प्रांतों से जुटी शिक्षाविद् महिलाओं के बीच आयोजित इस सम्मेलन में मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन के कारणों एवं उनमें शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के तौर तरीक़ों पर चर्चा हुई. कार्यक्रम में दारूल उलूम देवबंद के उपकुलपति मौलाना सालिम कासमी की पुत्री इज्मा नाहेद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि किसी भी कौम या समाज की उन्नति के लिए तालीम रीढ़ की हड्डी होती है. कौम की महिलाएं शिक्षित होंगी तो उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे. शिक्षित परिवार में ही धर्म के अनुरूप एक अच्छे आचरण की अपेक्षा की जा सकती है. परिवार शिक्षित होगा तो समाज भी शिक्षित होगा. मुस्लिम महिलाओं में पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका शिक्षित न होना है, जिसकी वजह से समाज की तरक्की भी प्रभावित होती हैं. सम्मेलन में जी सलाम टीवी चैनल की रीडर शमीना ताबिश ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को पढ़ने लिखने के साथ ही हुनरमंद भी होना चाहिए. इससे उनका आर्थिक पिछड़ापन भी दूर होगा. हर परिवार को यह कोशिश करनी चाहिए कि उनके परिवार में कोई भी लड़की अनपढ़ न रहे. दिल्ली से आई प्रो डॉ. हसीना हासिया ने कहा कि इस वैज्ञानिक युग में महिलाओं ने भी जहां हर क्षेत्र में तरक्की की है, वहीं मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के अभाव में आज भी पिछड़ी हुई हैं. उन्होंने अपनी सोच को बदलने तथा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को कहा. सम्मेलन में वाजिगा तबस्सुम, अलीगढ़, हमीदा बेगम रामपुर, बी बातमा लखनऊ, असमा एजाज दिल्ली, राफिया शमसी रामपुर ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए. संचालन गुलनाज परवीन ने किया. सम्मेलन में सपा की सरकार द्वारा मुस्लिम लड़कियों को हाईस्कूल पास करने पर तीस हज़ार रुपये दिए जाने की घोषणा पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की. कार्यक्रम को संपन्न कराने में मिल्लत एकेडमी के चेयरमैन मौलाना सिराजुद्दीन नदवी, यासीन जकी, रिजवान अहमद आदि ने सहयोग किया.

**दर्शन शर्मा**
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467



# सरकार के द्वारे पहुंचा कोपस्थल

फोटो-प्रभात पाण्डेय

संजय सक्सेना

सरकार से नाराज़ जनता-जनार्दन को अपनी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाने के लिए अब राजधानी के किसी कोने में बैठकर हक़ की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी. सरकार और शासन-प्रशासन से परेशान और दुखी लोग विधान भवन के ठीक सामने कोप में बैठकर अपनी मांगे और आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकेंगे. क़रीब पांच साल बाद पुराने कोप स्थल पर फिर से रौनक लौटेगी. बसपा राज में वर्ष 2009 में यहां से हटा कर कोप स्थल पहले गोमती नदी के किनारे शहीद स्मारक और फिर झूलेलाल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया था. यह दोनों ही स्थल विधान भवन से न केवल काफ़ी दूर थे बल्कि भीड़भाड़ वाले इलाक़े में गोमती के किनारे होने के कारण ख़तरनाक भी माने जाते थे. सपा सरकार ने पुराने कोप स्थल को बहाल करके उन्हें मनोबल प्रदान किया है जो अपने हक़ और न्याय के लिए सरकार से लड़ने से भी नहीं चूकते हैं. सरकार के इस फ़ैसले से एक तरह से कोप स्थल सरकार के द्वार पहुंच गया है. सबसे अच्छी बात यह रही कि सरकार ने यह घोषणा हमेशा सत्ता के ख़िलाफ़ संघर्ष करने वाले समाजवादी डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के दिन की. यह सच्चे अर्थों में लोहियाजी को श्रृद्धांजलि भी है.

अखिलेश सरकार के नए फरमान से उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है जो प्रदेश के कोने-कोने से अपनी मांगों को लेकर यहां आते हैं. भले ही इससे कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है, लेकिन सपा सरकार के इस फ़ैसले से सभी खुश नज़र आए. वह लोग ख़ासकर जो विधान भवन के समाने बने दशकों पुराने कोप स्थल की यादें अपने मन में समेटे हुए हैं. यहां से कई ऐसी जंग सरकार के ख़िलाफ़ लड़ी जा चुकी हैं जो अंजाम तक पहुंचने के बाद ही ख़त्म हुई थी. छोटे से लेकर बड़े तक सभी को विधान भवन के सामने का कोप भवन काफ़ी रास आता है. कई नामचीन हस्तियां और साधू-संत यहां सरकार के ख़िलाफ़ धरना देकर सुर्ख़ियां बटोर चुके हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने संघर्ष के दिनों में कई बार यहां डेरा डाल चुके हैं.

बात वर्ष 1998 की है तब प्रदेश में भाजपा की हुकूमत थी और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री. कल्याण की छवि कट्टर हिंदुत्व की थी. वह धर्मालंबियों का काफ़ी आदर-सम्मान करते थे. एक बार रामनगरी अयोध्या के कुछ साधू-संत भी उनसे मिलने के लिए पहुंच गए. कल्याण सिंह व्यस्तता के कारण उन्हें समय नहीं दे पाए. इससे नाराज़ साधू महात्मा विधान भवन के सामने कोप स्थल पर बैठ गए. पहले तो सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन साधू संतों का जमावड़ा बढ़ने लगा तो सरकार जागी. तुरंत संतों को मनाने की कोशिशें शुरू हो गईं. संत चाहते थे कि मुख्यमंत्री अपने कृत्य के लिए संतों से माफ़ी मांगे. सरकार की तरफ़ से मुख्य सचिव और फिर फ़ैज़ाबाद के तत्कालीन सांसद विनय कटियार को साधू महात्माओं को मनाने के लिए भेजा गया, लेकिन संतों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी. दस दिन तक संत डटे रहे. इसके बाद जब कल्याण ने माफ़ी मांगी तभी मामला शांत हुआ. इसी प्रकार राजनाथ की सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठने की ज़िद पर अड़ गए. सिंह धरने पर बैठते इससे पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह कोप स्थल पर पहुंच गए. उन्होंने किसानों की मांगे सुनी, उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, तब जाकर बात बनी. कटोरी देवी की चर्चा के बिना कोप स्थल का इतिहास अधूरा ही रहता है. वह लंबे समय तक कोप स्थल पर धरने की साक्षी बनी. कटोरी देवी एक शिक्षिका थीं जो क़रीब दो दशक पूर्व सुर्ख़ियों में आई थीं. अपने हक़ की लड़ाई को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया. उन्हें कभी पुलिस पकड़ कर ले जाती तो वह छूटते ही कोप स्थल पर आकर बैठ जाती. बाद में कटोरी देवी का ख़ाकी वर्दी से इतना विश्वास उठ गया कि वह उन्हें देखते ही पत्थर मारने लगती. कटोरी देवी ने अपने हक़ की लड़ाई कई वर्षों तक लड़ी. उस समय मोती लाल बोरा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे. वह कटोरी देवी के साथ हो रहे अन्याय से काफ़ी दुखी दिखे. तत्कालीन राज्यपाल मोती लाल बोरा ने उन्हें राजभवन बुलाकर उनकी पीड़ा को न केवल समझा बल्कि उनकी हर मांग भी पूरी की.

इसी तरह 2001-2002 में एक सिख युवक के आत्मदाह की ख़बर ने भी ख़ूब सुर्ख़ियां बटोरी थी. इस तरह की कई लड़ाई यहां से लड़ी गई. व्यवस्था के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ ने कोप स्थल को ही अपना ठिकाना बनाया. वर्ष 2007 में जब बसपा राज आया तो उसे यह अच्छा नहीं लगा कि विधान भवन के सामने से सरकार को चुनौती मिले. इसलिए उसने धरना स्थल (कोप में बैठने की जगह) को बदलने का मन बना लिया. काफ़ी हायतौबा मची तो कुछ समय के लिए सरकार ने अपने इरादों पर विराम लगा दिया, लेकिन मौक़ा मिलते ही मायावती ने वर्ष 2009 में कोप स्थल बदल दिया. इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन मायावती ने किसी की नहीं सुनी. पहले शहीद स्मारक को कोप स्थल बनाया गया, लेकिन कोर्ट की सख्ती और एक हादसे के कारण सरकार को यहां से कोप स्थल को दूसरी जगह ले जाना पड़ा. यह तब हुआ था जब शिक्षामित्र अपनी मांगों को लेकर काफ़ी संख्या में धरना देने आए थे, पुलिस प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास की तरफ़ कूच नहीं करने देना चाहती थी, जब शिक्षामित्र नहीं माने तो पुलिस ने लाठी जार्च कर दिया. पथराव और लाठीचार्ज में इतनी बुरी तरह से भगदड़ मच गई कि कई शिक्षामित्र तो डर के मारे नदी में कूद गए. समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो विधान भवन के बाहर कोप स्थल फिर से बहाल हो जाएगा. बहरहाल, सरकार के इस फ़ैसले से उन लोगों को तो फ़ायदा होगा जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन धरना-प्रदर्शनकारियों की वजह से यहां लगने वाले जाम और अव्यवस्था से राहगीरों का फिर दो-चार होना पड़ सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

## क्रांतिरथ के साथ राजमहल पहुंचे अखिलेश

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग में एक लहर उत्पन्न हुई है. वह सब कुछ एक ही दिन में कर लेना चाहते हैं. ढेर सारी अपेक्षाओं आकांक्षाओं को संजोए युवा वर्ग की तमन्ना है कि युवा मुख्यमंत्री इसी शक्ल को अख्तियार कर लें, जैसा कि फिल्म नायक में एक दिन के मुख्यमंत्री की कार्रवाइयों को दिखाया गया है. यही वजह है कि सपा सरकार बनते ही सेवायोजन कार्यालयों में बेरोज़गारों का मेला लगने लगा है. अभी मुख्यमंत्री अपने को सेट करने में जुटे हुए हैं. उन्होंने अपना पुश्तैनी घर बदला है. वह 5 कालिदास मार्ग स्थित राजमहल में परिवार के साथ आ गए हैं. नए मुख्यमंत्री अखिलेश से पहले सपा सुप्रीमो तीन बार इसी राजमहल में निवास कर चुके हैं. अखिलेश इस सरकारी बंगले पर अपनी युवामंडली के साथ आए. कहते हैं आम लोगों से आबाद रहने वाले इस मुख्यमंत्री निवास स्थल पर पिछले कई मुख्यमंत्रियों ने जनता दरबार लगाकर जनता की फरियादें सुनी. प्रदेश के कोने-कोने से थकी हारी जनता जब इस दरबार में मत्था टेकती तो यहां उसकी बात ज़रूर सुनी जाती थी. उसे न तो कोपभवन का सहारा लेना पड़ता था और न ही गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठने की नौबत ही आती थी, लेकिन पुरुष मुख्यमंत्रियों की इस पुरानी परंपरा को महिला मुख्यमंत्री ने तोड़ दिया. जनता के लिए सारे दरवाज़े बंद कर दिए गए. यहां लोहे के बैरिकेट लगाकर आने जाने वालों पर ज़्यादा सख्ती कर दी गई. सिर्फ़ अंदर से फरमान जारी होने लगे. इन्हीं फरमानों को कुछ फेथफुल ब्यूरोक्रेट्स मीडिया के सामने प्रस्तुत करने लगे. यह सिलसिला पूरे पांच साल चला. यही नहीं बसपा सरकार ने विधानसभा के पास के कोपभवन या धरना स्थल को काफ़ी दूर गोमती नदी के किनारे स्थित झूले वाले पार्क में स्थापित करा दिया, जिससे आम लोगों की आवाज़ दबती चली गई. जनता की आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचना दूभर हो गया. ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बहिनजी से कुछ पूछ लें. मुट्ठीभर लोगों के सहारे उत्तर प्रदेश का राजकाज चलता रहा हैं. नए सीएम के आते ही यह कोठी जगमगा उठी है. इसके रास्ते आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं. वह अपने युवा साथियों के साथ तेवर में दिखे. उनके साथ वही युवा टीम थी, जो पिछले छह महीने से उनके क्रांतिकारी आंदोलन में क्रांति रथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली. रथयात्रा में उनके साथ लगातार रहे आनंद भदौरिया एवं सुनील यादव के अलावा सांसद धर्मेंद्र यादव, संजय लाठर, रामवृक्ष यादव, नईमुल हसन, नफीस अहमद, राजपाल कश्यप, निर्भय सिंह पटेल, रामसागर यादव, मनीष यादव और प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी उन्हें बधाई देने पहुंचे. इन लोगों के नाम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ज़ुबां पर थे, वह स्वयं उनके नाम ले रहे थे. वहीं पिता मुलायम सिंह ने आकर अखिलेश के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने पर आशीर्वाद दिया. उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव भी सपरिवार अखिलेश के घर आए. बहरहाल कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में समाजवाद का झंडा फिर लहराने लगा है. मुख्यमंत्री दरबार में चहल-पहल शुरू हो गई है. राजनीतिक तौरतरीक़ों में बदलाव हुआ है. समाजवाद का चेहरा चमकने लगा है. अब देखना यह है कि नए मुख्यमंत्री का यह इकबाल समाजवाद को कितना आगे ले जाने में कामयाब हो पाता है.

दर्शन शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

केवल 250/- में वर्ष भर अख़बार पढ़ें**

आमंत्रण ऑफर

अख़बार बुक करें और ले जायें आकर्षक उपहार

देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

देश के सबसे निर्भीक व विश्वसनीय पत्रकार

चौथी दुनिया

बुकिंग फार्म

रसीद सं. 501

लक्ष्मी मीडिया पब्लिकेशन

कार्यलय प्रबन्ध सम्पादक उ.प्र.एवं उत्तराखण्ड : सी-20, ट्रान्स यमुना,एन.एच.-2, आगरा

फोन : 0526-4064901, ई-मेल : chauthiduniyaup.uk@gmail.com

कृपया विवरण भरें और यह बुकिंग फार्म चौथी दुनिया प्रतिनिधि को दें.

☐ जी हां, मैं इस ऑफर और संलग्न नियमों के अंतर्गत बारह महीने की अवधि के लिए चौथी दुनिया अख़बार बुक कराना चाहता/चाहती हूं. बुकिंग राशि 250 रुपये नकद या चेक या डी.डी. तथा अपना आई.डी. प्रूफ लक्ष्मी मीडिया पब्लिकेशन के पक्ष में संलग्न करता/करती हूं.

श्री/श्रीमती..........

पता..........

..........

शहर.......... पिन कोड..........

फोन नं0 (घर).......... (मोबाइल)..........

ई-मेल..........

प्राप्त राशि (शब्दों में)..........

द्वारा ड्राफ्ट नं0/चेक नं0..........

दिनांक.......... से.......... तक

हस्ताक्षर प्रतिनिधि

हस्ताक्षर पाठक

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर), प्रबंध संपादक : 09837082462